MARCH
2021

IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE

- नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश
- मैरीटाइम इंडिया समिट 2021
- स्वेज नहर की रुकावट
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि
- भारत की विश्व धरोहर स्थलों की सूची

VISIT…

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामसयकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तयैार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट **www.iasbaba.com**दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – 'इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए ?

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 66 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो NOVEMBER-2020 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें **https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/**से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।**
- **इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्निsnippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारितPrelims MCQs) प्रस्तुत किया हैं जो आपको बेहतर revisionके लिए मार्गदर्शन करेंगे।**
- '**Must Read' section,**आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

'**Must Read' section**: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनसुरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

"Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them."

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- सरस आजीविका मेला, 2021
- खुजली घर नागालैंड : सजा का पारंपरिक रूप
- प्रसाद योजना के तहत माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर
- भारत की विश्व धरोहर स्थलों की सूची
- बामियान बुद्ध
- सिंहगढ़ किले का संरक्षण कार्य
- कूर्ग का देवारा कादु
- जापी, जोराई और गमोसा
- MICE रोडशो - मीट इन इंडिया '; छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर

राजनीति / शासन

- नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश
- सुगम्य भारत ऐप लॉन्च
- स्वच्छता सारथी फेलोशिप का शुभारंभ
- "फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021: डेमोक्रेसी अंडर सीज" रिपोर्ट
- नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक (MPI) 2020
- 'ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक, 2020
- पुलिस और जेल सुधार
- उत्तराखंड ILP सिस्टम
- राज्य चुनाव आयुक्तों पर SC का शासन
- दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य
- चुनावी वित्तपोषण
- पूजा का स्थल
- असम की छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं
- अगला सीजेआई ने सिफारिश की
- बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021
- नौकरशाही में सुधार
- संसदीय समितियाँ
- कॉर्पोरेट प्रशासन: अल्पसंख्यक शेयरधारक अधिकार: टाटा बनाम मिस्त्री

सामाजिक मुद्दे / वेलफ़ेयर

- हरियाणा नौकरी कोटा कानून (स्थानीय आरक्षण)
- साइबराबाद में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
- श्रमिक कल्याण पोर्टल
- मेरा राशन मोबाइल ऐप
- यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए केरल मॉडल
- जनसंख्या स्थिरीकरण
- आरक्षण की समीक्षा
- सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश में बिजली पारेषण व्यवस्था मजबूत करने के लिये संशोधित लागत को मंजूरी
- सूचकांक निगरानी प्रकोष्ठ (IMC)
- घुमंतू जनजातियों के विकास की पहल
- स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार विधेयक, 2021

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

- रेप और विवाह
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम
- स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका
- माहवारी तब्बू
- ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
- महिलाओं के लिए स्थायी आयोग

स्वास्थय समस्या

- कोविद -19 की दूसरी लहर
- इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IMPCL)
- विश्व स्वास्थ्य सभा की मेनिनजाइटिस (तानिकाशोथ) पर पहला संकल्प
- स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड
- औषधि मूल्य नियंत्रण
- सरकार कोविशिल्ड की खुराक के बीच अंतराल को बढ़ाने का फैसला
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की पहल
- नेशनल एलायड फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2021
- UNITAR ने (NDCs) से समयपूर्व मृत्यु दर को कम करने में भारत की प्रगति की सराहना
- आदिवासी टीबी पहल की शुरूआत
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश अवसर

सरकारी योजनाएँ

- 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में E-Daakhil पोर्टल शुरू हुआ
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन: नीति आयोग
- OCI कार्डधारकों के लिए शैक्षिक संस्थानों में NRI कोटा सीट
- ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्र डिजिलॉकर से लिंक होंगे
- 3 छतरी योजनाओं के तहत डब्ल्यूसीडी मंत्रालय की योजनाएं
- सरकारी स्कूलों में नल के पानी की आपूर्ति पर जानकारी
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN)
- ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ

अंतरराष्ट्रीय

- एफएटीएफ ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान का प्रभाव
- विकास नीति के लिए संयुक्त राष्ट्र की समिति (CDP)
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021
- आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह (CGETI)
- जो बिडेन की अफगानिस्तान शांति योजना
- पारंपरिक दवाइयों के एक वैश्विक केंद्र
- समाचारों में ज़ो समुदाय के लोग (Zo People)
- पानी की गुणवत्ता परीक्षणपरीक्षण की रूपरेखा
- सना पर हवाई हमले
- उइगर दुरुपयोग के लिए चीन पर लगाए गए प्रतिबंध
- स्वेज नहर की रुकावट
- चीन-ईरान ने किया 25 साल के लिए सहयोग समझौता
- द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया (HoA-IP)

भारत और विश्व

- घाना 'कोवैक्स' पहल के तहत टीका प्राप्त करने वाला पहला देश
- भारत-यूरोपीय संघ
- भारत-नाइजीरिया के बीच पहला आतंकवाद-रोधी संवाद
- भारत - स्वीडन वर्चुअल समिट
- भारत-जापान अंतरिक्ष संबंध
- ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बांध
- क्वाड चुनौतियां
- श्रीलंका का आतंकवाद पर युद्ध

- भारत के लिये हीलियम संकट
- संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवाएं कार्यालय (UNOPS)
- स्थायी सिंधु आयोग की 116 वीं बैठक
- भारत - ताइवान संबंध
- भारत-बांग्लादेश
- भारत, संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों (UNPKF) को COVID-19 वैक्सीन का बितरण किया

अर्थव्यवस्था

- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए श्रम संहिता
- बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता
- चन्नपटना शहर के बने खिलौने
- नगर निगम का बजट
- CAFE विनियम
- 'मर्चेंट डिजिटाइज़ेशन सम्मेलन 2021: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना
- कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति
- केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL)
- निजीकरण (Privatization)
- स्पेक्ट्रम नीलामी
- AT1 बॉन्ड: SEBI न्यू नॉर्म्स
- केयर्न कर शासन
- नई अम्ब्रेला इकाई (NUE)
- जिलावार निर्यात प्रोत्साहन योजना
- वर्ल्ड समिट आन द इनफार्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम 2021
- डिजिटल रूप से MSMEs को सशक्त बनाना
- केंद्रीय संवीक्षा केंद्र (CSC) और IEPFA मोबाइल ऐप
- वाणिज्यिक कोयला खनन का दूसरा ट्रेंच
- सुर्खिओ में केप ऑफ गुड होप स्थान
- विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) योजना

कृषि

- सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन
- कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि वोल्टेज प्रौद्योगिकी
- सिल्क सेक्टर में एग्रोफोरेस्ट्री

पर्यावरण/ प्रदूषण

- नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना
- जलवायु परिवर्तन
- गहिरामाथा समुद्री अभयारण्य
- स्वतंत्र पर्यावरण नियामक स्थापित करने में विफलता
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस - 2020 पुरस्कार प्राप्त किया
- समुद्री हिरन का सींग
- बम्बूसा बम्बोस ने नीलगिरि जीवमंडल को धमकी दिया
- आईक्यू एयर की वैश्विक वायु प्रदूषण रिपोर्ट
- एकल उपयोग प्लास्टिक के छिपी हुई महामारी
- यूरोपीय संघ द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट
- हिमाचल प्रदेश में जल संकट
- वाहन परिमार्जन नीति
- केन-बेतवा लिंक परियोजना
- जलवायु डेटा सेवा पोर्टल का शुभारंभ
- AEG12 कोरोना वायरस पर लगाम

समाचारों में जंतु / राष्ट्रीय उद्यान

- सुर्खिओं में प्रजातियां: हिमालयन सीरो
- 'हिप्निया इंडिका' (Hypnea indica) और 'हिप्निया बुलैटा' (Hypnea bullata: समुद्री शैवाल की दो नई प्रजातियां
- नचदुबा सिनथला रामास्वामी सदाशिवन

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- उड़ान योजना के तहत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस
- सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) स्कीम
- दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन
- अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021
- रामागुंडम में 100 मेगावाट का तैरता हुआ सौर ऊर्जा सयंत्र
- वन नेशन, वन गैस ग्रिड
- ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की 'टिकाऊ' दृष्टि
- ई-टेंडि्रंग पोर्टल 'प्रणीत'
- दीघा और कंकड़बाग सीवरेज परियोजना

विज्ञान और तकनीक

- अमोनिया -1 उपग्रह का प्रक्षेपण
- टीएलआर 7/8: इंडियन लैब द्वारा विकसित कोवाक्सिन का प्रमुख अणु

- मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (MTRC)
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण को जुटाना
- हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग
- मार्टियन 'ब्लूबेरी' पृथ्वी पर एक समानांतर मिलना
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, 2019
- RE-HAB परियोजना का पुन: शुरूआत
- जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- CALM2 म्यूटेशन
- इसरो की अंतरिक्ष संपत्ति संचालित करने के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
- लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक : लिडार (LIDAR)

आपदाप्रबंधन

- सिमलीपाल वन की आग
- एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- चीन की साइबर आंख और भारत
- मैरीटाइम इंडिया समिट 2021
- नेगेव लाइट मशीन गन्स (LMGs)
- ईंधन सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम
- UAPA अधिनियम के तहत गिरफ्तारी में वृद्धि
- पार्श्व निगरानी: साइबर अपराध वालंटियर्स कार्यक्रम
- मिलान-2T

विविध

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मार्च 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

सरस आजीविका मेला, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - संस्कृति और जीएस - II - स्वयं सहायता समूह; नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में-

- हाल ही में नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला, 2021 का उद्घाटन किया गया।
- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्री

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में अधिक महिलाओं को शामिल करना जो परिवार की आय बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभात हैं।
- इस मेला में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्व-सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं।

खुजली घर नागालैंड : सजा का पारंपरिक रूप

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -I- संस्कृति / समाज

सुर्खिओ में-

- नागालैंड के कुछ गाँव अपराध को कम करने के लिए सजा के पारंपरिक रूप को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह, स्थानीय तौर पर पायी जाने वाली, खुजली पैदा करने वाली लकड़ियों से निर्मित एक तंग, त्रिकोणीय पिंजरा होता है।
- मसांग-फंग एक स्थानीय पेड़ है जो जलन का कारण बनता है।
- नागा प्रथागत कानूनों के सामाजिक अपराधियों ने समुदाय के भीतर अपमान के कारण इस सजा को खत्म कर दिया।
- ऐसे खुजली वाले पिंजरों को नागमसी में खुजली घर के रूप में संदर्भित किया जाता है - एक पिजिन लिंगुआ फ्रैंका - हालांकि, प्रत्येक नागा समुदाय में इसका अलग नाम होता है।
- औ (AOS), नागालैंड के प्रमुख जनजातियों में से एक, इसे शि-की (मांस-घर) कहते हैं
- इस पिंजरे को आमतौर पर गांव में, आमतौर पर मोरंग या कुंवारों के वास-गृह के सामने या किसी एक मुख्य स्थान पर रखा जाता है। जिससे कैदी को पूरा गाँव देख सके।

संबंधित आलेख:

- नागालैंड मुद्दा: चरमपंथी समूह काउंटर्स गवर्नर

प्रसाद योजना के तहत माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -I - संस्कृति

सुर्खिओ में-

- प्रधान योजना के तहत माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नींव का पत्थर रखा गया।
- **मंत्रालय:** पर्यटन मंत्रालय।

अन्य संबंधित तथ्य

तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना पर राष्ट्रीय मिशन

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है
- यह 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया
- **लक्ष्य:** पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास
- बुनियादी ढांचा विकास जैसे कि प्रवेश बिंदु (सड़क, रेल और जल परिवहन), अंतिम मील कनेक्टिविटी, एटीएम / मनी एक्सचेंज, अक्षय स्रोतों के साथ क्षेत्रीय प्रकाश और रोशनी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि।
- अब तक, 13 योजनाओं को सफलतापूर्वक प्रसाद योजना के तहत पूरा किया गया है।

भारत की विश्व धरोहर स्थलों की सूची

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -I - संस्कृति

सुर्खिओ में क्यों-

- लोकसभा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा के बारे में सूचित किया गया।
- मंत्रालयसंस्कृति और पर्यटन मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में, भारत के पास 38 विश्व विरासत संपत्ति हैं।
- सभी साइटें एएसआई की संरक्षण नीति के अनुसार संरक्षित हैं।
- भारत में 42 साइटें सूचीबद्ध हैं, जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में शिलालेख के लिए एक शर्त है।
- धोलावीरा: 2019-2020 में एक हड़प्पा शहर को विश्व विरासत स्थल के नामांकन के लिए दिया गया।
- वर्ष 2021-22 चक्र के लिए शांतिनिकेतन के नाममात्र का डोजियर, भारत और होयसला पवित्र पोशाक यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया।
- परिचालन दिशानिर्देशों और उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के प्रदर्शन के तहत मानदंडों को पूरा करने की क्षमता के आधार पर साइटों का चुना जाता है।

संबंधित आलेख:

- हम्पी विश्व विरासत स्थल
- राखीगढ़ी

बामियान बुद्ध

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

सुर्खिओ में क्यों-

- मार्च 2001 में, तालिबान ने अफ़गानिस्तान की बामियान घाटी में दो स्मारक बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया।
- अब, 20 साल बाद, सर्वनाश की सालगिरह पर, बामियान बुद्ध को "ए नाइट विद बुद्ध" नामक एक घटना में 3 डी अनुमानों के रूप में जीवन में वापस लाया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

बामियान बुद्ध

- बामियान बुद्ध गुप्त, ससानियन और हेलेनिस्टिक कलात्मक शैली के संगम के महत्यपूर्ण उदाहरण थे।

- उनके बारे में कहा जाता है कि वे 5 वीं शताब्दी ई. पू. के थे।
- वे एक समय विश्व में सबसे लंबे समय तक खड़े बुद्ध थे।
- उन्हें स्थानीय लोगो ने सलसल और शम्मा के नाम से बुलाया।
- सॅसल का अर्थ है "प्रकाश ब्रह्मांड के माध्यम से चमकता है"; और शमामा का अर्थ है "रानी माँ" है।
- यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में अवशेषों को शामिल किया
- उपलब्ध डेटा बुद्धों को उनके नखों में पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने के प्रयास किए गए हैं।

बामियान

- यह अफगानिस्तान के मध्य उच्चभूमि में हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है।
- यह घाटी बामियान नदी की रेखा के साथ स्थित है।
- यह सिल्क रोड्स के शुरुआती दिनों में समाकलित
- जो व्यापारियों, संस्कृति, धर्म और भाषा के लिए मार्ग प्रदान करता था।

सिंहगढ़ किले का संरक्षण कार्य

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों के लिए नींव रखी गयी
- उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए नक्काशीदार जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- सिंहगढ़ किला
- **स्थान:** मध्य प्रदेश।
- यह गोंडवाना साम्राज्य का एक पहाड़ी-किला है
- गोंड शासक संग्राम शाह ने 16 वीं शताब्दी की शुरुआत में चंदेल शासकों से सिंगोरगढ़ किले पर विजय प्राप्त की।
- यह वर्तमान में उजड़ी बर्बाद हालत में है।

कूर्ग का देवारा कादु

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - संस्कृति

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में कर्नाटक के कूर्ग का पवित्र ग्रोव या देवारा कादु सुर्खिओ में रहा ।

अन्य संबंधित तथ्य

- देवारा काडु (पवित्र वन) स्थानीय देवताओं के आराध्य के रूप में उल्लेखनीय एक छोटा जंगल है।
- कूर्ग के पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए कई ऐसे सौ पवित्र स्थल हैं।
- उनमें से कुछ छोटे पैमाने पर जंगलों में फैले हुए हैं, जबकि कुछ शेष हैं।
- उनके पवित्र स्वभाव के कारण पेड़ों को अछूता छोड़ दिया जाता है
- देवारा कादु के अंदर विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर हैं।

जापी, जोराई और गमोसा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - संस्कृति

सुर्खिओ में क्यों-

- आगामी विधानसभा चुनावों के कारण सजावटी जापिस (क्षेत्रिए टोपी), हाथ से बुने हुए गमोस और बेल-मेटल ज़ोराइस असम में लगातार दिखाई दिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- **जापी:** यह एक शंक्वाकार टोपी जो बांस से बनी और सूखे तोको (ऊपरी असम के वर्षावनों में पाया जाने वाला ताड़ का पेड़) से ढकी होती है
- आज, यह असम के जापियों का बड़ा हिस्सा रहे नलबाड़ी जिले के गांवों के एक समूह कारीगरों द्वारा बनाया गया।
- **गमोसा:** इसका बहुत व्यापक उपयोग हैं। यह घर पर एक तौलिया (uka gamosa) के रूप में या सार्वजनिक समारोहों (phulam / पुष्प gamosa) में प्रतिष्ठित व्यक्तियों या हस्तियों को सम्मानित करने के लिए इस्तेमाल किया जा है।
- **जोराई:** यह घंटी में उपयोग होने वाली धातु से बना होता है। यह लतगार तल पर एक स्टैंड के साथ या बिना कवर के एक ट्रे है। यह प्रत्येक असमिया घराने में मिलता है।

MICE रोडशो - मीट इन इंडिया '; छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - संस्कृति

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया
- **उद्घाटन किया गया:** पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
- **विकसित हुआ :** पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना

महत्वपूर्ण तथ्य

- पर्यटन मंत्रालय ने समग्र दृष्टिकोण के बाद देश में उन्नीस चिन्हित प्रतिष्ठित स्थलों के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 'आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस स्कीम' के विकास के लिए तैयार किया।
- वे मध्य प्रदेश के खजुराहो में "MICE रोडशो - मीट इन इंडिया" ब्रांड और रोडमैप को भारत के MICE गंतव्य (बैठकों, प्रोत्साहन, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों) के रूप में शुरू करेंगे।

राजनीति / शासन

नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश

संदर्भ:

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पार्श्व प्रवेश/लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन में संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर व्यक्तियों की भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है।

लेटरल एंट्री एडवरटाइजिंग की मुख्य विशेषताएं

- **रिक्तियां:** केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के तीन पद और निदेशक के 27 पद है
- **समय अवधि:** इन नौकरियों को तीन से पांच साल के लिए अनुबंधित किया जाएगा।
- संयुक्त सचिव पार्श्व प्रवेश के लिए मूल योग्यता 15 वर्ष का और निदेशकों के लिए यह 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए
- **आरक्षण:** ये पद "अनारक्षित" थे, अर्थात एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं था।

सरकार में 'पार्श्व प्रविष्टि' क्या है?

- पार्श्व प्रविष्टि शब्द का संबंध विशेषज्ञों की नियुक्ति से है, जो मुख्यतः सरकारी संगठनों के निजी क्षेत्र मे हैं।
- ये 'पार्श्व प्रवेशक' केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा रहेंगे जो सामान्य पाठ्यक्रम में केवल अखिल भारतीय सेवाओं / केंद्रीय सिविल सेवा से कैरियर अधिकारी हैं।
- **नीति आयोग अनुशंसा:** नीति आयोग ने अपने तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा, और सेक्टोरल सेक्रेटरी ऑफ़ सेक्रेटरीज (SGoS) ने फरवरी 2017 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, केंद्र सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की।

पार्श्व प्रविष्टि के लिए सरकार का तर्क क्या है?

- **डोमेन विशेषज्ञता:** सरकार का विचार निजी क्षेत्र से डोमेन विशेषज्ञता को केंद्रीय प्रशासन में लाना है जो वर्तमान प्रशासन की कठिनाई को दूर करने में मदद करता है
- **जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि:** सरकार को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ता है, अतः पार्श्व प्रवेशकों का यह विकल्प इस समस्या को हल करने में मदद करेगा।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता को शामिल करने के लिए:** विशेषज्ञों को शामिल करने का एक अन्य उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और शासन वितरण में प्रतिस्पर्धा पैदा करना है, जो कि इसके कामकाज में यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी होने के लिए आलोचना की जाती है।
- **उदारीकरण नीति के साथ संकलित:** 1991 में उदारीकरण के बाद, बाजार प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे वातावरण में, सरकार की नियामक क्षमता। महत्वपूर्ण है जो प्रशासकों के ज्ञान पर निर्भर करता है, जिसमें निजी क्षेत्र से ताजा सेवन की आवश्यकता होती है।
- **पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस:** वर्तमान समय में गवर्नेंस अधिक सहभागी और मल्टी एक्टर प्रयास बन रहा है, इस प्रकार पार्श्व प्रविष्टि निजी क्षेत्र जैसे हितधारकों और गैर-लाभकारी को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

क्या सरकार ने अब तक कोई लेटरल एंट्री 'नियुक्तियां की हैं?

- नया विज्ञापन ऐसी भर्तियों के दूसरे दौर के लिए है। इससे पहले, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों और उप सचिव / निदेशक के स्तर पर 40 पदों के लिए सरकार के बाहर के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था।

- 2018 की शुरुआत में जारी संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन ने 6,077 आवेदन आकर्षित किए; यूपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया के बाद, नौ अलग-अलग मंत्रालयों / विभागों में 2019 में नियुक्ति के लिए नौ व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी।

पार्श्व प्रविष्टि की कभी-कभी आलोचना क्यों की जाती है?

- **आरक्षण का अभाव:** SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने इस तथ्य का विरोध किया है कि इन नियुक्तियों में कोई आरक्षण नहीं है।
- **पारदर्शिता का मुद्दा:** पार्श्व प्रविष्टि की सफलता की कुंजी सही लोगों का चयन करने में निहित है जो खुले और पारदर्शी हैं। यूपीएससी जैसी विश्वसनीय संवैधानिक संस्था द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया आंशिक रूप से इस समस्या का समाधान करती है।
- **मूल्य प्रणाली में असमानता:** सरकार के दूसरी ओर निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण लाभ उन्मुख है, जो सार्वजनिक सेवा है। यह भी एक मौलिक संक्रमण है जिसे एक निजी क्षेत्र के व्यक्ति को सरकार में काम करते समय करना पड़ता है।
- **आंतरिक प्रतिरोध:** पार्श्व प्रविष्टि सिविल सेवकों की सेवा करने के लिए प्रतिरोध का सामना करती है, जिन्होंने इस तरह के शीर्ष स्तर के पदों पर कब्जा करने के लिए वर्षों तक प्रणाली में काम किया होगा। एक पार्श्व प्रविष्टि इस प्रकार मौजूदा नौकरशाहों के प्रतिरोध के साथ मिल सकती है
- **हितों का टकराव:** निजी क्षेत्र का आंदोलन हितों के संभावित टकराव के मुद्दों को उठाता है। इस मुद्दे के लिए निजी क्षेत्रों के प्रवेशकों के लिए कड़े संहिता की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितों का टकराव सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक नहीं है।
- **विशिष्ट मानदंडों का अभाव:** विज्ञापन में निर्धारित मापदंड व्यापक-आधारित थे और इसीलिए जिन क्षेत्रों में विज्ञापन दिए गए थे, वहां के लोगों या डोमेन विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए एक संकीर्ण खिड़की प्रदान करने में विफल रहे।
- **संस्थागत प्रक्रिया का अभाव:** अस्थायी और तदर्थ आधार पर पार्श्व प्रविष्टि की जा रही है। यह मानव संसाधन प्रबंधन का स्थायी मॉडल नहीं हो सकता।

निष्कर्ष

- निजी क्षेत्र से सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वालों के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जो उन्हें सरकार में काम की जटिल प्रकृति को समझने में मदद करें।
- सरकार में बाहरी प्रतिभाओं को शामिल करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने की भी आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- मिशन कर्मयोगी

सुगम्य भारत ऐप लॉन्च

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में सुगम्य भारत ऐप को शुरू किया गया।
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **द्वारा विकसित:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD)।

- यह एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है।
- यह भारत में सुगम्य भारत अभियान, निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और ICT पारिस्थितिकी तंत्र के 3 स्तंभों में संवेदनशीलता को बढ़ाने का एक साधन है।
- यह ऐप पांच मुख्य विशेषताओं के लिए प्रदान करता है, जिनमें से 4 सीधे पहुंच बढ़ाने से संबंधित हैं।
- पांचवां एक विशेष सुविधा है जो केवल कोविद संबंधित मुद्दों के लिए अलग तरह से पालन करने के लिए है।

स्वच्छता सारथी फेलोशिप का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में स्वच्छता सारथी फेलोशिप" (Swachhta Saarthi Fellowship) शुरू की गई।
- **द्वारा शुरू किया गया:** भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने "वेस्ट टू वेल्थ" (Waste to Wealth) मिशन के अंतर्गत

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** इस फेलोशिप का उद्देश्य उन छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, सफाई कर्मचारियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना है जो निरंतर अपने प्रयासों से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने में लगे हुए हैं।
- "द वेस्ट टू वेल्थ" मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के नौ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- फैलोशिप के तहत पुरस्कारों की तीन श्रेणियां निम्नानुसार हैं:
- श्रेणी-ए: यह श्रेणी उन स्कूली विद्यार्थियों के लिये है जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए हैं।
- श्रेणी-बी: इसके अंतर्गत कॉलेज के उन छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो स्नातक, परास्नातक तथा शोध छात्र हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन में लगे हुए हैं।
- श्रेणी-सी: इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदाय में कार्य कर रहे उन नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं।
- इस फेलोशिप के तहत 500 फॉलोवर्स को मान्यता दी जाएगी।

"फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021: डेमोक्रेसी अंडर सीज" रिपोर्ट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में स्वच्छता सारथी फेलोशिप" (Swachhta Saarthi Fellowship) शुरू की गई।
- **द्वारा शुरू किया गया:** भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने "वेस्ट टू वेल्थ" (Waste to Wealth) मिशन के अंतर्गत

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** इस फेलोशिप का उद्देश्य उन छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, सफाई कर्मचारियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना है जो निरंतर अपने प्रयासों से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने में लगे हुए हैं।

- "द वेस्ट टू वेल्थ" मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के नौ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- फैलोशिप के तहत पुरस्कारों की तीन श्रेणियां निम्नानुसार हैं:
- **श्रेणी-ए:** यह श्रेणी उन स्कूली विद्यार्थियों के लिये है जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए हैं।
- **श्रेणी-बी:** इसके अंतर्गत कॉलेज के उन छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो स्नातक, परास्नातक तथा शोध छात्र हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन में लगे हुए हैं।
- **श्रेणी-सी:** इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदाय में कार्य कर रहे उन नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं।
- इस फेलोशिप के तहत 500 फॉलोवर्स को मान्यता दी जाएगी।

नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक (MPI) 2020

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक (MPI) 2020 की घोषणा की गई।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **मिलियन-प्लस (million-plus) जनसंख्या श्रेणी:** इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर है, इसके बाद सूरत और भोपाल हैं
- **मिलियन से कम (less than million) श्रेणी:** नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के बाद तिरुपति और गांधीनगर।
- नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक (MPI) ने पाँच वर्टिकलों में 111 नगरपालिकाओं के क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की गई। जिसमें
- **पांच वर्टिकल हैं:** सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस।

'ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक, 2020

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक, 2020 (Ease of Living Index-EoLI, 2020) जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **EoLI का उद्देश्य:** 111 शहरों में भारतीय नागरिकों की भलाई को मापने के लिए, यह एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास की विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है।
- EoLI, 2020 में 'सिटीज़न परसेप्शन सर्वे' (CPS) को फ्रेमवर्क में शामिल करके मज़बूत बनाया गया है, इस सर्वेक्षण का भारांक 30 प्रतिशत रखा जाता है।
- एक लाख से अधिक आबादी वाले और एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई-
- **मिलियन + श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला :** बेंगलुरु

- **मिलियन से कम श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला:** शिमला

पुलिस और जेल सुधार

संदर्भ: हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जेलों के अधीक्षक के रूप में IPS अधिकारियों को पोस्ट करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

विश्लेषण

- **सुधारात्मक शासन प्रबंध के प्रतिकूल पुलिस की नियुक्ति:** जेल विभाग के प्रमुख के रूप में पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय, यह एक अभ्यास जो सुधारात्मक शासन प्रबंध शास्त्र के विरुद्ध है, इसके पहले 1980 के दशक में सुरक्षा को मजबूत करने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के आधार पर शुरू किया गया था।
- **प्रशिक्षण में भिन्नता:** पुलिस कर्मियों को अपराध का पता लगाने तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए , जबकि जेल अधिकारियों की भर्ती अपराधियों को सुधारने और पुनर्वास को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है
- **राष्ट्र विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध :** जेलों में पुलिस अधिकारियों को या तो अधीक्षक के रूप में नियुक्त करना या जेलरों को हमारे संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करना।
- **न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य:** न्यायिक हिरासत का अर्थ यह है कि पुलिस जांच समाप्त हो गई है और आरोपी को पुलिस हिरासत से बाहर निकाल कर, न्यायपालिका की निगरानी के तहत जेल हिरासत में सौंप दिया गया है।
- **जेल अधिकारियों पर प्रणालीगत दबाव:** जेल अधिकारियों को एक आपराधिक न्याय प्रणाली और मीडिया के अंत में अक्सर एक डिमोटिनेटेड लॉट दिया जाता है, जो अपने दुर्व्यवहारों और उल्लंघनों को उजागर करने के लिए त्वरित होता है, बिना व्यवस्थित कारणों से।
- **विशेष बल की सिफारिश:** जेल सुधार रिपोर्ट (1983) और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर कमेटी ऑन वीमेन प्रिजनर्स रिपोर्ट (1987) जैसी विभिन्न जेल सुधार समिति की रिपोर्टें इस बात की शिफारिश करती हैं कि जेल में कैदियों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए के घर होने चाहिए। और IPS या IAS की सलाह पर एक विशेष अखिल भारतीय जेल सेवा के निर्माण की सिफारिश की है।

आगे की राह

- **बढ़ा हुआ निवेश:** हम संसाधनों और कर्मचारियों के मामले में जेल प्रणाली में निवेश नहीं करते हैं। जेल प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बढ़े हुए निवेश को बुनियादी सुविधाओं और जेल अधिकारियों के प्रशिक्षण में शामिल होना होगा
- **सिविल सोसाइटी को शामिल करना :** हमें पर्याप्त संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता नियुक्त करने की आवश्यकता है।
- **प्रशिक्षण:** हमें मानव अधिकारों और जेल कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुदृढीकरण में नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है।
- **रिक्तियों को भरना:** हमें रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है, जो कि भारत न्याय रिपोर्ट 2020 के अनुसार 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक है।
- **व्यावसायिक पुरस्कार:** हमें जेल अधिकारियों के ऊपर अधिक कार्य क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है, ताकि अच्छे काम की पदोन्नति के साथ उन्हें पुरस्कृत किया जा सके।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पुलिस सुधार

उत्तराखंड ILP सिस्टम

संदर्भ: हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में, चमोली जिले की नीती घाटी (Neeti Valley) और राज्य के उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में "इनर-लाइन परमिट" (ILP) प्रणाली को वापस लेने की मांग की।

ILP सिस्टम क्या है?

- यह उत्तराखंड में चीन के साथ 350 किलोमीटर और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा है।
- ILP प्रणाली औपचारिक अनुमति वाले लोगों के अतिरिक्त सभी के लिए सीमा के समीप के क्षेत्रों में आने जाने पर प्रतिबंध लगाती है।
- उत्तराखंड में, पर्यटकों को कम से कम तीन राज्य उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में चीनी सीमा के पास स्थानों के लिए इनर-लाइन परमिट मिलती है।
- ITBP इन क्षेत्रों में पर्यटकों की न्यूनतम संभव संख्या की अनुमति देता है क्योंकि उस क्षेत्र में बर्फबारी में फंसने और गायब होने का खतरा रहता है।

सरकार और लोग ILP प्रणाली को हटाने के लिए क्यों पूछ रहे हैं

- आंदोलन में ढील देने से क्षेत्र में पर्यटक गतिविधियां बढ़ेंगी। वर्तमान में, विदेशी पर्यटकों को इस क्षेत्र में जाने से से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि घरेलू पर्यटकों को ILP के साथ प्रवेश की अनुमति दी गयी है। अनुमानित लोगों की अधिकतम संख्या एक दिन में 24 होती है और वे रात में वहां ठहर नहीं सकते।
- प्रतिबंध हटाने का अर्थ क्षेत्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होना
- गांवों का पुनर्वास किया जाएगा ताकि स्थानीय लोग निगरानी के लिए सीमा पर 'आंख' और 'कान' के रूप में भी काम कर सकें।
- यह बाहरी प्रवास को भी रोकेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश सीमावर्ती गांवों में आजीविका के अवसरों की कमी के कारण बाहरी प्रवासन देखा जाता है

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा

राज्य चुनाव आयुक्तों पर SC का शासन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - न्यायपालिका

सुर्खिओ में क्यों-

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्वाधीन व्यक्तियों और नौकरशाहों को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकारी कर्मचारियों को राज्य चुनाव आयुक्तों का अतिरिक्त प्रभार देना "संविधान का मजाक " बनाना है।
- यह निर्देश दिया कि राज्यों को पूरे भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

अनुच्छेद 243 K

- अनुच्छेद 243 K पंचायतों के चुनावों से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण, राज्य निर्वाचन आयोग में होंगे।

- इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाने वाला राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार होती हैं।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके कार्यालय से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस तरह के आधार पर नहीं हटाया जाएगा।
- राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी।

दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य

संदर्भ: हाल ही में केंद्र ने सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 (GNCTD) को लोकसभा में प्रस्तुत किया है, जो निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एल-जी) के बीच शक्तियों के विभाजन पर विवाद को पुनर्जीवित करता है।

दिल्ली का संवैधानिक ढांचा

- दिल्ली की वर्तमान स्थिति एक विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश के रूप में 69 वें संशोधन अधिनियम का एक परिणाम है जिसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239BB पेश किए गए।
- राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के परिशिष्ट के लिए GNCTD अधिनियम एक साथ पारित किया गया।
- सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, GNCTD अधिनियम विधानसभा की शक्तियों, एल-जी द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों और एल-जी को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की रूपरेखा देता है।

2021 संशोधन विधेयक क्या कहता है?

- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के जानकारी में:** वस्तुओं और कारणों से संबंधित अनुभाग में, केंद्र का दावा है कि संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को प्रभावी करने का प्रयास करता है और यह संवैधानिक योजना के अनुरूप निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
- **सरकार पर स्पष्टीकरण:** विधेयक स्पष्ट करता है कि विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में "सरकार" शब्द का अर्थ एल-जी होगा। यह अनिवार्य रूप से, पूर्व एल-जी के दावे पर प्रभाव डालता है कि "सरकार का अर्थ है दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल का अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत नामित" है
- **एलजी की पूर्व राय:** विधेयक में कहा गया है कि कैबिनेट या किसी भी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एल-जी की राय प्राप्त करनी होगी ।

संविधान पीठ ने क्या कहा?

- **एलजी की सहमति:** 2018 के अपने फैसले में, पांच न्यायाधीशों वाली बेंच ने कहा था कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा अन्य मुद्दों पर एलजी की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- **मंत्रिमंडल और एलजी के बीच संचार:** SC ने यह भी कहा था कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों को, L-G को सूचित करना होगा।
- **प्रतिनिधि शासन की भावना को बनाए रखा:** SC ने कहा कि "यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि उपराज्यपाल की पूर्व सहमति की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 239AA द्वारा दिल्ली के एनसीटी के लिए कल्पना की गई प्रतिनिधि शासन और लोकतंत्र के आदर्शों को पूरी तरह से इंकार कर देगी"।

- **L-G और दिल्ली की स्थिति:** न्यायालय ने कहा कि "दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में प्रशासक हैं, जो उपराज्यपाल के पद पर काम कर रहा है।" यह भी बताया गया है कि निर्वाचित सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है।

SC **निर्णय के परिणाम**

- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने, इसलिए 2018 के फैसले के माध्यम से चुनी हुई सरकार के पक्ष में तराजू को झुकाया।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित, निर्वाचित सरकार ने किसी भी फैसले के लागू होने से पहले एल-जी पर कार्यकारी मामलों की फाइलें भेजना बंद कर दिया था।
- यह L-G को सभी प्रशासनिक विकासों के साथ रखता है, लेकिन किसी भी फैसले को लागू करने या निष्पादित करने से पहले जरूरी नहीं है।
- यह देखा गया है कि इस निर्णय के कारण निर्वाचित सरकार के नीतिगत फैसलों को स्पष्ट करने में सक्षम थी जैसे कि 200 इकाइयों के तहत मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और राशन की डिलीवरी आदि।

क्या L-G को वर्तमान व्यवस्था के तहत कोई विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है?

- **अनुच्छेद 239AA (4):** L-G में किसी भी मामले को संदर्भित करने की शक्ति है, जिस पर अनुच्छेद 239AA (4) के तहत राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकार के साथ असहमति है।
- **2018 एससी निर्णय और अनुच्छेद 239**AA **(4):** वर्ष 2018 में दिये गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यानपूर्वक पढने से यह पता चलता है कि संविधान के तहत उपराज्यपाल के पास दिल्ली की निर्वाचित सरकार के निर्णय को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की विशेष शक्तियाँ हैं, परंतु उपराज्यपाल दुर्लभतम मामलों में ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- **239**AA **(4) का आह्वान करने पर SC**: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 AA के परंतुक (4) के अंतर्गत अपवाद स्वरुप 'किसी मामले (Any Matter)' के संबंध में ही राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है न कि 'प्रत्येक मामले (Every Matter)' में।

अगर संसद द्वारा संशोधन को मंजूरी दे दी जाए तो क्या बदलाव आएगा?

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधेयक, जो "चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर अत्यधिक नियंत्रण करना चाहता है", सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।
- संशोधन, यदि मंजूरी दी जाती है, तो किसी भी कैबिनेट के फैसले पर कार्रवाई करने से पहले निर्वाचित सरकार को एल-जी की सलाह लेने के लिए मजबूर करेगी।
- विधेयक मूल GNCTD अधिनियम, 1991 में एक प्रावधान जोड़ने का प्रयास करता है, विधानसभा या इसकी समितियों को नियम बनाने से लेकर दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित मामले उठाने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए।
- निर्वाचित सरकार को एल-जी के माध्यम से अपनी सभी फाइलों को रूट करने के लिए अनिवार्य बनाकर, संशोधन अनिवार्य रूप से सरकार की स्वायत्तता और राज्य के लिए पूर्ण राज्य का सपना पूरा करेगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पुडुचेरी में सत्ता का बिगुल: उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच

चुनावी वित्तपोषण

सन्दर्भ : भारत में राजनीतिक प्रणाली पारंपरिक रूप से चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता के विचार से विरोधपूर्ण रहा है।

क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम?

- एक चुनावी बांड एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से भारत में शामिल किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है।
- एक व्यक्ति या पार्टी को आपके ग्राहक (केवाईसी) के माध्यम से अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद डिजिटल या इन बॉन्ड को खरीदने की अनुमति होगी।
- नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के किसी भी योग्य राजनीतिक दल को समान दान कर सकते हैं।
- बांड बैंक नोटों के समान हैं जो मांग पर वाहक को देय हैं और ब्याज मुक्त हैं। इसे केवल 15 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा उनके निर्दिष्ट खाते में भुनाया जाता है
- चुनावी बांड वित्त विधेयक (2017) के साथ पेश किए गए थे। 29 जनवरी, 2018 को एनडीए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया।

चुनावी बांड के साथ मुद्दे

- चुनावी बांड दानकर्ताओं को राजनीतिक दलों को असीमित मात्रा में धन दान करने की अनुमति देता है।
- यह योजना पार्टियों को जनता, चुनाव आयोग या यहां तक कि आयकर विभाग को दाताओं की पहचान के बिना इन बांडों को प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- बड़े व्यवसायों द्वारा दान ट्रैक करने और क्विड प्रो क्वो को उजागर करने की लोगों की क्षमता कम हो गई है
- वे राजनीतिक पार्टी के वित्तपोषण में पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और ईसीआई के लिए यह पता लगाना असंभव होगा कि प्राप्त दान राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के अनुपालन में थे या नहीं।
- चुनावी बॉन्ड विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय हितों को विदेशी हितों के प्रभाव से खोलने के लिए नामरहित वित्तपोषण की अनुमति देते हैं
- इलेक्टोरल बॉन्ड में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की संभावना है क्योंकि 2017 में कंपनी अधिनियम में संशोधनों ने कंपनी द्वारा राजनीतिक योगदान पर 7.5% की सीमा को हटा दिया, जो कि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में है।
- इससे चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे ईसीआई और आरबीआई दोनों ने हरी झंडी दिखाई।
- जैसा कि बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं, पार्टी के लिए यह मुश्किल नहीं होगा कि वह खरीददारों की पहचान और उनके द्वारा बेचे गए बॉन्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर सके और उन लोगों को राजनीतिक पार्टी के खातों में जमा करवा सके।

आगे की राह

- चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय तुरंत मामले पर फैसला सुनाए।
- यदि बांड को राजनीतिक दलों में योगदान देने के लिए एक उपकरण के रूप में रखा जाये तथा दान को पारदर्शी बनाया जाये और पार्टियों को चुनाव आयोग और अन्य निगरानी निकायों के साथ दानकर्ताओं और प्राप्त राशि के नामों का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जाये।
- यह जानकारी सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में भी रखनी चाहिए।
- ये कदम लोकतंत्र की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि चुनाव केवल औपचारिकता न बनें।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- राजनीतिक दलों को नकद चंदा भी वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से 2000 रुपये पर कैप किया गया। फिर भी नकद दान की अनुमति क्यों है?
- क्या आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल आते हैं?

पूजा का स्थल

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक याचिका का जवाब देने के लिए कहा, जो उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है।

1991 अधिनियम क्या कहता है?

- 15 अगस्त, 1947 को देश में सभी पूजा स्थलों को मुक्त करने के लिए कानून बनाया गया।
- अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी पूजा स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। इसमें एक घोषणा शामिल है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल बना रहेगा
- गौरतलब है कि यह किसी भी कानूनी कार्यवाही को पूजा के स्थान के चरित्र के संबंध में स्थापित करने से रोकता है, और घोषित करता है कि सभी मुकदमा और अपील किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, जो पूजा स्थल के चरित्र के रूपांतरण के संबंध में कट-ऑफ तारीख पर है। छोड़ देना चाहिए।
- दूसरे शब्दों में, सभी लंबित मामले समाप्त हो जाएंगे और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
- हालांकि,कट-ऑफ की तारीख के बाद हुई स्थिति के किसी भी रूपांतरण से संबंधित कोई भी मुकदमा या कार्यवाही जारी रह सकती है
- **दंड का प्रावधान:** किसी को भी पूजा के स्थान की स्थिति में परिवर्तित करने पर रोक लगाने का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और एक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अपराध को अंजाम देने या आपराधिक साजिश में भाग लेने वालों को भी यही सजा मिलेगी।

अधिनियम के तहत अपवाद क्या हैं?

- बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए एक अपवाद बनाया गया क्योंकि संरचना तब मुकदमेबाजी का विषय थी।
- 1991 अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होगा और जो अवशेष प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा कवर किए गए हैं।
- यह किसी भी मुकदमे पर भी लागू नहीं होगा जो अंततः निपट गया है या इसका निपटारा किया गया है, 1991 के अधिनियम से पहले पार्टियों द्वारा सुलझाए गए किसी भी विवाद या किसी भी जगह के रूपांतरण से जो कि अधिग्रहण से हुआ था।

चुनौती के आधार क्या हैं?

- **न्यायिक उपाय की बाधाएं :** अधिनियम अदालतों के माध्यम से न्याय पाने और न्यायिक उपाय प्राप्त करने के लिए लोगों के अधिकार को छीन लेता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिनियम कानूनी कार्यवाही के माध्यम से अपने पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जैसे समुदायों के अधिकारों को अधीग्रहण कर लेते है।
- **कट-ऑफ तिथि पर ध्यान:** याचिकाकर्ता यह भी तर्क देता है कि 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तारीख मनमाना और तर्कहीन है।

- **छूट का मुद्दा:** याचिका में कहा गया है कि कानून अतीत में आक्रमणकारियों के कार्यों को वैध करता है जिन्होंने पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया था। यह आश्चर्यचकित करता है कि कानून राम के जन्मस्थान को कैसे छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण की नहीं।
- **धर्म के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध:** याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ-साथ पूजा स्थलों के प्रबंधन और प्रशासन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
- **धर्मनिरपेक्षता की भावना में नहीं:** इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य के कर्तव्य के खिलाफ है।

स्टेटस फ्रीज पर SC ने क्या कहा है?

- अयोध्या विवाद पर अपने अंतिम फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि अधिनियम "धर्मनिरपेक्षता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक गैर-अपमानजनक दायित्व" है।
- अदालत ने कहा: "गैर-प्रतिगमन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है, जिनमें से धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य घटक है।"
- न्यायालय ने कानून को स्वतंत्रता के बाद बदले जाने वाले पूजा स्थल की स्थिति की अनुमति न देकर धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने वाले कानून के रूप में वर्णित किया।
- पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पूजा के स्थान को बदलने के प्रयासों के खिलाफ सावधानी बरतने के संदर्भ में, "ऐतिहासिक गलतियों को कानून द्वारा अपने हाथों में लेने वाले लोगों द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता है।" सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने में, संसद ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के आदेश दिया है कि इतिहास और इसके गलत उपयोगों को वर्तमान और भविष्य पर अत्याचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

मामले के निहितार्थ क्या हैं?

- **विवादास्पद स्थान:** कुछ हिंदू संगठन वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर दावा करते हैं।
- **मथुरा में विवाद:** 17 वीं सदी की मस्जिद को इस स्थान से स्थानांतरित करने के लिए मथुरा की अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया गया है कि कुछ दावा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है
- **1991 के कानून की कमजोर पड़ने से परिणाम पर असर पड़ता है:** पूजा के स्थानों की स्थिति पर 1991 के कानून को तोड़ने या कमजोर करने वाले किसी भी आदेश से ऐसी कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित करने की संभावना है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राम मंदिर का इतिहास और महत्व

असम की छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - संविधान

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लोकसभा को सूचित किया कि "वर्तमान में, असम की छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है"।

अन्य संबंधित तथ्य

संविधान की छठी अनुसूची

- भारत के संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों के गठन की अनुमति देकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर कानून बना सकती हैं।

- वर्तमान में, 10 स्वायत्त परिषद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में मौजूद हैं।
- **असम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र:** उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र
- **मेघालय के निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्र:** खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स
- त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र
- **मिजोरम के निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्र:** चकमा, मारा और लाई जिले

संविधान (125 वां संशोधन) विधेयक, 2019

- जनवरी 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
- संविधान (125 वां संशोधन) विधेयक, 2019, बाद में फरवरी 2019 में राज्य सभा में पेश किया गया था, जो निर्वाचित ग्राम नगरपालिका परिषदों के लिए प्रदान करता है।
- वह विधेयक जो अभी भी सक्रिय है इसका प्रस्ताव है कि राज्य चुनाव आयोग स्वायत्त परिषदों, गाँव और नगरपालिका परिषदों के चुनाव कराएगा।

नए सीजेआई की सिफारिश

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - न्यायपालिका

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने अगले CJI के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना की सिफारिश की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- न्यायमूर्ति रमन्ना 24 अप्रैल को भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभाल सकते हैं।
- वह 26 अगस्त 2022 तक सीजेआई होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

CJI की नियुक्ति

- **अनुच्छेद 124:** अनुसूचित जाति के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रबंध।
- लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
- CJI, SC के सबसे वरिष्ठ जज होने चाहिए।
- कानून मंत्री को उचित समय पर नए CJI की नियुक्ति के लिए निवर्तमान CJI की सिफारिश लेनी होगी।
- अनुच्छेद 124[2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना अनिवार्य होगा।
- कानून मंत्री इसके बाद प्रधान मंत्री (PM) को सिफारिश देता है जो राष्ट्रपति को नियुक्ति के बारे में सलाह देगा।
- शीर्ष अदालत में वरिष्ठता उम्र से निर्धारित नहीं होती है, लेकिन तारीख तक SC को एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- यदि एक ही दिन में दो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में उच्चीकृत किए जाते हैं, (1) जो पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ लेता है, वह दूसरे को ट्रम्प करेगा; (2) यदि दोनों को उसी दिन न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाती है, तो उच्च न्यायालय सेवा के अधिक वर्षों के साथ वरिष्ठता के दांव में वरिष्ठता की जीत होगी; (3) पीठ से एक नियुक्ति 'ट्रम्प' वरिष्ठता में बार से एक नियुक्ति होगी।
- **कार्यकाल:**
  1. एक बार नियुक्त होने के बाद, सीजेआई 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
  2. **अनुच्छेद 124 (4):** CJI सहित एक SC न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही स्थानांतरित किया जा सकता है।

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021

संदर्भ: बिहार विधानसभा ने 23-24 मार्च को विधानसभा के अंदर और बाहर शोर-शराबा देखा, क्योंकि विपक्षी दलों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 को पारित करने के सरकार के प्रयास का विरोध किया।

विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों को मार्शलों और स्पीकर कार्यालय द्वारा बुलाए गए अतिरिक्त पुलिस बलों द्वारा जबरन हटा दिया गया, इसके बाद हुए हाथापाई में कई घायल हो गए। हालाँकि, विवादास्पद विधेयक, दोनों सदनों में पारित किया गया था।

नया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 क्या है?

- **विशेष सशस्त्र बल:** विवादास्पद बिल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा या चरमपंथ के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए एक विशेष सशस्त्र बल स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह स्पष्ट रूप से बिहार मिलिट्री पुलिस को पकड़ने, उनका नाम बदलने और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (**CISF**) की तर्ज पर सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
- **लोगों को केवल संदेह पर गिरफ़्तार करने की शक्ति:** विधेयक की धारा 7 राज्य सरकार के कार्यों को बाधित करने, या अपराध या संज्ञेय अपराध के उद्देश्य से अपनी उपस्थिति को छिपाने के प्रयास के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है।
- **वारंट की कोई आवश्यकता नहीं:** बलों को गिरफ्तारी या उनके परिसर की तलाशी लेने के लिए एक मजिस्ट्रेट से वारंट की आवश्यकता नहीं होगी और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत खोज करने के प्रावधान लागू होंगे।

- **गिरफ्तारी शक्ति पर जाँच करें:** इसके लिए एकमात्र जाँच यह है कि यह किसी भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी को, गिरफ्तारी करने के लिए अधिसूचित रैंक से नीचे की अनुमति नहीं देगा। गिरफ्तारी का विवरण दर्ज करने के लिए अधिकारी को नजदीकी पुलिस स्टेशन में संदिग्ध व्यक्ति को ले जाना चाहिए।
- **न्यायालयों और सरकारी मंजूरी की भूमिका:** विशेष सशस्त्र बल के जवानों को तब तक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि उनके खिलाफ सरकार द्वारा अधिकृत न किया जाए।

क्या कह रही है सरकार?

- विधेयक कहता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए होगा, चरमपंथ का मुकाबला करना, निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बिहार सरकार ने कहा कि बिहार सैन्य पुलिस, अपनी अलग संगठनात्मक संरचना के साथ, हवाई अड्डों और महानगरों में औद्योगिक सुरक्षा को संभाल रही है, और राज्य की सुरक्षा की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष सशस्त्र बलों के रूप में एक अलग पहचान की आवश्यकता है।
- मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष रूप से प्रशिक्षित बल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।

विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है?

- विपक्ष ने विधेयक को "सख्त और असंवैधानिक" कहा है और सरकार द्वारा राज्य में "पुलिस राज" को लागू करने का प्रयास किया है।
- संयुक्त विपक्ष के बयान में कहा गया है कि विधेयक "लोगों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, राजनीतिक विपक्ष और उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल को एक सशस्त्र मिलिशिया में प्रभावी रूप से बदल देगा, जो सच बोलने की हिम्मत करेंगे"।
- सत्ता के अलग होने के आधार पर विधेयक की आलोचना भी है। विधेयक की धारा 15 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, तो भी पूछताछ अदालत में या मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा की जाएगी।
- इस अधिनियम के माध्यम से, विरोधियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि बीएमपी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के रूप में कार्य करेगी।

नौकरशाही में सुधार

रक्षा नौकरशाही सुधार पर एक नज़र -CDS

- उच्च रक्षा प्रबंधन पर कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश के लगभग 20 साल बाद, प्रधानमंत्री ने 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद बनाने की घोषणा की
- यह निर्णय इतना सरल नहीं था क्योंकि रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर कई लोग एक व्यक्ति में सैन्य निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार के विरोध में थे।
- जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी, 2020 को तीन वर्षों के लिए पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें नवसृजित मामलों के विभाग (DMA) का सचिव भी बनाया गया।
- सीडीएस को भूमि, वायु और समुद्र-आधारित बलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए पारदर्शी आवश्यकता-आधारित हार्डवेयर अधिग्रहण और थिएटर कमांड के निर्माण के माध्यम से सैन्य सुधारों को देने का काम सौंपा गया था।
- रक्षा मंत्रालय में नौकरशाही लाल-टेप के माध्यम से कटौती करने और निर्णय लेने में तेजी लाने का विचार था

भारतीय नौकरशाही प्रणाली के साथ प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **लैक रिजल्ट ओरिएंटेशन:** भारतीय नौकरशाही परिणाम के बजाय प्रक्रिया द्वारा संचालित होती रहती है।

- **जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही:** आम आदमी और नौकरशाही के बीच का अंतर कम नहीं हुआ है क्योंकि नौकरशाह फाइल को सही रखने में अधिक रुचि रखते हैं
- **औपनिवेशिक हैंगओवर:** नौकरशाही अभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी अतीत की अपनी विरासत को जारी रखती है क्योंकि अधिकारी कभी-कभी जमीन पर स्थिति के बारे में जागरूकता के बिना एक कब्जे वाली शक्ति के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं।
- **लेक्स डोमेन विशेषज्ञता:** एअर इंडिया और बहु-स्वरूपित जानकारी के युग में, नौकरशाहों को आमतौर पर कार्य के क्षेत्रों के अपर्याप्त ज्ञान, नीति बनाने के लिए अग्रणी होते हैं।
- **उनके दृष्टिकोण में यथास्थितिवादी:** नौकरशाहों की सेवा करने से ताजा रक्त और विचारों के जलसेक का विरोध होता है और उन्हें अपनी उभरती भूमिकाओं में मार्गदर्शन करने के लिए और विशेष रूप से भारतीय युवाओं के साथ अपर्याप्त संचार होता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति के अस्तित्व के साथ भी चुनौतियां:** कई मंत्रियों का कहना है कि वे अपने नौकरशाहों को स्थायी विपक्ष की तरह व्यवहार करते हुए पाते हैं, जो प्रक्रियाओं पर अत्यधिक निर्भरता के माध्यम से राजनीतिक अधिकारियों को बाहर करने के लिए निर्धारित हैं।
- **पूर्व के लिए:** सरकार के मानव संसाधन प्रबंधक, कर्मियों और प्रशिक्षण विभाग को सैन्य मामलों के विभाग में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय लगा।

आगे की राह

- **तीसरी ARC नियुक्त करें:** भारतीय नौकरशाही में सरकार को अत्याधुनिक सुधारों के लिए तीसरा प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त करने का समय आ गया है। और इस बार, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिफारिशों को वास्तव में लागू किया जाए और न केवल दूसरे प्रशासनिक सुधारों की तरह कागज पर
- **बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिविल सेवकों को प्रोत्साहित करना:** सरकार के लिए वैकल्पिक फास्ट-ट्रैक करियर प्रगति चैनल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं को जुताई से अलग करना है। इससे शीर्ष अधिकारियों की आयु प्रोफ़ाइल भी कम हो जाएगी।
- **पदोन्नति की वैकल्पिक प्रणाली:** सरकार को उच्च स्तर पर पदोन्नति पर भी विचार करना चाहिए, जो कि अतिरिक्त सचिव या सचिव स्तर के पद हैं जो एक साथ चार से पांच बैचों के पूल से हैं और एक साल-दर-साल के आधार पर नहीं हैं जैसा कि अब किया जाता है। इससे सरकार को अपना चयन करने के लिए अधिकारियों का एक बड़ा पूल मिलेगा।
- **संविदात्मक नियुक्ति प्रणाली:** शायद, अतिरिक्त सचिव या सचिव-स्तर पर नियुक्तियों को भी अनुबंध के आधार पर प्रत्येक पक्ष पर समयपूर्व अलगाव या समाप्ति के मुआवजे के साथ पांच से दस साल के लिए पेश किया जा सकता है। यह जमीन पर वितरण के मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
- **विस्तार लेटरल एंट्री:** जबकि सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर पर या नीचे के स्तर पर प्रवेश के माध्यम से अधिकारियों को शामिल किया है, इसे अतिरिक्त सचिव या सचिव स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि लैगर्ड शीर्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्श्व प्रवेशक के पास कोई काम नहीं है

निष्कर्ष

भारत के पास एक नई परिणाम-उन्मुख नौकरशाही होनी चाहिए जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मनाए, क्योंकि वर्तमान वास्तुकला को हटाकर फिर से बनाने की आवश्यकता है

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- मिशन कर्मयोगी

संसदीय समितियाँ

संदर्भ: हाल ही में भारत की संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जो दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस बिल के व्यापक बदलाव की प्रकृति के बावजूद, इसे एक संसदीय समिति को नहीं भेजा गया और संसद के दोनों सदनों के माध्यम से जल्दी से जल्दी निकलने से पहले हितधारकों, नागरिक समाज या विशेषज्ञों के साथ कोई औपचारिक परामर्श नहीं किया गया

समितियों का महत्व

- **मुद्दों का संपूर्ण विश्लेषण:** अधिकांश सांसद सामान्यवादी होते हैं जो निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं। इसलिए, समितियां सांसदों को विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करने के लिए होती हैं और उन्हें मुद्दों के बारे में विस्तार से सोचने का समय देती हैं।
- **सभी दलों को उनकी राय सुनिश्चित करना:** संसद में उनकी पावर के समान अनुपात में सभी समितियों के सांसद अलग-अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं
- **कई हितधारकों से प्रतिक्रिया:** जब इन समितियों को बिल भेजे जाते हैं, तो उनकी बारीकी से जांच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हितधारकों से इनपुट मांगे जाते हैं।
- **लोकवादी आसन का कम बोझ :** बंद दरवाजे के होने और सार्वजनिक नज़रों से दूर होने के कारण, समिति की बैठकों में चर्चा भी अधिक सहयोगी होती है, जिसमें सांसदों को मीडिया दीर्घाओं के लिए आसन का दबाव कम महसूस होता है।
- **सरकार पर दबाव डालें:** हालांकि समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टें उन परामर्शों का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाती हैं जो सरकार पर बहस के प्रावधानों पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव डालते हैं।

मुद्दे

- **समितियों को बिल भेजना अनिवार्य नहीं है:** भारतीय प्रणाली में, दुर्भाग्य से, समितियों को बिल भेजना अनिवार्य नहीं है। यह अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया गया - लोकसभा और राज्य सभा के अध्यक्ष पर
- **संसदीय समितियों को दरकिनार करने की चिंता की प्रवृत्ति:** भारत में सिडलीनिंग समितियां तेजी से आदर्श बन रही हैं। 14 वीं (2004-2009) में 60% और 15 वीं लोकसभा (2009-14) में 71% की तुलना में केवल 25% बिलों को 16 वीं लोकसभा (2014-2019) में भेजा गया था।
- **संसद को कमजोर करने का खतरा :** चीजों की संवैधानिक योजना में, संसद को सरकार पर निगरानी रखने और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए माना जाता है। संसद में उचित परिश्रम को दरकिनार करके, हम लोकतंत्र को कमजोर करने का खतरा मोल लेते हैं।
- **प्रत्यक्ष चर्चा समिति के विचार-विमर्श का विकल्प नहीं है:** 16 वीं लोकसभा (2014-19) ने 1,615 घंटे, पिछली लोकसभा की तुलना में 20% अधिक और 133 बिलों को पारित किया, 15 वीं लोकसभा की तुलना में 15% अधिक। इस प्रकार, सांसद सदन के पटल पर प्रत्यक्ष विचार-विमर्श पर अधिक समय दे रहे हैं। हालाँकि, ये समिति के विचार-विमर्श का विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि इस खंड चर्चा में गहन विश्लेषण का अभाव है और अधिकांश सांसद विषय-वस्तु विशेषज्ञ नहीं हैं
- **ब्रूट मेजोरिटी:** बिल को समिति को भेजा जाना है या नहीं, यह तय करने के लिए चेयर को विवेकाधीन शक्ति देकर, सिस्टम को विशेष रूप से एक लोकसभा में कमजोर रूप से पेश किया गया है, जहां सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत है

आगे का रास्ता

- **स्वीडन मॉडल:** स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में सभी बिल समितियों में भेजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, बिल समिति का चयन, जिसमें विपक्ष के सदस्य शामिल होते हैं, उनको बिलों की पहचान करने का काम सौंपा जाता है जिन्हें समितियों में जाना चाहिए।
- **गुणवत्ता और शासन को बनाए रखने की आवश्यकता:** कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत समिति प्रणाली ही एकमात्र तरीका है।

कॉर्पोरेट प्रशासन: अल्पसंख्यक शेयरधारक अधिकार: टाटा बनाम मिस्त्री

टाटा बनाम मिस्त्री विवाद की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- साइरस मिस्त्री का परिवार शापूरजी पल्लोनजी (एसपी), टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा संस में 18.46% इक्विटी पूंजी का मालिक है। टाटा संस का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो वर्तमान में इस समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा द्वारा नियंत्रित है
- **दिसंबर** 2012 **में**, **मिस्त्री की नियुक्ति:** साइरस मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **अक्टूबर** 2016 **में**, **मिस्त्री को हटा दिया गया:** उन्हें निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया।
- **फरवरी** 2017 **में**, **टाटा संस के खिलाफ मामला दर्ज:** शेयरधारकों ने एक असाधारण आम बैठक के दौरान मिस्त्री को टाटा संस के बोर्ड से हटाने के लिए वोट दिया। बाद में मिस्त्री ने टाटा संस में उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दायर किया।
- **जुलाई 2018- NLCT में टाटा की जीत:** नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने टाटा संस के खिलाफ मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी। उनके आरोपों को खारिज करते हुए, NCLT का नियम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सक्षम हैं। ट्रिब्यूनल यह कहा है कि उसने टाटा संस में कुप्रबंधन के तर्कों में कोई गुण नहीं पाया।
- **दिसंबर 2019- टाटा NCLT में हार गए:** नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) ने फैसले को पलट दिया और कहा कि टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में मिस्त्री को हटाना गैरकानूनी था।
- NCLAT ने यह भी पाया कि टाटा संस के मामलों को उसके अल्पसंख्यक शेयरधारकों अर्थात् साइरस मिस्त्री और उनकी पारिवारिक कंपनियों के साथ-साथ कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण और दमनकारी तरीके से संचालित किया गया था।
- **जनवरी** 2020- SC **से अपील:** टाटा संस और रतन टाटा ने NCLAT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती देते हुए कहा कि NCLAT के फैसले ने कॉर्पोरेट लोकतंत्र और इसके निदेशक मंडल के अधिकारों को कम कर दिया।
- इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के लिए NCLAT के फैसले पर रोक लगा दी।
- **सितंबर 2020 :** सुप्रीम कोर्ट ने धन जुटाने के लिए मिस्त्री के शापूरजी पलोनजी समूह को टाटा संस में अपने शेयर गिरवी रखने से रोक दिया।
- **मार्च 2021:** केस पर अंतिम फैसला

मिस्त्री द्वारा लगाए गए आरोप / चिंताएँ क्या थीं?

- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हिस्सा शेयरधारकों का उत्पीड़न:** एसपी समूह ने यह भी आरोप लगाया था कि टाटा संस को अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों के लिए "दमनकारी" और "पूर्वाग्रहपूर्ण" तरीके से चला कर संचालित किया गया । और यह आरोप लगा कि साइरस मिस्त्री को हटाने का मतलब अल्पसंख्यक शेयरधारकों का उत्पीड़न था।

- **टाटा समूह के संघ के अनुच्छेद 75:** अनुच्छेद 75 कंपनी को अल्पसंख्यक या छोटे शेयरधारक से उचित बाजार मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार देता है। डर है कि टाटा समूह एसपी समूह को खरीदने और इसका इस्तेमाल कर सकता है, बाद में कंपनी कानून न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 75 का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया।
- **निर्णयों ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों को असंगत रूप से प्रभावित किया:** इसके अलावा, मिस्त्री शिविर ने यह भी आरोप लगाया था कि टाटा समूह ने कई वाणिज्यिक निर्णय लिए थे, जो वांछित परिणाम नहीं देते थे और इस प्रकार बहुसंख्यक शेयरधारकों की तुलना में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए अधिक नुकसान हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था?

1. बोर्ड में सीट के लिए कोई प्रवेश नहीं:

- अल्पसंख्यक और छोटे शेयरधारकों के अधिकारों और कंपनी के बोर्ड में उनके महत्व के बारे में चर्चा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों या उनके प्रतिनिधि स्वचालित रूप से निजी कंपनी के बोर्ड पर एक छोटे हिस्सेदार के प्रतिनिधि की तरह सीट के हकदार नहीं हैं।
- इसका मतलब था कि SC ने NCLAT के आदेश को अलग रखा और मिस्त्री तथा SP समूह की अपील को खारिज कर दिया।

2. छोटे बनाम अल्पसंख्यक शेयरधारक:

- SC ने कहा कि 2013 के कंपनी अधिनियम में निहित प्रावधान केवल सूचीबद्ध कंपनियों के छोटे शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऐसी कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम एक निदेशक को ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने जाने के लिए कहते हैं।
- छोटे शेयरधारकों, कंपनी अधिनियम के अनुसार, शेयरधारकों का एक समूह जो 20,000 रुपये से अधिक के नाममात्र मूल्य के शेयर नहीं रखते हैं।
- चूंकि मिस्त्री परिवार और एसपी समूह "छोटे" शेयरधारक नहीं थे, लेकिन "अल्पसंख्यक शेयरधारकों", कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, जिसने उन्हें टाटा संस के बोर्ड में "आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार" दिया।

3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं

- एससी ने उल्लेख किया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में, एसपी समूह के लिए भी संविदात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- न तो एसपी समूह और न ही सीपीएम (साइरस पल्लोनजी मिस्त्री) एसोसिएशन के लेखों के संशोधन की मांग करके, ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) को अनुबंध को फिर से लिखने का अनुरोध कर सकते हैं।
- एसोसिएशन के लेख, जैसा कि वे आज भी मौजूद हैं, एसपी ग्रुप और सीपीएम के लिए बाध्यकारी हैं

निर्णय का प्रभाव

- सर्वोच्च न्यायालय ने अर्ध-भागीदारी या एक संविदात्मक समझौते की अवधारणा को मना नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि निर्णय अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार को सीधे प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने पर, ऐसे शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बहुमत शेयरधारकों के साथ अनुबंध हो या कंपनी के प्रमोटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास बोर्ड पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर

हरियाणा नौकरी कोटा कानून (स्थानीय आरक्षण)

संदर्भ: हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक नए कानून को अधिसूचित किया है जिसमें राज्य में 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों की आवश्यकता है, एक निर्दिष्ट वेतन स्लैब तक (प्रति माह 50,000 रुपये से कम), स्थानीय उम्मीदवार के लिए आरक्षित (राज्य में पैदा हुआ या पांच साल से रह रहा है)

- **उद्देश्य:** कानून, सरकार ने तर्क दिया, विशेष रूप से अकुशल नौकरियों में युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है।
- **कानून की उपयुक्तता:** स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020, सभी कंपनियों, एलएलपी, ट्रस्ट, समाज और 10 से अधिक कर्मचारियों के साथ भागीदारी फर्मों को इन स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं का पालन करने की जरुरत है
- **प्रवर्तन शक्ति:** कानून विशेष रूप से जिला प्रशासन को 24 घंटे के नोटिस के साथ निरीक्षण के माध्यम से नए नियमों को लागू करने का अधिकार देता है

विधान की आलोचना

- **अव्यवहारिक:** हरियाणा में एक पर्याप्त बड़े योग्य घरेलू कार्यबल की कमी ने नए अधिनियम के कार्यान्वयन को "अव्यवहारिक" बना दिया।

भारत के श्रम बाजार का बैलकनीज़ेशन

- इस तरह के प्रतिबंध प्रधान मंत्री के "एक भारत श्रेष्ठ भारत ' के दृष्टिकोण को बाधित करते हैं, जिसका उद्देश्य देश के भीतर अन्य चीजों के अलावा, एक एकीकृत और मोबाइल श्रम बाजार हो। श्रम की मुक्त अस्थिरता राज्यों के बीच कई जनसांख्यिकीय और आर्थिक असंतुलन को सही करती है और इस पर अंकुश लगाने से समग्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन बाधित होगा
- **अनौपचारिकता को बढ़ाएगा:** इस कदम से कम-कुशल श्रमिकों को आघात पहुंच सकती है और राज्य के औद्योगिक और सेवा क्षेत्र को "अनौपचारिककरण" की ओर दबाव बना सकती है। दूसरे शब्दों में, समान श्रमिकों को कम भुगतान किया जाएगा और उनके पास कुछ भी सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी क्योंकि वे पेरोल पर औपचारिक रूप से नहीं होंगे
- **अफसरशाही और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन:** कानून में ऐसा प्रावधान जिसमें जिला प्रशासन से छूट लेने की आवश्यकता है, अगर वह पर्याप्त योग्य श्रमिकों को पूरी प्रक्रिया में नौकरशाही विवेक के तत्व में नहीं लाता है, इस तरह पुरानी अफसरशाही, भ्रष्टाचार और किराए पर लेने की राह प्रशस्त होता है
- **प्रभाव आर्थिक सुधार:** आर्थिक प्रतिबंध (पोस्ट-कोविद) निश्चित रूप से इन प्रतिबंधों से प्रभावित होंगे

- **प्रभाव निवेश:** गुड़गांव-मानेसर बेल्ट हरियाणा में, उच्च व्यापार निवेश आकर्षित किया है - दोनों विनिर्माण और सेवाओं में। इस तरह का श्रम प्रतिबंध मुक्त बाजार सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है जो हरियाणा में आने वाले निवेश में बाधा बन सकता है
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** यह कदम हरियाणा की प्रतिस्पर्धा को और प्रभावित कर सकता है तथा इस प्रकार निवेश और उद्योगों को गुजरात और कर्नाटक जैसे अधिक बाजार अनुकूल राज्यों में बदल सकता है।
- **बढ़ा हुआ अनुपालन बोझ:** नियमों के तहत, फर्मों और कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों को सरकारी पोर्टल पर 50,000 रुपये या उससे कम का सकल वेतन प्राप्त करना होगा और इसे नियमित अंतराल पर अपडेट करना होगा। यह व्यवसाय करने में आसानी से केंद्र सरकार के एजेंडे के अनुरूप नहीं होगी
- **राज्य के सभी श्रम बाजार पर प्रभाव:** केंद्र सरकार के अपने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, निजी क्षेत्र के लगभग 97% श्रमिक प्रति माह 50,000 रुपये से कम का वेतन प्राप्त करते हैं। इसलिए 50,000 रुपये मासिक वेतन सीमा काफी महत्वपूर्ण है और यह राज्य में अधिकांश निजी क्षेत्र के रोजगार को कवर करेगा।
- **परामर्श अभाव :** उद्योग संघ के अधिकांश सदस्यों ने इस आधार पर भी इसकी आलोचना की कि परिवर्तन की घोषणा से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया था।
- **तैयारी के लिए समय की कमी:** इतने कुशल और अर्ध-कुशल स्थानीय श्रमिकों के लिए इतनी जल्दी उपलब्ध होना संभव नहीं है। इसके बजाय, सरकार को इस नियमन के कार्यान्वयन में नर्म होना चाहिए जिससे व्यवसायों को "शांतिपूर्वक" जारी रखा जा सके।
- **छोटी कंपनियों की प्रभाव विस्तार योजनाएं:** उद्योग संगठन की राय है कि कानून से छोटी कंपनियों को नुकसान होगा और विस्तार योजनाओं को रोक दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन के बजाय नौकरी की बर्बादी होगी क्योंकि राज्य में कोई भी परिचालन का विस्तार नहीं करेगा।
- **मुक्त बाजार की भावना के खिलाफ:** इस कानून ने इस बहस को नया कर दिया है कि क्या सरकारी प्रभाव को निजी कंपनियों को नौकरियों में अपनी आरक्षण नीति अपनानी चाहिए।
- **कानून की संवैधानिकता पर प्रश्न:** जबकि आरक्षण की संवैधानिक गारंटी सार्वजनिक रोजगार (अनुच्छेद 16 (4)) तक सीमित है, इसे निजी क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रयास किया जाता है। संविधान में निजी रोजगार के लिए कोई प्रकट प्रावधान नहीं है, जहां से राज्य आरक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाए।
- **राज्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है:** संविधान राज्य पर सभी नागरिकों को अवसर की समानता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है। निजी क्षेत्र को आरक्षण नीति अपनाने के लिए, राज्य अपनी भूमिका नागरिक को सौंपता है, जिसकी आलोचना कुछ लोगों ने की।

ऐसे कानूनों को लाने में सरकार का औचित्य क्या है?

- **पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है:** सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में सभी नौकरियों का केवल एक छोटा अनुपात होता है, विधायकों ने सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक जनादेश को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की बात की है।
- **निजी क्षेत्र को बर्डन साझा करने के लिए पूछने का वैध अधिकार:** चूंकि निजी उद्योग कई तरीकों से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं (बुनियादी ढांचे, रियायती भूमि और ऋण, आदि) राज्य को आरक्षण नीति का पालन करने की आवश्यकता के लिए एक वैध अधिकार है।
- **शिक्षा में समान आरक्षण को कायम रखना :** शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करने के लिए निजी स्कूलों की आवश्यकता में एक समान तर्क दिया गया , जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया।

- **अन्य देशों में इसी तरह की सकारात्मक कार्रवाई:** हालांकि अमेरिका में, नियोक्ताओं के लिए कोटा की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, अदालतें मौद्रिक क्षति का आदेश देती हैं और भेदभाव के शिकार लोगों के लिए निषेधाज्ञा राहत देती हैं (अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। दौड़, रंग, राष्ट्रीय मूल, धर्म और सेक्स)। कनाडा में रोजगार समानता अधिनियम अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा करता है, विशेष रूप से आदिवासियों को निजी क्षेत्र में भी, संघटित विनियमित उद्योगों में भेदभाव से बचाता है।

निष्कर्ष

- जुलाई 2019 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक समान कानून पारित किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई। AP HC ने एक प्रथम दृष्टया अवलोकन किया था कि यह कदम असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन इस चुनौती को योग्यता के आधार पर सुना जाना चाहिए।

संबंधित लेख पढ़ें

- आंध्र प्रदेश स्थानीय लोगों की पहली नीति
- मध्य प्रदेश अधिवास आधारित कोटा
- आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है

साइबराबाद में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - सामाजिक मुद्दे और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोव्ली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला 'ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क (Transgender Community Desk)' लॉन्च किया है।
- यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग-समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है और इसका प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिन्हें एक सामुदायिक समन्वयक के रूप में नामित किया गया है
- यह साइबराबाद कमिश्नरी में ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच सभी शिकायत निवारण के लिए केंद्र बिंदु भी होगा।
- अन्य सेवाओं के अलावा, डेस्क महिला एवं बाल कल्याण विभाग और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कल्याणकारी योजनाओं के लिए परामर्श, कानूनी सहायता, जीवन-कौशल, सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, जॉब प्लेसमेंट और रेफरल लिंक भी प्रदान करेगा।

संबंधित आलेख:

- गरिमा गेरे: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ई-उद्घाटन के लिए एक आश्रय गृह
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाएँ

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

- रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र को गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए प्रदान की गई "अल्प" पेंशन में वृद्धि करनी होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- समिति ने देखा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत, इसके विभिन्न घटकों के तहत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है
- पैनल ने पहले भी ग्रामीण विकास विभाग (BoaRD) की 2019-20 और 2020-21 में अनुदान की मांग पर अपनी रिपोर्ट में इन पेंशन में वृद्धि का आग्रह किया था।

अन्य संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **प्रशासित:** ग्रामीण विकास मंत्रालय
- इसमें पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं:
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
  - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
  - अन्नपूर्णा योजना

श्रमिक कल्याण पोर्टल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - रोजगार

सुर्खिओ में क्यों-

- भारतीय रेलवे ई-एप्लीकेशन श्रमिक कल्याण पोर्टल के माध्यम से ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का 100% अनुपालन सुनिश्चित करता है

अन्य संबंधित तथ्य

भारतीय रेलवे श्रमिक कल्याण

- **विकसित और लॉन्च:** 1 अक्टूबर, 2018
- यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- ठेकेदारों को नियमित रूप से मजदूरी भुगतान डेटा ई-अनुप्रयोग में अपलोड करना
- यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय रेलवे के संविदाकर्मियों को उनका यथोचित हक मिले

मेरा राशन मोबाइल ऐप

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाएँ

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।

- **मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **लक्षित दर्शक:** उन राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए जो आजीविका की तलाश में नए जगहों पर चले जाते हैं।
- वर्तमान में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) के अंतर्गत आते हैं।
- वर्तमान में, यह प्रणाली देश में लगभग 69 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- NFSA लाभार्थियों में शामिल है।

यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए केरल मॉडल

संदर्भ: आउट ऑफ स्कूल बच्चों वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 84 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते तथा 47 मिलियन बच्चे 10 वीं कक्षा से पहले ही सीमित हो जाते हैं।

क्या तुम्हें पता था?

- संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुच्छेद 26 (1) और (2) में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (स्पष्ट) इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और यह समग्र विकास के लिए लक्ष्य होना चाहिए। जिसके बदले में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान विकसित होगा।
- UDHR के सात दशक बाद, 58 मिलियन बच्चे वैश्विक स्तर पर आउट ऑफ स्कूल हैं और 100 मिलियन से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूली शिक्षा प्रणाली में नहीं हैं

केरल मॉडल

केरल देश में उच्चतम साक्षरता दर और माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के 100 प्रतिशत नामांकन के लिए जाना जाता है। केरल मॉडल की सफलता के कारण हैं:

- **औपनिवेशिक काल में जड़ें:** 1817 के ऐतिहासिक शाही पुनरुत्थान ने शिक्षा को राज्य की "जिम्मेदारी" के रूप में घोषित किया। इसके साथ ही, इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा पर खर्च तय करने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था की तुलना में "राजनीतिक इच्छाशक्ति" अधिक महत्वपूर्ण है।
- **शिक्षकों की सामर्थ्य:** लगभग 46 लाख छात्र, 16,000 स्कूल और 1.69 लाख शिक्षकों के साथ, छात्र-शिक्षक का अनुपात एक वांछनीय परिदृश्य को प्रकट करता हैं। 20,000 से अधिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ, शिक्षक या प्रशासनिक काम के बोझ से दबे नहीं होते हैं बल्कि अपनी शैक्षणिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- **नीतियों की संगति:** 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कुल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। PRISM का सफल क्रियान्वयन (क्षेत्रीय विद्यालयों को एक से अधिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना) और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित करने के लिए आवंटन निजी से लेकर सार्वजनिक स्कूलों में 2.35 लाख छात्रों के विवर्तनिक बदलाव के कारण के रूप में देखा गया
- **अनुदान:** केरल में सफल सरकारों ने शिक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि की है और साथ ही स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा के विकेन्द्रीकृत वित्तपोषण को बढ़ावा दिया है। शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च भी लगातार बढ़ रहा है
- **व्यापक हस्तक्षेप:** केरल मॉडल से पता चलता है कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रारंभिक बहाने से संबंधित व्यापक हस्तक्षेप मानव विकास में स्थायी विकास प्राप्त करने में मदद करता

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में चुनौतियां

भारत का संविधान 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया है। हालांकि, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी भी हमारी पहुंच से दूर है। इसके लिए जिन कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं

- **सार्वजनिक कम खर्च:** केंद्रीय बजट 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.75 प्रतिशत शिक्षा को आवंटित किया गया। हालाँकि, इन्कॉन घोषणा में भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, उम्मीद है कि सदस्य राज्यों को SDG4 प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4-6% खर्च करना होगा।
- **शिक्षा का निजीकरण:** पब्लिक स्कूल प्रणाली की गिरावट और साथ ही महंगी निजी स्कूली शिक्षा के विकास ने बड़ी संख्या में बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में प्रणाली से समाप्त कर दिया है। निजी स्कूल में उनकी कम गुणवत्ता, मूल्यों की उपेक्षा, नौकरियों पर अत्यधिक ध्यान देने और प्रणालीगत अक्षमताओं के लिए भी आलोचना की जाती है।
- **गुणात्मक मुद्दा:** अनिवार्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण वांछित लक्ष्य को पकड़ने में विफल रहा है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण नहीं रखा गया। क्रमिक ASER सर्वेक्षण प्राथमिक शिक्षा में सीखने के परिणामों की खराब स्थिति को दर्शाता है।

आगे की राह

- **राज्य की सक्रिय भूमिका:** शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए राज्य को स्कूली स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, पाठ्यपुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति, लेखन सामग्री, स्कूल यूनिफॉर्म आदि जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधन लाने चाहिए (केरल मॉडल के व्यापक हस्तक्षेप के समान)।
- **सिविल सोसाइटी की भागीदारी:** केरल की सफलता को सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और मैत्रीपूर्ण संघों के सामूहिक प्रयासों की बदौलत संभव बनाया गया है।
- **सामाजिक ऑडिटिंग :** प्रत्येक गाँव या शहरी क्षेत्र में एक गाँव या मोहल्ला स्कूल समिति होनी चाहिए। ऐसी समिति भवनों, खेल के मैदानों और स्कूल के बगीचों के निर्माण और रखरखाव, सहायक सेवाओं के लिए प्रावधान, उपकरणों की खरीद, आदि की देखभाल करेगी।
- **बढ़ी हुई प्रतिबद्धता:** बिजली, पानी और सड़क के प्रावधानों के लिए जिस तरह की प्रतिबद्धता या सामूहिकता दिखाई जाएगी, उसे शिक्षा के लिए भी विकसित करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

जब तक शिक्षा राष्ट्रवाद के लिए एक चुनावी और भावनात्मक मुद्दा नहीं बन जाती, तब तक हमारे पास केरल की तरह महत्त्वपूर्ण कुछ कम शहर होंगे

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

जनसंख्या स्थिरीकरण

संदर्भ: राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (2.1 की कुल प्रजनन दर) को 2010 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- **दस राज्यों -** कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश**,** पश्चिम बंगाल**,** महाराष्ट्र**,** तमिलनाडु और केरल और जम्मू और कश्मीर ने इस लक्ष्य को हासिल किया है**,** भले ही बहुत देरी हो गई।
- केरल और तमिलनाडु ने दशकों पहले इसे पूरा किया।
- **धर्मनिरपेक्ष गिरावट:** भारत के आधे से अधिक प्रजनन दर ने समाज के सभी वर्गों में कटौती की है - विशेषाधिकार प्राप्त और गरीब**,** शिक्षित या नहीं और उच्च और निम्न जाति।

दक्षिणी राज्यों की सफलता से मुख्य रास्ते

- **पूर्वापेक्षाओं पर प्रश्न:** दक्षिणी राज्यों की प्रजनन दर में कमी उस पारंपरिक ज्ञान के विपरीत है जिसके अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण के लिये साक्षरता**,** शिक्षा और विकास आवश्यक शर्तें हैं।।

- **राज्य सरकारों की सक्रियता:** दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट का कारण यह है कि इन राज्यों की सरकारों ने लोगों से आग्रह किया कि वे केवल दो बच्चे पैदा करें और उसके तुरंत बाद नसबंदी कर दी गई। लगभग पूरे राज्य तंत्र को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित किया गया था। उत्तरी राज्यों को भी इस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

यूपी और बिहार का मुद्दा

- उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य: यूपी और बिहार भारत की आबादी का 23 प्रतिशत हैं और अगले 15 वर्षों में 12 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। उनके उच्च **TFR** सभी धार्मिक समूहों में व्याप्त हैं।
- **गर्भनिरोधक का अपर्याप्त उपयोग:** यूपी, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अभी भी चार या इससे अधिक बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि इन राज्यों में गर्भनिरोधक के प्रयोग की दर 10% से भी कम है।
- इन राज्यों के अनेक ज़िलों में महिलाएँ आधुनिक परिवार नियोजन विधियों का उपयोग नहीं करती हैं, जबकि वे पारंपरिक गर्भनिरोधक विधियों पर ज़्यादा भरोसा करती हैं।
- **महिला नसबंदी पर भरोसा:** दुनिया का कोई अन्य देश महिला नसबंदी का इस्तेमाल भारत की तरह नहीं करता है। 2014 के बाद बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में कोहराम मच गया, जब छह घंटे से कम समय में 80 से अधिक नसबंदी की गई और कई महिलाओं की मृत्यु हो गई, यह उम्मीद थी कि राज्य अनिवार्य महिला नसबंदी पर धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में धीमा नहीं हुआ है

जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे (राष्ट्रीय स्तर पर)

- **आधुनिक तरीकों को देर से अपनाना:** इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने 1980 के दशक के सही इंजेक्टेबल्स की शुरुआत की लेकिन भारत ने केवल 2016 में ऐसा किया। ठीक से निष्पादित, एक जैब गर्भावस्था से तीन महीने तक सुरक्षा प्रदान करता है
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: जहां राष्ट्रीय और राज्य की नीतियां पुरुष नसबंदी पर जोर देती हैं, वहीं राजनेता कभी भी इसे अपनाते नहीं हैं
- **संवैधानिक प्रेरणा की विफलता:** 2026 तक संसद में सीटों के राज्य-वार आवंटन पर रोक को संवैधानिक (84 वें संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से "जनसंख्या स्थिरीकरण को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरक उपाय" के रूप में सेवा करने के लिए बढ़ाया गया था -एक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। आगे विस्तार के अभाव में, यह राजनीतिक रूप से अस्थिर हो जाएगा।
- **आर्थिक विकास पर प्रभाव:** जनसांख्यिकी आर्थिक विकास को ग्रहण करेगी और युवा आबादी से लाभ को नष्ट करेगी।
- **पितृसत्ता और लिंग अनुपात:** पुत्र को वरीयता देने के प्रमुख कारणों में से एक पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाना है।
- **मृद कथाओं से पुत्र का उद्भव:** दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल कर लिया है जो अब कामकाजी उम्र की आबादी के बाहर बुजुर्गों के मुद्दे का सामना करते हैं। परिणामस्वरूप, दक्षिणी राज्यों में काम करने वाले उत्तरी राज्यों के लोगों के प्रतिरोध में बढ़ोतरी होगी।

आगे की राह

- बाद में विवाह और बच्चे के जन्म को प्रोत्साहन देना
- **महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक आसान बनाएं:** गर्भनिरोधक के पारंपरिक तरीकों पर अधिक निर्भरता को विश्वसनीय और आसान विकल्पों के साथ तेजी से बदलने की जरूरत है
- महिलाओं के श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देना

- स्थिरीकरण केवल जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है सामाजिक सामंजस्य को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है।

निष्कर्ष

जनसंख्या की गति, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में ठीक से प्रबंधित की जाती है, तो 2055 तक भारत की सबसे बड़ी पूंजी होगी। 2040 तक, भारत मानव पूंजी का निर्विवाद किंग होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- जनसंख्या की चिंता

आरक्षण की समीक्षा

संदर्भ: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया है कि वर्ष 1992 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आरक्षण की 50% सीमा (इंद्रा साहनी मामले) के निर्णय को बाद में हुए संवैधानिक संशोधनों तथा सामाजिक परिवर्तनों के कारण संशोधित किया जाना चाहिये।

मुद्दे की पृष्ठभूमि

- शीर्ष अदालत ने 2018 में महाराष्ट्र कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए तय किए जाने वाले कई सवालों में से एक के रूप में इसे तैयार किया
- महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को कुल सीटों का 16% आरक्षण देने का निर्णय किया।
- इस कानून को जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करके सरकारी नौकरियों में 12% एवं शैक्षणिक संस्थानों में 13% कर दिया था।
- इस अधिनियम की शुरुआत के साथ, राज्य में आरक्षण लाभ 50 प्रतिशत से अधिक हो गया।
- महाराष्ट्र के अलावा, तीन अन्य राज्य हैं - तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़ - जो 50% सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किये हैं। और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं।

वर्तमान में, संविधान पीठ निम्नलिखित व्यापक मुद्दों पर निर्णय लेगी

- **आरक्षण की सीमा से संबंधित:** सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने के लिये इंद्रा साहनी मामले पर विचार करेगा।
- **मराठा आरक्षण:** 'असाधारण परिस्थिति' के साथ मुद्दा उठता है कि क्या वास्तव में किसी मामले में असाधारण परिस्थिति है अथवा नहीं और यदि है तो आरक्षण 50% की सीमा से कितना अधिक हो सकता है।
- **संघवाद और राज्यों की शक्ति:** SC को यह भी जांचना होगा कि क्या 102 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक कानून बनाने के लिए राज्य की विधायिका को उसकी शक्ति से वंचित करता है ताकि उन्हें राज्य का लाभ दिया जा सके।
- **अनुच्छेद 342A:** अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति। एससी इस बात पर ध्यान देगा कि क्या अनुच्छेद 342A किसी पिछड़े वर्गों को कानून बनाने या वर्गीकृत करने के लिए किसी राज्य की शक्ति को निरस्त करता है। नागरिक और इससे संघीय नीति / संरचना प्रभावित होती है।

इंद्र साहनी केस के लिए पृष्ठभूमि

- **मंडल आयोग:** दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मापदंड निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया।

- **ओबीसी आरक्षण:** मंडल रिपोर्ट में उस समय की 52 प्रतिशत आबादी को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग '(SEBCs) के रूप में पहचाना गया था और एससी / एसटी के लिए पहले से मौजूद 22.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा एसईबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी।
- **न्यायालय में चुनौती:** तत्कालीन वी पी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहती थी, लेकिन इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। नौ न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष आए इंदिरा साहनी मामले में फैसला 1992 में दिया गया।
- **अपवादों के साथ आरक्षण पर सेलिंग:** इंद्रा साहनी मामले में 16 नवंबर, 1992 को निर्णय दिया गया था। इसमें नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय दिया गया था, इस पीठ ने आरक्षण में 50% सीमा जैसे कई ऐतिहासिक प्रस्ताव रखे।
- **IR Coelho केस:** इस मामले में, SC ने किसी भी कानून की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका के अधिकार को कायम रखते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जो मूल अधिकारों में बताए गए बुनियादी ढांचे को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर देता है, भले ही उन्हें 9 वीं अनुसूची में डाल दिया गया हो।

102 वां संविधान संशोधन अधिनियम

- 102 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है (पहले यह वैधानिक निकाय था)
- 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नए लेख 338 B और 342 A डाला गया
- अनुच्छेद 338 B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC को अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 342 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए एक राष्ट्रपति का अधिकार प्रदान करता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। हालाँकि, संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया है।

संबंधित लेख पढ़ें

- आंध्र प्रदेश स्थानीय लोगों की पहली नीति
- मध्य प्रदेश अधिवास आधारित कोटा
- आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है

सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश में बिजली पारेषण व्यवस्था मजबूत करने के लिये संशोधित लागत को मंजूरी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमानित लागत पर अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली पारेषण और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 9,129.32 करोड़ रुपये की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के माध्यम से योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना को शुरू में दिसंबर, 2014 में केंद्रीय क्षेत्र योजना योजना के रूप में अनुमोदित किया गया।
- योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
- इसे दिसंबर 2021 तक चरणबद्ध तरीके से चालू करने का लक्ष्य है।

- कमीशन के बाद, बनाई गई ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली का स्वामित्व और रखरखाव संबंधित राज्य उपयोगिताओं द्वारा किया जाएगा।
- यह इंट्रा - स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सूचकांक निगरानी प्रकोष्ठ (IMC)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में, 'सूचकांक निगरानी प्रकोष्ठ' / इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल (IMC) द्वारा केंद्र सरकार के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल (IMC)

- **द्वारा स्थापित:** सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- **उद्देश्य:** इसका कार्य 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है तथा मीडिया की स्वतंत्रता को मापने हेतु एक वस्तुनिष्ठ मापदंड विकसित करना है।
- यह 15 सदस्यीय समिति है।
- इसमें चार पत्रकार और सरकारी अधिकारी हैं।
- **अध्यक्षता:** कुलदीप सिंह धतवालिया, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक
- मानहानि को गैर-अपराध घोषित किया जाए।
- किसी मीडिया या प्रकाशन के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' की सहमति, पहले से आवश्यक बनाई जानी चाहिए।

घुमंतू जनजातियों के विकास की पहल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यसभा को घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए पहल के बारे में सूचित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2019 में देश में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNCs) का गठन किया गया था।
- **उद्देश्य:** DNTs, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
- केंद्र सरकार द्वारा DNTs के लिए राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:
  - DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अम्बेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
  - DNT बॉयज और गर्ल्स के लिए हॉस्टल के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति ने DNT समुदायों की पहचान का कार्य किया है जिन्हें औपचारिक रूप से वर्गीकृत किया जाना अभी शेष है।

- नीति आयोग ने भारत के विभिन्न भागों में इन समुदायों के अध्ययन का संचालन करने के लिए 62 जनजातियों के मानव जाति विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण का कार्य मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) को सौंपा।

स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार विधेयक, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 30,000 रुपये तक के वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस प्रस्तावित विधेयक में, दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उद्यमों, उद्योगों, कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, तथा दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले व्यक्ति को निजी क्षेत्र अथवा इकाई माना गया है।
- इस विधेयक के पारित होने तथा अधिनियम के रूप में लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी नियोक्ताओं को, 30,000 रुपये से कम कुल मासिक वेतन या मजदूरी- अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निर्देशों के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।
- कोई भी स्थानीय उम्मीदवार स्वयं को पंजीकृत पोर्टल में पंजीकृत किए बिना 75% लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी (AO) द्वारा पारित किसी आदेश के खिलाफ असंतुष्ट नियोक्ता द्वारा 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, झारखंड सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है।

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

रेप और विवाह

संदर्भ: हाल ही में, CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी से पूछा कि 'क्या वह लड़की से शादी करने को तैयार है?
आरोपी ने अपनी मां को इस शिकायत पर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करने के लिए भी मजबूर किया था कि वह 18 साल की होने पर पीड़िता से शादी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव से उस व्यक्ति ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह पहले से शादीशुदा है।

SC द्वारा की गई टिप्पणी (प्रस्ताव) का कार्यान्वयन

- **समाज पर प्रभाव:** भूमि के उच्चतम, सबसे सबसे पूर्व-प्रतिष्ठित न्यायालय में शब्द बड़े समाज में व्याप्त हैं। इस तरह के प्रस्ताव करने से पहले SC को अधिक सतर्क रहना चाहिए था
- **प्रतिगामी प्रस्ताव के रूप में आलोचना:** इस मामले में, SC की टिप्पणी, दुर्भाग्य से, आघात और बलात्कार के उल्लंघन के लिए भुगतान के रूप में शादी के आक्रामक और प्रतिगामी विचार को समाप्त करने का जोखिम है।
- **अपराध की रोकथाम:** भूमि के कानून के तहत, बलात्कार एक "गैर-यौगिक" अपराध है। अर्थात्, किसी भी बंदोबस्त को अदालत के बाहर पहुंचकर अपराध को कम या कम नहीं किया जा सकता है। इस तरह के समझौते करना अपराध को कम करना माना जाता है।
- **SC की अपनी पूर्वता के खिलाफ:** MP बनाम मदनलाल के राज्य के 2015 के एक फैसले में, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था, "बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में, किसी भी परिस्थिति में समझौता करने की अवधारणा को वास्तव में नहीं सोचा जा सकता है। हरियाणा के शिंभू बनाम राज्य में पहले के एक फैसले में, SC ने कहा था, "बलात्कार को समझौता और समझौता करने के लिए पार्टियों के लिए छोड़ दिया जाने वाला मामला नहीं है।"
- **पितृसत्ता को नष्ट करना:** इस प्रकार का समझौता महिलाओं के साथ बलात्कार (बलात्कार) का उल्लंघन कर रहा है, जो परिवारों के बीच सुलझने के लिए एक मामला है ताकि पुरुष हमलावरों की प्रतिष्ठा और सम्मान को संरक्षित किया जा सके।
- **अनुच्छेद 21 के विरुद्ध:** बलात्कार पीड़िता के समाधान के रूप में शादी की पेशकश करके, न्यायपालिका एक लड़की के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही। इस तरह के अश्लील मैचमेकिंग और एक महिला के जीवन की गरिमा और उसके जीवन की गरिमा को प्रभावित करते हैं।
- **अनुच्छेद 14 के विरुद्ध:** इस प्रकार की टिप्पणियों को भारतीय महिलाओं की समान नागरिक के रूप में स्वायत्तता पर हमला माना जाता है। समान अधिकार कार्यकर्ताओं ने हमेशा गलत बलात्कार, पितृसत्तात्मक मानसिकता और अन्य विफलताओं के खिलाफ कड़ी मेहनत की है जैसे बलात्कार के लिए पीड़ित को दोष देना। समानता के लिए यह लड़ाई और भी कठिन हो जाती है जब उच्च कार्यालयों में लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं
- **भेद्यता बढ़ जाती है:** इस तरह का समझौता पीड़ित को उसके पति / हमलावर से अधिक हिंसा के लिए बेनकाब करता है
- **मौजूदा प्रथा:** यहां यह ध्यान रखना उचित है कि भारतीय दंड संहिता के तहत वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। इस तरह के समझौते पुलिस, ग्राम सभाओं और निचली अदालतों द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। लेकिन न्यायालय में CJI की टिप्पणी इस अघोषित परंपरा को खत्म कर सकती है और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में हुई प्रगति को पटरी से उतार सकती है।
- यहां यह ध्यान रखना उचित है कि भारतीय दंड संहिता के तहत वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। इस तरह के समझौते पुलिस, ग्राम सभाओं और निचली अदालतों द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। CJI की खुली अदालत में की गई टिप्पणी

इस अकर्मण्य परंपरा को खत्म कर सकती है और कई निर्णय जो कि भारतीय महिलाओं की समान नागरिकता की स्वायत्तता की पुष्टि करते हैं, द्वारा की गई प्रगति को रोक सकती है।

निष्कर्ष

जबकि निर्भया मामले के निशान अभी भी अधूरी हैं, और नाबालिगों, विशेष रूप से दलितों के खिलाफ बलात्कार और हत्याओं की एक श्रृंखला रिपोर्ट की जा रही है, तो न्यायपालिका की चौंकाने वाली टिप्पणी लिंग समानता के खिलाफ एक गहरी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वैवाहिक बलात्कार
- यौन शोषण और हमारे बच्चों की सुरक्षा

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और शासन और जीएस - III - उद्यमिता

सुर्खिओ में क्यों-

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से कुछ नीचे चर्चा की गई है।

प्रधानमंत्री आवास (प्रधानमंत्री युवा) योजना

- **मंत्रालय:** कौशल विकास मंत्रालय
- **उद्देश्य:** उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, वकालत और उद्यमशीलता नेटवर्क के लिए आसान पहुँच के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट-अप्स
- **कौशल विकास मंत्रालय:** डॉयचे गेसल्सचफ्ट फेर इंटरनेशनल जुसमेनर्बिट (Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit) जर्मनी के सहयोग से।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- **मंत्रालय:** MSME मंत्रालय
- इसमें गैर-कृषि क्षेत्र के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)

- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय
- यह कौशल विकास कार्यक्रम है
- इसमें एक प्रशिक्षु को बैंक क्रेडिट लेने और अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाना शामिल है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए बहु आजीविका उन्नयन के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को दूर करना है

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यक्रम (SVEP)

- डीएवाई-एनआरएलएम की इस उप-योजना के तहत, 31 जनवरी, 2021 तक कुल 194,144 उद्यम स्थापित किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका

संदर्भ: सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 6.2) को 2030 तक भारत की आवश्यकता है, सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करने और खुले में शौच को समाप्त करने के लिए, महिलाओं और लड़कियों तथा कमजोर स्थितियों में लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।

महिला, स्वच्छता और स्वच्छ बारात अभियान

- **लैंगिक संवेदनशील उद्देश्य:** योजना, खरीद, बुनियादी निर्माण, रखरखाव और निगरानी आदि स्वच्छ भारत योजना के कार्यान्वयन के मूल सिद्धांत हैं। इसके अलावा स्वच्छभारतमिशन - ग्रामीण (चरण1)के दिशा निर्देशों (2017) के अनुसार स्वच्छता कार्यक्रमों के सभी चरणों में लिंग संबंधित संवेदनशीलता का ध्यान रखे जाने की बात भी की गई थी तथा इस चरण में स्वच्छता से जुड़े कार्यों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की बात भी की गई थी।
- **दिशानिर्देश w.r.t लैंगिक आयाम:** पेयजल और स्वच्छता विभाग ने भारत में स्वच्छता के लैंगिक आयामों को पहचानते हुए दिशानिर्देश जारी किए। इसने न केवल स्वच्छता हस्तक्षेपों की योजना और कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, बल्कि "एसबीएम-जी समितियों और संस्थानों में उनके नेतृत्व" पर भी जोर दिया।
- **राज्यों को दिशानिर्देश:** राज्यों से भी यह अपेक्षा की गई थी कि वे ग्राम स्तर पर'जल व स्वच्छता समितियों' (VWSCs) में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें, जिससे लैंगिक असमानता कम हो सके।स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (चरण 1) के दिशा निर्देशों में सिफारिश की गई थी कि इन समितियों में 50% से अधिक सदस्य महिलाएँ होनी चाहिये।
- **व्यवहार परिवर्तन के लिए महिलाएं:** सरकार ने 8 लाख से अधिक स्वच्छाग्रहियों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।स्वच्छाग्रही कम मानदेय पर कार्य करने वाली महिलाएँ होती हैं, जो सामुदायिक स्तर पर व्यवहार-गत परिवर्तन लाने का प्रयासकरती हैं।

लैंगिक और स्वच्छता में शामिल चुनौतियां

- **खुले में शौच करने से जुड़े जोखिम:** खुले में शौच के लिए जाते समय महिलाएं अपने जीवन में खतरे या असुरक्षित महसूस करती हैं।
- यह महिलाओं द्वारा शौचालय का उपयोग करने, घर से बाहर न निकलने, कम भोजन और पानी की खपत की ओर जाता है
- **महिलाओं पर असम्बद्ध बोझ:** स्नान और शौच के दौरान गोपनीयता की इच्छा पुरुषों की तुलना में लड़कियों और महिलाओं के मामले में अलग है। इस प्रकार, उचित स्वच्छता सुविधाओं की अनुपलब्धता महिलाओं के लिए एक असहाय स्थिति पैदा करती है और यह कई रोगों को जन्म देती है।
- **पुरुषों के लिए कमजोर भागीदारी और प्रॉक्सी:** पुरुषों के लिए कमजोर भागीदारी और प्रॉक्सी: व्यवहार में, स्वछता के प्रवर्तक शायद ही कभी महिलाओं को पानी और स्वच्छता समितियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उनकी भागीदारी की गारंटी नहीं देता है। अनिवार्य रूप से ऐसे मामले थे जहां महिलाएं पति-पत्नी के लिए सम्मुख थीं

आगे की राह

- **निरंतर व्यवहार परिवर्तन:** सूचना, शिक्षा और संचार, जिसका उद्देश्य जनता के व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य है, सफलता की कुंजी है स्वच्छ भारत मिशन 2 .0 के द्वारा। मिशन स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल और पुन: उपयोग के सुरक्षित निपटान के नए एजेंडों को शुरू करते हुए निरंतर व्यवहार परिवर्तन की चर्चा होती है ।
- **वित्तीय और आजीविका अनुबंध:** आजीविका के साथ स्वच्छता और स्वच्छता को इंटरलिंक करने की आवश्यकता है: भारत स्वच्छता गठबंधन ने स्वच्छता जरूरतों के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों के साथ सूक्ष्म वित्त को जोड़ने में मदद की।
- **ट्रैकिंग लैंगिक परिणाम:** विकास अभ्यास में लैंगिक विश्लेषण रूपरेखा डिजाइन, कार्यान्वयन और माप का समर्थन करती है जो स्वच्छता में लैंगिक समानता अंतर को भर सकती है। SBM में लैंगिक परिणामों को ट्रैक और मापने के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक है

- **लैंगिक संवेदीकरण और प्रशिक्षण:** हस्तक्षेपों की आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों में, लैंगिक लक्ष्यीकरण पर हितधारकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रभावी संचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- **सिविल सोसाइटी को शामिल करना:** सरकार के अलावा, गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका, जिसमें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ और कई गैर-सरकारी संगठनों जैसे संस्थान शामिल हैं इसकी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि हम एक शक्तिशाली लैंगिक लेंस का उपयोग करके स्थायी स्वच्छता का पीछा कर रहे हैं

निष्कर्ष

- घर में शौचालय की उपलब्धता एवं उसका उपयोग महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।यदि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है तो समाज में बड़ा एवं सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

माहवारी संबंधित वर्जना

संदर्भ: एक जनहित याचिका मामले में निर्झारी मुकुल सिन्हा बनाम भारत संघ, गुजरात उच्च न्यायालय ने नौ दिशानिर्देशों का प्रस्ताव करते हुए एक आदेश पारित किया है कि राज्य को मासिक धर्म वर्जित और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने का पालन करना चाहिए।

दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में

- फरवरी 2020 में, गुजरात के भुज के श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट (एसएसजीआई) में 68 लड़कियों के अंत:वस्त्र जांचे गए हैं ताकि यह पता लगया जा सके की उन्हें मासिक धर्म हो रहा है या नहीं। हॉस्टल में रहने वाली स्नातक की छात्राओं को कॉलेज के रेस्टरुम ले जाकर उन्हें अपने अंत:वस्त्र उतारने के लिए मजबूर किया गया।
- प्रारंभिक जांच के बाद, विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति, दर्शन ढोलकिया, जो कॉलेज से संबद्ध हैं, ने कार्रवाई को सही ठहराया था, कहा कि लड़कियों की जाँच की गई थी क्योंकि छात्रावास का नियम है कि उनके मासिक धर्म पर लड़कियों को नहीं माना जाता है अन्य रहने वाला के साथ भोजन करें।
- इसने जल्द ही चार लोगों की गिरफ्तारी और गुजरात उच्च न्यायालय में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक व्यापक सार्वजनिक आक्रोश का नेतृत्व किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ उनके मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर बहिष्करण प्रथा, संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 17, 19, और 21 में निहित, मानवीय, कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

न्यायालय ने राज्य सरकार को पालन करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव दिया;

- सभी स्थानों, वह यह निजी हो या सार्वजनिक, धार्मिक हो या शैक्षिक, पर मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधित हो;
- राज्य सरकार को नागरिकों में मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के सबंध में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलानी चाहिए
- शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ाना भी इस संबंध में सहायता कर सकता है;
- मासिक धर्म जीव विज्ञान के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संवेदीकरण भी किया जाना चाहिए ताकि वे समुदाय में इस ज्ञान का प्रसार कर सकें और मासिक धर्म से संबंधित मिथकों का पर्दाफाश करने के लिए सामाजिक समर्थन जुटा सकें।
- राज्य सरकार को इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए अभियान, गैर सरकारी संगठनों और अन्य निजी संगठनों को शामिल करना चाहिए;

- राज्य सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों और रहने की जगहों को, वह निजी या सार्वजनिक, जो भी हों, उन्हें किसी भी तरीके से महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार करने से निषिद्ध करना चाहिए;
- राज्य सरकार को औचक निरीक्षण करना चाहिए, एक उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए और इस तरह के अन्य कार्यों को करना चाहिए, इसके अनुपालन के लिए कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें गलती करने वाले संस्थान के खिलाफ उचित जुर्माना लगाना भी शामिल है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उक्त मामले में उपरोक्त निर्देश प्रथमदृष्टया अवलोकन है।

मुद्दे का विश्लेषण

- **अस्पृश्यता का रूप:** यह तर्क दिया गया है कि महिलाओं के मासिक धर्म का इलाज करने से अस्पृश्यता की प्रथा अलग-अलग हो जाती है।
- **मासिक धर्म का दोषारोपण:** हमारे समाज में मासिक धर्म को कलंकित किया गया है। यह कलंक मासिक धर्म की महिलाओं की अशुद्धता में पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य रूप से चर्चा करने की हमारी अनिच्छा के कारण है।
- **महिलाओं के सामने दैनिक प्रतिबंध:** "पूजा" कक्ष में प्रवेश नहीं करना, शहरी लड़कियों पर प्रमुख प्रतिबंध है, जबकि, रसोई में प्रवेश नहीं करना मासिक धर्म की अवधि में ग्रामीण लड़कियों पर प्रमुख प्रतिबंध है। मासिक धर्म की अवधि में लड़कियों और महिलाओं को पूजा करने और पवित्र पुस्तकों को छूने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।"
- **पितृसत्तात्मक मान्यताएँ:** इस मिथक का अंतर्निहित आधार मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता का सांस्कृतिक विश्वास है और यह माना जाता है कि मासिक धर्म में महिलाएं अस्वच्छ और अशुद्ध होती हैं और इसलिए वे जो भोजन तैयार करती हैं या संभालती हैं, वह दूषित हो सकता है।
- **शिक्षा पर प्रभाव:** कई कम विकसित देशों में बड़ी संख्या में लड़कियों को मासिक धर्म शुरू होने पर (भारत में 23% से अधिक) स्कूल छोड़ना पड़ता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** कई समाजों में मौजूद "मासिक धर्म के संबंध में इस प्रकार की वर्जनाएं कई समाजों में मौजूद हैं, जिनका लड़कियों और महिलाओं की भावनात्मक, मानसिक स्थिति, जीवन शैली और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।" और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि "भारत में 88% महिलाएं मासिक धर्म में राख, अखबार, सूखे पत्ते और भूसी रेत का इस्तेमाल करती हैं। खराब सुरक्षा और धोने की अपर्याप्त सुविधाओं से संक्रमण की आशंका बढ़ सकती है, मासिक धर्म के खून की गंध से लड़कियों को कलंकित होने का खतरा होता है।"
- **जागरूकता और सार्वजनिक बहस में कमी:** युवा लड़कियां अक्सर मासिक धर्म के सीमित ज्ञान के साथ बढ़ती हैं क्योंकि उनकी माताएं और अन्य महिलाएं उनके साथ मुद्दों पर चर्चा करने से कतराती हैं।
- **निजता के अधिकार के खिलाफ:** मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर बहिष्करण न केवल महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन है, बल्कि निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
- **सबरीमाला फैसले में न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ:** याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला मंदिर प्रवेश निर्णय पर भरोसा किया है जहां 4: 1 बहुमत वाली पीठ ने माना था कि महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, को असंवैधानिक माना और इस प्रावधान को खत्म कर दिया।
- लैंगिक -मैत्रीपूर्ण स्कूल संस्कृति और बुनियादी ढांचे और पर्याप्त मासिक धर्म संरक्षण विकल्पों और / या स्वच्छ, सुरक्षित और निजी स्वच्छता सुविधाओं की कमी महिला शिक्षकों और लड़कियों की निजता के अधिकार को कमजोर करती है

निष्कर्ष

हालाँकि, उचित निर्देश जारी करने से पहले, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ-साथ भारत संघ से भी जवाब मांगा है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- सबरीमाला मुद्दा

ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण

महिलाओं और पर्यावरण के बीच अंतर

- **विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन महिलाओं की मदद करता है:** सुदूर क्षेत्रों में वितरित अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों - जैसे मिनी-ग्रिड, सोलर पंप और अन्य स्टैंडअलोन उत्पादक बिजली प्रणालियों को तैनात करने के लिए यह सस्ता और अधिक कुशल है - बजाय केंद्रीकृत, ग्रिड-आधारित शक्ति का विस्तार करने के लिए।
- **महिलाओं के कार्यभार को कम करता है:** विद्युत उपकरण घरेलू कामों के बोझ को भी कम करते हैं, जो आमतौर पर महिलाओं पर असर पड़ता है
- **जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने में समय बचाता है:** खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, जलाऊ लकड़ी या गोबर जैसे गंदे ईंधन को इकट्ठा करने में लगने वाले समय को बचाता है और इनडोर वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करता है 3.8 मिलियन समय से पहले होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार
- **साक्षरता और उत्पादकता में वृद्धि:** रात में प्रकाश में महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करना और अध्ययन करना संभव बनाता है। बिजली न केवल आय अर्जित करने में मदद करती है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाती है।
- **स्व-रोजगार को बढ़ावा देता है:** विश्वसनीय बिजली तक पहुंच और फलस्वरूप समय की बचत महिलाओं को कौशल-प्रशिक्षण के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, जो उन्हें एक कर्मचारी के रूप में आय अर्जित करने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकता है।
- **गैर-कृषि रोजगार:** विश्व बैंक के एक पेपर में बताया गया है कि ग्रामीण भारत में घरेलू विद्युतीकरण के कारण महिलाओं के गैर-कृषि स्वरोजगार में छोटी वृद्धि हुई है और लड़कियों के स्कूली शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- हालांकि, ऊर्जा पहुंच पर्याप्त नहीं है; हमें ऊर्जा कार्यबल में महिलाओं के अधिक से अधिक समावेशी परिणामों की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला महिलाओं को उच्च मजदूरी कमाने और पारंपरिक आय-उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।
- चूंकि कई स्वच्छ ऊर्जा नौकरियां अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के पास जाती हैं, वे महिलाओं के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती हैं, जिन्हें औपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक शिक्षा या प्रशिक्षण की संभावना कम है।
- एक महिला कार्यबल भी अधिक ऊर्जा पहुंच में योगदान कर सकती है। चूंकि महिलाएं अलग-अलग सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो पुरुषों के लिए एक दृश्य हैं, उनका समावेश व्यवसायों को अधिक घरों तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
- अध्ययनों से पता चला है कि महिलाएं पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र होने के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति व्यवसायों में पुरुषों के समान प्रदर्शन करती हैं। उद्योग में महिलाओं को रोजगार देना पारंपरिक मानदंडों और रूढ़ियों को चुनौती देता है कि महिलाएं क्या करने में सक्षम हैं।
- **बिजली दीदी का उदाहरण:** ओडिशा में बिजली आपूर्तिकर्ताओं के लिए, ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने के लिए महिलाओं को रोजगार देना न केवल घाटे में है, बल्कि इससे राजस्व में 7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 120 महिलाओं का एक नेटवर्क, जिसे बिजुले दीदी के नाम से जाना जाता है, बिल भुगतान एकत्र करते हैं और उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त 8,000 ग्राहकों ने समय पर बिलों का भुगतान करना शुरू कर दिया और 1,250 से अधिक घर और 300 व्यवसाय सौर ग्रिड से जुड़ गए।

- महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए ऊर्जा की पहुँच के लिए, नीतियों को "लैंगिक -जागरूक" होने की आवश्यकता है, अर्थात, उन्हें सामाजिक पदानुक्रम और पुरुषों और महिलाओं के बीच ऊर्जा के उपयोग में अंतर को समझना चाहिए।

निष्कर्ष

वितरित अक्षय ऊर्जा महिलाओं के जीवन को बदल सकती है। हमें ऊर्जा पहुंच, कृषि, जल उपलब्धता और लैंगिक इक्विटी के बीच संबंध बनाने की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021

पृष्ठभूमि

- **स्वैच्छिक समाप्ति:** भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत, स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करना एक आपराधिक अपराध है।
- **विशिष्ट कानून:** विधेयक का उद्देश्य गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करना है।
- **चिकित्सा समाप्ति के लिए विभिन्न शर्तें:** गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020 गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के गर्भधारण को समाप्त करने के लिए एक प्रदाता से राय लेने का प्रस्ताव करता है। इसने 20-24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो प्रदाताओं से राय की आवश्यकता की शुरुआत की है। इस विधेयक में महिलाओं की विशेष श्रेणियों जैसे बलात्कार की पीड़ित, दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग के लिए ऊपरी गर्भधारण की सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक बढ़ जाती है।
- **अवैध सेवा प्रदाताओं की ओर प्रणालीगत प्रेरणा:** यदि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक हो गई है, तो महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की तलाश करनी होगी। इस प्रकार धीमी न्यायिक प्रक्रिया उसे अवांछित गर्भधारण की समाप्ति के लिए अवैध सेवा प्रदाताओं पर निर्भर होने के लिए प्रेरित करेगी
- **एमटीपी में संशोधन के लिए तर्क:** भ्रूण असामान्यता या बलात्कार के कारण महिलाओं द्वारा 20 सप्ताह से अधिक गर्भपात की अनुमति के लिए कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। यह भी तर्क है कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, गर्भधारण को समाप्त करने के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने की गुंजाइश है

क्या आपको पता है?

- 2015 के इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स द्वारा एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि भारत में मातृ मृत्यु के 10-13% असुरक्षित गर्भपात के कारण होते हैं - भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण।
- भारत में 2015 में अनुमानित 15.6 मिलियन गर्भपात किए गए थे। यह 15-49 की आयु वाली प्रति 1,000 महिलाओं की गर्भपात दर का बताता है।
- वर्तमान में, चार से कम गर्भपात स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान किया जाता हैं
- एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के लगभग 67% देशों (जिनमें गर्भावस्था को नियंत्रित करने वाला एक संघीय कानून है) को गर्भपात कराने के लिए कम से कम एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
- एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के लगभग 67% देशों (जिनमें गर्भावस्था को नियंत्रित करने वाला एक संघीय कानून है) को गर्भपात कराने के लिए कम से कम एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं

1. गर्भावस्था को समाप्त करने की समय सीमा

गर्भधारण का समय	गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति

	एमटीपी अधिनियम, 1971	एमटीपी (संशोधन) विधेयक, 2020
12 सप्ताह तक	एक डॉक्टर की राय	एक डॉक्टर की राय
12 से 20 सप्ताह	दो डॉक्टरों की राय	एक डॉक्टर की राय
20 से 24 सप्ताह	अनुमति नहीं हैं	गर्भवती महिलाओं की कुछ श्रेणियों के लिए दो डॉक्टर जैसे बलात्कार / अनाचार पीड़ित, अलग-अलग महिलाओं और अवयस्क।
24 सप्ताह से अधिक	अनुमति नहीं हैं	भ्रूण की असामान्यताओं के मामले में मेडिकल बोर्ड
गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय	एक डॉक्टर, यदि गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो	
	डॉक्टर स्त्रीरोग या प्रसूति विज्ञान में अनुभव / प्रशिक्षण के साथ पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को संदर्भित करता है	

2. गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण समाप्ति:

- अधिनियम के तहत गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।
- विधेयक अविवाहित महिलाओं को इस कारण से गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।

3. चिकित्सा बोर्ड:

- सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगी।
- बोर्ड यह तय करेगा कि क्या भ्रूण की असामान्यताओं के कारण 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।
- प्रत्येक बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट / सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य होंगे।

4. गोपनीयता

- एक पंजीकृत चिकित्सक केवल एक महिला के विवरण को प्रकट कर सकता है, जिसकी गर्भावस्था को कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को समाप्त कर दिया गया है।
- उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है।

विधेयक के गुणदोष

- **महिलाओं की गरिमा की पुष्टि:** विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करता है कि "गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय" के उद्देश्य को पूरा करता है"
- **संस्थागत और संगठित गर्भपात सेवाएँ:** पुराने अधिनियमितियों में लाखो ने कई महिलाओं के जीवन को खतरे में डालते हुए अवैध रूप से गर्भपात क्लीनिक चलाने वाले कई शाप और अयोग्य व्यक्तियों को उजागर किया। यह उम्मीद की जाती है कि नए संशोधन इन मुद्दों से निपटने और संगठित क्षेत्र में और अधिक गर्भपात करने में मदद करेंगे, जिसमें योग्य चिकित्सा चिकित्सक निर्णय ले कर सुरक्षित गर्भपात कर सकते हैं।
- **महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार:** अविवाहित महिलाओं को अपनी पहचान की रक्षा के लिए कानूनी रूप से अवांछित गर्भावस्था का अधिकार देने का अधिकार महिलाओं को प्रजनन अधिकार प्रदान करेगा।
- **मातृ मृत्यु दर को कम करता है:** बिल महिलाओं की कानूनी और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच बढ़ाता है जो बदले में मातृ मृत्यु दर और असुरक्षित गर्भपात और संबंधित जटिलताओं के कारण रुग्णता को कम करेगा

चिंता / आलोचना

1. नैतिक दुविधा:

- एक राय है कि गर्भावस्था को समाप्त करना गर्भवती महिला की पसंद है, और उसके प्रजनन अधिकारों का एक हिस्सा है।
- अन्य राय यह है कि राज्य के पास जीवन की रक्षा करने का दायित्व है, इसलिए उसे भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए
- दुनिया भर में, देशों ने गर्भपात की अनुमति देने के लिए भ्रूण की व्यवहार्यता (गर्भ के बाहर भ्रूण जिस बिंदु पर जीवित रह सकता है), भ्रूण की असामान्यताएं, या गर्भवती महिला के लिए जोखिम जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग स्थिति और समय सीमा निर्धारित की है।

2. 24 सप्ताह से ऊपर

- विधेयक केवल उन मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है जब मेडिकल बोर्ड भ्रूण की असामान्यताओं का निदान करता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि बलात्कार के कारण गर्भधारण को समाप्त करने के लिए जो 24-सप्ताह की सीमा को पार कर चुके हैं, इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है: एक रिट याचिका के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने के लिए एकमात्र सहारा है

3. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है

- विधेयक भ्रूण की असामान्यताओं के मामले में मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। विधेयक एक समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर मेडिकल बोर्ड को अपना निर्णय करना होगा।
- गर्भधारण की समाप्ति एक संवेदनशील मामला है, और मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में देरी गर्भवती महिला के लिए और जटिलताएं हो सकती है।

4. अस्पष्ट अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर किया जाएगा

- चूंकि अधिनियम और विधेयक केवल महिलाओं के मामले में गर्भधारण की समाप्ति के लिए प्रदान करते हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विधेयक के तहत कवर किया जाएगा।

5. गर्भधारण को समाप्त करने के लिए योग्य चिकित्सा पेशेवरों की अनुपलब्धता

- अखिल भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2018-19) इंगित करता है कि पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में 1,351 स्त्रीरोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, और कमी 4,002 है, अर्थात योग्य डॉक्टरों की 75% कमी है।
- योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच सीमित कर देती है।
- ध्यान दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, केवल 53% गर्भपात एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किए जाते हैं और शेष नर्स, दाई, परिवार के सदस्य या स्वयं द्वारा संचालित किए जाते हैं।

6. विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रह

- "गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं" और "पर्याप्त भ्रूण असामान्यताएं" के विशेष वर्गीकरण भी विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों की पुनरावृत्ति करते हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महिलाओं के प्रजनन अधिकार बनाम एक अजन्मे बच्चे का अधिकार (यदि कोई हो)

महिलाओं के लिए स्थायी आयोग

कहानी अब तक:

- **सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया केस:** सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) और साथ ही युद्ध के अलावा सभी सेवाओं में कमांड पोस्टिंग दी जाए।
- **महिलाओं द्वारा लागू करने की अपील करना:** बाद में, निर्णय में निर्देशों के साथ सेना के अनुपालन पर सवाल उठाते हुए, लगभग 80 महिला लघु सेवा आयोग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अनैतिक चिकित्सा मानकों सहित मनमानी प्रक्रिया को चुनौती दी गई, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार कर दिया।
- **लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम भारत संघ मामला:** 25 मार्च 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेना की चयनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया ने स्थायी आयोग की मांग करने वाली महिला अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव किया है

स्थायी आयोग के मुद्दे की संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने क्या समीक्षा किया ?

- SC ने देखा कि मूल्यांकन के पैटर्न ने महिलाओं के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक हानि पहुंचाया।
- फैसले में कहा गया है कि सेना द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंड याचिकाकर्ताओं के खिलाफ "प्रणालीगत भेदभाव" का गठन है।
- SC ने महिला अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए सेना द्वारा अपनाए गए मानकों में कई विचलन पाए।
- अदालत ने देखा कि स्थायी कमीशन के अनुदान का निर्धारण करने के लिए महिला अधिकारियों की ACR [वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट] मूल्यांकन पर निर्भरता अनुचित थी।

स्थायी कमीशन देने की क्या प्रक्रिया है?

- 1992 में, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके महिलाओं को गैर-लड़ाकू शाखाओं में अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया।
- 2008 में, सरकार ने महिलाओं के लिए दो शाखाओं में स्थायी आयोग का विस्तार किया - जज एडवोकेट जनरल (JAG) और सेना शैक्षिक कोर (AEC)।
- समानता के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई में, 322 महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
- जुलाई 2020 में, रक्षा मंत्रालय ने सरकार की मंजूरी पत्र जारी किया, जिसमें सभी धाराओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का उल्लेख किया गया था, जिसमें वे वर्तमान में सेवारत हैं

सेना ने मंजूरी पत्र का जवाब कैसे दिया?

- मंजूरी पत्र के बाद, सेना ने महिला विशेष प्रवेश योजना (डब्लूएसईएस) और लघु सेवा आयोग महिला (एसएससीडब्ल्यू) के माध्यम से सेवा में शामिल होने वाले स्थायी आयोग के अनुदान के लिए महिला अधिकारियों की जांच के लिए एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया।
- चयन बोर्ड द्वारा स्थायी आयोग के लिए उपयुक्त माने जाने वाले 365 ऑप्टी अधिकारियों में से 277 महिला लघु सेवा आयोग के अधिकारियों (WSSCO) को चिकित्सा जांच के बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया।
- हालांकि, कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके बाद की प्रक्रिया मनमानी थी और इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी।

नये निर्देश क्या हैं?

- **पुरुष बैच के खिलाफ बेंचमार्किंग तर्कहीन है:** सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान किया कि संबंधित पुरुष बैच में सबसे कम योग्यता वाले अधिकारियों के खिलाफ बेंचमार्किंग महिला अधिकारियों की सेना प्रक्रिया "तर्कहीन और मनमाना" है, और कहा कि इस आवश्यकता को हटा दिया जाना चाहिए।
- **स्थायी आयोग के अनुदान के लिए मानदंड:** सभी महिला अधिकारी जिन्होंने सितंबर 2020 में आयोजित विशेष चयन बोर्ड में 60% की कट-ऑफ ग्रेड को पूरा किया है, स्थायी आयोग के अनुदान के हकदार होंगे, निर्णय ने कहा, उनकी बैठक के अधीन निर्धारित चिकित्सा मानदंड और अनुशासनात्मक और सतर्कता मंजूरी प्राप्त होगी
- **समानता को बरकरार रखा:** एससी ने कहा कि संबंधित बैचों में पुरुष समकक्षों के साथ सही समानता की भावना में, WSSCO को उनकी चिकित्सा फिटनेस पर निर्भरता द्वारा पीसी के अनुदान के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट माना जाना चाहिए, जैसा कि उनकी सेवा के 5 वें या 10 वें वर्ष में दर्ज किया गया है।
- **याचिकाकर्ताओं के मामले पर पुनर्विचार किया जाना:** "गैर-ऑप्टिंग" के अलावा, सभी WSSCO के मामले, जिनमें याचिकाकर्ता शामिल हैं, जिन्हें चिकित्सा आधार पर खारिज कर दिया गया है, एक महीने के भीतर पुनर्विचार किया जाएगा और दो महीने के भीतर स्थायी आयोग के अनुदान के आदेश जारी किए जाएंगे।
- साथ ही, बबीता पुनिया मामले के लिए, अदालत ने कहा कि 10 से 14 साल के सेवा वर्ग के अधिकारियों के लिए जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया है, इसने उन्हें 20 साल की पेंशन सेवा प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी है।

स्वास्थय समस्या

कोविद -19 की दूसरी लहर

संदर्भ: विशेषज्ञ इस सवाल पर बने रहते हैं कि क्या देश में फरवरी 2021 के आखिरी सप्ताह में COVID-19 मामलों की संख्या में धीमी गति से लगातार वृद्धि 'दूसरी लहर' की शुरुआत का संकेत है।

लेकिन केंद्र और कुछ राज्य सरकारें बढ़ती संख्या के खिलाफ सजग हैं और आक्रामक परीक्षण और उचित सामाजिक और स्वच्छता प्रोटोकॉल को मजबूत कर रही हैं

दुनिया भर में क्या हो रहा है?

- **यूरोप में दूसरी लहर:** यूरोप में, मई 2020 में पहली लहर के बाद, दूसरी लहर नवंबर 2020 में आई। विशेषज्ञों ने कहा कि यूरोप का हर देश पहली लहर के साथ हल्के से दूर होने में कामयाब रहा, दूसरे ने लगभग अपंग कर दिया।
- **दूसरी लहर में भी इसी तरह का संकट:** यहां तक कि वे देश इटली सहित जो शुरू में बुरी तरह से पीड़ित हुए थे, फिर से कड़ी मेहनत कर रहे थे। अस्पतालों ने भरना शुरू कर दिया, बिस्तर फिर से खराब हो गए और मृत्यु दर बढ़ने लगी।
- **सरकार की प्रतिक्रिया w.r.t दूसरी लहर:** कर्फ्यू और लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, कर्फ्यू और सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं पर प्रतिबंध के साथ; स्कूल फिर से बंद हो गए, क्योंकि सरकारें इस नई लहर से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है।
- **उत्परिवर्तित उपभेद:** 2020 के अंत में, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वायरस के नए, उत्परिवर्तित उपभेदों के उद्भव का मतलब कुछ देशों में तेजी से फैलता हुआ संस्करण था। हालांकि, वैज्ञानिकों ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि नए ब्रिटिश प्रयास ने अधिक गंभीर बीमारी पैदा की।

क्या भारत में मामले बढ़ रहे हैं?

- पिछले साल सितंबर में हुए संक्रमण के बाद, पूरे देश में मामलें लगातार गिरावट आ रही थी, केरल के अपवाद के साथ, एक बाहरी राज्य जो वक्र को समतल करने में प्रारंभिक सफलता देखने के बाद उच्च संख्या को देखता रहा।
- हालांकि, इस साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में, प्रवृत्ति उलट गई, कुछ राज्यों ने उच्च संख्या की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया।
- औसत वृद्धि प्रति दिन लगभग 14,000 नए संक्रमण थे और दो राज्यों, महाराष्ट्र और पंजाब ने मामलों की संख्या में वृद्धि हुयी, यहां तक कि पिछले कुछ महीनों में उनके परीक्षण संख्या में गिरावट आई थी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हाल के 24 घंटे की अवधि में दर्ज किए गए 16,400 से अधिक मामलों में से लगभग 86% छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से थे।

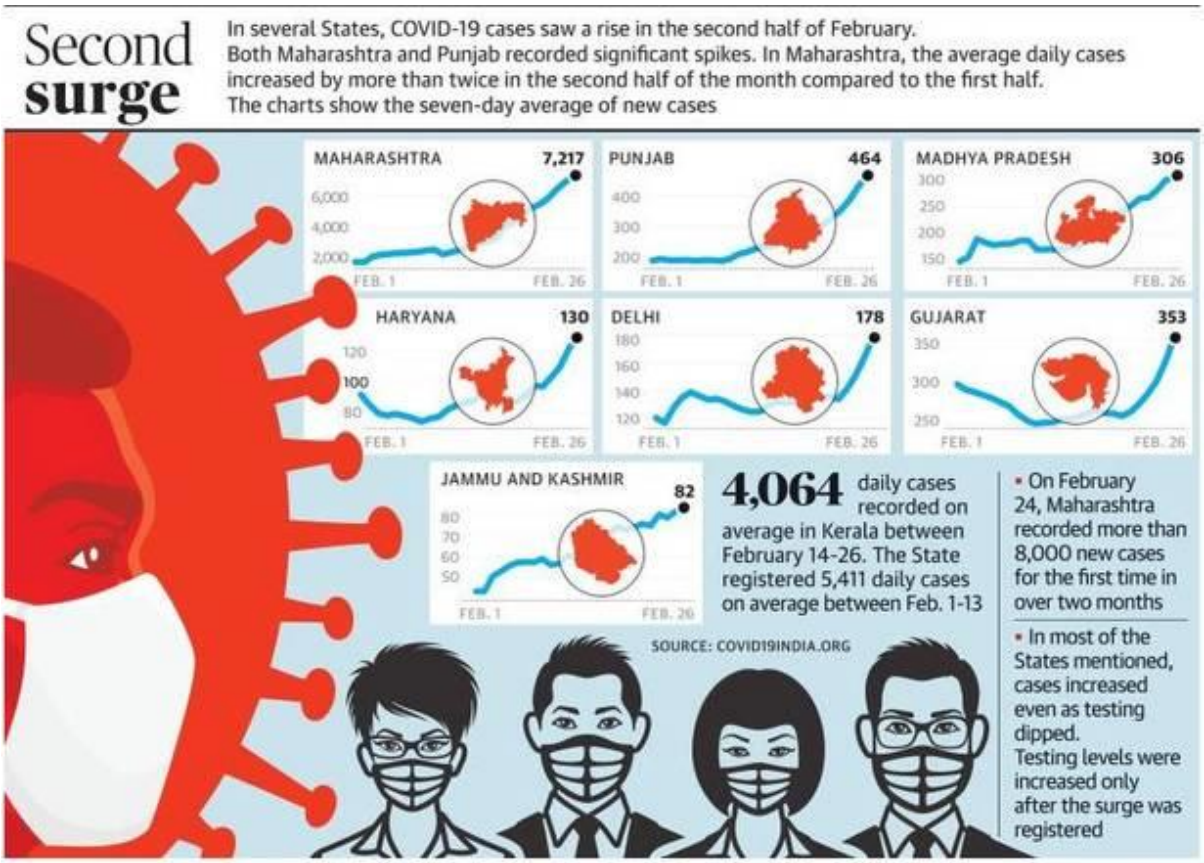

स्रोत: द हिंदू

स्पाइक के क्या कारण है?

- **क्लस्टर-स्प्रेडर घटनाएं:** महाराष्ट्र में स्पाइक्स सुपर-स्प्रेडर घटनाओं या समूहों की एक श्रृंखला के कारण हुए। विशेषज्ञ मानते हैं कि मामलों की संख्या में वृद्धि वायरस के एक प्रकार के कारण होती है जो तेजी से संचारित होने की प्रवृत्ति के साथ नहीं होती है, लेकिन चुनिंदा सुपर-स्प्रेडर घटनाओं के कारण।
- **सख्त विनियमों का अभाव:** पिछले वृद्धि के दौरान, राज्यों द्वारा लगाए गए सख्त नियमों के साथ-साथ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जो जुर्माना अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। लेकिन, मामलों की घटती संख्या के साथ, सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज कर दिया गया, संभवतः उन समूहों के लिए अग्रणी जिन्होंने संख्याओं को फिर से आगे बढ़ाया है।
- **एक ब्लिप हो सकता है:** ऐसे अन्य लोग हैं जो मानते हैं कि 'सेकंड वेव' वास्तव में एक लहर नहीं है, बल्कि एक ब्लिप से अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत की 60% आबादी पहले ही वायरस के संपर्क में आ गई थी और देश ने भीड़ की प्रतिरक्षा के लिए संपर्क किया होगा।

आगे की राह

- वायरस से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के केवल दो तरीके हैं, एक संक्रमित होना है और दूसरा एक टीका के माध्यम से है
- देश भर में वैक्सीन कार्यक्रम को तेजी से ट्रैक करना महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
- परीक्षणों की संख्या फिर से बढ़नी चाहिए और ट्रेसिंग से संपर्क करना चाहिए, आदर्श रूप से हर मामले के लिए 20 व्यक्तियों को,आशय से लिया जाना चाहिए।

- विशेषज्ञ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए नए सिरे से जोर देने के लिए कहते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना और भौतिक दूरी बनाए रखना संभव दूसरी लहर 'या संख्या में निरंतर वृद्धि। कुल सख्त लॉकडाउन अब आवश्यक नहीं हैं

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- COVID-19 और भीड़ प्रतिरक्षा

इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IMPCL)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य; शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IMPCL) ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए सरकारी ई-मार्केट (GeM) पोर्टल के साथ गठबंधन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- GeM ने 31 श्रेणियां बनाई हैं जिसके तहत IMPCL पोर्टल पर दवाइयां अपलोड कर सकता है।
- अब, सैकड़ों सरकारी क्षेत्र के खरीदारों के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं पोर्टल पर आ जाएंगी।
- लागत को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा है।

क्या आप जानते हैं?

- IMPCL आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण इकाई है।
- यह आयुष मंत्रालय के तहत एकमात्र CPSE है।

संबंधित आलेख:

- आयुष निर्यात संवर्धन परिषद
- आयुष कल्याण केंद्र नाम के तहत आने के लिए

विश्व स्वास्थ्य सभा का मेनिनजाइटिस (तानिकाशोथ) पर पहला संकल्प

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य समाचार

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने मेनिन्जाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण पर पहला संकल्प का समर्थन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

मस्तिष्कावरण शोथ

- यह मेनिन्जेस का एक गंभीर संक्रमण है - मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली होती है
- यह एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है जो हर साल 5 मिलियन मुद्दों का कारण है।
- यह बैक्टीरिया, कवक या वायरस सहित कई अलग-अलग रोगजनकों के कारण हो सकता है।
- सबसे ज्यादा वैश्विक बोझ बैक्टीरिया मेनिन्जाइटिस के साथ रहता है।
- **बैक्टीरिया के उदाहरण:** स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निसेरिया मेनिटिडिडिस
- **ट्रांसमिशन:** वाहक से श्वसन या गले के स्राव की बूंदों के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति के द्वारा

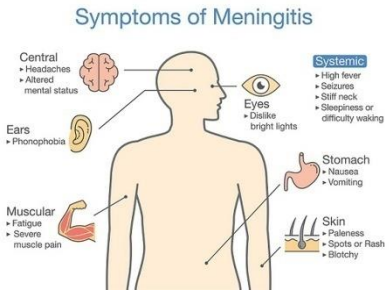

स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड (Stop TB Partnership Board) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- वह जुलाई 2021 से आगामी तीन वर्ष के कार्यकाल तक 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड' के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड

- स्थापना वर्ष 2000
- **उद्देश्य:** सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को समाप्त करने हेतु आज्ञापित करना।
- मार्च 1998 में लंदन में आयोजित तपेदिक महामारी पर तदर्थ समिति के पहले सत्र की बैठक के बाद संगठन की कल्पना की गई थी।
- मार्च 1998 में लंदन में आयोजित 'तपेदिक महामारी पर तदर्थ समिति' (Ad Hoc Committee on the Tuberculosis Epidemic) के प्रथम सत्र की बैठक के बाद इस संगठन की परिकल्पना की गई थी।
- इसमें 1500 भागीदार संगठन हैं
- **सचिवालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2019 की तुलना में जनवरी और फरवरी 2020 के बीच 6% अधिक मामले आए।
- लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, अप्रैल और मई में निजी सार्वजनिक क्षेत्र में सूचनाएं 38% और 44% तक गिर गईं।
- 2019 के रिपोर्ट द्वारा 24.04 लाख टीबी मामलों में से, उपचार सफलता 82% तथा मृत्यु दर 4% थी।
- कार्यक्रम के अनुमोदित बजट 2019-20 में 3,333 करोड़ से घटाकर 2020-21 में 3,110 करोड़ कर दिया गया।
- रिपोर्ट में कहा गया कि 20,892 (42%) रोगियों को निदान के समय कम एमडीआर-टीबी परहेज शुरू किया गया।
- यह 2019 से महत्वपूर्ण गिरावट है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वैश्विक समय सीमा 2030 है।

औषधि मूल्य नियंत्रण

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 81 दवाओं की कीमत तय की, जिसमें ऑफ-पेटेंट एंटी-डायबिटिक दवाएं शामिल हैं, जो रोगियों को लाभ पहुँचाती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि स्वदेशी R&D के कारण इन दवाओं को दी गई 5 साल की कीमत में छूट मिली।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर अनुसूचित योगों की मौजूदा थोक बिक्री की कीमतों में संशोधन को भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।
- संशोधित कीमतें अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी।
- ये सितंबर 2021 तक हेपरिन इंजेक्शन की संशोधित थोक बिक्री की कीमत को बनाए रखने का भी फैसला किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में दवा दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।
- यह 1997 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के संलग्न कार्यालय के रूप में गठित किया गया था
- **मंत्रालय:** रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

सरकार का कोविशिल्ड की खुराक के बीच अंतराल को बढ़ाने का फैसला

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- सरकार ने कोविद -19 के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में कोविशिल्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतराल को 8 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की AZD1222 संस्करण है, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है.
- AZD122 के ग्लोबल ट्रायल के कुछ आंकड़ों से पता चला है कि खुराक के बीच की अवधि को 12 सप्ताह तक बढ़ाने से इसकी प्रभावकारिता बहुत अधिक बढ़ गई.
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दो विशेषज्ञ समूहों की सिफारिश पर निर्णय लिया - राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह) और कोविद -19 (NEGVAC) के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह।
- टीके के क्लिनिकल परीक्षणों से उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों को देखने के बाद, समूहों ने निष्कर्ष निकाला कि यह सुरक्षा जो कोविद -19 के खिलाफ प्रदान करता है, वह "संवर्धित" है यदि दूसरी खुराक 6-8 सप्ताह के बीच दिलाई जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की पहल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य; नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रगति से अवगत कराया।

महत्वपूर्ण तथ्य

एनएचएम ने 2019-20 में नई पहल की परिकल्पना की :

- **निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (SAANS):** बचपन में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाना।
- **सुरक्षीत मातृत्व आश्वासन (सुमन):** किसी भी कीमत पर सुनिश्चित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, सेवाओं से वंचित करने के लिए शून्य सहिष्णुता और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए सभी मौजूदा योजनाओं को एक छत्र के तहत लाया गया।
- **मिडवाइफ़री सेवाएँ:** मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनर्स का एक कैडर बनाने के लिए जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइव्स (ICM) द्वारा निर्धारित दक्षताओं के अनुसार कुशल हो और करुणावान महिला-केंद्रित, प्रजनन, मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने के लिए जानकार और सक्षम हो।

स्कूली बच्चों के बीच एक सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में AB-HWCs कार्यक्रम के तहत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों को शुरू किया गया।

नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य; शिक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- लोकसभा ने नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बिल, 2021 को मंजूरी दी।
- इसे पिछले सप्ताह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विधेयक संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित और मानकीकृत करेगा।
- **संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर की परिभाषा:** किसी भी बीमारी, चोट या हानि के निदान और उपचार का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित एक सहयोगी, तकनीशियन, या प्रौद्योगिकीविद।
- इस तरह के एक पेशेवर को इस विधेयक के तहत डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
- **मान्यता प्राप्त श्रेणियों के रूप में संबद्ध और स्वास्थ्य व्यवसाय:** एक वैज्ञानिक, चिकित्सक या कोई अन्य पेशेवर जो अध्ययन, सलाह, अनुसंधान, पर्यवेक्षण करता है, या निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, उपचारात्मक, या प्रचारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
- इस तरह के एक पेशेवर को इस विधेयक के तहत डिग्री प्राप्त करनी चाहिए थी।
- **संबद्ध श्रेणियों के रूप में स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय:** जीवन विज्ञान पेशेवरों, आघात , सर्जिकल और संज्ञाहरण संबंधित प्रौद्योगिकी पेशेवरों, फिजियोथेरेपिस्ट, और पोषण विज्ञान पेशेवरों आदि
- विधेयक राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा आयोग का गठन करता है। यह
  1. शिक्षा और व्यवहार को विनियमित करने के लिए नीतियां और मानक
  2. सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर बनाएं रखना, और
  3. दूसरों के बीच एक समान प्रवेश और निकास परीक्षा के लिए प्रदान करना।

- आयोग संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की हर मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए एक पेशेवर परिषद का गठन करेगा।
- विधेयक के पारित होने के छह महीने के भीतर राज्य सरकारें , राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य परिषद का गठन करेंगी।

UNITAR ने (NDCs) से समयपूर्व मृत्यु दर को कम करने में भारत की प्रगति की सराहना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- UNITAR ने गैर-संचारी रोगों से समय से पहले मृत्यु दर को कम करने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की।

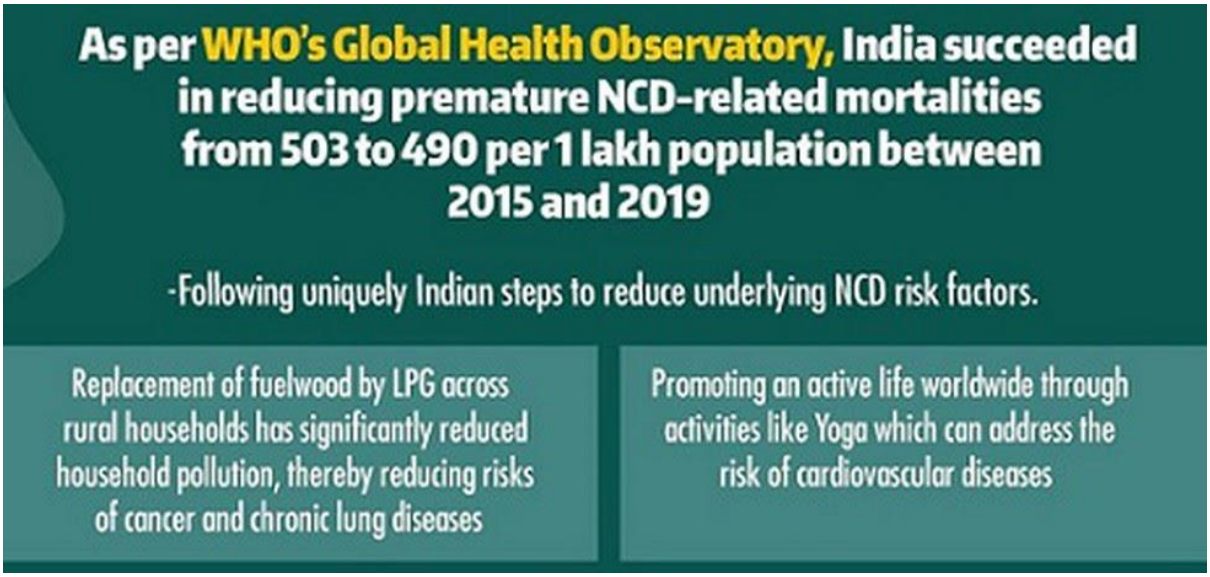

अन्य संबंधित तथ्य

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR)

- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है।
- **जनादेश:** UNITAR मुख्य रूप से विकासशील देशों (LDC), स्माल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SIDS) और अन्य समूहों के लिए विशेष ध्यान देने वाले विकासशील देशों की सहायता के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियाँ प्रदान करता है, जो सबसे अधिक असुरक्षित हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की महासभा की सिफारिश के बाद:** 1963 में स्थापित।
- **शासन:** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त निकाय के रूप में संचालित
- **इसके प्रमुख:** कार्यकारी निदेशक
- **अनुदान:** UNITAR एक परियोजना-आधारित संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से कोई धन प्राप्त नहीं होता है।
- यह पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्तपोषित है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा (स्विट्जरलैंड)

आदिवासी टीबी पहल की शुरूआत

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत की खोज में 'आदिवासी टीबी पहल' की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- टीबी पर जनजातीय मंत्रालय के प्रकाशन 'ALEKH 'का एक विशेष संस्करण, क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन के लिए संयुक्त कार्य योजना पर एक मार्गदर्शन नोट, और इस कार्यक्रम में आदिवासी तपेदिक (टीबी) पहल पर एक दस्तावेज़ भी जारी किया गया था।
- 104 मिलियन से अधिक जनजातियों की आबादी भारत में रहती है, जो 705 जनजातियों में भारत की आबादी का 8.6% हिस्सा है।
- 177 आदिवासी जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में पहचाना गया, जहाँ पर शारीरिक कष्ट, कुपोषण, रहने की स्थिति और जागरूकता की कमी के कारण आदिवासी आबादी टीबी की चपेट में आ गए।
- प्रारंभ में, संयुक्त योजना की गतिविधियां 18 चिन्हित राज्यों में 161 जिलों पर केंद्रित होंगी।
- इसमें समय-समय पर टीबी के सक्रिय मामले को खोजना और कमजोर आबादी की पहचान करने के लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी (आईपीटी) का प्रावधान और भेद्यता में कमी के लिए दीर्घकालिक तंत्र विकसित करना शामिल है।

क्या आप जानते हैं?

- लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले को विश्व टीबी दिवस 2021 पर टीबी मुक्त घोषित किया गया।
- पिछले 5 वर्षों में सरकार ने भारत में टीबी के लिए बजट आवंटन पहले ही चार गुना बढ़ा दिया।

संबंधित आलेख:

- भारत टीबी की रिपोर्ट
- स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत शहर केन्द्रित कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से चिह्नित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठित संस्थानों (IoRs) द्वारा 26 मार्च, 2021 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्य संबंधित तथ्य

- देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार पाने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2024 तक (आधार वर्ष 2017 के साथ) पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20% से 30% तक कटौती के लक्ष्य रखता है।
- अग्रणी वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों को मिलाकर एक तकनीक परामर्श समूह के रूप में एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का गठन भी किया गया है, जो एनसीएपी के अंतर्गत गतिविधियों को समर्थन देगा।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश अवसर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 'भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर' के बारे में कहा गया है

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह रिपोर्ट अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों , स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन, गृह स्वास्थ्य और चिकित्सा मूल्य यात्रा सहित भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की रूपरेखा शामिल है।
- 2016 से लगभग भारत का स्वास्थ्य उद्योग 22% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- इस दर पर, यह 2022 में 372 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- निजी कंपनियों के लिये अस्पतालों के मामले में छोटे एवं मझोले शहरों (टियर दो और टियर तीन) में विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। उनके लिये महानगरों से छोटे शहर में निवेश के आकर्षक अवसर हैं।

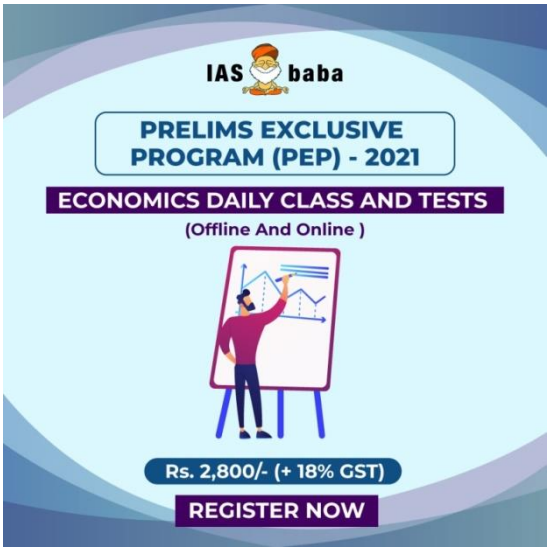

सरकारी योजनाएँ

15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में E-Daakhil पोर्टल शुरू हुआ

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; शासन

सुर्खिओ में क्यों-

- उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ।
- **मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- ई-फाइलिंग को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा सितंबर, 2020 में शुरू किया गया था।
- दिल्ली इसे लागू करने वाला पहला राज्य था।
- 2019 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता शिकायतों की। ज्ञात है कि ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने का प्रावधान है।
- शिकायत दर्ज करने के लिए डिजिटल सॉफ्टवेयर में ई-नोटिस, विपरीत पार्टी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने, एसएमएस / ईमेल के माध्यम से अलर्ट आदि जैसी विशेषताएं हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन: नीति आयोग

संदर्भ: हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act, 2013) में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा पत्र (Discussion Paper) प्रस्तुत किया।

NFSA क्या है?

- **अधिकार आधारित ढांचा:** एनएफएसए "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) पर आधारित है
- **लाभार्थी:** अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत, "पात्र परिवारों" शब्द में दो श्रेणियां शामिल हैं - "प्राथमिकता वाले घर" और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) द्वारा कवर किए गए परिवार।
- **लाभ:** प्राथमिकता वाले घरों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को समान कीमतों पर प्रति माह 35 किलोग्राम का प्रावधान है।
- **कवरेज:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने पात्र परिवारों (Eligible Households) को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया है इसके अंतर्गत अंतर्गत कुल ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत लाभान्वित हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में 81.35 करोड़ व्यक्ति एनएफएसए के तहत लाभ प्राप्त करते हैं।
- प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिशत कवरेज, धारा 3 के उप-खंड (2) के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- राज्य के ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना जनसंख्या के अनुमान के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।
- **राज्यों से मांग:** इस प्रकार, NFSA लाभार्थियों की संख्या 2013 में अवरुद्ध थी। हालांकि, तब से जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, NFSA के तहत एक वार्षिक अद्यतन प्रणाली सुनिश्चित करके सूची को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी गई।

नीति आयोग ने क्यों प्रस्तावित किया है?

- **कवरेज अनुपात में संशोधन:** नीति आयोग ने अपने चर्चा पत्र में सिफ़ारिश की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी कवरेज जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत है, को घटाकर क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक कर दिया जाये।
- **CIP का संशोधन:** इसी के साथ ही नीति आयोग ने अपने चर्चा पत्र में केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) में संशोधन का जिक्र किया गया है। आपको बता दे केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) वह मूल्य है जिस पर सरकार खाद्यान्नों को राज्यों को उपलब्ध कराती है। एनएफएसए के तहत चावल/ गेहूं/मोटे अनाज के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) क्रमश: 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम है।

केंद्र और राज्यों के लिए संशोधन का क्या निहितार्थ है?

- कानून में ये बदलाव करने के लिए, सरकार को NFSA की धारा 3 की उपधारा (2) में संशोधन करना होगा। इसके लिए उसे संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी
- **खाद्य सब्सिडी बिल में बचत:** यदि खाद्य सुरक्षा के कवरेज को वर्तमान अनुपात से प्रस्तावित अनुपात की ओर संशोधित किया जाता है, तो केंद्र सरकार को इससे 47,229 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। हालाँकि, इस कदम का कुछ राज्यों द्वारा विरोध किया जा सकता है।
- **संशोधित नहीं होने पर राजकोषीय बोझ में वृद्धि:** दूसरी ओर, यदि ग्रामीण-शहरी कवरेज अनुपात 75-50 रहता है, तो कवर किए गए लोगों की कुल संख्या मौजूदा 81.35 करोड़ से बढ़कर 89.52 करोड़ हो जाएगी यानि नवीनतम जनसंख्या(अनुमानित 2020 की आबादी पर आधारित) संबंधी आँकड़ों के आधार 8.17 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप 14,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- राज्यों को नीति आयोग द्वारा लोगों की खाद्य सुरक्षा और उनके वित्तीय बोझ को झेलने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- COVID और खाद्य सुरक्षा

OCI कार्डधारकों के लिए शैक्षिक संस्थानों में NRI कोटा सीट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - शिक्षा; नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, OCI (ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ़ इंडिया) कार्डधारक NEET, JEE (मेन्स और एडवांस्ड), आदि जैसे परीक्षणों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में "केवल NRI कोटा सीटों" पर मांग कर सकते हैं।
- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय (MHA)

महत्वपूर्ण तथ्य

- OCI भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी "मिशनरी, पर्वतारोहण, पत्रकारिता और वर्जित गतिविधियों" के लिए हकदार नहीं हैं।
- हालांकि यह अधिसूचना तीन पिछली अधिसूचनाओं को बदल देती है जो इन गतिविधियों के लिए आवश्यक विशेष अनुमति को निर्दिष्ट नहीं करती है।

क्या आप जानते हैं?

- OCI नागरिक भारतीय मूल के हैं।

- वे विदेशी पासपोर्ट धारक हैं और भारत के नागरिक नहीं हैं।
- भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है लेकिन नागरिकता अधिनियम, 1955 से OCI को कुछ लाभ प्रदान करता है।

संबंधित आलेख:

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्र डिजिलॉकर से लिंक होंगे

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - शिक्षा; नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षक पुपिल पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली (OTPRMS) प्रमाणपत्रों को DigiLocker के साथ जोड़ने का निर्णय लिया।
- **उद्देश्य:** सत्यापित ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्र के लिए परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना

महत्वपूर्ण तथ्य

- जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजीलॉकर को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की वेबसाइट पर इसका पता लगाया जा सकता है।
- प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया।
- इससे पूरे भारत में सभी हितधारकों को कारोबार करने में आसानी के साथ डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

डिजिटल लॉकर

- डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य:** नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों का 'डिजिटल सशक्तिकरण'
- डिजीलॉकर प्रणाली में जारी दस्तावेजों को सूचना नियम 2016 के नियम 9A के अनुसार मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।

---

3 अमब्रेला योजनाओं के तहत डब्ल्यूसीडी मंत्रालय की योजनाएं

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाएँ

सुर्खिओ में क्यों-

- महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को 3 छतरी योजनाओं के तहत वर्गीकृत किया गया।
- ये मिशन पोशन 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सक्षण आंगनवाड़ी और पोषन 2.0 में छाता आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवा, पोशन अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना शामिल होगी।
- मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ शामिल होंगी।
- मिशन शक्ति (महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकारिता के लिए मिशन) में निम्नलिखित शामिल होंगे

- SAMBAL (वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वालंटियर, महिला हेल्पलाइन / स्वाधार / उज्जवला / विधवा गृह आदि)
- SAMARTHYA (बेटी बचाओ बेटी पढाओ, क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लिंग बजट / अनुसंधान)

सरकारी स्कूलों में नल के पानी की आपूर्ति पर जानकारी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - शिक्षा; स्वास्थ्य; कल्याणकारी योजनाएँ और जीएस- III - अवसंरचना

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में, जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति को नल जल आपूर्ति की जानकारी प्रदान की गई।

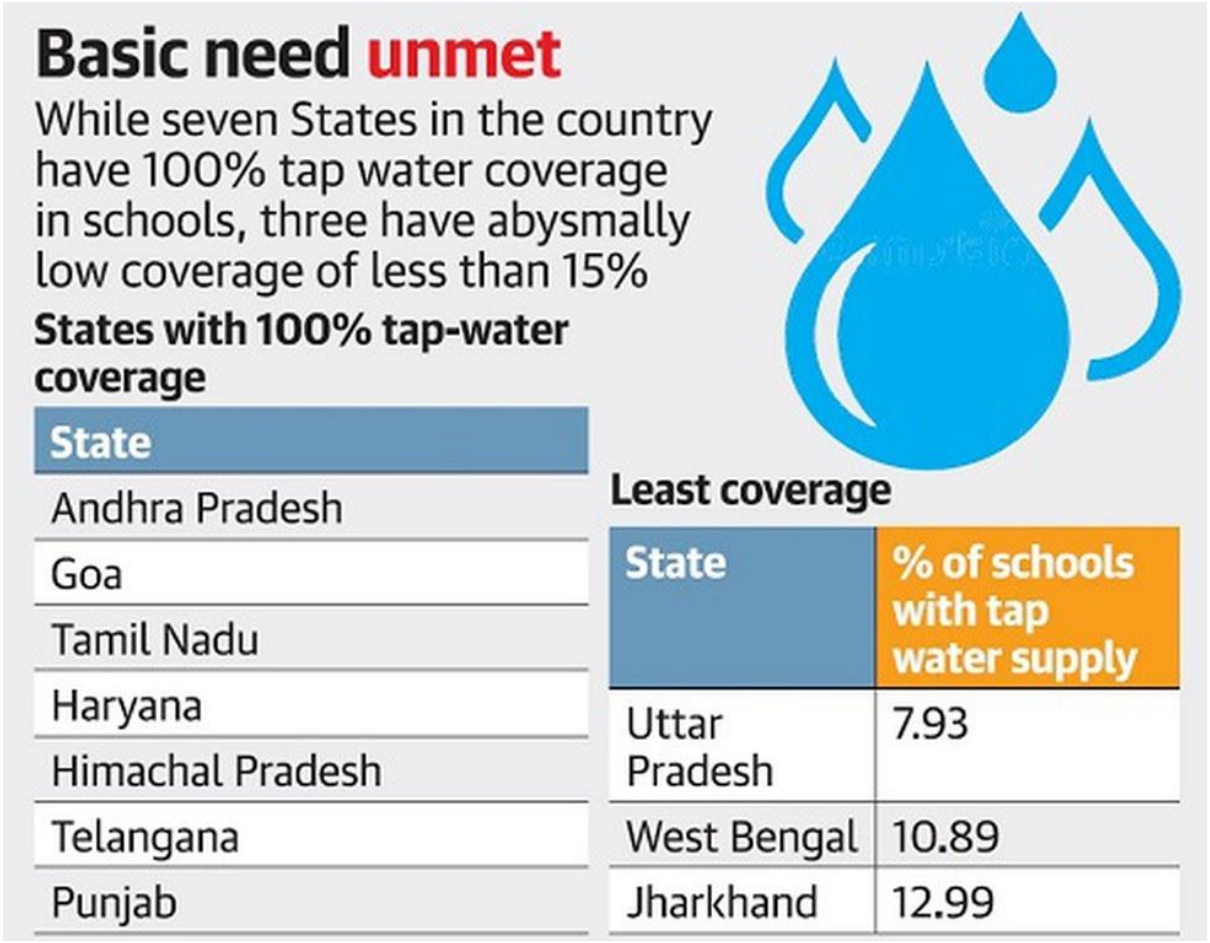

महत्वपूर्ण तथ्य

- केवल आधे सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में नल का पानी है।
- उत्तर प्रदेश में 8% से कम और पश्चिम बंगाल में 11% स्कूल हैं।
- नल जल आपूर्ति से संबंधित एक अभियान अक्टूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** पीने और खाना पकाने के उद्देश्यों और पीने के लिए नल का पानी पीने के लिए और हर स्कूल, आंगनवाड़ी और आश्रमशाला या आवासीय आदिवासी स्कूल में शौचालय के लिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करना
- **अवधि:** 100 दिन की अवधि (10 जनवरी, 2021 तक)

- हालांकि, 15 फरवरी तक, केवल 48.5% आंगनवाड़ियों और 53.3% स्कूलों में नल का जल आपूर्ति था
- **सात राज्यों ने 100% कवरेज हासिल की:** आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - सरकार की योजनाएं और पहल; स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) को वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136-बी के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के लिए एक एकल गैर-उत्तरदायी आरक्षित निधि की मंजूरी दी।
- 2018 के बजट में, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए, मौजूदा 3% शिक्षा उपकर को 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा बदलने की घोषणा की।
- **PMSSN के प्रमुख लाभ :** यह सार्वभौमिक और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाएगा

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना सुविधाएँ

1. सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य के लिए एक गैर-व्यपगत आरक्षित निधि।
2. स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में स्वास्थ्य की हिस्सेदारी का श्रेय PMSSN में दिया जाएगा।
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (AB-HWCs) , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के लिए PMSSN में उपयोग किया जाएगा।
4. आपातकालीन और आपदा तैयारी और स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान प्रतिक्रियाएं
5. कोई भी भविष्य का कार्यक्रम / योजना जो एसडीजी की दिशा में प्रगति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है। PMSSN का प्रशासन और रखरखाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा जाता है।
6. किसी भी वित्तीय वर्ष में, MoHFW की ऐसी योजनाओं पर शुरू में PMSSN से और उसके बाद सकल बजटीय सहायता (GBS) से व्यय किया जाएगा।

ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम बिहार के आरा में शुरू किया गया।
- **मंत्रालय:** विद्युत मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कार्यक्रम के तहत, 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12-वाट एलईडी बल्ब ग्रामीण उपभोक्ताओं को काम करने वाले तापदीप्त बल्बों को प्रदान करने के खिलाफ दिया जाएगा।
- एलईडी प्रत्येक घर के लिए केवल 10 रुपये में उपलब्ध होगी।
- प्रत्येक घर में 5 एलईडी तक लगेंगे।

- पहले चरण में, 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण आरा (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र) और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में किया जाएगा।
- ग्राम उजाला कार्यक्रम केवल 5 जिलों के गांवों में लागू किया जाएगा।
- इन ग्रामीण घरों में उपयोग के लिए अपने घरों में मीटर भी लगाए जाएंगे।

क्या आप जानते हैं?

- कार्यक्रम पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा।
- कार्बन क्रेडिट गतिविधियों की शाइन प्रोग्राम के तहत खरीदारों की जरूरतों के आधार पर, स्वैच्छिक कार्बन मानक के तहत सत्यापित करने के विकल्प के साथ तैयार किया जाएगा।
- कार्बन क्रेडिट खरीदारों को बाजार के साथ प्रारंभिक चर्चा के आधार पर एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से भी मांगा जाएगा।
- एलईडी लागत पर शेष लागत और मार्जिन अर्जित कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पुन: प्राप्त किया जाएगा।

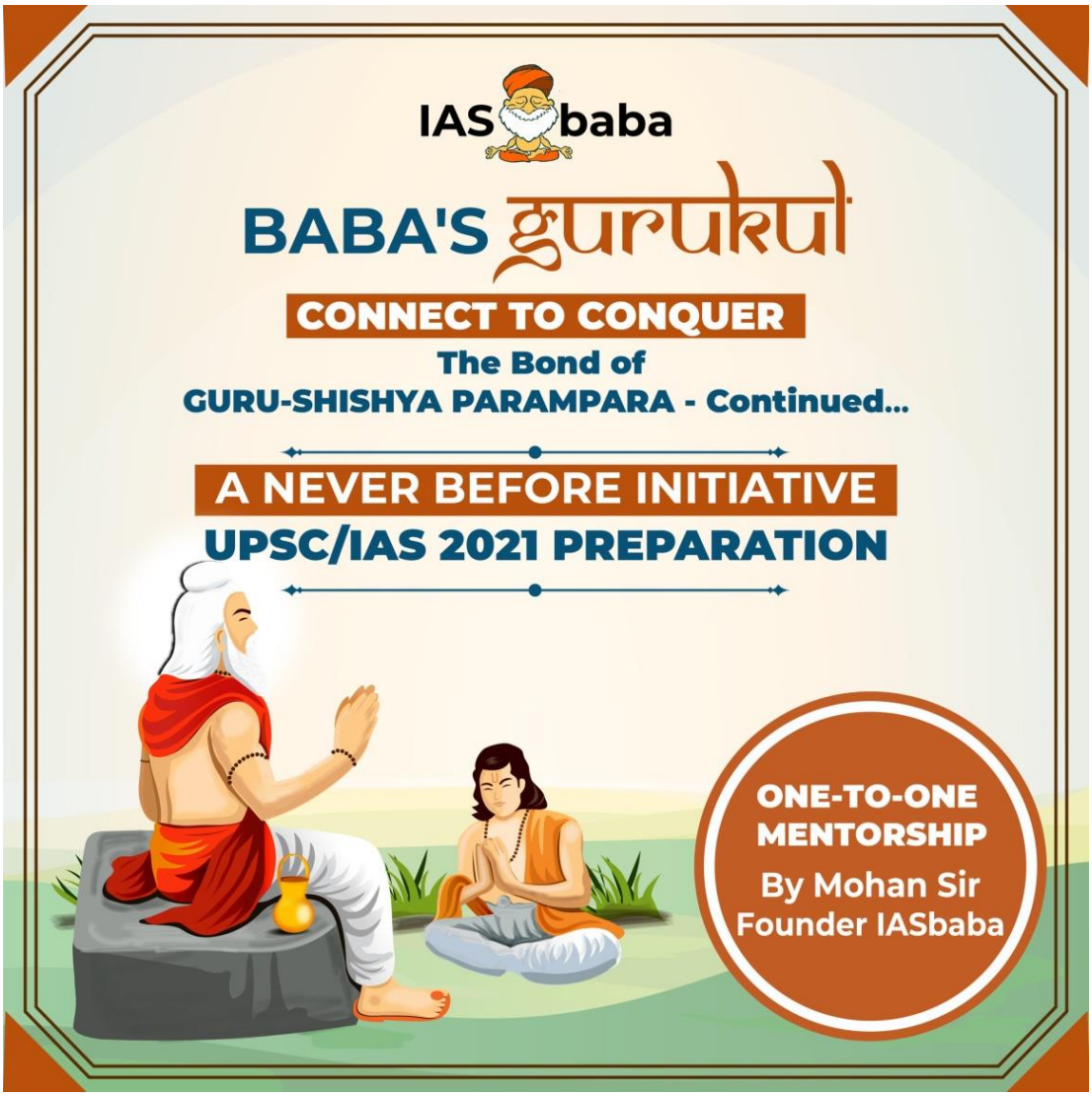

अंतरराष्ट्रीय

एफएटीएफ ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान का प्रभाव

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपने आतंकवाद के वित्तपोषण पर "ग्रे सूची" रखने का फैसला किया है

महत्वपूर्ण तथ्य

- पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ ग्रे सूची से हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
- एक बार जब पाकिस्तान तीन अधूरे कार्यों को पूरा करता है, तो जून में इसकी वर्तमान स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा
- FATF के 27 में से छह मुद्दों को पूरा करने में पाकिस्तान विफल रहा।

अन्य संबंधित तथ्य

- एफएटीएफ 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए धन शोधन, आतंक वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना
- वर्तमान में, इसमें 39 सदस्य हैं।
- पाकिस्तान जून 2018 से 'ग्रे सूची' में है।

संबंधित आलेख:

- एफएटीएफ की रिपोर्ट में वन्यजीवों के व्यापार के निशान हैं।
- एफएटीएफ पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखने का फैसला किया।

विकास नीति के लिए संयुक्त राष्ट्र की समिति (CDP)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- संयुक्त राष्ट्र की विकास नीति समिति (सीडीपी) ने बांग्लादेश को कम से कम विकसित देश (एलडीसी) की श्रेणी से हटाने की सिफारिश की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति तथा आर्थिक और पर्यावरण भेद्यता के संदर्भ में पात्रता मानदंडों को पूरा किया।
- यह 2018 के बाद से लगातार दूसरी बार है कि सीडीपी ने बांग्लादेश के लिए सिफारिश की।
- सीडीपी तीन मानदंडों के आधार पर एक देश के एलडीसी स्थिति पर निर्णय लेता है- (1) प्रति व्यक्ति आय; (2) मानव संपत्ति सूचकांक और आर्थिक भेद्यता सूचकांक।
- एक देश को स्नातक होने पर विचार की जाने वाली लगातार तीन त्रैमासिक समीक्षाओं में से तीन मानदंडों में से कम से कम दो को प्राप्त करना होगा।
- सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित होने के लिए जून में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) को प्रस्ताव भेजा गया।

- प्रभाव: (1) निर्यात में अधिमान्य प्रावधान, कृषि और शिशु उद्योगों को सब्सिडी का प्रावधान और एलडीसी से संक्रमण के बाद जलवायु वित्त तक पहुंच बंद होने की संभावना है; (2) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकायों का बढ़ा हुआ विश्वास, बेहतर क्रेडिट रेटिंग और उच्च एफडीआई से संक्रमण अवधि पूरी होने के बाद बांग्लादेश को लाभ होने की उम्मीद है।

अन्य संबंधित तथ्य

विकास नीति के लिए समिति

- यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की एक सहायक संस्था है।
- **समारोह:** विकास नीति के मुद्दों पर परिषद को स्वतंत्र सलाह प्रदान करने के लिए।
- समिति यह निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार है कि किन देशों को कम से कम विकसित देश (एलडीसी) माना जाय।
- इस समिति में 24 सदस्य हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नामित और तीन वर्षों की अवधि के लिए ECOSOC द्वारा नियुक्त किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- विकासशील देश की स्थिति में परिवर्तन के लिए बांग्लादेश को 2026 तक का समय मिला।
- अधिकतर देशों को संक्रमण के लिए तीन साल दिए जाते हैं लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण बांग्लादेश को इस प्रक्रिया के लिए पांच साल दिए गए हैं।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; शिक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग घोषित की गई।
- भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के 25 सब्जेक्ट को उनकी संबंधित विषय श्रेणियों में दुनिया के शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- तीन IIT को शीर्ष 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थान मिला।
- **इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी:** IIT बॉम्बे - 49 वां स्थान; IIT दिल्ली (54) और IIT मद्रास (94)।
- MIT, USA ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
- **प्राकृतिक विज्ञान:** भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर - 92 वां; IIT बॉम्बे (114), IIT मद्रास (187), और IIT दिल्ली (210)।
- **पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कार्यक्रम:** IIT मद्रास - 30 वां
- **खनिज और खनन इंजीनियरिंग:** IIT बॉम्बे - 41 वां; IIT खड़गपुर - 44 वां
- **जीवन विज्ञान और चिकित्सा:** एम्स - 248 वाँ।
- **कला और मानविकी:** JNU - 159 वीं, दिल्ली विश्वविद्यालय- 252 वीं
- **सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी:** दिल्ली विश्वविद्यालय - 208 वीं

क्या आप जानते हैं?

- क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) रैंकिंग विषय के आधार पर चार मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन की गणना करती है - शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अनुसंधान प्रभाव और किसी संस्थान के शोध संकाय की उत्पादकता।

- इसमें भारत के 52 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 51 अकादमिक विषयों के 253 कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर स्वतंत्र आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया।

आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह (CGETI)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत की अध्यक्षता में, ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों (Contact Group on Economic and Trade Issues- CGETI) पर 9 मार्च 2021 से 11 मार्च, 2021 तक आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **थीम:** ब्रिक्स @ 15: निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशो सहयोग।
- **प्रस्तावित प्रस्तुतियां जारी हैं:** (1) विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स छूट प्रस्ताव के लिए सहयोग सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर ब्रिक्स सहयोग; (2) ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण के लिए रूपरेखा; (3) गैर-टैरिफ उपाय (NTM) रिज़ॉल्यूशन तंत्र; (4) स्वच्छता और फाइटो-सेनेटरी (SPS) कार्य तंत्र; आदि।
- **ब्रिक्स के पांच देश:** ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।

जो बिडेन की अफगानिस्तान शांति योजना

संदर्भ: जो बिडेन प्रशासन ने अफगान सरकार और तालिबान को एक नई शांति योजना का प्रस्ताव दिया है, जो हिंसा रोकने और अंतरिम सरकार बनाने की मांग किया।

अमेरिकी प्रस्ताव क्या है?

- **अन्य हितधारकों को शामिल करना:** अमेरिका ने रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन का प्रस्ताव दिया है "अफगानिस्तान में शांति का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए"।
- **ट्रस्ट बढ़ाने का लिखित प्रस्ताव:** वार्ता को तेज करने के लिए अमेरिका अफगान नेतृत्व और तालिबान के साथ लिखित प्रस्ताव साझा करेंगे
- **व्यापक युद्धविराम और समावेशी सरकार:** अमेरिका ने दोनों पक्षों से अफगानिस्तान के भविष्य की संवैधानिक और शासन व्यवस्था पर आम सहमति तक पहुंचने का आग्रह किया है; एक नई "समावेशी सरकार" के लिए एक रोड मैप खोजें; और "स्थायी और व्यापक युद्ध विराम" की शर्तों पर सहमत हो।
- **तीसरे देश में वार्ता:** अमेरिका ने शक्ति साझाकरण, हिंसा में कमी और अन्य विशिष्ट लक्ष्यों पर चर्चा के लिए तुर्की सरकार और तुर्की में तालिबान की एक वरिष्ठ स्तर की बैठक का भी प्रस्ताव दिया है।

अमेरिका इस शांति को क्यों आगे बढ़ा रहा है?

- **रणनीति की समीक्षा:** बिडेन प्रशासन वर्तमान में अपनी अफगान रणनीति की समीक्षा कर रहा है। हालांकि समीक्षा पूरी नहीं हुई है, प्रशासन में एक सहमति है कि "शांति प्रक्रिया को तेज करना" अमेरिकी और अफगान सरकार के साझा हितों को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है।
- **दोहा समझौता (यूएस विदड्रॉल प्लान):** फरवरी 2020 में तालिबान के साथ अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, अमेरिकी सैनिक - वर्तमान में कुछ 2,500 सैनिक अफगानिस्तान में हैं जो 1 मई तक देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। तालिबान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेना समय सीमा से बाहर नहीं करता है तो वे लड़ाई लड़ेंगे।

- **शांति वार्ता की धीमी गति:** सितंबर 2020 में तालिबान और अफगान सरकार ने दोहा में शांति वार्ता शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बिडेन प्रशासन वार्ता की धीमी गति के बारे में चिंतित है।
- **तालिबान और क्षेत्रीय स्थिरता को रोकना:** अमेरिकी मूल्यांकन यह है कि यदि अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जाता है, तो तालिबान त्वरित लाभ कमाएगा और सुरक्षा स्थिति खराब हो जाएगी। इस आशा के साथ कि पूर्ण तालिबान अधिग्रहण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका एक क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया और अंतरिम एकता सरकार है। तालिबान को अभी अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब नहीं मिला है।

अफगान सरकार का क्या रुख है?

- **तालिबान के साथ अमेरिका की सीधी बातचीत:** ग़नी प्रशासन लगातार अमेरिकी तालिबान के प्रत्यक्ष आउटरीच के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रम्प प्रशासन ने सरकार को छोड़कर, तालिबान के साथ सीधी बातचीत की। बाद में, अमेरिका ने काबुल पर दबाव डाला कि तालिबान कैदियों को दोहा समझौते के हिस्से के रूप में रिहा किया जाए।
- **तालिबान को रियायत देने के खिलाफ:** यहां तक कि जब तालिबान और अफगान सरकार के बीच दोहा वार्ता चल रही थी, श्री गनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति, अफगान लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि हैं और वे तालिबान रियायतों का विरोध किया।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आंतरिक हस्तक्षेप:** राष्ट्रपति गनी ने चुनावों को छोड़कर सत्ता के किसी भी हस्तांतरण के लिए अपना विरोध दोहराया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमृतुल्लाह सालेह ने तालिबान के एक कट्टर आलोचक ने कहा कि अमेरिकी "अपने सैनिकों पर निर्णय ले सकते हैं, अफगानिस्तान के लोगों पर नहीं"।

आगे का दृष्टकोण

- जबकि तालिबान के साथ सत्ता साझा करने के अफगान सरकार के विरोध को अच्छी तरह से जाना जाता है, यह स्पष्ट नहीं है कि श्री गनी अमेरिकी दबाव का विरोध करना जारी रखेंगे, खासकर यू.एस., भारत सहित क्षेत्रीय शक्तियों को बोर्ड पर लाया जाता है।
- अगर अमेरिका मई तक तालिबान के समझौते पर कायम रहने और सैनिकों को वापस लेने का फैसला करता है, तो श्री गनी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है। यदि वह अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो युद्ध हमेशा के लिए जारी रहेगा।
- तालिबान ने पहले ही देश के अधिकांश हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है और अपने शहरों की गर्दन दबा रहा है।
- अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें तालिबान के साथ सत्ता साझा करनी होगी तथा संविधान और भविष्य के शासन ढांचे में संशोधन पर चर्चा करनी होगी।
- किसी भी तरह से, तालिबान लाभ कमाने के लिए तैयार हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाएं - सलमा बांध
- भारत विरोधी आतंकवादी समूहों पर समझौते का नैतिक प्रभाव

पारंपरिक दवाइयों के एक वैश्विक केंद्र

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; स्वास्थ्य

सुर्खिओ में क्यों-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक दवाइयों के एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह नया केंद्र डब्ल्यूएचओ की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को क्रियान्वित करने के डब्ल्यूएचओ के प्रयासों में मदद करेगा।
- **दवा की रणनीति का उद्देश्य:** इस रणनीति का उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित विश्व के लिए देशों को नीतयां बनाने और उसमें पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मजबूती देना है।

समाचारों में ज़ो समुदाय के लोग (Zo People)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - सोसायटी और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में 'ज़ो समुदाय' खबरों में थे।
- मिजोरम स्थित समूह ने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को सैन्य शासित म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 'ज़ो लोग' भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का एक जातीय समूह हैं।
- उन्हें म्यांमार में "चिन" और "ज़ोमी" और भारत में "मिज़ो", "ज़ोमी" और "कूकी" के रूप में जाना जाता है।
- **उत्तर-पूर्वी भारत में, ये मौजूद हैं:** नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम।

पानी की गुणवत्ता परीक्षण की रूपरेखा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में जल गुणवत्ता परीक्षण ढाँचे को जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया ।
- नागरिकों को अब उचित दरों पर परीक्षण किए गए नल में पानी की गुणवत्ता, ढांचे के हिस्से के रूप में मिल सकती है

महत्वपूर्ण तथ्य

- अगले वर्ष से प्रत्येक राज्य, जिला और ब्लॉक में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- पंचायत स्तर पर, गांव का पानी और स्वच्छता समितियों की महिलाओं की टीमों को फील्ड परीक्षण किट दिए जाएंगे।
- निजी खिलाड़ियों की सीमित संख्या भी शामिल की जा सकती है।
- **अनुमानित लागत:** सभी 16 जल गुणवत्ता मानकों के लिए 600 करोड़
- **रासायनिक परीक्षणों के लिए टर्नअराउंड समय:** 24 घंटे
- **जैविक दूषित पदार्थों के लिए समय:** 48 घंटे
- परीक्षण के सभी परिणामों को जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली (WQMIS) में सिंचित किया जाएगा।
- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के समर्थन से विकसित एक पोर्टल है।

साना पर हवाई हमले

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- यमन की राजधानी साना पर सऊदी-नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हवाई हमले किए।
- स्ट्राइक से पहले सऊदी ने हौथिस द्वारा लॉन्च किए गए 10 ड्रोनों को रोक दिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- साना यमन का सबसे बड़ा शहर है।
- संवैधानिक रूप से, साना यमन की राजधानी है।
- हौथी उपद्रव के बाद, राजधानी अदन में स्थानांतरित हो गई - दक्षिण यमन की पूर्व राजधानी।
- अदन देश के सबसे ऊंचे पहाड़ों और इस क्षेत्र में सबसे ऊंचे पर्वत माने जाने वाले जबल अन-नबी शुऐब और जबल तियाल के सरवत पर्वत के बगल में स्थित है।
- साना एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- इसका एक विशिष्ट वास्तुशिल्प चरित्र है, जो ज्यामितीय पैटर्न से सजाए गए अपने बहुमंजिला भवनों में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है।

उइगर उत्पीड़न के लिए चीन पर लगाए गए प्रतिबंध

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- **II** - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- शिनजियांग प्रांत में उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के लिए यूरोपीय संघ, अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीनी अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए।

- यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के प्रतिबंधों में यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों की हिमीकरण शामिल है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी शक्तियाँ एक साथ रहती हैं।
- यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ ने चीन के साथ 1989 के तियानमेन स्क्वेयर क्रैकडाउन के बाद हथियारों के जखीरे पर प्रतिबंध लगाया है।
- यह व्यापार प्रतिषेध अभी भी यथावत है।
- यूरोपीय संघ के प्रतिबंध अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के खिलाफ रुख को सख्त करते हैं।
- चीन ने उइगरों के खिलाफ अत्याचार की सभी रिपोर्टों का लगातार खंडन किया है, यह बनाए रखना कि यह सुरक्षा के हितों में अपनी आबादी के केवल "अपमानजनक" तत्व है।

क्या आप जानते हैं?

- झिंजियांग में तुर्क वंश के मुसलमानों की बड़ी संख्या में उइगर हैं।
- पिछले कुछ दशकों में, अधिक से अधिक हान चीनी झिनझिनग में बस गए हैं, जिसमें उनके और उइगरों के बीच हिंसक झड़पें हुई।
- चीन पर अब एक लाख से अधिक लोगों को नजरबंद करने का आरोप लगाकर उन्हें "डी-मुस्लिमाइज" कर दिया गया है और कम्युनिस्ट देश में बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
- उत्तरजीवी और मानवाधिकार संगठनों ने शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
- लोगों को "अतिवाद" के किसी भी लक्षण को दिखाने के लिए शिविरों में भेजा जा सकता है - खेल दाढ़ी, रमजान के दौरान उपवास, बहुमत से अलग कपड़े पहनना, ईद की बधाई भेजना, "बहुत बार" प्रार्थना करना आदि।

स्वेज नहर की रुकावट

संदर्भ: स्वेज नहर में एक कंटेनर जहाज फंसने के बाद वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ।

स्वेज नहर के बारे में

- मिस्र में स्थित, कृत्रिम समुद्र-स्तरीय जलमार्ग 1859 और 1869 के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के बीच बनाया गया था।
- यह अटलांटिक महासागर और भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के आसपास की भूमि के बीच सबसे छोटा मार्ग प्रदान करता है।
- यह नहर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है, जो अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के चारों ओर नौचालन करने की आवश्यकता को रोकती है इस तरह 7,000 किमी तक की दूरी काम करती है।
- **आर्थिक जीवन रेखा:** यह नहर पश्चिम और पूर्व के बीच सभी व्यापारों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है क्योंकि हर साल वैश्विक व्यापार का 10 प्रतिशत इससे गुजरता है। रोजाना जो औसत 50 जहाज इस नहर से गुजरते हैं, वे हर दिन लगभग 9.5 बिलियन डॉलर का सामान ले जाते हैं।

स्वेज नहर का लंबा इतिहास

- नहर एक रूप या दूसरे में अस्तित्व में रही है, क्योंकि इसका निर्माण मिस्र के फैरोस सेनोस्रेट **III** (1887-1849 ईसा पूर्व) के शासनकाल में शुरू हुआ था। बाद में शासन करने वाले कई राजा इस नहर में सुधार और विस्तार करते रहे।
- यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इसका निर्माण लगभग 300 साल पहले गति पकड़ लिया।

- 1800 के दशक के मध्य में, फ्रांसीसी राजनयिक और इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेप्स ने नहर के निर्माण का समर्थन करने के लिए मिस्र के वाइसराय सईद पाशा को आश्वस्त किया।
- 1858 में, यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी को 99 साल के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया, जिसके बाद मिस्र सरकार को अधिकार सौंप दिए गए।
- ब्रिटिश और तुर्क द्वारा निर्माण को रोकने के लिए वित्तीय कठिनाइयों और प्रयासों से लेकर कई समस्याओं का सामना करने के बावजूद, नहर को 1869 में अंतर्राष्ट्रीय नौचालन के लिए खोला गया।
- फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने नहर कंपनी में अधिकांश शेयर रखे थे। अंग्रेजों ने 1936 की संधि के तहत स्वेज नहर क्षेत्र के साथ रक्षात्मक बल बनाकर अपने समुद्री और औपनिवेशिक हितों को बनाए रखने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया।

मिस्र का स्वेज नहर पर अधिकार

- 1954 में, मिस्र के राष्ट्रवादियों के दबाव का सामना करते हुए, दोनों देशों ने सात साल की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके कारण ब्रिटिश सैनिकों की वापसी हुई।
- 1956 में, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल नासर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करके नील नदी पर बांध के निर्माण का भुगतान किया। इसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल के साथ स्वेज संकट के कारण मिस्र पर हमला की आशंका बढ़ गई।
- संयुक्त राष्ट्र के शामिल होने के बाद 1957 में संघर्ष समाप्त हो गया और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के पहले उदाहरण के रूप में दुनिया में कहीं भी तैनात किया गया।
- 1967 में, नासिर ने सिनाई से शांति सेनाओं का आदेश दिया, जिससे दोनों देशों के बीच एक नया युद्ध हुआ। इजरायलियों ने सिनाई पर कब्जा कर लिया और जवाब में, मिस्र ने सभी शिपिंग के लिए नहर को बंद कर दिया।
- यह बंद 1975 तक चला, जब दोनों देशों ने एक विघटन समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिस्र और सीरिया के नेतृत्व वाले अरब गठबंधन के साथ नहर 1973 के अरब-इजरायल युद्ध का केंद्र बिंदु थी

स्वेज नहर के सबसे लंबे समय तक आकस्मिक बंद का प्रभाव

- **सभी ट्रैफ़िक को अवरुद्ध करना:** 23 मार्च को, एक विशाल कंटेनर जहाज, एमवी एवर गिवेन की वजह से मौसम की रुकावटों के कारण, चीन से नीदरलैंड तक जाने वाला मार्ग नहर के संकीर्ण हिस्सों में फंस गया, जिससे यातायात बाधित हो गए।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर तनाव:** 200 से अधिक जहाज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर तनाव डालते हुए नहर के दोनों किनारों पर फंस गए।
- **तेल की बढ़ी हुई कीमतें:** इस ब्लॉक का दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कितने समय तक चलता है, लेकिन कुछ देशों ने पहले ही रुकावट के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि देखी है।
- **भारत- स्वेज नहर के माध्यम से सबसे बड़ा आयातक:** भारत स्वेज नहर के माध्यम से कच्चे तेल और उत्पादों का शीर्ष आयातक है, जो चीन, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर से अधिक है। यदि यह समस्या जल्दी हल नहीं होती है तो इसका बड़े व्यापार प्रवाह और शिपिंग क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और व्यापक स्तर पर परिशोधन कार्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा।
- **भारत-अमेरिका संबंध:** हालांकि भारत के लिए, अमेरिका ईथेन के आयात और निर्यात और लैटिन अमेरिका से कच्चे तेल के आयात पर मुख्य मार देखी जा सकती है, हाल ही में जिसकी वृद्धि हुई। जितना अधिक समय तक बंद रहेगा, प्रभाव उतना ही अधिक विघटनकारी होगा।
- **इस संकीर्ण जलमार्ग पर वैश्विक निर्भरता:** यह घटना भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने और इस संकीर्ण जलमार्ग पर वैश्विक निर्भरता को कम करने के बारे में भी सवाल उठाती है।

चीन-ईरान ने किया 25 साल के लिए सहयोग समझौता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में चीन और ईरान ने 25 साल के "रणनीतिक सहयोग समझौते" पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसमें "राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक" घटक शामिल हैं।
- यह दस्तावेज़ संबंधों को मजबूत बनाने में काफी प्रभावी हो सकता है
- यह "परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में पारस्परिक निवेश" का ढांचा तैयार करेगा।
- यह समझौता चीन के ईरान को पीछे करने के लिए एक मुख्य प्रेरणा है क्योंकि यह प्रतिबंधों के निरंतर महत्व से संबंधित है
- चीन इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

क्या आप जानते हैं?

- चीन और रूस ने अमेरिका से "संयुक्त रूप से संयुक्त व्यापक योजना (JCPOA) पर जल्द से जल्द लौटने और ईरान के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों को रद्द करने का आह्वान किया।"
- इस संदर्भ में, उन्होंने "क्षेत्र में देशों की सुरक्षा चिंताओं को हल करने पर एक नई सहमति बनाने के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच की स्थापना" का प्रस्ताव रखा।

द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया (होआ-आईपी)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत के विदेश मंत्री ने ताज़िकिस्तान के दुशांबे में आयोजित 9वीं हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लिया।
- स्थान - ताजिकिस्तान

अन्य संबंधित तथ्य

- द हार्ट ऑफ एशिया - इस्तांबुल प्रक्रिया (होआ-आईपी) अफगानिस्तान और तुर्की की एक पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2011 में इस्तांबुल में तुर्की द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में शुरू किया गया था।
- तब से, अफगानिस्तान ने 14 भाग लेने वाले हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र का समर्थन किया, इस क्षेत्र से 16 सहायक देश और 12 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस प्रक्रिया का नेतृत्व और समन्वय कर रहे हैं।
- यह बातचीत के माध्यम से अफगानिस्तान पर केंद्रित क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने और विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) का एक मंच है।
- **डी फैक्टो सचिवालय:** अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय सहयोग के लिए महानिदेशालय
- HoA-IP के 15 भाग लेने वाले देशों को कवर करने वाले भौगोलिक क्षेत्र को हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसमें एक सामूहिक भौगोलिक क्षेत्र है जो पृथ्वी के लगभग 27% भूमि क्षेत्र को कवर करता है।

क्या आप जानते हैं?

- HoA-IP के तहत व्यापार, वाणिज्य और निवेश विश्वास निर्माण उपाय के लिए प्रमुख देश के रूप में, भारत ने इस क्षेत्र के साथ अफगानिस्तान के अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं।
- भारत और अफगानिस्तान के शहरों और ईरान में चाबहार पोर्ट के संचालन के बीच एक समर्पित एयर फ्रेट कॉरिडोर उस दिशा में कदम हैं।
- विदेश मंत्री ने दुशांबे-चोर्टुट राजमार्ग परियोजना का भी दौरा किया और भारतीय अनुदान सहायता के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
- 8-लेन राजमार्ग दुशांबे को विस्थापित करेगा।

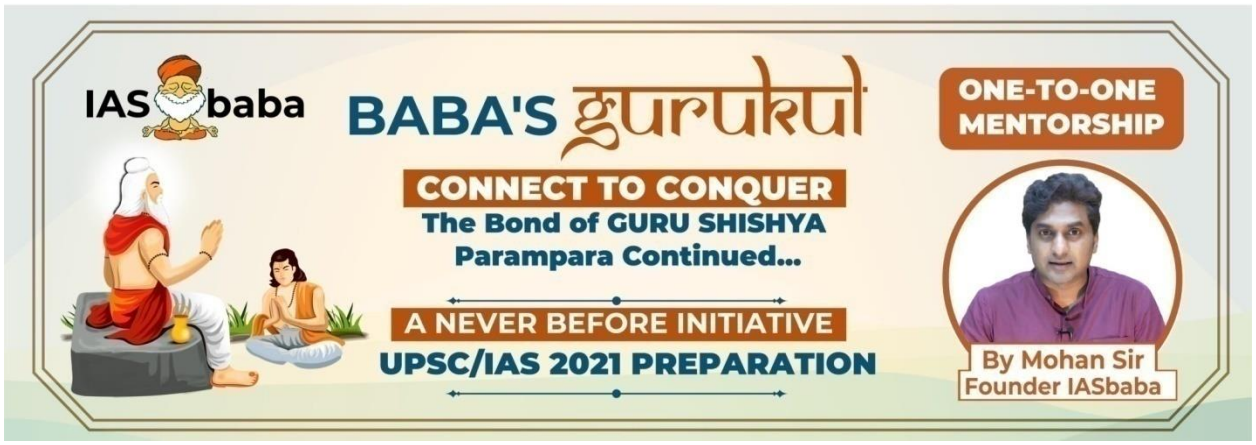

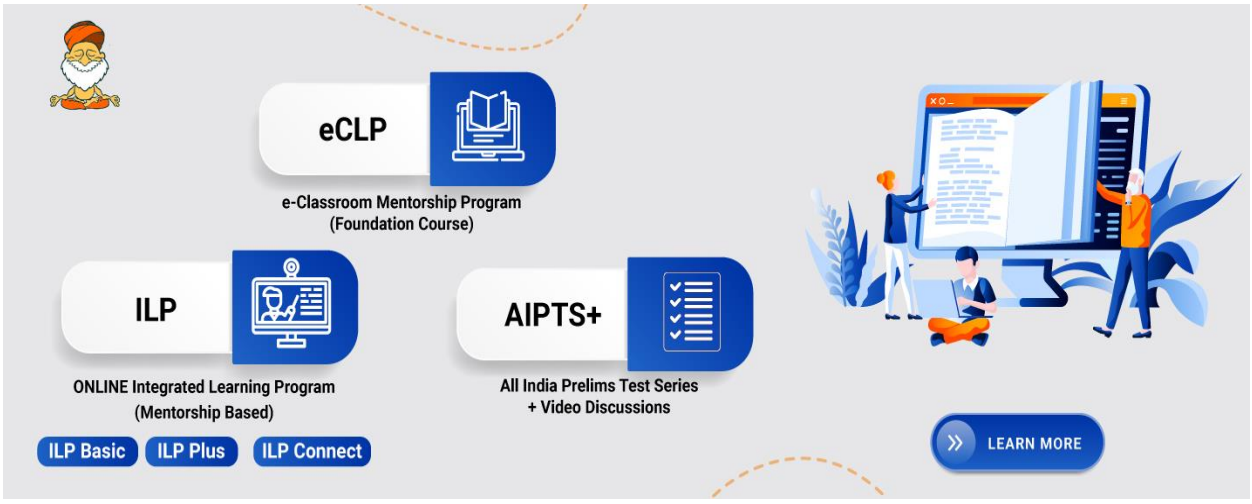

भारत और विश्व

घाना 'कोवैक्स' पहल के तहत टीका प्राप्त करने वाला पहला देश

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य; अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- घाना कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोनावायरस टीकों की खेप प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- 23 फरवरी को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लगभग 600,000 खुराक घाना के अकरा को भेजे गए।
- वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII), पुणे द्वारा किया गया है जो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कोवैक्स कार्यक्रम का नेतृत्व टीकाकरण GAVI, WHO और गठबंधन के लिए महामारी संबंधी तैयारी नवाचारों (CEPI) के साथ यूनिसेफ, टीके निर्माताओं और विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किया गया है।
- **उद्देश्य:** विश्व स्तर पर COVID-19 टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करना।
- यह इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीन खरीद और आपूर्ति ऑपरेशन माना जाता है।
- कार्यक्रम 92 एडवांस मार्केट कमिटमेंट (एएमसी) देशों में लगभग 20 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करना चाहता है, जिसमें मध्यम और निम्न-आय वाले राष्ट्र शामिल हैं जो COVID-19 टीकों का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
- सकल राष्ट्रीय आय (GNI) वाले देशों में प्रति व्यक्ति US $ 4000 से कम और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के तहत योग्य कुछ अन्य देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

क्या आप जानते हैं?

- एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में कोविशिल्ड के रूप में जाना जाता है।
- इसे WHO द्वारा फरवरी, 2021 में इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग (EUL) दिया गया।

संबंधित आलेख:

- वैक्सीन राष्ट्रवाद
- वैक्सीन डिप्लोमेसी

भारत-यूरोपीय संघ

भारत का यूरोपीय संघ को निर्यात क्षमता

- भारत के पास यूरोपीय संघ और पश्चिमी यूरोप में $ 39.9 बिलियन की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता है।
- निर्यात क्षमता वाले शीर्ष उत्पादों में परिधान, रत्न और आभूषण, रसायन, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक शामिल हैं। भारत इन उत्पादों में से कई के लिए यूरोपीय संघ के सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों को बाज़ार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश देते हैं) से लाभान्वित होता है।
- भारत यूरोपीय संघ के जीएसपी के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है, जीएसपी के तहत भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 19.4 बिलियन डॉलर निर्यात किया है। भारत का लगभग 37% व्यापारिक निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है।

चिंताओं

- हालाँकि, ऐसे कई उत्पाद हैं जहाँ भारत की यूरोपीय संघ में निर्यात क्षमता है, लेकिन ये "ग्रेजुएटेड"(Graduated) हैं या यूरोपीय संघ के जीएसपी के तहत "ग्रेजुएशन" (Graduation) के कगार पर हैं।
- उत्पाद स्नातक तब लागू होता है जब किसी लाभार्थी देश से उत्पाद का औसत आयात तीन वर्षों में सभी लाभार्थी देशों से एक ही उत्पाद के यूरोपीय संघ-जीएसपी आयात का 17.5% से अधिक हो।
- भारत के उत्पाद जैसे कपड़ा, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, रत्न और आभूषण, लोहा, इस्पात और उनसे निर्मित वस्तुएँ, बेस मेटल्स और मोटर वाहन जैसे उत्पाद पहले से ही जीएसपी लाभों के दायरे से बाहर हैं।
- उत्पाद के स्नातक होने के कारण परिधान, रबर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खेल के सामान और खिलौने जैसी अन्य श्रेणियों में यूरोपीय संघ-जीएसपी लाभ खोने की संभावना भी है।
- वर्ष 2019 में परिधान में, यूरोपीय संघ के लिए भारत का निर्यात 7 बिलियन डॉलर था। इस बीच भारत को बांग्लादेश जैसे परिधान निर्यात देश से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, बांग्लादेश भी यूरोपीय संघ से जीएसपी टैरिफ का लाभ ले रहा है।
- एक अन्य प्रतियोगी देश वियतनाम ने 2019 में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) संपन्न किया।
- ऑटोमोटिव तथा डेयरी और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों में सहमति के अभाव के कारण एक व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते के लिए भारत की बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है।

आगे की राह

- इसके अलावा बहुत से देश अब मुक्त व्यापार के बजाय संरक्षणवादी व्यवस्था को तरज़ीह दे रहे हैं, ताकि वो अपने घरेलू उद्योग धंधों को वैश्विक स्तर पर प्रतिद्वंदिता से बचा सकें। इसीलिए, आज ज़रूरत इस बात की है कि भारत और यूरोपीय संघ वास्तविक बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देने के लिए मिल जुलकर प्रयास करें।
- घरेलू उत्पादकों के लिए एफटीए से लाभों का गहन मूल्यांकन किया गया है, जो संवेदनशील क्षेत्रों के प्रभाव पर विचार करने के साथ-साथ कुछ वस्तुओं के लिए रियायतों पर सावधि विधि खंड जैसे सुरक्षा उपायों को शामिल करने की संभावना है।
- निवेश और गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) जैसे पहलुओं के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।
- भारत को द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने और मजबूत मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के साथ निवेश से संबंधित पहलुओं पर बातचीत करने की आवश्यकता है विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्रों में जिसमें यूरोपीय संघ का तुलनात्मक लाभ है।

निष्कर्ष

- पोस्ट-ब्रेक्सिट यूरोपीय संघ खुद को अपने साथी देशों के साथ संबंधों की पुनरावृत्ति की बढ़ती आवश्यकता के बीच है।
- पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के माध्यम से क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने तथा भारतीय विनिर्माण को मजबूत करने और प्रचलित निर्यात को फिर से जीवित करने में मदद मिल सकती है।

भारत-नाइजीरिया के बीच पहला आतंकवाद-रोधी संवाद

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत और नाइजीरिया के बीच पहला रणनीतिक और आतंकवाद-रोधी संवाद आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आतंकवाद, अतिवाद और कट्टरता से लोकतांत्रिक समाजों के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों पर चर्चा हुई।
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाने के लिए सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई।

क्या आप जानते हैं?

- नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में एक देश है जिसके उत्तर में नाइजर है उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में कैमरून और पश्चिम में बेनिन है।
- इसका दक्षिणी तट अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में है
- इसकी राजधानी अबूजा है।

संबंधित आलेख:

- एक 'स्वस्थ' भारत-अफ्रीका साझेदारी की ओर

भारत - स्वीडन वर्चुअल समिट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत और स्वीडन के बीच आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इसमें द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दोनों देशों ने संयुक्त कार्य योजना और नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।
- 2018 में भारतीय प्रधान मंत्री की स्वीडन-भारत यात्रा के दौरान इन पर सहमति व्यक्त की गई।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) में शामिल होने के स्वीडन के फैसले का स्वागत किया।
- नेताओं ने भारत-स्वीडन संयुक्त पहल की बढ़ती सदस्यता सिंधु-ट्राय ट्रांजिशन पर लीडरशिप ग्रुप (Indus-try Transition-LeadIT) का उल्लेख भी किया।
- जिसे न्यूयॉर्क में सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था

क्या आप जानते हैं?

- नॉर्डिक क्षेत्र में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, साथ ही फ़रो आइलैंड्स, ग्रीनलैंड और ओलैंड भी हैं।

भारत-जापान अंतरिक्ष संबंध

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के बीच द्विपक्षीय बैठक क्रमश: आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने पृथ्वी अवलोकन, चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन में सहयोग की समीक्षा की।
- वे देश अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम में सहयोग के अवसर तलाशने पर भी सहमत हुए।
- दोनों एजेंसियों ने उपग्रह डेटा का उपयोग कर चावल की फसल क्षेत्र और वायु गुणवत्ता निगरानी पर सहयोगी गतिविधियों के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बांध

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- चीन की पंचवर्षीय योजना (2021-2025) के एक मसौदे के अनुसार, पहले बांध यारलुंग ज़ंग्बो नदी के निचले छोर पर बनाए जाने की मंजूरी दी।
- भारत में बहने से पहले ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग ज़ंग्बो नदी से जानते है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस योजना में विशेष रूप से जलविद्युत आधारों के निर्माण का उल्लेख है जो प्राथमिकता वाली ऊर्जा परियोजनाएँ होंगी।
- यह नदी के जलविद्युत दोहन में एक नया अध्याय है।
- अन्य प्रमुख परियोजनाओं में तटीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और बिजली ब्राडकास्ट चैनलों का निर्माण शामिल है।
- यह परियोजना सिचुआन-तिब्बत रेलवे और राष्ट्रीय जल नेटवर्क के साथ भी सूचीबद्ध है।

क्वाड चुनौतियां

संदर्भ: क्वाड, जिसमें यू.एस., जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं इसका वर्णन यू.एस. द्वारा "आवश्यक गति और महत्वपूर्ण क्षमता" के रूप में किया गया है।

भारत का क्वाड से जुड़ाव

- **चीन की कार्रवाई:** भारत का क्वाड के साथ जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में चीन के दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत के सामरिक अंतरिक्ष में अतिक्रमण के रूप में देखा गया।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं की उन्नति और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंध बढ़ाने और उत्तर क्षेत्र में अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा की गई चिंता:** चीन के उदय से संबंधित उनकी साझा की गई चिंताओं के परिणामस्वरूप, भारत अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को गहरा बना रहा है, जो रक्षा उपकरणों, प्रशिक्षण, भूमि और समुद्री अभ्यासों के आधार पर केंद्रित है।

समूहीकरण समय के साथ कैसे विकसित हुआ है?

- **आरंभिक अनिच्छा:** भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र विरोधी गठबंधन में शामिल होने की अनिच्छा के कारण क्वाड के साथ भारत की भागीदारी शुरू में सतर्क थी।
- **दायरे का विस्तार:** नवंबर 2017 के बाद से, क्वाड सदस्यों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों को सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक परामर्श द्वारा जोड़ कर बनाया जा रहा है
- **मंत्री स्तर तक उन्नति:** सितंबर 2019 में, भारत ने क्वाड प्लेटफॉर्म को मंत्री स्तर तक बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की
- **शिखर सम्मेलन के स्तर की संभावना:** यह बताया गया है कि क्वाड 2021 वें शिखर सम्मेलन में जल्द ही बैठक करेगा, जो अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस समूह से जुड़े महत्व को दर्शाता है।

भारत के लिए चिंता

- **इंडो-पैसिफिक के दायरे में खींचा गया:** आक्रामक चीनी समुद्री गतिविधि के कारण पश्चिमी प्रशांत पर यू.एस. का ध्यान धीरे-धीरे भारत को एक ऐसे इंडो-पैसिफिक के दायरे में खींच गया, जो पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर को एकीकृत भू-राजनीतिक अंतरिक्ष के रूप में देखता है।
- **भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी:** अमेरिकी नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन के साथ संबद्ध करके, भारत ने उत्तरी सीमाओं में अपनी सुरक्षा चिंताओं के प्रमुख क्षेत्रों की अनदेखी की। हाल ही में सीमा पर संघर्ष के साथ, चीन ने भारत को कठोर चेतावनी दी है कि भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्तरी प्रशांत में नहीं बल्कि उसकी उत्तरी सीमाओं में हैं।

- **अमेरिका के साथ विचलन:** नई दिल्ली और वाशिंगटन, समुद्री रणनीति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन एशियाई मुख्य भूमि पर क्या करना है, इस पर कोई प्रतिकिर्या नहीं है
- **क्वाड की अमेरिका में धुरी के कारण संरचनात्मक मुद्दे:** क्वाड में एक मुख्य संरचनात्मक समस्या है कि यह अमेरिका के चारों ओर घूमता है अमेरिका वैश्विक हितों की एक महाशक्ति है, लेकिन यह अपने हितों को परिभाषित करने और आगे बढ़ाने में भी आत्म-केंद्रित है। यहां तक कि इसकी नीतियां सरकारी बदलाव या घरेलू लॉबी के कारण प्रमुख बदलाव का अनुभव करती हैं
- **सामरिक दृष्टि नहीं है:** एक नियम-आधारित 'विश्व व्यवस्था के प्रचार से संबंधित बयानबाजी के बावजूद (यू.एस. द्वारा ही नियमों का सबसे अधिक उल्लंघन किया जा रहा है), क्वाड न तो रणनीतिक दृष्टि साझा करता है और न ही किसी साझा एजेंडे से अनुप्राणित है।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति अक्सर एक व्यापक रणनीतिक संस्कृति की अनुपस्थिति को दर्शाती है, तदर्थ, प्रतिक्रियाशील और अल्पकालिक है। जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य अधिक जटिल होता जा रहा है भारत की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, एक सामंजस्यपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से भारत को अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रूप से पदार्थ और ड्राइव मिलेगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
- चीन से निपटने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करना

श्रीलंका का आतंकवाद पर युद्ध

संदर्भ: श्रीलंकाई सरकार जल्द ही बुर्का पर प्रतिबंध लगाएगी।

सरकार के प्रस्ताव

- **COVID-19 और दफन:** सरकारी नियम है कि कोविद -19 से मरने वाले मुसलमानों को दफन नहीं होने के कारण इनके धर्म सांप्रदायिक लोग कोर्ट चले में जाते हैं। मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के नाराजगी के कारण श्रीलंकाई सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा
- **जांच समिति की रिपोर्ट:** कोलंबो में चर्चों और दो अन्य स्थानों पर छह आत्मघाती हमलों को जिसमे 260 लोगों की हत्या कर दी गयी इसकी जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंप दी है लेकिन सार्वजनिक नहीं किया।
- **बुर्का बैन:** 2018 के ईस्टर बम विस्फोटों के बाद, श्रीलंकाई सरकार ने कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले नक़ाब पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि यह शब्द था कि अस्पष्ट शब्दों में सभी चेहरे को कवर करने पर प्रतिबंध लगाया गया। बुर्का प्रतिबंध को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और इस्लामी चरमपंथ से जोड़ा गया
- **मदरसों को बंद करना:** बुर्का प्रतिबंध के साथ, सरकार ने 1,000 मदरसों को बंद करने का भी प्रस्ताव दिया।
- **ड्रैकियन टेररिज्म लॉ:** उग्रवादियों के कट्टर विचारों, या धार्मिक, सांप्रदायिक या जातीय घृणा फैलाने के संदेह में किसी के "अपमानजनक" होने के उद्देश्य से सरकार ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम तथा नए नियमों के तहत दो साल तक के लिए खुद को सशस्त्र कर लिया है।

प्रस्तावों का महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **अल्पसंख्यक आबादी का बड़ा वर्ग प्रभावित:** श्रीलंका में, जहाँ मुस्लिमों की आबादी 21 मिलियन की 10% से कम है वे ज्यादातर तमिल भाषी हैं और मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं।

- **सामूहिक सजा:** प्रतिबंध से श्रीलंका के मुसलमानों में यह भावना बढ़ने की संभावना है कि समुदाय में कुछ लोगों के कार्यों के लिए उन्हें सामूहिक रूप से दंडित किया जा रहा है।
- **मौलिक स्वतंत्रता का आक्रामक प्रतिबंध:** मौलिक स्वतंत्रता का आक्रामक प्रतिबंध: श्रीलंका में कोई भी सामुदायिक फ़र्मान यह मांग नहीं करता है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए। लेकिन जो लोग विश्व के कई अन्य स्थानों की तरह इसे पहनते हैं, यह पहचान के आधार पर व्यक्तिगत पसंद का है कानून के द्वारा प्रतिबंध को मौलिक स्वतंत्रता पर अवैध माना जाता है।
- **श्रीलंकाई सोसाइटी में नई अधिक त्रुटि :** ईस्टर के हमले और उसके बाद हुए मुसलमानों के "अन्य" ने अल्पसंख्यक समुदाय को किनारे कर दिया, जिसे कभी तमिलों की तुलना में राष्ट्रीय और राजनीतिक मुख्यधारा में बेहतर रूप में देखा गया था। सरकार के नए प्रस्ताव को दो समुदायों के बीच उग्रता और अविश्वास को बढ़ा दिया ।
- **स्विटज़रलैंड मॉडल:** श्रीलंका में बुर्का प्रतिबंध की घोषणा 8 मार्च को परिधान पर प्रतिबंध के कारण हुई, जो राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद आया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने तीखे शब्दों में कहा कि स्विस प्रतिबंध को "भेदभावपूर्ण" और "गहरा अफसोसजनक" कहा गया है। जिन देशों ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नीदरलैंड, डेनमार्क और फ्रांस शामिल हैं।

भारत संकल्प 46 / L1 पर मतदान करने से रोकता है

- भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के एक प्रस्ताव पर मतदान से बच गया, जो श्रीलंका में मानव अधिकारों की स्थिति पर व्यापक और हानिकारक टिप्पणी करता है

चाबी छीन लेना

- संकल्प 46 / L1 ने अन्य बातों के अलावा, मानव अधिकारों पर उच्चायुक्त के कार्यालय को "मजबूत" तथा सबूत इकट्ठा करने और श्रीलंका में मानव अधिकारों के सकल उल्लंघन, भविष्य की जवाबदेही प्रक्रियाओं के लिए संभावित रणनीति विकसित करने का निर्णय लिया है।
- यह श्रीलंका में "सभी दलों" द्वारा वर्षों से किए गए अधिकारों के हनन के लिए "निरंतर" अभाव की ओर इशारा करता है।
- सबसे विचारणीय रूप में, यह वर्तमान सरकार की कमियों को दूर करने की क्षमता में विश्वास की कमी को दर्शाता है।
- जिन 14 देशों को रोका गया उनमें जापान, इंडोनेशिया, बहरीन और नेपाल थे।
- जिन 11 के विरुद्ध मतदान हुआ उनमें चीन, क्यूबा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और वेनेजुएला थे।

क्या आप जानते हैं?

- 2009 में लिट्टे के खिलाफ युद्ध की समाप्ति के बाद से मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका पर यह 8 वां प्रस्ताव है।
- इन प्रस्तावों पर भारत के मतदान का रिकॉर्ड नई दिल्ली-कोलंबो संबंधों के उतार-चढ़ाव, भारत में गठबंधन पर दबाव, तमिलनाडु में राजनीति और पार्टियों के प्रभाव, और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति के उतार और चढ़ाव को दर्शाता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-30
- श्रीलंका की भारत पहली नीति

भारत के लिये हीलियम संकट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- यूएसए 2021 से हीलियम के निर्यात में कटौती करेगा।

- इसके कारण, भारत के हीलियम आयात करने के बाद से भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

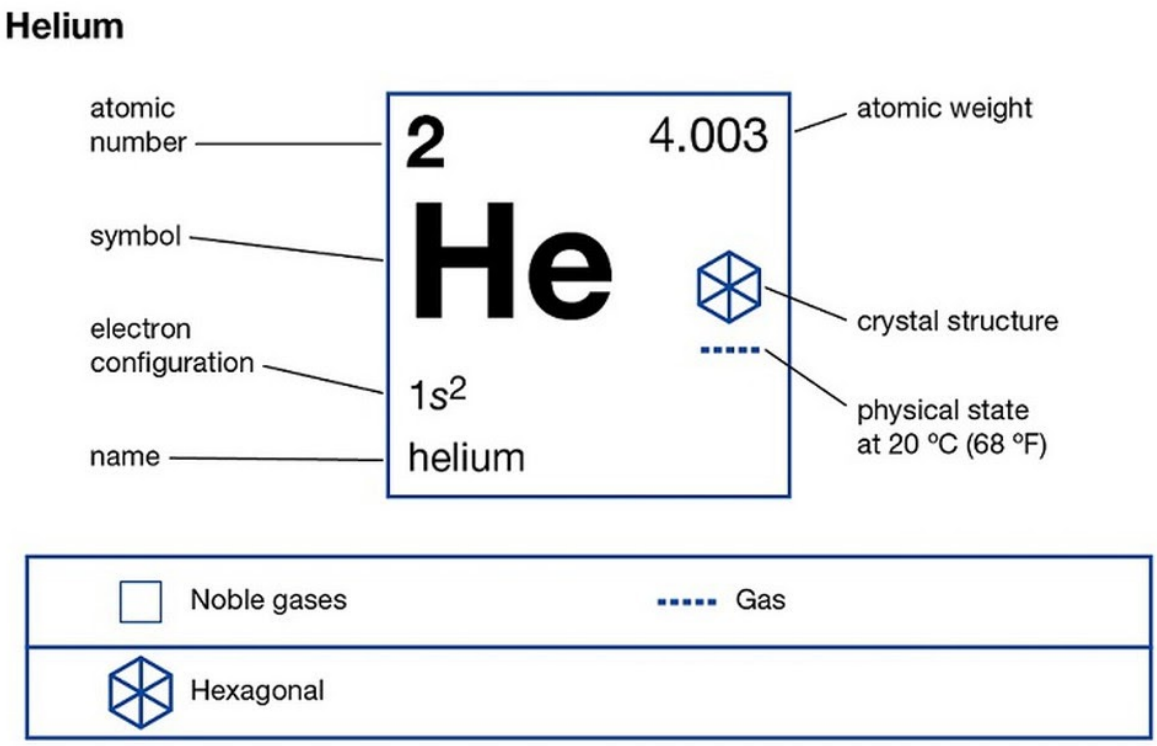

अन्य संबंधित तथ्य

- यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय तथा एकल परमाण्विक नोबल गैस (Noble Gas) है।
- **अनुप्रयोग:** रॉकेट और परमाणु रिएक्टरों में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) स्कैन।
- डच भौतिक विज्ञानी कमरलिंगह ओनेस ने -270 डिग्री सेल्सियस तक गैस को ठंडा करके हीलियम को तरलीकृत किया।
- अरबों वर्षों से फंसे भारत के झारखंड में राजमहल ज्वालामुखी बेसिन हीलियम का भंडार है।
- वर्तमान में, भारत हिमालयी भविष्य की खोज और दोहन के लिए बड़े पैमाने पर राजमहल बेसिन की मैपिंग कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवाएं कार्यालय (UNOPS)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवाएं कार्यालय (UNOPS) ने भारत के प्रमुख कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का समर्थन करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ एक साझेदारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **लक्ष्य:** जल जीवन मिशन (जल कार्यक्रम) के लिए रणनीतिक तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- UNOPS बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 11 जल-केंद्रित जिलों में स्केलेबल वितरण मॉडल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **जीवन जीवन मिशन का उद्देश्य:** 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना।

- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य -6 के साथ मेल खाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवाएं कार्यालय (UNOPS)

- UNOPS संयुक्त राष्ट्र का एक अतिरिक्त संसाधन है।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, सरकारों और विश्व भर के अन्य भागीदारों के लिए परियोजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित है।
- **मुख्यालय:** कोपेनहेगन, डेनमार्क में संयुक्त राष्ट्र शहर का परिसर।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के हिस्से के रूप में 1973 में स्थापित किया गया।
- यह 1995 में एक स्वतंत्र, स्व-वित्तपोषण संगठन बन गया।

स्थायी सिंधु आयोग की 116 वीं बैठक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - **II -** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- 2.5 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।

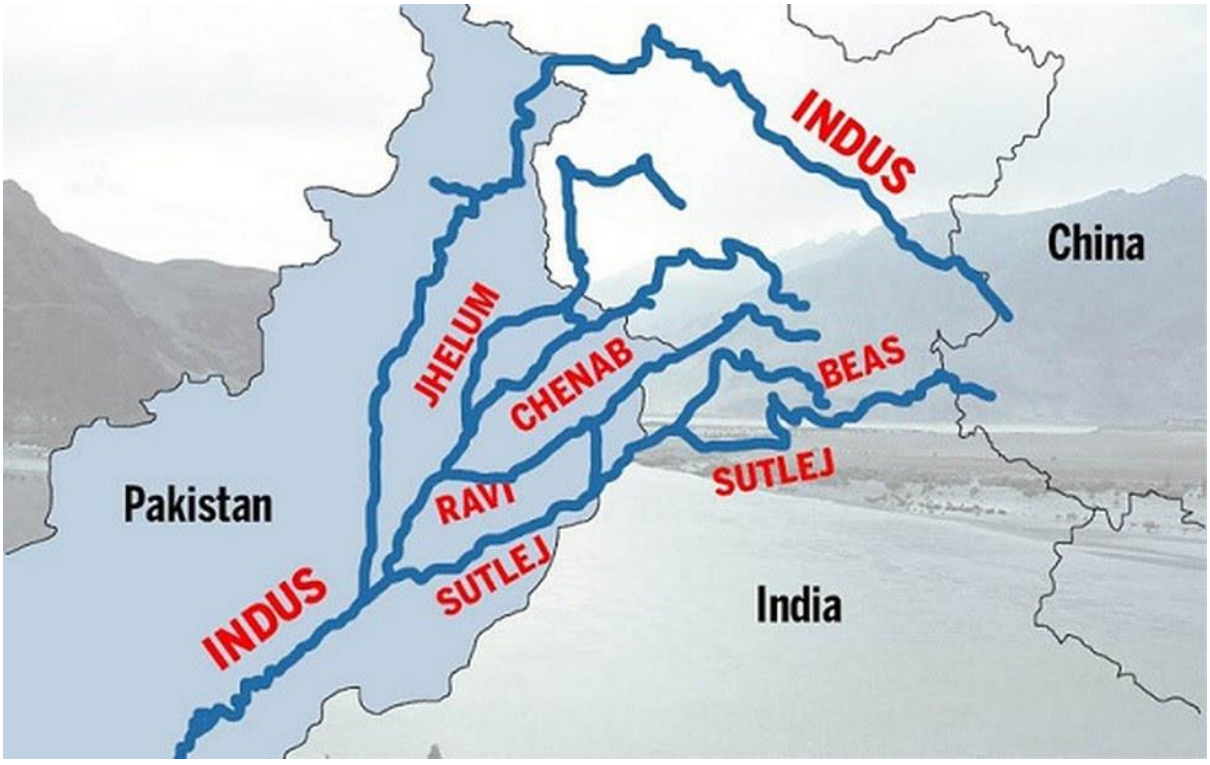

महत्वपूर्ण तथ्य

1. PIC एक द्विपक्षीय आयोग है जिसमें भारत और पाकिस्तान के अधिकारी शामिल हैं।

2. उद्देश्य: सिंधु जल संधि (IWT) के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रूपरेखा को लागू करना और प्रबंधित करना, जिस पर सितंबर 1960 में किसी भी विवाद समाधान के लिए विश्व बैंक की स्थायी गारंटी के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

- हाल ही में यह बैठक पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर हुई।
- इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा गया।

क्या आप जानते हैं?

- पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च, 1940 को लाहौर के प्रस्ताव को याद करता है जिसने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

भारत - ताइवान संबंध

अभिबिन्दुता

- दोनों देशों ने सामूहिक विकास के लिए प्रमुख सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र और विविधता के साथ स्पष्टता से बढ़ते आपसी सम्मान को मजबूत किया।
- स्वतंत्रता, मानवाधिकार, न्याय और कानून के शासन में साझा विश्वास उनकी भागीदारी को जारी रखता है।

रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए संभावित हैं:

आर्थिक संबंध	• भारत का बड़ा बाजार ताइवान को निवेश के अवसर प्रदान करता है। अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व के नेता के रूप में ताइवान की प्रतिष्ठा आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा) में भारत के नेतृत्व का पूरक है। • भारत की मौजूदा कारोबारी रैंकिंग में आसानी से न केवल आकर्षक व्यापार के अवसरों के साथ ताइवान प्रदान करता है, बल्कि यह निवेश के अवसरों के लिए एक देश पर अपनी निर्भरता को कम करने में भी मदद करता है।
पर्यटन	• भारत और ताइवान के लोगों को आपस में गहराई से जुड़ने की जरूरत है। • पर्यटन इस आदान-प्रदान का प्रमुख साधन है। • अविश्वसनीय भारत की विविधता को दर्शाने के अलावा, बौद्ध तीर्थ यात्रा को बेहतर कनेक्टिविटी और दृश्यता की आवश्यकता है। इससे ताइवान के पर्यटकों के आवागमन में बढ़ोतरी होगी । • मुंबई टूरिज्म के साथ ताइवान टूरिज्म ब्यूरो की भागीदारी से, ताइवान देश के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय पर्यटकों की अन्तर्वाह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
स्वास्थ्य देखभाल	• भारत COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है। • ताइवान की महामारी से निपटने और कई अन्य देशों को इसका समर्थन स्वास्थ्य देखभाल सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता रहा। • भारत और ताइवान पहले से ही पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। इस समय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार करना है।
वायु प्रदूषण	• ताइवान अपनी जैव-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से इस चुनौती से निपटने में एक महत्यपूर्ण भागीदार हो सकता है। • कृषि अपशिष्टों को मूल्य-वर्धित और पर्यावरण हितैषी नवीकरणीय ऊर्जा या जैव रासायनिक में परिवर्तित करने के लिए ऐसी विधियाँ लागू की जाती हैं। • इसके अलावा, नई दिल्ली और ताइपे भी जैविक खेती के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास की

	पहल कर सकते हैं। • इसके अलावा, नई दिल्ली और ताइपे भी जैविक खेती के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास की पहल कर सकते हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना
चीन-ताइवान संबंध

- **वन कंट्री टू सिस्टम:** यह हांगकांग और मकाऊ के शासन का वर्णन करते हुए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक संवैधानिक सिद्धांत है क्योंकि वे क्रमशः 1997 और 1999 में चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SARs) बने थे।

भारत-बांग्लादेश

संदर्भ: पिछले एक दशक में भारत-बांग्लादेश संबंधों को बढ़ावा मिला है, दोनों देश सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग कर हैं।

- भारत और बांग्लादेश ने आपदा प्रबंधन, व्यापार, एनसीसी, आईसीटी और हाल ही में खेल सुविधाओं की स्थापना के क्षेत्र में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली निकासी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नींव रखा गया।
- बनगबंधु-बापू डिजिटल प्रदर्शनी के बांग्लादेश लेग का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया।
- इसे संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व के अन्य हिस्सों में ले जाया गया।
- दोनों नेताओं ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को सम्मानित करते हुए आशूगंज में एक स्मारक के निर्माण के लिए आधारशिला भी रखी।
- भारत ने बांग्लादेश को 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और कोविशिल वैक्सीन की 1.2 मिलियन खुराक दी।
- भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ तीन सीमा हाट भी खोले गए।

सीमा समझौता	• 2015 में बांग्लादेश और भारत ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते की पुष्टि करके अपनी सीमा के मुद्दों को शांति से हल करने के असाधरण उपलब्धि हासिल की, जहां निवासियों को अपने निवास स्थान का चयन करने और भारत या बांग्लादेश के नागरिक बनने की अनुमति दी गई।
सुरक्षा और उग्रवाद	• भारत-बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादी तत्त्वों के समाप्त होने से भारत को अपने संसाधनों का पुनर्वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है यानी यह अपने सैन्य संसाधनों को उन सीमाओं पर स्थानांतरित कर सकता है जो अधिक विवादास्पद हैं।
आर्थिक और व्यापार संबंध	• बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.21 बिलियन डॉलर और आयात 1.04 बिलियन डॉलर का था। • भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त करने की पेशकश की है। • विकास के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत ने सड़कों, रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की राशि लाइन ऑफ क्रेडिट (एक प्रकार का ऋण) के रूप में प्रदान की है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी	• बांग्लादेश अपने मोंगला और चटोग्राम (चटगांव) समुद्र से सड़क, रेल और पानी के रास्ते से माल ले जाने की अनुमति देता है। • यह असम, मेघालय और त्रिपुरा में छत्रोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से सीधे जल मार्गों तक आने की अनुमति देता है।
पर्यटन	• बांग्लादेशी भारत में पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा रहते हैं। • बांग्लादेश भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों का 35% से अधिक खाता है और चिकित्सा पर्यटन से भारत के राजस्व का 50% से अधिक योगदान रहता है।

भारत-बांग्लादेश के संबंध में चिंता

- अनारक्षित तीस्ता जल बंटवारे का बड़ा मुद्दा है ।
- सीमा हत्याओं को रोकना अभी शेष।
- सम्पूर्ण भारत में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर भारत-बांग्लादेश संबंधों पर कमजोरी को दर्शाता है।
- चीन, अपनी चेक-बुक डिप्लोमेसी के आधार पर दक्षिण एशिया में अच्छी पहुँच स्थापित करने में सफल रहा है। दक्षिण एशिया के जिन देशों में चीन अपनी पहुँच बढ़ाने में सफल हुआ है उनमें बांग्लादेश भी शामिल है जिसके साथ इसने महत्त्वपूर्ण आर्थिक और रक्षा संबंध स्थापित किये हैं।

मैत्री सेतु

- भारतीय प्रधान मंत्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया।
- **द्वारा निर्मित:** राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड

महत्वपूर्ण तथ्य

- फेनी नदी पर 'मैत्री सेतु' बनाया गया।
- त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच नदी बहती है।
- यह पुल सबरूम (त्रिपुरा में) को रामगढ़ (बांग्लादेश में) से जुड़ता है।
- इस पुल के साथ, त्रिपुरा बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ 'नॉर्थ ईस्ट का गेटवे' बनने के लिए तैयार है, जो सबरूम से 80 किमी दूर है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- तीस्ता चैलेंज में चीन का ट्विस्ट

भारत, संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों (UNPKF) को COVID-19 वैक्सीन का बितरण किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत ने विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों (UNPKF) के लिए COVID-19 टीकों के 2,00,000 खुराक वितरण वादे को पूरा किया, जो कोपेनहेगन के लिए एक नौवहन भेजा।

अन्य संबंधित तथ्य

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों (UNPKF)

- संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सुरक्षा और देशों को शांति से संघर्ष से कठिन, प्रारंभिक संक्रमण में मदद करने के लिए राजनीतिक और शांति निर्माण सहायता प्रदान करते हैं।

- **सिद्धांत:** (1) पार्टियों की सहमति; (2) निष्पक्षता; (3) जनादेश के आत्मरक्षा और बचाव को छोड़कर बल का गैर-उपयोग
- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान मौजूद हैं।

क्या आप जानते हैं?

- अपनी सेवाओं के लिए, यूएन पीसकीपिंग को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला।
- संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों को अक्सर उनके हल्के नीले रंग के हेलमेट या हेलमेट के कारण ब्लू बेरेट या ब्लू हेल्मेट के रूप में जाना जाता है।

अर्थव्यवस्था

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए श्रम संहिता

संदर्भ: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में चार श्रम संहिता के कार्यान्वयन का उल्लेख किया, जो 20 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया को बंद कर रही थी।

क्या आपको पता है?

- भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कुल अनुमानित 450 मिलियन श्रमिकों की देश के कुल कार्यबल में लगभग 90% हिस्सेदारी है, साथ ही इसमें प्रतिवर्ष 5-10 मिलियन नए श्रमिक जुड़ जाते हैं।
- इनमें से लगभग 40 फीसदी MSMEs के साथ कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त ऑक्सफैम की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में नौकरी गँवाने वाले कुल 122 मिलियन श्रमिकों में से 75% अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित थे।
- रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि तालाबंदी के कारण 300 से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिसमें भुखमरी, आत्महत्या, थकावट, सड़क और रेल दुर्घटनाओं, पुलिस की बर्बरता और समय पर चिकित्सा देखभाल से वंचित करने के कारण शामिल थे।

जबकि रोजगार पैदा करके अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है, COVID-19 महामारी का अनुभव हमें बताता है कि सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से 450 मिलियन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को।

मुद्दे

- श्रम संहिता पर प्रस्तुत नियमों के मसौदे के तहत सभी श्रमिकों को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम होने के लिये श्रम सुरक्षा पोर्टल पर अपना पंजीकरण (आधार कार्ड के साथ) करना अनिवार्य बनाया गया है।
- इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों द्वारा निरंतर अंतराल पर इस पोर्टल में अपनी जानकारी को अद्यतन करना एक और संभावित चुनौती हो सकती है।
- **बहिष्करण के मुद्दे:** इससे जहाँ एक तरफ आधार-चालित बहिष्करण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अधिकांश श्रमिक आधार पंजीकरण प्रणाली के प्रति जागरूकता के अभाव में स्वयं ही पंजीकरण को पूरा नहीं कर सकेंगे।
- वर्तमान में मसौदा नियम 299 से अधिक श्रमिकों के साथ विनिर्माण फर्मों पर लागू होते हैं। यह 71 प्रतिशत विनिर्माण कंपनियों को इसके दायरे से बाहर करता है।
- **प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बोझ:** मसौदा नियम श्रम सुरक्षा पोर्टल पर सभी श्रमिकों के पंजीकरण (आधार कार्ड के साथ) को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए अनिवार्य करते हैं। पंजीकरण करने में विफलता (आधार-विशेष बहिष्करण या प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव) तो लाभ के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा, प्रवासी श्रमिकों को नियमित अंतराल पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अद्यतन करने की चुनौती का सामना करना पड़ता सकता है
- **लाभों की प्रयोज्यता पर अस्पष्टता:** यह स्पष्ट नहीं है कि एक प्रवासी श्रमिक जिसके पास उसके / उसके गृह राज्य बिहार में पंजीकृत है, वह गुजरात में सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र है जहाँ वह वर्तमान में कार्यरत है।
- **नो-राइट बेस्ड फ्रेमवर्क:** कोड सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में महत्व नहीं देता है, न ही यह संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार इसका अनुबद्ध करता है। इसके अलावा, यह किसी भी उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र को निर्धारित नहीं करता है जो लाखों श्रमिकों को स्पष्ट सामाजिक सुरक्षा के बिना असुरक्षित छोड़ दे।

भारतीय श्रमिकों पर ILO रिपोर्ट

- हाल ही में 'ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21: COVID-19 के समय में मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी जारी की गई थी।
- **द्वारा जारी:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

महत्वपूर्ण तथ्य

- रिपोर्ट में भारतीय कामगारों पर कम औसत मजदूरी, लंबे समय सहित विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी की गई।
- इसने यह भी बताया कि एशिया और प्रशांत में श्रमिकों ने 2006-1919 की अवधि में सभी क्षेत्रों में उच्चतम वास्तविक मजदूरी वृद्धि का आनंद लिया।
- रिपोर्ट में राष्ट्रीय तल स्तर न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा गया है जो प्रति दिन 76/ - रु है। हालांकि, वास्तविक मजदूरी कहीं अधिक है।
- यदि विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी का औसत निकाला जाता है, तो यह भारत में रु .69 / - प्रतिदिन होगा।

क्या आप जानते हैं?

कोडन वेज्स, 2019

- यह संगठित या असंगठित क्षेत्र में सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक अधिकार बनाता है।
- संहिता पर मजदूरी में वैधानिक तल मजदूरी की एक नई अवधारणा भी पेश की गई है।
- संहिता यह भी प्रदान करती है कि न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जानी चाहिए और पांच वर्षों से अधिक के अंतराल में उपयुक्त सरकारों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा पर कोड की परिकल्पना भारत में बड़ी संख्या में अनौपचारिक श्रमिकों के लिए एक कानूनी सुरक्षात्मक उपाय के रूप में की गई थी, लेकिन जब तक कि श्रम कोड नहीं बना कर लागू नहीं किए जाते, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, असमानता की खाई को भरना असंभव हो जाएगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- गिग वर्कर्स और उनकी चुनौतियां
- गिग इकॉनमी और यूएसए का प्रस्ताव -22

बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) या संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में बांड पर बढ़ती पैदावार ने शेयर बाजारों, सोने जैसी अन्य परिसंपत्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई है।
- हाल ही में भारत में 10 साल के बॉन्ड पर उपज 5.76% के निचले स्तर से बढ़कर 6.20% हो गई, जो कि अमेरिकी शुरुआत में वृद्धि के साथ है विदित हो कि यह शेयर बाजार के माध्यम से चिंता को बढ़ा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक उस बॉन्ड या एक विशेष जी-सेक पर प्राप्त है।
- उपज को प्रभावित करने वाले कारक: आरबीआई की मौद्रिक नीति (ब्याज दरें), सरकार की राजकोषीय स्थिति और इसके उधार कार्यक्रम, वैश्विक बाजार, अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति।
- ब्याज दरों में गिरावट से बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है।

- ब्याज दरें बढ़ने से बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं।
- अर्थात बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का मतलब है कि मौद्रिक प्रणाली में ब्याज दरें गिर गई हैं और निवेशकों के लिए रिटर्न में गिरावट आई है।

चन्नपटना शहर के बने खिलौने

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III- जीआई टैग; अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में चन्नपटना खिलौना निर्माता सुर्खिओ में थे।

अन्य संबंधित तथ्य

- चन्नपटना कर्नाटक, भारत का एक शहर है।
- यह शहर अपने लकड़ी और लाख से बने खिलौने के लिए प्रसिद्ध है।
- चन्नपटना को टाउन ऑफ़ टॉयज (गोमबेगला नगारा) भी कहा जाता है।
- खिलौनों की उत्पत्ति टीपू सुल्तान के शासनकाल में हुई है।
- इन खिलौनों को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया।

संबंधित आलेख:

- जीआई टैग क्या है?
- जीआई टैग एसटी उद्यमियों को कामयाब होने में मदद करता है।

नगर निगम का बजट

संदर्भ: केंद्रीय बजट और राज्य बजट ध्यान और व्यापक प्रेस कवरेज प्राप्त करते हैं जो नगर निगम के बजट के मामले में नहीं है।

आम आदमी के लिए नगर निगम का बजट क्यों मायने रखता है?

- **प्रभाव बड़ी संख्या में लोग:** एक चौंका देने वाला 4,500+ नगरपालिका जिसमें 300 मिलियन से अधिक लोग हर साल बजट सत्र के दौरान अपने बजट पेश करते हैं।
- **प्रतिदिन के मामलों को लेकर चिंता:** नगर निगम के बजट में साफ हवा, पीने का शुद्ध पानी, कूड़े को ठीक से साफ करना और समय पर घर और सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सुथरे शौचालयों तक पहुंच, अपशिष्ट जल उपचार और सुरक्षित निपटान, बच्चों और बूढ़े-बुजुर्ग सार्वजनिक स्थानों आदि से संबंधित हैं ।
- **पर्याप्त वित्तीय संसाधन:** हमारे पास अभी तक सटीक आंकड़े नहीं हैं, अनुमान है कि एक साथ लिए गए इन 4,500+ शहर के बजट में सालाना 1,50,000-1,80,000 करोड़ रुपये की राशि मिलती है।

नगर निगम के बजट के साथ चुनौती

- **नागरिक भागीदारी में कमी:** अधिकांश नगरपालिका कानून नागरिक कार्यों में नागरिक भागीदारी या नागरिक कार्यों और निविदाओं में पारदर्शिता नहीं दिखाते करते हैं
- **नॉट पीपुल फ्रेंडली:** बजट दस्तावेज स्वयं को एक औसत नागरिक के लिए पढ़ना और समझना आसान नहीं है
- **पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा:** शहर में व्यापक व्यय विकास प्राधिकरणों, परिवहन निगमों और जल आपूर्ति बोर्डों जैसी अर्धसैनिक एजेंसियों के माध्यम से होता है, जिनके अलग-अलग बजट होते हैं जिनकी नगर परिषद में कभी चर्चा नहीं होती है या मीडिया में कवर नहीं किया जाता है।

भागीदारी बजट क्या है?

- "पार्टिसिपेटरी बजटिंग" एक अवधारणा है जिसे ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे में 1980 के दशक के मध्य में चलाया गया था। अब यह विश्व भर के हजारों शहरों में एक-दूसरे रूप में प्रचलित है।
- भागीदारी बजट (पीबी) लोकतांत्रिक विचार-विमर्श और निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, जिसमें आम लोग तय करते हैं कि कैसे एक नगरपालिका या सार्वजनिक बजट का हिस्सा आवंटित किया जाए।
- हाल ही में 2015 में शुरू किया गया MyCityMyBudget अभियान, बेंगलुरु, मंगलुरु और विशाखापत्तनम, संबंधित नगर निगमों, पड़ोस समुदायों और जनग्रह के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में।
- इन शहरों में, नागरिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 350 से अधिक वार्डों में 80,000 से अधिक नागरिकों से 85,000 से अधिक बजट इनपुट प्राप्त हुए हैं। इन इनपुटों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें शहर के बजट में शामिल किया जाएगा।

सहभागी बजट के गुण

- **उत्तरदायी शासन की ओर पहला कदम:** यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी प्रणाली में, बजट आवंटित करना किसी भी कार्य को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है।
- **स्थानीय समाधान:** यह बजट और समस्या-समाधान पर लक्षित, हाइपरलोकल फोकस की सुविधा प्रदान करता है।
- **राजनीतिक और सार्वजनिक विश्वाश को बढ़ाना:** यह नागरिकों को यह महसूस कराता है कि उनके पास नागरिक प्रशासन में एक आवाज है और इससे विश्वास उत्पन्न होता है
- **दक्षता में सुधार:** यह नागरिक आवश्यकताओं के सापेक्ष नागरिक कार्यों के गलत प्राथमिकता से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को संबोधित करता है।
- **जवाबदेही बढ़ी:** अंत में, यह अंतिम मील पर नागरिक कार्यों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है (जैसा कि नागरिक बजट निष्पादन की निगरानी करेंगे)।
- **समावेशी शासन:** बच्चे, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, अलग-अलग अभिभावक और कई रुचि समूह सीधे प्रतिनिधित्व के माध्यम से नगर बजट में अपने कारणों और आकांक्षाओं के लिए एक मामला बनाने में सक्षम होंगे और उन्हें पूरा किया जाएगा
- **परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव में मदद करता है:** यह नागरिक संपत्ति और सुविधाओं के लिए समुदायों में अधिक से अधिक स्वामित्व को बढ़ावा देगा, जिससे बेहतर रखरखाव होगा। स्थानीय स्तर पर, यह समुदायों, निर्वाचित पार्षदों और शहर प्रशासन के लिए एक जीत है।
- **जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना:** केंद्रीय बजट के विपरीत, नगरपालिका का बजट केवल एक वित्तीय या कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह शहरों में घास की जड़ों के लोकतंत्र और समुदायों विशेषकर बच्चों, महिलाओं और शहरी गरीबों के लिए ठोस परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है।

निष्कर्ष

- हमें गली, मोहल्ले और वार्ड स्तर पर वास्तविक परिवर्तन के साधन बनने के लिए नगर निगम के बजट पर नागरिक सहभागिता और मीडिया जुड़ाव की अधिक आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- 73 वां और 74 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

CAFE विनियम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - तृतीय - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के कार्मिकों ने सड़क परिवहन के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है कि BS-VI के CAF चरण (II) नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि उद्योग अभी भी COVID के प्रभाव से ठीक हो रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CAFE (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) नियम BS VI के समान नियम हैं।
- हालांकि, वाहन के निकास गैसों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में इसका एक अलग तरीका है।
- CAFE प्रमुख रूप से COx उत्सर्जन पर केंद्रित है।
- जबकि, BS VI समग्र उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें NOx (नाइट्रोजन ऑक्साइड), SOx (सल्फर ऑक्साइड) शामिल हैं।
- सीएएफई नियमों का उद्देश्य: वाहन के निकास से समग्र सीओएक्स (कार्बन ऑक्साइड) को कम करना।
- कम कार्बन फुटप्रिंट ईंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है।
- इन नियमों को भारत में पहली बार अप्रैल 2017 को BS4 निकास उत्सर्जन मानदंडों के साथ लागू किया गया था।

'मर्चेंट डिजिटाइज़ेशन सम्मेलन 2021: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; आईटी

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021: आत्मनिर्भर भारत (सेल्फ रिलायंस) भारत को आयोजित किया गया था।
- **मेजबान:** भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और 'बेटर दैन कैश अलायंस' (UN-based Better Than Cash Alliance) द्वारा ।
- **विशेष ध्यान:** हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र और भारत के आकांक्षी जिले।

अन्य संबंधित तथ्य

कैश अलायंस से बेहतर

- संयुक्त राष्ट्र के आधार पर।
- यह सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की साझेदारी है।
- यह नकदी से डिजिटल भुगतान को बढ़ाता है।
- इसके 75 सदस्य हैं।
- एलायंस सचिवालय सदस्यों के साथ भुगतान को डिजिटाइज़ करने के लिए काम करता है:
  1. उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।
  2. जिम्मेदार अभ्यासों पर क्रिया-उन्मुख अनुसंधान और सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देना।
  3. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सिफारिश का संचालन करना।
- इसका गठन वर्ष 2012 में किया गया था।
- द्वारा शुरू किया गया: इसे यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडयार नेटवर्क तथा वीज़ा इंक।

संबंधित आलेख:

- ARISE - अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया
- आत्मानिर्भर भारत 3.0

कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ER & D) नीति कर्नाटक द्वारा शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में कर्नाटक के योगदान को 45% तक बढ़ाना।

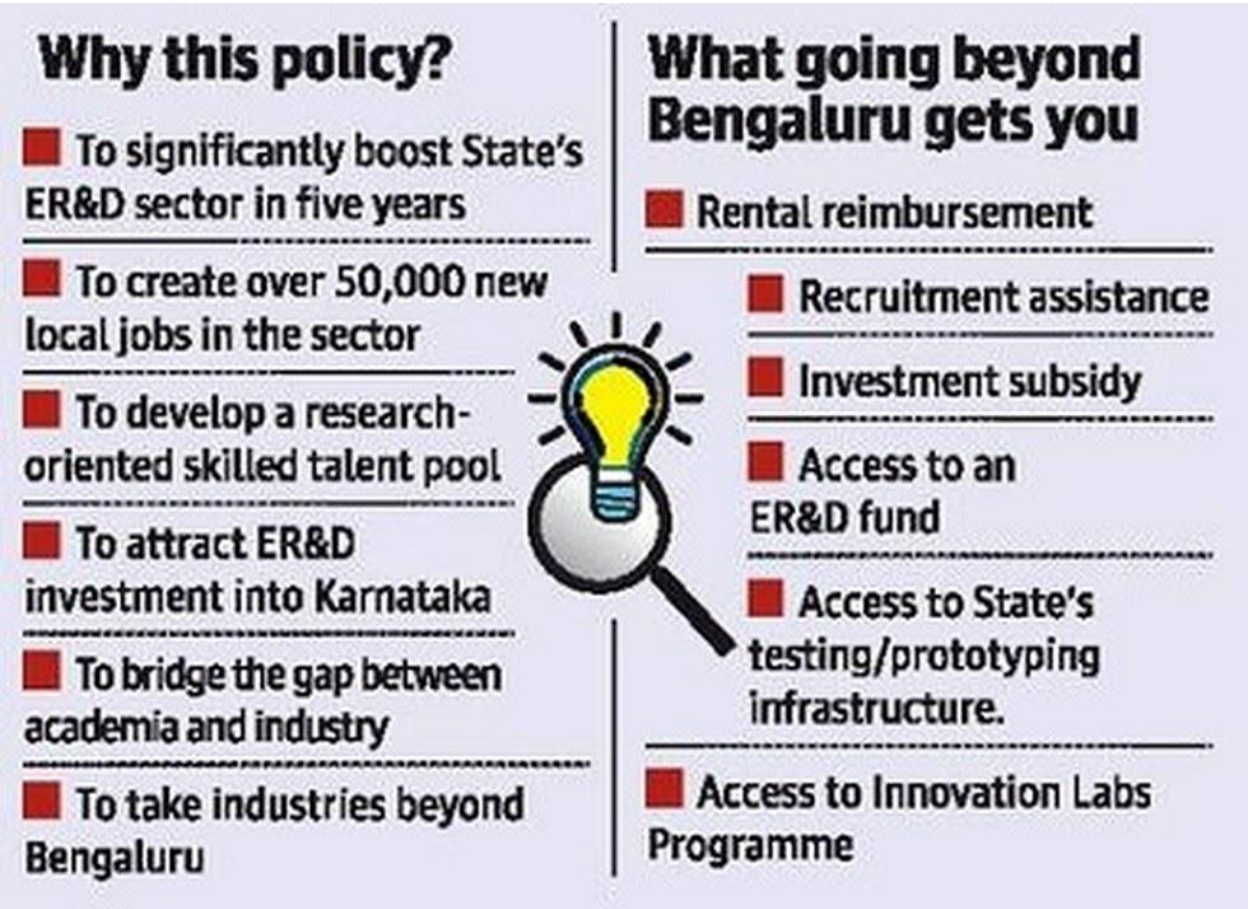

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि नीति में ER & D क्षेत्र में पाँच वर्षों में 50,000 से अधिक नौकरियाँ सृजित करने की क्षमता है।
- ER & D में अगले पांच वर्षों में भारत में $ 100 बिलियन का उद्योग बनने की क्षमता है।
- यह क्षेत्र 12.8% की CAGR के साथ भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है।
- वैश्विक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास उद्योग भी 2025 तक $ 2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

- **पांच प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र:** एयरोस्पेस और रक्षा; ऑटो, ऑटो घटकों और ईवी; जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा और चिकित्सा उपकरण; अर्धचालक, दूरसंचार, ईएसडीएम; और सॉफ्टवेयर उत्पादों।

केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; कर लगाना

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (Central Revenues Control Laboratory), नई दिल्ली को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organisation) की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला (Regional Customs Laboratory) के रूप में मान्यता दी गई।

अन्य संबंधित तथ्य

केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL)

- CRCL केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- CRCL की स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी।
- RCL के रूप में अपनी मान्यता के साथ, CRCL जापान और कोरिया जैसे क्षेत्र में सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया।

विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)

- 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के रूप में स्थापित हुआ
- यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है
- **विशेष कार्य:** सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए
- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स, बेल्जियम।

निजीकरण (Privatization)

स्वतंत्रता के समय, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया। इस संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSEs) विकास के एक समाजवादी पैटर्न पर स्थापित किए गए।

हालांकि, कई सार्वजनिक उपक्रमों के खराब प्रदर्शन और परिणामस्वरूप भारी वित्तीय घाटे के कारण, निजीकरण का मुद्दा सबसे आगे आया।

भारत में, निजीकरण को दो उपायों के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाती है:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश (निजी क्षेत्र को सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना)
- अब तक निजी भागीदारी के लिए बंद क्षेत्रों का उद्घाटन।

निजीकरण और विनिवेश की योग्यता

- सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता में सुधार करता है
- विदेशी निवेश आकर्षित करता है
- सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय अनुशासन में सुधार
- सार्वजनिक उपक्रमों के आधुनिकीकरण की सुविधा
- PSUs को बनाए रखने में सरकार पर राजकोषीय बोझ को कम करता है

- बाजार के लिए संकेत है कि सरकार मुक्त बाजार सिद्धांत को बढ़ावा दे रही है

आलोचना

सामाजिक न्याय

- निजीकरण की नीति सामाजिक न्याय को धोखा देती है।
- पीएसयू ने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
- महत्वपूर्ण रूप से, आरक्षण के माध्यम से, पीएसयू ने दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को सुनिश्चित किया।
- एक बार सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या 50% से कम सरकारी स्वामित्व का विनिवेश हो जाने के बाद, इन ऐतिहासिक रूप से अधिकारहीन वर्गों के लिए आरक्षण इतिहास बन जाएगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को इस बात से वंचित करना होगा कि अनिवार्य रूप से किस प्रकार के छंटनी का सामना करना पड़ेगा।

बैंकों

- यस बैंक और अन्य निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ भारत का अनुभव शायद ही बताता है कि निजीकरण बैंकिंग में लालच और भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा।
- यह राष्ट्रीयकृत बैंकों का लचीलापन था जिसने 2008-09 में वैश्विक मंदी के सबसे बुरे प्रभावों से हमें बचाने में मदद की।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी पिछले पांच दशकों में भारत में असंबद्ध के लिए वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए मध्य रहे हैं
- ग्रामीण शाखाएँ जो मुनाफे पैदा करने से ज्यादा एक सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा करती हैं, संभवतः कॉर्पोरेट्स द्वारा बंद कर दी जाएंगी।

निष्कर्ष

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निजीकरण की नीतियों को फेरबदल करते समय उसके कल्याण एजेंडे को नजरअंदाज नहीं किया जाए।

स्पेक्ट्रम नीलामी

संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने पांच साल में दूरसंचार स्पेक्ट्रम की अपनी पहली नीलामी का समापन किया, जिससे इस अभ्यास से 77,815 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

नीलामी के प्रमुख परिणाम

- रिलायंस जियो के पास खरीदे गए स्पेक्ट्रम के करीब 60% हिस्से हैं, इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हैं
- प्रस्ताव पर सरकार द्वारा नीलामी के लिए 8 3.92 लाख करोड़ के लागत के रेडियो तरंगों के स्पेक्ट्रम का 2,308 मेगाहर्ट्ज़ (मेगाहर्ट्ज) मूल्य से अधिक था और 37% या 855.6 मेगाहर्ट्ज के लिए बोलियां सफलतापूर्वक लगी।

आखिरी नीलामी के बाद से उद्योग कैसा है?

- **2016 में अधिक प्रतिस्पर्धी:** 2016 की नीलामी के दौरान प्रतिभागियों में टाटा टेलीसर्विसेज, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल शामिल थे।
- **सेक्टर का एकत्रीकरण:** पिछले कुछ वर्षों में, उद्योग का एकत्रीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अब केवल तीन प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं - रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया।

- **एकाधिकार की ओर बढ़ रहा है:** रिलायंस जियो, भारती एयरटेल ने अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर, उद्योग को "लगभग दो-प्रतिभागी संरचना" की ओर आकार दे रहे हैं। दूसरी तरफ , वोडाफोन तथा आइडिया आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे है।
- **सेक्टर में वित्तीय तनाव:** हाल के वर्षों में, जब उपयोगकर्ता का आधार जब बड़ा हो गया है, तो उद्योग ने स्वयं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अदालत के मामले के रूप में अप्रत्याशित वित्तीय तनाव देखा है अर्थात समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue) मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

अब एक नीलामी की आवश्यकता क्यों थी?

- सभी तीन प्रतिभागी को अपने कुछ स्पेक्ट्रम को नवीनीकृत करने की आवश्यकता थी क्योंकि वैधता इस साल के अंत में समाप्त होने के लिए निर्धारित की गई।

यह 5G रोलआउट के लिए नहीं था?

- नहीं। नीलामी बाद में होने की संभावना है। 1 और 2 मार्च को हुई नीलामी में, सरकार ने निम्नलिखित बैंड में 4 जी के लिए स्पेक्ट्रम की पेशकश की: 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज, 2,300 मेगाहर्ट्ज और 2,500 मेगाहर्ट्ज।

ये बैंड किस लिए रहते हैं?

- इसे समझाने के लिए, हमें 'स्पेक्ट्रम' शब्द से शुरू करना होगा, जो इस संदर्भ में, विद्युत चुम्बकीय तरंग सीमा के उस हिस्से के लिए है जो संचार उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि यह एक विशाल आर्थिक संसाधन है, जो किसी भी आबादी को अकल्पनीय लाभ प्रदान करता है, यह सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- स्पेक्ट्रम बैंड की अलग-अलग विशेषताएं हैं और यह उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- सामान्य तौर पर, कम आवृत्ति वाले प्रसारण अपनी समग्रता खोने से पहले अधिक दूरी की यात्रा कर सकते हैं, और वे घने कारकों से अधिक आसानी से गुजर सकते हैं। हालाँकि इन रेडियो तरंगों पर कम डेटा प्रसारित किया जाता है।
- उच्च-आवृत्ति प्रसारण अधिक डेटा लेते हैं, लेकिन तीव्र बाधाओं पर खराब हो जाते हैं।
- इस संदर्भ में, हर्ट्ज प्रति सेकंड चक्र की संख्या का एक माप है और 1 मेगाहर्ट्ज़ 1 मिलियन फ़ुट्ज़ के लिए है। दूरसंचार प्रदाता कम और उच्च आवृत्ति बैंड दोनों का उपयोग करके अपने स्थानों को कवर करते हैं।

700 मेगाहर्ट्ज बैंड के पास कोई लेने वाला क्यों नहीं था?

- 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, साथ ही 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज और 2,300 मेगाहर्ट्ज बैंड , 5 जी रोलआउट (मोबाइल नेटवर्क की पांचवीं पीढ़ी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो हर किसी को बहुत तेजी और कम विलंबता के रूप में भी जोड़ते है।)
- 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को इसकी निषेधात्मक बेस मूल्य को देखते हुए किसी को भी लेने की उम्मीद नहीं थी।
- कुछ इसे सरकार द्वारा भविष्य में बोली लगाने के लिए आरक्षित मूल्य को कम करने के लिए शुरुआत के रूप में देखते हैं। इसके अलावा, 5G में "राजा", सी-बैंड जो 3,300 मेगाहर्ट्ज और 4,200 मेगाहर्ट्ज के बीच का बैंड है, नीलामी के दौरान प्रस्ताव पर नहीं था।

इस नीलामी की तुलना पिछले दौर से कैसे की गई?

- 2016 में, 2,355 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का लगभग 40% (5.6 लाख करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर) बेचा गया, जिससे सरकार को राजस्व में 65,789 करोड़ मिले। इस बार, केंद्र अधिक पाने में कामयाब रहा है।
- सरकार ने कहा कि नीलामी से उत्पन्न राजस्व उसकी अपेक्षाओं से अधिक है, जो लगभग 45,000 करोड़ उत्पन्न हुआ था।

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी और इस तथ्य के कारण उम्मीदें कम थीं कि शीर्ष तीन दूरसंचार प्रतिभागी स्पेक्ट्रम को समाप्त करने और चुनिंदा बैंड में सम्पत्ति को मजबूत करने के लिए देख रहे थे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- 2020 नीलामी सिद्धांत पर अर्थशास्त्र पुरस्कार

AT1 बॉन्ड: SEBI न्यू नॉर्म्स

संदर्भ: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के म्यूचुअल फंड (एमएफ) निवेश पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से एडिशनल टियर -1 (एटी 1) बॉन्ड में एमएफ और बैंकिंग क्षेत्रों में तहलका मचा दिया है।

वित्त मंत्रालय ने नियामक से उन बदलावों को वापस लेने को कहा है क्योंकि इससे म्यूचुअल फंडों के निवेश और बैंकों के फंड जुटाने की योजना में व्यवधान पैदा हो सकता है।

AT1 बांड क्या हैं? इन बॉन्ड में कुल कितना बकाया है?

- एटी 1 बॉन्ड एडिशनल टियर -1 बॉन्ड के लिए स्थिर है।
- ये असुरक्षित बॉन्ड हैं जिनका स्थायी कार्यकाल है। दूसरे शब्दों में, बांड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं है।
- उनके पास कॉल विकल्प है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा निवेशकों से वापस इन बांडों को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
- इन बांडों का उपयोग आम तौर पर बैंकों द्वारा अपने कोर या टियर -1 पूंजी को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- एटी 1 बॉन्ड अन्य सभी ऋणों के अधीनस्थ हैं और केवल सामान्य इक्विटी से पुराने हैं।
- म्युचुअल फंड (म्यूचुअल फंड) स्थायी ऋण साधनों में सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं और 90,000 करोड़ रुपये के बकाया एडिशनल टियर- I बॉन्ड जारी करने के 35,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं।

हाल ही में सेबी द्वारा क्या और क्यों कार्रवाई की गई है?

- **100 साल का विकल्प :** हाल के एक परिपत्र में, सेबी ने म्यूचुअल फंड को 100 साल के विकल्प के रूप में इन सतत बांडों को महत्व देने के लिए कहा। अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि एमएफ को यह धारणा बनानी होगी कि इन बांडों को 100 वर्षों में भुनाया जाएगा।
- **सीमा स्वामित्व:** नियामक ने भी किसी योजना की परिसंपत्तियों के 10 प्रतिशत पर बॉन्ड के स्वामित्व को सीमित करने के लिए म्यूचुअल फंड को कहा।
- **यस बैंक क्राइसिस के साथ संबंध:** सेबी के अनुसार, ये उपकरण अन्य ऋण साधनों की तुलना में जोखिम भरा हो सकता है। सेबी ने संभवत: यह निर्णय एसबीआई द्वारा जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा यस बैंक लिमिटेड द्वारा बताये गए एटी -1 बांड पर 8,400 करोड़ रुपये के राइट-ऑफ की अनुमति देने के बाद किया है।

इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है?

- **बढ़ा हुआ जोखिम:** आमतौर पर, MF ने AT1 बांड पर कॉल विकल्प की तारीख को परिपक्वता तिथि के रूप में माना है। तथा इन बांडों को 100-वर्ष के बांड के रूप में माना जाता है और इन बांडों में जोखिम होता है क्योंकि ये अधिक दीर्घकालिक होते हैं।
- **बॉन्ड की कीमतों में अस्थिरता को बढ़ाता है:** इससे इन बॉन्डों की कीमतों में अस्थिरता होती है क्योंकि इन खतरों से बॉन्डों की वृद्धि बढ़ जाती है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की कीमतें विपरीत दिशाओं में रहती हैं इसलिए, उच्च उपज बॉन्ड की कीमत को नीचे हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप इन बॉन्डों को रखने वाले एमएफ योजनाओं के सही संपत्ति मूल्य में कमी आती है।

- **पैनिक सेलिंग में संलग्न होने के लिए एमएफ को ज़ोर दे :** इसके अलावा, ये बॉन्ड स्पष्ट नहीं हैं और एमएफ के लिए छूटने के दबाव को पूरा करने के लिए इन्हें बेचना मुश्किल होगा। इस नए नियम के कारण संभावित छूट के कारण म्यूचुअल फंड हाउसों को द्वितीयक बाजार में बॉन्ड्स की घबराहट में उलझाने से उपज बढ़ेगी।
- **बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर प्रभाव:** एटी-1 बांड राज्य के बैंकों के लिए पसंद के पूंजी साधन के रूप में उभरा है क्योंकि वे पूंजी अनुपात को हटाने प्रयास करते हैं। यदि इस तरह के बॉन्ड में म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश पर प्रतिबंध हैं, तो बैंकों को उस समय पूंजी जुटाने में मुश्किल होगी जब उन्हें खराब संपत्ति के मद्देनजर धन की आवश्यकता होगी।

वित्त मंत्रालय ने सेबी को फैसले की समीक्षा करने के लिए क्यों कहा है?

- वित्त मंत्रालय ने म्यूचुअल फंड हाउसों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित AT1 बॉन्ड के लिए वैल्यूएशन मानदंड वापस लेने की मांग की है क्योंकि इससे म्यूचुअल फंड को नुकसान हो सकता है और इन बॉन्ड्स से बाहर निकलकर, PSU बैंकों की पूंजी जुटाने की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
- सरकार ऐसे समय में बैंकों के कोष जुटाने की कवायद में व्यवधान नहीं चाहती जब दो पीएसयू बैंक निजीकरण के खंड में हों।
- बैंकों को अभी तक वित्त वर्ष 21 में प्रस्तावित पूंजी अन्तःक्षेपण प्राप्त करना बाकी है, हालांकि उन्हें भविष्य में संभावित गुणवत्ता की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

केयर्न कर शासन

संदर्भ: दिसंबर 2020 में, नीदरलैंड स्थित स्थायी न्यायालय में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने ब्रिटेन स्थित तेल और गैस कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी और एक सहायक, केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया। नीदरलैंड के पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को कंपनी को लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।

केयर्न द्वारा कार्रवाई:

- केयर्न एनर्जी ने मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार अपने दावे को मान्यता देने के लिए पांच देशों- नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में सफलतापूर्वक अदालतों का रुख किया है।
- अदालतों द्वारा इस तरह की मान्यता केयर्न एनर्जी के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार की संपत्ति का दावा करने के लिए अपने दावे को लागू करने का रास्ता बताती है, यदि बाद में अपना बकाया भुगतान नहीं किया।

मामला क्या है?

- वर्ष 2006-07 के संदर्भ में , एक बड़ा कॉर्पोरेट परिवर्तन और विकास केयर्न एनर्जी में हुआ।
- यह वह वर्ष था जिसमें इसने न केवल एक कॉर्पोरेट पुनर्गठन का काम किया, बल्कि एक भारतीय सहायक कंपनी, केयर्न इंडिया भी शुरू की, जो 2007 की शुरुआत में भारतीय सीमाओं पर सूचीबद्ध हुई।
- कॉरपोरेट पुनर्गठन प्रक्रिया के माध्यम से, केयर्न एनर्जी ने अपनी भारत की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित कर दिया, जो तब तक विभिन्न देशों में नौ सहायक कंपनियों द्वारा नवगठित केयर्न इंडिया को हस्तांतरित किया गया था।
- लेकिन कर अधिकारियों ने दावा किया कि इस पुनर्गठन की प्रक्रिया में केयर्न एनर्जी ने 24,500 करोड़ का पूंजीगत लाभ कमाया। विभाग ने दावा किया, 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की कर मांग का आधार था।
- 2011 में, यू.के. आधारित वेदांत संसाधन ने केयर्न इंडिया में लगभग 60% हिस्सेदारी खरीदी। वास्तव में, इसके चार साल बाद, केयर्न इंडिया को अपनी पूर्व मूल कंपनी को प्राप्त लाभ के लिए कर नहीं हटाने के लिए एक कर नोटिस मिला हुआ।

केयर्न ऊर्जा विवाद में कर के दावों के बाद क्या हुआ?

- कर अधिकारियों से एक मसौदा मूल्यांकन आदेश प्राप्त करने के बाद, केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की।हालांकि, अधिकरण ने कंपनी को बैक डेट की ब्याज मांगों से राहत प्रदान करते हुए मुख्य कर मांग को बरकरार रखा।
- कंपनी ने यू.के.-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत बीच की कार्यवाही शुरू की।
- लेकिन इस समय के दौरान, "सरकार ने केयर्न की वेदांता लिमिटेड में लगभग 5% हिस्सेदारी बेची" (केयर्न इंडिया को बेचने के बाद मालिकाना हक़ रखने वाली कंपनी), "उन लोगों की रोक से कुल 1,140 करोड़ का लाभांश जब्त" और "सेट ऑफ" मांग के विरुद्ध ”1,590 करोड़ का कर को लौटाया

मध्यस्थता के दौरान केयर्न एनर्जी का मुख्य तर्क क्या था?

- केयर्न एनर्जी और केयर्न यूके होल्डिंग्स के दावेदारों ने तर्क दिया कि जब तक 2012 में कर पूर्वव्यापी कर में संशोधन नहीं किया गया, तब तक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण (गैर-भारतीय कंपनियों में शेयरों के एक अनिवासी द्वारा हस्तांतरण) पर कोई कर नहीं होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संपत्ति रखते थे।)
- उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 2006 के पुनर्गठन को मंजूरी दी।
- 2012 के संशोधनों के आवेदन, उन्होंने आरोप लगाया, यू.के.-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रकट उल्लंघनों का गठन किया।

मध्यस्थता के दौरान भारत की रक्षा क्या थी?

- केयर्न एनर्जी के मुख्य प्रभार के लिए भारत का विरोध यह था कि इसके 2006 के लेनदेन 2012 के संशोधनों के बावजूद कर योग्य थे।
- यह तर्क दिया गया कि "भारतीय कानून ने लंबे समय तक कराधान की अनुमति दी है जहां एक लेनदेन में भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक गठजोड़ है"।
- इसने कहा कि भले ही यह पूर्वव्यापी है, यह "संवैधानिक, विधायी और कानूनी ढांचे को लागू करने वाला वैध और बाध्यकारी है जिसमें दावेदारों ने निवेश किया है"।

पंचाट न्यायाधिकरण ने क्या नियम बनाए?

- ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर की मांग ने यू.के.-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते के तहत केयर्न एनर्जी के निवेश को उचित और न्यायसंगत उपचार में विफल रहा।
- इसने संधि के उल्लंघनों के परिणामस्वरूप भारत को केयर्न एनर्जी और इसकी सहायक कंपनी को "कुल नुकसान का सामना" करने की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।

आगे की राह

- मीडिया में यह बताया गया है कि भारत ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वोडाफोन केस

नई अम्ब्रेला इकाई (NUE)

संदर्भ: RBI ने नई अम्ब्रेला इकाई (NUE) के लिए फर्मों का 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है।

NUE क्या हैं?

- जैसा कि आरबीआई द्वारा परिकल्पित किया गया है, एक NUE एक गैर-लाभकारी इकाई होगी, जो नए भुगतान प्रणालियों को स्थापित, प्रबंधित और संचालित करेगी, विशेष रूप से खुदरा स्थान जैसे एटीएम, व्हाइट-लेबल पीओएस में; आधार-आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाएं।
- NUE को भुगतान प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे विकासात्मक उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए।
- NUE को क्लीयरिंग और सेटलमेंट सिस्टम में काम करना चाहिए और निपटान, ऋण, तरलता और परिचालन जैसे प्रासंगिक जोखिमों की पहचान एवं प्रबंधन और सिस्टम की अखंडता को बनाए रखना तथा खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास की निगरानी करना।
- इसके अलावा, वे नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे और साथ ही क्लियरिंग और निपटान प्रणाली भी संचालित करेंगे।
- NUE देश में खुदरा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए उपयुक्त किसी अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के लिए एक वैकल्पिक तंत्र बनाने के लिए एक विचार है।

कौन से प्रतिभागी NUE सेट करने की योजना बना रहे हैं?

- भुगतान सेगमेंट में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव वाले भारतीय नागरिकों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जाने वाली केवल वे संस्थाएँ ही NUE के प्रवर्तक बन सकती हैं
- जब तक वे मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, तब तक NUE में विदेशी निवेश की अनुमति है।
- कई कंपनियों ने NUE आवेदन करने के लिए बैंकों या प्रमुख तकनीकी प्रतिभागिओ को जोड़ लिया है।

NUE की क्या आवश्यकता है?

- वर्तमान में, खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करने के लिए नई अम्ब्रेला इकाई है, जो बैंकों द्वारा स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी इकाई है।
- एनपीसीआई निपटान प्रणाली जैसे कि UPI, AEPS, RuPay, Fastag आदि का संचालन करती है।
- भुगतान स्थान के प्रतिभागिओ ने एनपीसीआई के विभिन्न नुकसानों को इंगित किया है जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने वाली एकमात्र इकाई है।
- भुगतान प्रणाली के लिए अन्य संगठनों को नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने की अनुमति देने के लिए आरबीआई की योजना इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का विस्तार करना है।
- इन NUE को स्थापित करने की योजना बना रहे प्रतिभागिओ का उद्देश्य डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करना है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- UPI- भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति

जिलावार निर्यात प्रोत्साहन योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- सरकार ने ऐसे उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने के बाद 451 जिलों के लिए जिलेवार निर्यात प्रोत्साहन योजना का मसौदा जारी किया है, जिनकी निर्यात क्षमता है

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार ने 3-5 वर्षों में 500 जिलों से दोहरे अंकों के निर्यात विकास का लक्ष्य रखा है।
- राज्यों को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की सहायता से निर्यात प्रतिस्पर्धा पर जिलों का वार्षिक) निर्यात रैंकिंग सूचकांक तैयार करने के लिए कहा।
- जबकि विदेशी व्यापार भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 45% है, निर्यात के अधिकांश प्रयास केंद्र द्वारा संचालित हैं।
- जिला-विशिष्ट दृष्टिकोण में राज्यों को संभावित निर्यात क्षेत्रों की पहचान करना और लॉजिस्टिक की बाधाए शामिल हैं
- प्रारंभिक चरण में, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है और निर्यात बढ़ने के लिए एक कार्य योजना के साथ राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (SEPC) का एक संस्थागत तंत्र बनाया जा रहा है।
- जिला निर्यात संवर्धन समितियों को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के जिलों में अधिसूचित किया गया है।

वर्ल्ड समिट आन द इनफार्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने वर्ल्ड समिट आन द इनफार्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम 2021 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रमुख कार्यक्रम BharatNet के तहत, लगभग 6,00,000 गाँवों को 4,00,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और उपग्रह संचार सेवाओं के उपयोग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।
- पनडुब्बी केबल नेटवर्कों के माध्यम से अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप और अन्य दुर्गम क्षेत्रों के छोटे और दूरदराज के द्वीपों को सरकार से वित्त पोषण के साथ जोड़ा जा रहा है।
- इस क्षेत्र में SMEs, एकेडेमिया और स्टार्टअप्स की भागीदारी के साथ भारत में ITU एरिया कार्यालय और इनोवेशन सेंटर की स्थापना, विकासशील देशों के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम रूप से प्रौद्योगिकियों, मानकों और समाधानों के विकास में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

वर्ल्ड समिट आन द इनफार्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम 2021 के बारे में

- WSIS फोरम 'ICT फार डेवलपमेंट' समुदाय की वार्षिक सभा में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
- **द्वारा आयोजित:** अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), UNESCO, UNDP और UNCTAD

डिजिटल रूप से MSMEs को सशक्त बनाना

संदर्भ: भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान विनिर्माण क्षेत्र का होना है। प्रभावी ढंग से सुविधा प्रदान करने वाली छोटी इकाइयों, कुटीर इकाइयों और एसएमई द्वारा विनिर्माण, गेम चेंजर होगा।

Existing and Revised Definition of MSMEs

Existing MSME Classification			
Criteria : Investment in Plant & Machinery or Equipment			
Classification	Micro	Small	Medium
Mfg. Enterprises	Investment<Rs. 25 lac	Investment<Rs. 5 cr.	Investment <Rs. 10 cr.
Services Enterprise	Investment<Rs. 10 lac	Investment< Rs. 2 cr.	Investment<Rs. 5 cr.

Revised MSME Classification			
Composite Criteria : Investment And Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment< Rs. 1 cr. and Turnover < Rs.5 cr.	Investment< Rs. 10 cr. and Turnover < Rs.50 cr.	Investment< Rs. 20 cr. and Turnover < Rs.100 cr.

एमएसएमई के लाभ

- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** भारत में लगभग 6.3 करोड़ MSME देश के सकल घरेलू उत्पाद एक तिहाई का योगदान करता हैं
- **समाज के बड़े वर्गों के लिए आजीविका:** MSME क्षेत्र आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और लगभग 110 मिलियन रोजगार देता है
- **क्षेत्रीय संतुलित विकास:** MSME मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 51% भारतीय एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित हैं।
- **सरकार की विशाल क्षमता और फोकस:** भारत सरकार (2019 में) ने इस बात की कल्पना की कि यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा होगा और अगले पांच वर्षों में 50 मिलियन नए रोजगार जोड़ेगा।

MSMEs द्वारा जारी किए गए मुद्दे

- **अनकैप्ड पोटेंशियल:** जर्मनी और चीन की जीडीपी में क्रमशः MSMEs का योगदान 55% और 60% है, यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत को अभी भी अपनी MSME सफर में एक लंबा रास्ता तय करना है
- **MSMEs को ऋण आपूर्ति की कमी:** इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध औपचारिक ऋण 16 ट्रिलियन है। व्यवहार्य ऋण अंतर 36 ट्रिलियन की कुल मांग के मुकाबले 20 ट्रिलियन है
- **MSMEs के बीच औपचारिककरण का अभाव:** देश में कार्यरत लगभग 86% विनिर्माण MSMEs पंजीकृत नहीं हैं। आज भी, 6.3 करोड़ MSMEs में से केवल 1.1 करोड़ वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के साथ पंजीकृत हैं
- **तकनीकी व्यवधान:** भारत का MSME क्षेत्र पुराना और प्रभावहीन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो इसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बाधित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों (सामूहिक रूप से उद्योग क्रांति 4.0 के रूप में कहा जाता है) जैसी नई प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर संगठित निर्माण की तुलना में एमएसएमई के लिए एक बड़ी चुनौती है।

- **सत्तावाद बाधाएं:** निर्माण परमिट, अनुबंध लागू करना, करों का भुगतान , व्यापार शुरू करना और सीमाओं के पार व्यापार करना इसकी बाधाएं है
- **स्केलिंग मुद्दे:** MSME स्पेस साधारणतया एक माइक्रो स्पेस है जो छोटी और स्थानीय दुकानों के ढेर से बनता है इसलिए, उन्हें स्केल करना एक समस्या है, खासकर जब फंड की पहुंच चुनौतीपूर्ण हो

MSMEs के टिकाऊ और प्रभावी होने के लिए समय की आवश्यकता है

- इनपुट पक्ष पर अधिक क्षमता के लिए उत्पादन प्रक्रिया में बेहतर स्वचालन
- राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए अधिक से अधिक बाजारों और अवसरों तक पहुँचने के लिए अधिक माध्यम।
- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस आज न्यूनतम लागत, नवाचार और निवेश में इस परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम समर्थक हैं

MSMEs और ई-कॉमर्स

- **आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ संकलित:** प्रधान मंत्री ने "लोकल के लिए वोकल " बनने का नारा दिया है और कई बार आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण के बारे में बात की है। ई-कॉमर्स इस दृष्टि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है
- **भारत में बढ़ता हुआ ई-कॉमर्स स्पेस:** अध्ययनों से पता चलता है कि 2017 में भारत के ई-कॉमर्स बाजार का विस्तार 2021 तक 24 बिलियन अमरीकी डालर से 84 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।
- **बड़े बाजारों तक पहुंच:** ई-कॉमर्स उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए भी अनुमति देता है, इस प्रकार अपने स्थानीय कैचमेंट से परे ग्राहकों को ऑनलाइन बेचने के लिए टियर -2 / 3 शहरों के कारीगरों और छोटे विक्रेताओं को अवसर प्रदान करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला क्षमता बढ़ाता है:** आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करके, ई-कॉमर्स क्षेत्र MSMEs के लिए उन्हें आपूर्ति और वितरण नेटवर्क में भागीदार बनाने के अवसर प्रदान करता है और इस प्रकार उनकी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने में मदद करता है
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है:** स्टार्ट-अप्स और युवा ब्रांडों को MSMEs के साथ जुड़कर, राष्ट्रीय ब्रांड बनाने और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर भी मिलते हैं।
- **अतिरिक्त आय सृजन:** कई ऑफ़लाइन स्टोर भी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए ई-कॉमर्स को अपना रहे हैं तथा पारंपरिक और आधुनिक खुदरा मॉडल अधिक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी व्यापार में वृद्धि करके आय प्राप्त करते हैं

एक मजबूत ई-कॉमर्स-एमएसएमई क्षेत्र के निर्माण में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

1. ऑनलाइन व्यापार करने में आसानी

- सबसे पहले, हमें उन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है जो ई-कॉमर्स क्षेत्र के संदर्भ में ऑनलाइन व्यापार करने में आसानी से ग्रस्त हैं
- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर विक्रेताओं को इंट्रा-स्टेट आपूर्ति के लिए जीएसटी सीमा छूट (40 लाख रुपये) का लाभ नहीं मिलता है, जो ऑफ़लाइन विक्रेताओं का उपभोग करते हैं क्योंकि उन्हें अपने टर्नओवर कम होने के बावजूद "अनिवार्य पंजीकरण" करना पड़ता है।

2. शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता के साथ दूर करना

- सरकार विशेष रूप से ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए "डिजिटल का मुख्य स्थान" (PPoB) को सरल बनाने में अच्छा करेगी और इसे अपने गृह राज्य के बाहर अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

- आज, जैसा कि ऑफ़लाइन में है विक्रेताओं को एक भौतिक PPoB की आवश्यकता होती है, जो ई-कॉमर्स की प्रकृति को देखते हुए व्यावहारिक नहीं है।
- संचार के स्थान के साथ भौतिक PPoB को बदलना बेहतर है।
- राज्य विशिष्ट भौतिक PPoB की आवश्यकता को समाप्त करने से विक्रेताओं को व्यापार के एक ही राष्ट्रीय स्थान के साथ राज्य-स्तरीय जीएसटी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

3. हैंडहोल्डिंग का सहारा

- ई-कॉमर्स के कार्यों को समझने के लिए MSMEs को हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सरकार ई-कॉमर्स संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकती है ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर विशेष ऑन-बोर्डिंग कार्यक्रम तैयार कर , जागरूकता सत्रों की श्रंखला बना सके तथा महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे इमेजिंग और कैटलॉग इत्यादि प्रदान कर सके।
- ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

4. फेरबदलनीतियां और योजनाएं

- MSMEs के लिए मौजूदा योजनाओं और लाभों की जांच करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो ऑनलाइन बिक्री चैनलों का लाभ उठाने के लिए विशेष जरूरतों को शामिल करने के लिए ऑफ़लाइन, भौतिक बाजार को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे।
- उदाहरण के लिए, MSME को बाजारों तक पहुंचने और डिजिटल मार्केटिंग में निवेश करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उद्देश्य उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल मोड में जाते हैं।
- ई-कॉमर्स क्षेत्र की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कुशल नीति और कार्यक्रमों को पूरा करने की आवश्यकता है

5. आधारभूत संरचना का निर्माण

- बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर - डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है।
- सड़क और दूरसंचार नेटवर्क न केवल उपभोक्ता तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि विक्रेता को दूरदराज के क्षेत्रों से बड़े राष्ट्रीय बाजार और साथ ही निर्यात बाजार में प्रवेश करने में सक्षम करेगा।
- ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा बनाई गई एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क और वेयरहाउस श्रृंखलाएं समान पहुंच और पहुंच को सक्षम करती हैं।
- राष्ट्रीय संचालन नीति को ई-कॉमर्स क्षेत्र की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।

6. निर्यात क्षमता

सरकार को ई-कॉमर्स जैसे निर्यात बढ़ाने के लिए विशिष्ट कदम उठाने की जरूरत है

- उन उत्पादों की पहचान करें, जिनमें निर्यात बाजार की क्षमता है
- निर्यात उन्मुख विनिर्माण समूहों के साथ ई-कॉमर्स जुड़े
- सेक्टर-विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ टाई-अप को प्रोत्साहित करें
- ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट ज़ोन बनाने के लिए मौजूदा SEZs का लाभ उठाएं।

7. मौजूदा भारतीय डाक नेटवर्क का लाभ उठाना

- इंडिया पोस्ट प्रतिस्पर्धी दरों पर ई-कॉमर्स के विशिष्ट छोटे पार्सल समाधान बनाकर, पार्सल ट्रैकिंग सिस्टम का निर्माण और सीमा शुल्क मंजूरी को सक्षम करने के लिए विदेशी डाकघरों के साथ साझेदारी करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

8. ई-कॉमर्स और विदेश व्यापार नीति (FTP)

- विदेश व्यापार नीति को वैश्विक बाजारों में सफल होने के लिए ऑनलाइन विक्रेताओं द्वारा आवश्यक क्षेत्रों की पहचान कर आगामी संशोधित नीति में ई-कॉमर्स निर्यात विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना चाहिए।
- **इसमें यह शामिल हो सकता है:** ई-कॉमर्स निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और ई-कॉमर्स निर्यात के लिए डिजिटलीकरण को समाप्त करने के लिए विशिष्ट नीति प्रावधान।

निष्कर्ष

- MSMEs यदि डिजिटलीकरण द्वारा प्रभावी ढंग से सुविधा प्राप्त करते हैं, तो आर्थिक विकास, रोजगार, आय के स्तर में तेजी लाने और आपूर्ति श्रृंखला क्षमता बढ़ाने के लिए गेम चेंजर होगा। MSMEs के लिए डिजिटल प्रवीणता ऑनलाइन बाजार में सफलतापूर्वक अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना क्षेत्र भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकता।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय संवीक्षा केंद्र (CSC) और IEPFA मोबाइल ऐप

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर (CSC) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (Investor Education and Protection Fund Authority-IEPFA) मोबाइल ऐप का वर्चुअली उद्घाटन किया.
- **मंत्रालय:** कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)

महत्वपूर्ण तथ्य

सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर (CSC)

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा गुणवत्ता असम्बद्ध और दोष से मुक्त है, CSC लॉन्च किया गया।
- CSC, MCA21 रजिस्ट्री पर कॉरपोरेट्स द्वारा दायर किए गए कुछ सीधे प्रक्रिया (STP) फॉर्मों की जांच करेगा और कंपनियों को अधिक गहन जांच के लिए चिह्नित करेगा।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) मोबाइल ऐप

- **उद्देश्य:** यह निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक सहभागिता और सूचना प्रसार के लिए विकसित किया गया है।
- इसमें IEPF क्लेम रिफंड प्रक्रिया की स्थिति और प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा होगी।
- यह संदिग्ध धोखाधड़ी योजनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए निवेशकों और आम नागरिकों के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है।

वाणिज्यिक कोयला खनन का दूसरा ट्रेंच

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- भारत ने कोयले की बिक्री के लिए 67 खानों की पेशकश करने वाले वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी के अपने दूसरे ट्रेन्च को शुरू किया।
- केंद्रीय कोयला मंत्री ने नीलामी प्रक्रिया शुरू की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2014 के बाद से नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद नीलामी की एक विशेष किश्त में प्रस्ताव पर यह सबसे अधिक संख्या है।
- कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कुल 67 खानों में से 23 खदानें CM(SP) अधिनियम और 44 MMDR अधिनियम के तहत हैं।
- प्रस्ताव पर कोयला खदानें 6 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैली हुई हैं।

क्या आप जानते हैं?

रोलिंग नीलामी

- भारत सरकार भविष्य की नीलामी आयोजित करने के लिए 'रोलिंग ऑक्शन' तंत्र को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
- कोयला पहला खनिज संसाधन है जहां रोलिंग नीलामी तंत्र लागू किया जा रहा है जिसमें नीलामी के लिए कोयला ब्लॉकों का एक पूल हमेशा उपलब्ध रहेगा।

सुर्खिओ में केप ऑफ गुड होप स्थान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - भूगोल और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- स्वेज नहर के अवरुद्ध होने के कारण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भारत के $ 200 बिलियन के व्यापार के लिए वाणिज्य विभाग, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुन: रूटिंग शिपमेंट की योजना बना रहा है।

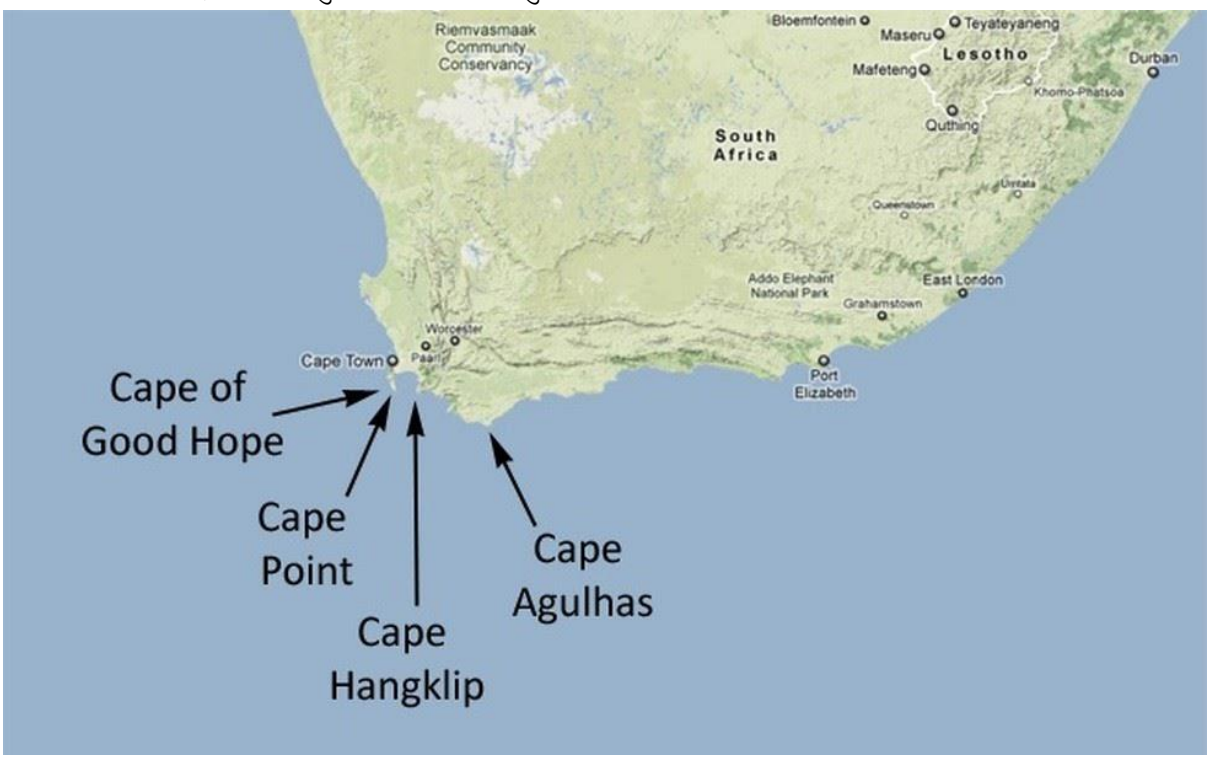

अन्य संबंधित तथ्य

- केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में केप प्रायद्वीप के अटलांटिक तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है।
- एक आम गलत धारणा यह है कि केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है।

- समकालीन भौगोलिक ज्ञान के बजाय अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास है।
- भूमध्य रेखा से अफ्रीकी तटरेखा के पश्चिमी भाग का अनुसरण करते समय, केप ऑफ गुड होप उस बिंदु को चिह्नित करता है जहां एक जहाज दक्षिण पूर्व की तुलना में अधिक पूर्व की ओर यात्रा करता है।

केप अगुलहास

- केप अगुलहास पश्चिमी केप, दक्षिण अफ्रीका में एक चट्टानी मुख्य भूमि है।
- यह अफ्रीकी महाद्वीप का भौगोलिक दक्षिणी छोर अटलांटिक और भारतीय महासागरों के बीच विभाजन रेखा की शुरुआत करती है।

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्र की योजना एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों की 'विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या' (Unique Land Parcel Identification Number) जारी करने की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह बाद में राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस और आधार संख्या स्वैच्छिक आधार को एकीकृत करेगा।
- 2021 में 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) योजना शुरू की गई है
- इसे मार्च 2022 तक पूरे भारत में लागू किया जाएगा
- ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
- इसके तहत भूखंड की पहचान, उसके देशांतर और अक्षांश के आधार पर की जाएगी जो विस्तृत सर्वेक्षण और संदर्भित भू संपत्ति-मानचित्रीकरण पर निर्भर होगी।
- यह वर्ष 2008 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme- DILRMP) का अगला चरण है।

IASbaba
One Stop Destination for UPSC Preparation

TLP 2021

Think Learn Perform (TLP) CONNECT 2021

TEST SERIES (Prelims + Mains) Based Mentorship Program

Key Features :

- **INTEGRATED PROGRAMME** – includes Prelims, Mains and Interview
- Includes **MAINS TESTS & SYNOPSIS** – TOTAL = 40 TESTS
- Includes **PRELIMS TEST SERIES** – TOTAL = 53 TESTS
- One-to-One **MENTORSHIP** and top notch feedback
- It is an **INCENTIVE-BASED PROGRAMME***
- **WELL-PLANNED SCHEDULE AND APPROACH PAPER** before the test
- **DISCUSSION (VIDEO & OFFLINE), SYNOPSIS, EVALUATION, RANKING** after every MAINS test
- Includes **BABAPEDIA** – One-Stop Destination of Current Affairs Preparation
- **PRACTICAL PLANNING** maintaining quantity and quality
- **TESTS are FLEXIBLE**

***INCENTIVE-BASED PROGRAMME** – TLP 2nd Phase and Interview Mentorship Programme (IMP) will be free for those who clear Prelims and Mains respectively

Why TLP Connect Plus (+)?

- Includes both **Prelims and Mains Test Series**
- **Dedicated Mentorship** and **Incentive-based Programme**
- Special sessions for Essay, Ethics and other GS Mains Papers under the **SERIES OF INTERACTIVE LECTURES (SOIL)**

- Total No. of Prelims tests - **53 TESTS** (43 GS Paper I tests + 10 CSAT Paper II Tests)
- Total No. of Mains tests - **40 TESTS** (24 Sectional tests + 8 Essay tests + 8 Comprehensive Mocks)
- Includes **Babapedia** – both Prelimspedia and Mainspedia

WHY IASbaba?

VISION: Enabling an aspirant located at the remotest corner of the country, in not only fulfilling his/her dreams of clearing the toughest UPSC/Civil Services Exam, but securing Rank 1.

2M+	350+	1200+	>70%	>80%
MONTHLY ACTIVE USERS	RANKS FROM ILP/TLP	RANKS FROM WEBSITE	HIT RATIO IN UPSC PRELIMS	HIT RATIO IN UPSC MAINS

Contact us

Admission Centre
#38, 3rd Cross Rd, 60feet Main Road,
Chandra Layout, Bengaluru-560040
Landmark: Opp BBMP Office / Cult Fit

Vijayanagara Centre
1737/37, Mrcr Layout, Vijayanagar Service Road,
Vijayanagar, Bengaluru - 560040
Landmark: Opp. to Vijayanagar Metro Station

Delhi Centre
5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

www.iasbaba.com tlp@iasbaba.com +91 91691 91888

कृषि

सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; कृषि

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी गई है।
- इसे 21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस मिशन में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थानों में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया जाएगा जो देश के किसानों तथा उद्योगों की निर्यात ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।
- फ्लोरीकल्चर, बागवानी (Horticulture) विज्ञान की एक शाखा है जो छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है।
- **द्वारा कार्यान्वित:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से CSIR - फ्लोरीकल्चर के अप्रत्यक्ष; केवीआईसी; एपीडा, ट्राइफेड; खुशबू और स्वाद विकास केंद्र (FFDC), कन्नौज, MSME और विश्वविद्यालयों के मंत्रालय।
- विविध कृषि-जलवायु और इडेफिक परिस्थितियों (मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण) तथा पौधों की समृद्ध विविधता जैसे कारक विद्यमान होने के बावजूद भी वैश्विक पुष्प कृषि बाज़ार में भारत का केवल 0.6% ही योगदान है।
- विभिन्न देशों से हर वर्ष कम से कम 1200 मिलियन अमेरिकी डालर के पुष्प उत्पाद का आयात किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि वोल्टेज प्रौद्योगिकी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - प्रौद्योगिकी; कृषि

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि वोल्टेज प्रौद्योगिकी के बारे में लोकसभा को अवगत किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 'केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान' (ICAR) जोधपुर ने 105 किलोवाट क्षमता की कृषि-वोल्टेइक प्रणाली विकसित की है।
- यह तकनीक कृषि भूमि पर एक-साथ विद्युत और नकदी फसलों का उत्पादन कर किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक हो सकती है।
- विदित है कि 'कुसुम योजना' (किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान) के घटक-I के अंतर्गत खेतों में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली कृषि-वोल्टेइक प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- 'नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया' (NSEFI) ने देश में 13 परिचालन कृषि-वोल्टेईक प्रणालियों को विकसित करने के लिये दस्तावेज़ तैयार किया है।

सिल्क सेक्टर में एग्रोफोरेस्ट्री

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - कृषि; अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह उप-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (एसएमएएफ) योजना के तहत रेशम क्षेत्र में एग्रोफोरेस्ट्री के कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल के बारे में है।
- **उद्देश्य:** रेशम कीट पालन वाले पौधों (मलबरी, असन, अर्जुन, सोम, सलू, केसरू, बड़ा केसरू, इत्यादि) को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित है ताकि खेतों पर ब्लॉक पौधारोपण या परिधीय वृक्षारोपण दोनों के रूप में खेती की जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB)

- यह एक वैधानिक निकाय है।
- **स्थापित:** 1948
- **मंत्रालय:** कपड़ा मंत्रालय
- **मुख्यालय**: बेंगलुरु

एग्रोफोरेस्ट्री (एसएमएएफ) योजना पर उप-मिशन

- 2016-17 से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC & FW) द्वारा लागू किया गया
- यह योजना राष्ट्रीय कृषि नीति 2014 की सिफारिश का एक हिस्सा है।
- भारत ऐसी व्यापक नीति रखने वाला पहला देश है
- इस नीति को फरवरी, 2014 में दिल्ली में आयोजित 'वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री काॅन्ग्रेस में लॉन्च किया गया था और भारत इस प्रकार की व्यापक नीति वाला पहला देश है।
- वर्तमान में, यह योजना 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।
- **उद्देश्य:** किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने तथा खाद्य भंडारों में वृद्धि के लिये जलवायु अनुकूल कृषि फसलों के साथ बहु-उद्देश्यीय वृक्ष लगाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना।

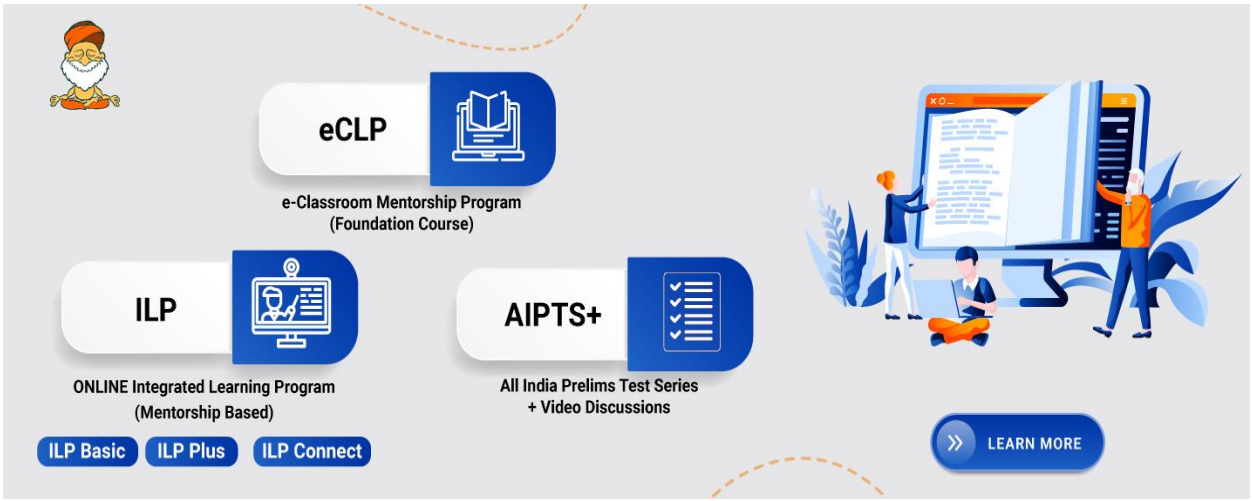

पर्यावरण/प्रदूषण

नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण; प्रदूषण

सुर्खिओ में क्यों-

- 2,117.54 करोड़ रुपये की लागत से नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के द्वारा मंजूरी मिली।
- इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (NRCD) द्वारा लागू किया जाएगा।
- यह अनुपचारित सीवेज, बहते ठोस अपशिष्ट, नाग नदी और उसकी सहायक नदियों में बहने वाली अन्य अशुद्धियों के संदर्भ में प्रदूषण के स्तर को कम करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- नाग नदी नागपुर, महाराष्ट्र से होकर बहने वाली नदी है।
- इसलिए इस शहर का नाम नाग नदी से लिया गया है
- कन्हान-पेंच नदी प्रणाली का एक हिस्सा बनाते हुए, नाग नदी वाडी के पास लावा पहाड़ियों में बनाती है।

संबंधित आलेख:

- राष्ट्रीय गंगा परिषद (एनजीसी)

जलवायु परिवर्तन

- जब तक जलवायु परिवर्तन को प्राथमिक दोषी के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता, तब तक जलवायु कार्रवाई लड़खड़ाती रहेगी।

हिमालयन ग्लेशियर का पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग

- उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन के संकेत देने वाले हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग के निशान हैं।
- अल्बेडो को कम करना: जैसा कि ग्लेशियर के आवरण को पानी या भूमि द्वारा बदल दिया जाता है, परावर्तित होने वाली प्रकाश की मात्रा वायुमंडल के बढ़ते ताप को और कम कर देती है

टेक्सास और ग्लोबल वार्मिंग में अत्यधिक ठंड

- टेक्सास में अत्यधिक ठंडा मौसम, आर्कटिक-प्रायद्वीप वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, वैश्विक औसत से लगभग दोगुना दर पर।
- **ध्रुवीय भंवर:** आमतौर पर, आर्कटिक के चारों ओर हवाओं का एक संग्रह होता है, जो उत्तर में दूर तक ठंड को बंद रखता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इन सुरक्षात्मक हवाओं में अंतराल पैदा कर दिया है, जिससे तीव्रता से ठंडी हवा दक्षिण की ओर बढ़ रही है - एक घटना बहुत तेज हो रही है।

चिंता

- **भारत की जलवायु भेद्यता:** जबकि एचएसबीसी जलवायु भेद्यता (2018) में 67 देशों में भारत शीर्ष पर है, जर्मनवाच जलवायु जोखिम (2020) के मामले में भारत को 181 देशों में पांचवें स्थान पर रखा है। लेकिन सार्वजनिक खर्च इन खतरों को नहीं दर्शाता है।

- **संचित कार्बन का प्रभाव:** भले ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जलवायु शमन को गति देती हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसी तबाही वायुमंडल में संचित कार्बन उत्सर्जन के कारण अधिक बार हुई।
- **जलवायु सुरक्षा उपायों का दायरा:** अध्ययन ने हिमालय में बर्फ के नुकसान, घनी आबादी वाले खतरों के लिए बर्फ के इलाके को चिह्नित किया , लेकिन नीतिगत प्रतिक्रिया की कमी रही। इसी तरह, केरल ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील स्थानों में खनन, उत्खनन और बांध निर्माण के नियमन के लिए एक ऐतिहासिक अध्ययन की अनदेखी की, इसलिए 2018 और 2019 में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन में योगदान दिया।

आगे की राह

- **क्लीनर ऊर्जा स्रोतों में बदलाव:** अत्यधिक प्रदूषणकारी कोयले और पेट्रोलियम से लेकर क्लीनर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक निर्णायक स्विच की आवश्यकता है।
- **कार्बन तटस्थता की घोषणा करने की आवश्यकता:** भारत को कार्बन तटस्थता लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए। चीन ने अक्टूबर 2020 में अपने जलवायु तटस्थता लक्ष्यों की घोषणा की, इसी तरह यूरोपीय संघ और जापान ने भी घोषणाएं की हैं।
- **जलवायु बजट:** ऊर्जा बजट, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ सरकारी बजट में जलवायु शमन के लिए नीतियों को स्पष्ट करना। विशेष रूप से, विकास लक्ष्यों में क्लीनर ऊर्जा पर स्विच करने की समयसीमा शामिल होनी चाहिए।
- **जलवायु वित्त जुटाना:** सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जलवायु वित्त जुटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को जोखिम में कमी के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए, जैसे बाढ़ के विरुद्ध बेहतर बचाव या सूखे को झेलने के लिए कृषि नवाचार।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पेरिस जलवायु सौदा

गहिरामाथा समुद्री अभयारण्य

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण; जैव विविधता

सुर्खिओ में क्यों-

- उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल ने लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए किए गए उपायों का आकलन करने के लिए गहिरामाथा समुद्री अभयारण्य क्षेत्र की यात्रा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एक पर्यावरण पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों के वन और मत्स्य विभाग की लापरवाही के कारण जनवरी से अब तक 800 ओलिव रिडले कछुए मर गए।
- गहिरमाथा (हिंद महासागर) का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है।
- ओडिशा में बंगाल तट की खाड़ी से गहिरमाथा समुद्र तट इन कछुओं की दुनिया के सबसे बड़े घोंसले के मैदान के रूप में प्रशंसित है।

स्वतंत्र पर्यावरण नियामक स्थापित करने में विफलता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सरकार से ग्रीन क्लीयरेंस (Green Clearance) की निगरानी के लिये "स्वतंत्र पर्यावरण नियामक" (Independent Environment Regulator) की स्थापना नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने के लिये कहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सर्वोच्च न्यायालय ने लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Lafarge Umiam Mining Private Limited v. Union of India Case), 2011 जिसे आमतौर पर 'लाफार्ज माइनिंग केस' (Lafarge Mining Case) के रूप में जाना जाता है, मामले की सुनवाई के दौरान ग्रीन क्लीयरेंस की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक संस्था की स्थापना का आदेश दिया था।
- यह नियामक पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ इन शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाएगा।
- SC ने यह स्पष्ट किया था कि जब तक इस तरह के तंत्र को लागू नहीं किया जाता है, तब तक पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) को मान्यता प्राप्त संस्थानों का एक पैनल तैयार करना चाहिए, जहाँ से परियोजना के प्रस्तावक को संदर्भ की शर्तों पर शीघ्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्राप्त करना चाहिए। यह एमओईएफ द्वारा तैयार किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस - 2020 पुरस्कार प्राप्त किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), रोम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जीता है।
- आईसीएआर ने 2020 के दौरान "मृदा स्वास्थ्य जागरूकता" विषय पर अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए "मृदा कटाव रोकें, हमारा भविष्य बचाएं" के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार
- 2018 में प्रारंभ किया गया
- यह उन व्यक्तियों या संस्थानों को स्वीकार करता है जो मिट्टी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाते हैं
- **द्वारा प्रायोजित:** थाईलैंड का साम्राज्य
- इसका नाम थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के नाम पर रखा गया है

समुद्री हिरन का सींग

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता; वातावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न लगाने का फैसला किया।

अन्य संबंधित तथ्य

सीबकथॉर्न

- यह एक झाड़ी है जो नारंगी-पीले रंग की खाद्य बेर का उत्पादन करती है।
- भारत में, यह हिमालय क्षेत्र में पेड़ की छाल के ऊपर पाया जाता है, आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों जैसे लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान में।
- हिमाचल प्रदेश में, इसे स्थानीय रूप से चर्मा कहा जाता है।
- पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक लाभ: (1) पेट, हृदय और त्वचा की समस्याओं का इलाज करना; (2) इसके फल और पत्तियाँ विटामिन, कैरोटिनॉइड और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होती हैं; (3) अधिक ऊँचाई तक पहुँचने में सैनिकों की मदद करता है; (4) ईंधन और चारे का महत्वपूर्ण स्रोत; (5) मृदा-अपरदन को रोकता है; (6) नदियों में गाद को चेक करना ; (7) पुष्प जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है; (8) रस, जैम, पोषण कैप्सूल आदि बनाने में उपयोग किया जाता है।

बम्बूसा बम्बोस ने नीलगिरि जीवमंडल को धमकी दिया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण; जैव विविधता

सुर्खिओ में क्यों-

- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (चार्टर) के अंदर बांस का फूल, नीलगिरि जीवमंडल के प्रमुख बाघ और हाथी आवास में वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वायनाड के जंगल में बांस की खदानें गर्मियों के दौरान नीलगिरि जीवमंडल में जड़ी-बूटियों का मुख्य स्रोत हैं।
- गर्मियों के शुरुआत में, चारे और पानी की कमी के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु में समीपवर्ती अभयारण्यों से जंगली जानवरों का प्रवास शुरू होता है
- फूल आने के बाद यह विशेष रूप से हाथियों, जंगली गौर और अन्य निचले शाकाहारी जानवरों द्वारा सामूहिक रूप से पलायन को प्रभावित करता हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह एक लंबा, चमकीले-हरे रंग का चमकदार बांस की प्रजाति है जो बड़ी संख्या में भारी ब्रंच युक्त, बारीकी से घनीभूत चट्टानों से युक्त होती है।
- बाँसोसा बम्बोस एक मोनोकार्पिक (केवल एक बार का फूल) है।
- **परिवार:** यह पोएसी परिवार (घास परिवार) से सम्बंधित है।
- इसका फूल चक्र 40 से 60 वर्ष तक भिन्न होता है।
- इसे बड़े कांटेदार बांस, भारतीय कांटेदार बांस, चमकदार बांस या कांटेदार बांस के रूप में भी जाना जाता है।
- यह दक्षिणी एशिया के बांस के झुरमुट की एक प्रजाति है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में केरल वायनाड वन्यजीव अभयारण्य का एक पशु अभयारण्य है।

आईक्यू एयर की वैश्विक वायु प्रदूषण रिपोर्ट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण; प्रदूषण

सुर्खिओ में क्यों-

- आईक्यू एयर से वैश्विक वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की गई।
- यह एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो हवाई प्रदूषकों के खिलाफ सुरक्षा, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों के विकास में विशेषज्ञता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना।
- कुल मिलाकर, भारत ने 2019-2020 में अपने औसत वार्षिक PM2.5 (पार्टिकुलेट मैटर) के स्तर में सुधार किया।
- भारत 2020 में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है।
- भारत की तुलना में बांग्लादेश और पाकिस्तान का पीएम 2.5 का औसत स्तर काफी ख़राब है।
- नवीनतम रिपोर्ट में चीन 11 वें स्थान पर है, जबकि पिछले संस्करण में 14 वें से एक की गिरावट है।
- शहरों में, चीन का होटन सबसे अधिक प्रदूषित था उसके बाद उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद था।
- 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के थे।
- प्रदूषण का स्तर औसत भारित होता है, जिसका अर्थ है कि किसी देश की जनसंख्या रिपोर्ट किए गए प्रदूषण मूल्यों को प्रभावित करती है।
- सभी निरीक्षण किए गए देशों के 84% ने वायु गुणवत्ता में सुधार देखा।
- हालांकि, 106 निरीक्षण किये गए देशों में केवल 24 ने पीएम 2.5 के लिए डब्ल्यूएचओ के वार्षिक दिशानिर्देशों को पूरा किया।

एकल उपयोग प्लास्टिक के पीछे छिपी हुई महामारी

संदर्भ: प्लास्टिक को भारी मात्रा में कोविद के खिलाफ ढाल के रूप में तैनात किया गया है। लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात है कि बढ़े हुए प्लास्टिक कचरे का अंत कहां होगा

कोविद -19 और एकल उपयोग प्लास्टिक

- **कोविद -19 महामारी से पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्य:** 2019 में, केंद्र सरकार ने 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से चरणबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध किया। प्रतिबद्धता ने एकल-उपयोग प्लास्टिक को इकट्ठा, संग्रहीत और पुन: उपयोग करने के लिए बेहतर व्यवस्था करने का आह्वान किया। महामारी रुकी और कुछ मामलों में इस प्रगति से बहुत उलट है।
- **कोविद -19 के कारण प्लास्टिक सर्वव्यापी हो गया:** मास्क, सैनिटाइजर बोतलें, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, खाद्य पैकेजिंग, पानी की बोतलें सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है।
- **माइक्रोप्लास्टिक पर चिंता:** समय के साथ, यह प्लास्टिक पांच मिलीमीटर से कम के सूक्ष्म कणों में विघटित हो जाती है - जिसे माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में जाना जाता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हवा में सांस लेने के लिए जल निकायों और खेत की मिट्टी के माध्यम से चलते हैं।

- **बहुत कम पुनर्चक्रण:** अभी तक उत्पादित सभी प्लास्टिकों में से केवल 9 प्रतिशत का पुनर्नवीनीकरण किया गया है, जबकि उत्पादित सभी प्लास्टिकों का 79 प्रतिशत दुनिया की लैंडफिल और वायु, जल, मिट्टी तथा अन्य प्राकृतिक प्रणालियों में पाया जा सकता है।
- **अपरिहार्यता:** प्लास्टिक अभी भी महत्वपूर्ण है। टिकाऊ वस्तुओं, दवा और खाद्य सुरक्षा में इसकी मुख्य भूमिका का मतलब है कि यह पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए व्यावहारिक नहीं है। इसके बजाय हमें इसके बारे में अधिक विचारशील होना चाहिए कि हम कब, कहां और कैसे इसका उपयोग करना हैं

आगे की राह

- कोविद -19 के खिलाफ संघर्ष के दौरान भी हम कई कदम उठा सकते हैं, यहां तक कि यह ध्यान में रखते हुए कि ऊपर से हमें यथासंभव एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से बचना चाहिए।
- **बढ़ा हुआ संग्रह:** हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट संग्रह उसी तेजी से हो जो अपशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है
- **प्रारंभिक अवस्था में अलगाव:** हम अपशिष्ट-से-मूल्य चक्र में कचरे को अलग करने और प्लास्टिक का जल्दी उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए ताकि प्लास्टिक उपचार और रीसाइक्लिंग के लिए उपयुक्त रहे। महामारी के दौरान कुछ स्रोत अलगाव के प्रयास अधिक सामान्य हो गए और यह प्रक्रिया चलती रही। यह रीसाइक्लिंग को बहुत आसान और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना देती है
- **पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को प्रोत्साहित करें:** सरकार को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए जहां वे मौजूद हैं और जहां मौजूद नहीं हैं वहां इस विकल्प को शुरू करें। व्यवसाय मॉडल जो वैकल्पिक उत्पाद वितरण प्रणालियों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे से बचते हैं, परिपत्रता को बढ़ावा देते हैं, तथा प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते है
- **हितधारकों के बीच समन्वय:** यह मानते हुए कि प्लास्टिक प्रदूषण वास्तव में एक समाज-व्यापी समस्या है, इसका समाधान खोजने के लिए सरकार, व्यवसायों और नागरिक समाज को समन्वय करना महत्वपूर्ण है।
- **नीति की रूपरेखा:** राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और क्रियाओं के लिए नदियों में समुद्री जल और प्लास्टिक प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ केंद्र सरकार को आना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्लास्टिक प्रतिबंध की खामिया

यूरोपीय संघ द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट

संदर्भ: 17 मार्च, 2021 को, यूरोपीय आयोग ने COVID-19 महामारी के बीच यूरोपीय संघ (ईयू) के भीतर नागरिकों के सुरक्षित और मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा।
सर्टिफिकेट्स को गर्मियों तक रोल आउट किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि देशों के पास आवश्यक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का समय है।

डिजिटल ग्रीन प्रमाणपत्र वास्तव में क्या है?

- **COVID-19 ट्रांसमिशन का कोई खतरा नहीं:** एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि किसी व्यक्ति को COVID -19 के खिलाफ टीका लगाया गया तो एक नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है या COVID -19 से निकले।

- **डिजिटल प्रारूप और नि: शुल्क:** प्रमाण पत्र की मुख्य विशेषताएं है कि यह एक QR कोड के साथ पूरा डिजिटल या कागज प्रारूप में नि: शुल्क होगा।
- **प्राधिकरण जारी करना:** प्रमाण पत्र अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें अस्पताल, परीक्षण केंद्र और स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं।
- **समन्वित तरीके से प्रतिबंधों को उठाना:** एक बार डिजिटल प्रमाणपत्रों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद, इसे सभी ईयू देशों में स्वीकार किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यूरोपीय संघ के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंधों को समन्वित तरीके से उठाया जा सकता है।
- **पात्रता:** यूरोपीय संघ के सभी नागरिक या तीसरे देश के नागरिक जो यूरोपीय संघ में कानूनी रूप से रह रहे हैं, वे इन डिजिटल प्रमाणपत्रों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और इस तरह उन्हें मुक्त आंदोलन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी।
- **सूचित करने वाला आयोग:** यदि यूरोपीय संघ के सदस्य देश को किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन या परीक्षण से है, तो उसे आयोग को सूचित करना होगा और अन्य सभी सदस्य राज्यों को अपने निर्णय को उचित ठहराना होगा।

ऐसे दस्तावेज़ की क्या आवश्यकता है?

- **मुक्त आंदोलन प्रतिबंधों को छोड़ देता है:** यूरोपीय संघ और विश्व भर में, बीमारी के फैलाव के कारण पर्यटन उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इसलिए, कई देशों ने डिजिटल प्रमाण पत्र या पासपोर्ट पर विचार किया, जो इस बात का प्रमाण होगा कि एक व्यक्ति को टीका लगाया गया या कोविद -19 से स्वस्थ हुआ है।
- **इज़राइल का वैक्सीन पासपोर्ट मॉडल:** फरवरी में, इज़राइल पहला देश बना जिसने "वैक्सीन पासपोर्ट" नामक प्रमाण पत्र जारी किया, जो वैक्सीन वाले व्यक्तियों को कुछ सुविधाओं का उपयोग करने और घटनाओं में भाग लेने की अनुमति देगा।
- **ग्लोबल प्रैक्टिस:** डेनमार्क ने यह भी कहा कि यह डिजिटल पासपोर्ट को चालू करने की प्रक्रिया में था जो उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण के रूप में काम करेगा जिन्हें टीका लगाया गया है। फिर भी, मई 2020 की शुरुआत में, चिली जैसे देशों ने उन लोगों के लिए "रिलीज सर्टिफिकेट" प्रस्तावित किया, जो कोविद -19 से स्वस्थ हुए थे।

चिंताजनक

- **डब्ल्यूएचओ का उदेश्य:** हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ऐसे प्रमाणों का उपयोग करने के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण सलाह दी थी कि कोविद -19 से संक्रमित व्यक्ति को फिर से संक्रमण नहीं हो सकता है।
- **पुन: संक्रमण की संभावना:** हालांकि, अब यह ज्ञात है कि COVID-19 के मामले में पुन: संक्रमण दुर्लभ है। हाल ही में जर्नल लांसेट में प्रकाशित शोध में यह बताया गया है कि जिन लोगों को COVID-19 हुआ है, उनमें से अधिकांश को छह महीने की अवधि के लिए पुन: संक्रमण से बचाया जाता है। हालांकि, सर्वे का कहना है कि बुजुर्ग रोगियों में अधिक संक्रमण का खतरा होता है

बिंदुओं को जोड़ना

- क्या सार्क / बिम्सटेक राष्ट्र ऐसे प्रमाणपत्र भी ला सकते हैं, जो उपमहाद्वीप में आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करता है जिससे COVID-19 स्थिति में राष्ट्रों का तेजी से एकीकरण हो सके?

हिमाचल प्रदेश में जल संकट

संदर्भ: हिमाचल प्रदेश राज्य के जल मंत्री ने विधान सभा को बार-बार चेतावनी दी कि राज्य में पानी की कमी का सामना करने की संभावना पड़ सकती है

सतलज और ब्यास नदियों जैसे जल के बारहमासी स्रोतों के साथ राज्य जल संकट में क्यों है?

- **वर्षा और हिमपात:** हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष कम हिमपात और वर्षा हुई। सर्दियों के बाद ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी नियमित रूप से भूजल के साथ-साथ अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, कुओं, बावड़ियों, झीलों, नालों और नदियों आदि में आ जाता है, लेकिन इस साल बर्फबारी कम होने से जल स्रोत सूखने लगे हैं
- **सामान्य से 69% कम वर्षा :** भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में इस सर्दी (1 जनवरी से 28 फरवरी) तक केवल 59 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 69 प्रतिशत कम थी।
- **बढ़ती मांग:** आम तौर पर दशकों से राज्य में बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग बढ़ रही है, अब लोग पारंपरिक स्रोतों जैसे झरनों और बावड़ियों के बजाय पाइप जलापूर्ति योजनाओं पर अधिक भरोसा कर रहे हैं.
- **जलवायु परिवर्तन:** बारिश के पैटर्न भी अनिश्चित हो गए हैं। ड्राई पीरियड के दौरान, पानी के स्रोत कुछ क्षेत्रों में जल्दी सूख जाते हैं, खासकर शिवालिक पहाड़ियों में जहाँ मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है।

इसी तरह की स्थिति पहले भी थी

- हिमाचल में 2018 में भी बर्फबारी हुई थी, जब राजधानी शिमला में गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था।
- तब से शिमला में स्थिति बेहतर है क्योंकि शहर से 10 मिलियन लीटर (mld) अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिए गुम्मा धारा से इसका जल आपूर्ति स्रोत बढ़ाया गया।
- इस साल पानी की समस्या आने वाले गर्मियों के महीनों में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन सरकार ने दावा किया कि हिमाचल में इससे पहले कभी भी सूखा नहीं पड़ा है। "ब्यास नदी के कुछ हिस्से हैं जो अब केवल पैदल चलकर पार किए जा सकते हैं." दरअसल, इसका अर्थ यह कि पानी का स्तर गिर गया है

प्रस्तावित समाधान क्या हैं?

- पानी की कमी को देखते हुए पिछले साल हैंड-पंप और बोरवेल लगाना रोक दिया था, लेकिन जहां भी आवश्यक होगा उसे फिर से शुरू किया जाएगा।
- पूरे राज्य में जल संचयन टैंक बनाए जाएंगे और सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शुरू करना होगा।
- हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में बस्तियाँ सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन इनसे जुड़े गाँवों में पानी की कमी के दौरान पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सरकार उच्चतम पहुँच में "स्नो हार्वेस्टिंग" के विकल्प का पता लगाने की कोशिश करेगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत का जल संकट
- शहरीकरण और जल संकट

वाहन परिमार्जन नीति

संदर्भ: यह अनुमान है कि 17 लाख मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने थे और बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बने रहे

नीति के बारे में

- **फिटनेस टेस्ट:** नई नीति में निजी स्वामित्व वाले वाहनों के मामले में 20 साल और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 15 साल पूरे होने के बाद फिटनेस परीक्षण का प्रावधान है। कोई भी वाहन जो फिटनेस परीक्षण में फेल हो जाता है या अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण का प्रबंधन नहीं करता है, तो उसे "एंड-ऑफ-लाइफ" वाहन के रूप में घोषित किया जायेगा है।
- **सरकारी वाहन:** सभी सरकारी वाहन और पीएसयू के स्वामित्व वाले लोग 15 साल बाद डी-पंजीकृत हो जाएंगे।
- **कार्यान्वयन का चरणबद्ध तरीका:** नीति 1 अप्रैल, 2022 से सरकारी वाहनों के लिए किक-इन करेगी। भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होगा और निजी वाहनों सहित अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए 1 जून, 2024 से चरणों में यह शुरू होगा।
- **स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन:** नीति में राज्यों को निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25% तक छूट देने और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक छूट देने के लिए राज्यों को केंद्रीय सलाह शामिल हैं। सरकार नए वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क की छूट भी प्रदान करेगी।
- **वाहन निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन:** केंद्र सरकार ऑटो निर्माताओं को एडवांस सर्टिफिकेट जारी करने के बाद नया वाहन खरीदने वालों को 5% की छूट देने की पेशकश करेगी है।
- **पुराने वाहनों का विघटन:** पुराने वाहन पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। एक विघटनकारी के रूप में, बढ़ी हुई पुनः पंजीकरण शुल्क वाहनों के लिए 15 वर्ष या प्रारंभिक तिथि पंजीकरण से पुरानी होगी।
- पुराने वाहन पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। विघटनकारी के रूप में, बढ़ी हुई नई पंजीकरण फीस वाहनों के लिए 15 वर्ष या उससे प्रारंभिक पंजीकरण तिथि से पुरानी होगी

पॉलिसी के लाभ

- **ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देता है:** पुराने वाहनों को चरणबद्ध करके नए वाहनों की खरीद के लिए नीति को आगे बढ़ाता है। यह अनुमान है कि भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग 4.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक के कारोबार में आगे बढ़ जाएगा।
- नए वाहनों की बिक्री से सरकार के राजस्व संग्रह को बढ़ाएं।
- **प्रदूषण को कम करने में मदद:** पुराने वाहनों को नए वाहनों की तुलना में पर्यावरण को 10-12 गुना अधिक प्रदूषित करने के लिए जाना जाता है, इस प्रकार यह नीति प्रदूषण को कम करने के लिए एक कदम है।
- **ईंधन दक्षता में सुधार:** पुराने वाहनों का कार्य क्षमता कम होती है जिससे अधिक ईंधन की खपत होती है। पुराने वाहनों को नए वाहनों के साथ बदलने से अर्थव्यवस्था की ईंधन दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
- स्पेयर पार्ट्स की कीमतें गिरेंगी: धातु और प्लास्टिक भागों के पुनर्चक्रण से ऑटो सामानो की कीमतें काफी ज्यादा गिर जाएंगी।

- **पोस्ट-कोविड रिकवरी:** वाहन खुरचना और प्रतिस्थापन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को हरित प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को विशेषाधिकार प्रदान करने के मार्ग के रूप में देखा जाता है।
- **पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है:** नीति वाहनों के परिमार्जन की पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और पुनर्नवीनीकरण कच्चे माल के लिए बाजार का मार्ग प्रशस्त करता है
- **पेरिस जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है:** नीति को पेरिस समझौते के तहत मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने की एक पहल के रूप में देखा गया।

चुनौतियों

- एक बार उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने और छोटे शहरों में जाने से रोकने के लिए प्रवर्तन उन्हें निकाल देगा
- **संघीय चुनौतियां:** सभी राज्यों को बोर्ड पर होना चाहिए।
- निर्माताओं का समर्थन भी आवश्यक है जो मांग में तेजी से लाभ के लिए खड़े रहते हैं।
- भारी वाणिज्यिक वाहन, जो प्रदूषण में असमान रूप से योगदान करते हैं - 1.7 मिलियन में फिटनेस प्रमाणपत्र की कमी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है।
- **छोटे ऑपरेटरों पर असंगत रूप से प्रभाव डालता है:** इनमें से कई को छोटे ऑपरेटरों के लिए वित्तीय व्यवस्था के अभाव में जल्दी से नहीं बदला जा सकता है, जिन्होंने नए उपायों का विरोध किया है।
- **सलाहकारों की प्रकृति:** दिलचस्प बात यह है कि प्रमाणपत्रों को खत्म करने की छूट मात्र एक सलाह है, न कि एक जनादेश अर्थात यह ऑटोमेकर्स पर छूट प्रदान करने के लिए होगा।

और क्या किया जा सकता है?

- राज्यों को भी रोड टैक्स और पंजीकरण रियायत प्रदान करने के लिए बोर्ड पर आना चाहिए, जबकि ऑटोमोबाइल उद्योग से नए वाहनों पर वास्तविक छूट के साथ सौदा करने की उम्मीद है।
- केंद्र को एक संतुलन पर पहुंचना पड़ता है और ऐसे प्रोत्साहन मिलते हैं जो वाहनों के निर्माताओं को पुरस्कृत करते हैं जो सबसे अधिक ईंधन सक्षम रहते हैं
- ईंधन दक्षता को प्राथमिकता देने और यहां तक कि उच्च मानकों को पूरा करने में विफलता और ईंधन गजलरो पर करों में वृद्धि केवल विदेश में वाहन विनिमय कार्यक्रमों की गलतियों को दोहराएगी, जहां पूर्ण पर्यावरणीय लाभ का एहसास नहीं होगा और करदाताओं ने सब्सिडी की अक्षमता को समाप्त कर देगा।

निष्कर्ष

- पारिस्थितिक स्क्रैपिंग, एक अवधारणा के रूप में, सामग्री की वसूली की उच्च दर का नेतृत्व करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण, खनन और पर्यावरण पर दबाव कम हो सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- इलेक्ट्रिक वाहन बनाम हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहन

केन-बेतवा लिंक परियोजना

संदर्भ: केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) को लागू करने के लिए केंद्रीय जल मंत्री, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

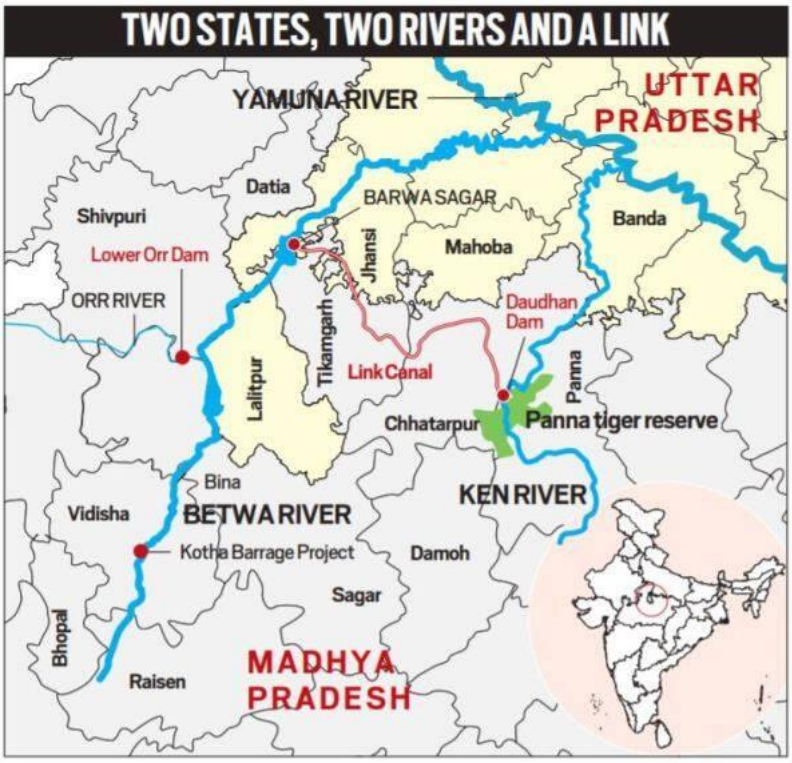

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है?

- **नदियों का परस्पर जुड़ाव:** केन-बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा केन नदी के पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। ये दोनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं
- **पहला चरण:** केन-बेतवा लिंक परियोजना के दो चरण हैं। फेज- I के तहत, घटकों में से एक दौधन बांध परिसर और निम्न स्तर की सुरंग तथा उच्च स्तर की सुरंग, केन-बेतवा लिंक नहर और पावर हाउस जैसे इसके मूल्यांकन को पूरा किया जाएगा।
- **दूसरा चरण:** जबकि फेज-II में, तीन घटक - लोअर ऑयर बांध, बीना जटिल परियोजना और कोठा बैराज का निर्माण किया जाएगा।
- **अनुमानित लागत:** व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, केन-बेतवा लिंक परियोजना की लागत 2017-18 की कीमतों पर 35,111.24 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- **क्षेत्र लाभान्वित:** केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में है, जो एक सूखा क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला है। इस परियोजना से इस पिछड़े क्षेत्र को काफी फायदा होगा और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी।
- **पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित:** केन बेतवा लिंक परियोजना के दौधन बांध के डूबे क्षेत्र में आने वाले 6,017 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 4,206 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य बाघ निवास के अंदर स्थित है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** वन सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना के लिए अनुमानित 4.6 मिलियन पेड़ों को काट दिया गया, जो पहले से ही सूखे बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा।

- **क्लीयरेंस रिक्वायरमेंट:** सामान्यतः रिवर प्रोजेक्ट्स को इंटरलिंक करने के लिए 4-5 तरह के क्लीयरेंस की जरूरत होती है। ये है-
  - o तकनीकी-आर्थिक (केंद्रीय जल आयोग द्वारा दिया गया)
  - o वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी (पर्यावरण और वन मंत्रालय)
  - o आदिवासी जनसंख्या का पुनर्वास और पुनर्वास योजना (जनजातीय मामलों का मंत्रालय)
  - o वन्यजीव निकासी (केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति)

केन-बेतवा परियोजना के लाभ

परियोजना प्रदान करने की उम्मीद-

- 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई,
- लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति
- पनबिजली के 103 मेगावाट उत्पन्न करना
- यह नदी परियोजनाओं के अधिक अंतःक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी की कमी देश में विकास के लिए अवरोधक न बने।

क्या भारत में नदी-जोड़ने के पिछले उदाहरण हैं?

- पिछले दिनों, कई नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को लिया गया। उदाहरण के लिए पेरियार परियोजना के तहत, पेरियार बेसिन से वैगाई बेसिन तक पानी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई।
- यह 1895 में चालू किया गया। इसी तरह अन्य परियोजनाएं जैसे परम्बिकुलम अलियार, कुर्नूल कुडप्पा नहर, तेलुगु गंगा परियोजना, और रवि-ब्यास-सतलज आदि

भारत में नदियों को आपस में जोड़ने पर हालिया घटनाक्रम

- 1970 के दशक में, नदी से जल-घाटे वाले क्षेत्र में अधिशेष जल को स्थानांतरित करने के विचार को तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री (पहले जल शक्ति मंत्रालय सिंचाई मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) डॉ के एल राव द्वारा वाद-विवाद किया गया।
- डॉ. राव, जो खुद एक इंजीनियर थे उन्होंने जल-समृद्ध क्षेत्रों से जल-कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण का सुझाव दिया।
- इसी तरह, कप्तान दिनशॉ जे दस्तूर ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी के पुनर्वितरण के लिए गारलैंड नहर का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, सरकार ने इन दोनों विचारों को आगे नहीं बढ़ाया।
- अगस्त, 1980 में सिंचाई मंत्रालय ने देश में अंतर बेसिन जल हस्तांतरण की परिकल्पना करते हुए जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनएनपी) तैयार की।
- एनपीपी में दो घटक शामिल थे: (i) हिमालयी नदियाँ विकास; और (ii) प्रायद्वीपीय नदियों का विकास।
- एनपीपी के आधार पर, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) ने 30 लिंक्स (प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 16 और हिमालयी क्षेत्र में 14) की पहचान की है।
- बाद में, तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत नदी को जोड़ने वाले विचार को पुनर्जीवित किया गया।
- केन बेतवा लिंक परियोजना प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं में से एक है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- क्या आपको लगता है कि भारत में जल प्रबंधन के लिए रिवर इंटरलिंकिंग सबसे उपयुक्त तरीका है? विवेचनात्मक रूप से जांच करें।

जलवायु डेटा सेवा पोर्टल का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जलवायु डेटा सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया गया
- **मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **द्वारा विकसित:** आईएमडी, पुणे
- इसमें जलवायु डेटा प्रबंधन और उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति के लिए अनुकूल आधारशिला हैं
- यह पूरी तरह से स्वचालित जलवायु डेटा प्रबंधन प्रक्रिया का पूरक है
- **प्रमुख घटक:**
  1. आईएमडी वेधशालाओं द्वारा ज्ञात मौसम टिप्पणियों की वास्तविक समय की निगरानी।
  2. आईएमडी मेटाडेटा पोर्टल, अन्य रिपोर्ट और डैशबोर्ड एनकैप्सुलेटेड
  3. डाटा आपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मौसम संबंधी डेटा तक ऑनलाइन पहुंच।
  4. भारत के ग्रिडिड तापमान और वर्षा डेटा के लिए मुफ्त डाउनलोड की सुविधा।
  5. क्लेमैटोलॉजिकल टेबल, एक्सट्रीम और नॉर्मल।
  6. मानसून वर्षा और चक्रवात आवृत्तियों पर जानकारी।
  7. डेटा एनालिटिक्स और जानकारी ग्राफिक्स

AEG12 कोरोना वायरस पर लगाम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता; विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों के अनुसार, AEG12 नामक एक मच्छर पीले बुखार, डेंगू, वेस्ट नाइल और ज़ीका के वायरस को रोकता है और कोरोनावायरस को भी कमजोर करता है

सुर्खिओ में क्यों-

- शोधकर्ताओं ने पाया कि AEG12 मच्छर वायरल एनवेलप को रोकता है और उसके प्रोटेक्शन के परत को तोड़कर उसे कमजोर बनाता है
- प्रोटीन उन वायरस को प्रभावित नहीं करता है जिनके पास एक वायरल एनवेलप नहीं है।
- आणविक स्तर पर, AEG12 लिपिड को बाहर निकालता है
- निष्कर्षों से विश्व भर के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विषाणुओं के खिलाफ उपचार हो सकता है।
- AEG12 अन्य वायरसों के तुलना में flaviviruses पर सबसे ज्यादा असरदार है। flaviviruse वायरस का एक परिवार है जिसमें ज़ीका, वेस्ट नाइल, और अन्य शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह भी पाया कि AEG12 वायरस SAR12-CoV-2 के खिलाफ प्रभावी हो सकता है।

- लेकिन, Covid-19 के लिए AEG12 की मदद से कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बायोइंजीनियरिंग में कई साल लगेंगे।

IAS BABA

INTERVIEW MENTORSHIP PROGRAM (IMP) 2020

OUR INTERVIEW PANELISTS

Shri SS Meenakshisundaram - IAS (Retd.)
Executive Vice- Chairman of MYRADA
Professor, National Institute of Advanced Studies, Bangalore.

Shri Gurucharan Gollarkeri - IAS (Retd.)
Secretary (Budget and Resources) to the Govt. of Karnataka.

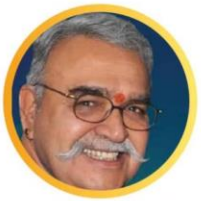

Shri C V Gopinath IES
Former Union Additional Secretary.

Mr. Sunil Oberoi- IAS (Retd.)
Worked on Civil Service Reforms in India with UNDP and DOPT And associated with Civil Service Training.

Shri P.D. Hallur
Major General (Retd.)

Dr. R M Kummur
Ph.D (IARI), Chief General Manager NABARD
President Agricos Foundation for New India (AFIN), Director IDF Financial Services Ltd.

Shri M G Chandrakanth
Professor & Director of the Institute for Social & Economic Change (ISEC)
Head of Agricultural Economics.

Mr. Gaurav Bansal, IRTS
Former Director of North Central zone cultural centre (NCZCC), Chief public relations officer of North Central Railways.

Shri T.S Somashekar
Professor of Economics, Director-Center for Competition & Regulation, National law School of India University Bengaluru.

Shri K.H. Mishra
DIG/ Range commandant, UP

Smt.Kavitha
Senior Academician, an Industry Expert with 21+ years of experience in Academics, Strategy , Consulting & Management.

Dr. Akash Shankar, IAS
AIR 78, CSE 2018.
Interview Topper - scored 204 in Personality test.

समाचारों में एम्स / नेशनल पार्क्स

सुर्खिओं में प्रजातियां: हिमालयन सीरो

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता; वातावरण

सुर्खिओ में क्यों-

हाल ही में असम के मानस टाइगर रिज़र्व में हिमालयन सीरो को देखा गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- हिमालयन सीरो या 'केप्रिकार्निस सुमाट्रेन्सिस थार' (Capricornis sumatraensis thar) मुख्य भूमि सीरो (केप्रिकार्निस सुमाट्रेन्सिस) की एक उप-प्रजाति है।
- **सामान्य नाम:** हिमालयन सीरो
- **वैज्ञानिक नाम:** मकरिस सुमत्रेन्सी थार
- **स्थानीय नाम:** जिंगल, येमु
- 'हिमालयन सीरो' एक बकरी, एक गधा, एक गाय और एक सुअर का संकर (Cross) प्रतीत होता है।
- यह एक बड़े सिर, मोटी गर्दन, छोटे अंग, लंबे, खच्चर जैसे कान, और काले बालों के आवरण के साथ एक मध्यम आकार का स्तनपायी है।
- इसका मोटे कोट काले से लाल रंग में भिन्न होता है।
- **आईयूसीएन स्थिति:** कमजोर
- यह CITES परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है
- यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध है, जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

- हिमालयी सीरो का पहले 'संकटासन्न' (Near threatened) के रूप में मूल्यांकन किया गया था, लेकिन अब इसे IUCN रेड लिस्ट में 'अतिसंवेदनशील' (vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

'हिप्निया इंडिका' (Hypnea indica) और 'हिप्निया बुलैटा' (Hypnea bullata: समुद्री शैवाल की दो नई प्रजातियां

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता

सुर्खिओ में क्यों-

- सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा के समुद्री जीवविज्ञानी के एक समूह द्वारा समुद्री शैवाल की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इनका नाम 'हिप्निया इंडिका' (Hypnea indica) और 'हिप्निया बुलैटा' (Hypnea bullata) है, समुद्री शैवाल 'हिप्निया वंश' या लाल समुद्री शैवाल का हिस्सा हैं।
- 'हिप्निया इंडिका' को तमिलनाडु में कन्याकुमारी, गुजरात में सोमनाथ पठान और शिवराजपुर में खोजा गया, जबकि 'हिप्निया बुलैटा' को कन्याकुमारी और दमन और दीव के द्वीप में खोजा गया।
- अध्ययन में पहली बार भारतीय तट में एक अन्य हिप्निया प्रजाति 'हिप्निया निडिफिका' (Hypnea nidifica) भी दर्ज की गई।
- जीनस हिप्निया में कैल्केरियास, इरेक्ट, ब्रांकेड लाल समुद्री शैवाल होते हैं।

नचदुबा सिनथला रामास्वामी सदाशिवन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता

सुर्खिओ में क्यों-

- लेपिडोप्टेरिस्ट्स के एक समूह ने भारत में एक नई तितली प्रजाति पाई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस प्रजाति का नाम नाकाडुबा सिनथला रामास्वामी सदाशिवन है
- यह पश्चिमी घाट में अगस्त्यमाली में खोजा गया
- लाइकेनिड तितलियों का नया टैक्सन नाकाडुबा नस्ल से संबंधित है।
- लाइन ब्लूज़ छोटी तितलियाँ हैं जो सबफ़ैमिली लाइकैनेडी से संबंधित हैं।
- इनका फैलाव भारत और श्रीलंका से लेकर पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और समोआ तक है।
- यह पहली बार है कि एक तितली प्रजाति को पश्चिमी घाट के एक अखिल भारतीय अनुसंधान दल द्वारा खोजा गया।

क्या आप जानते हैं?

- लेपिडोप्टेरोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन और तितलियों के तीन सुपरफैमिली से संबंधित एंटोमोलॉजी की एक शाखा है।
- इस क्षेत्र में अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति लेपिडोप्टेरिस्ट या एक यूरेलियन है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

उड़ान योजना के तहत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बरेली हवाई अड्डे पर नए अपग्रेड त्रिशूल सैन्य एयरबेस के लिए पहली उड़ान को रवाना किया गया।
- **मंत्रालय:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम - उड़े देश का आम नागरिक (RCS-UDAN) योजना के तहत किया गया है।
- त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस, बरेली भारतीय वायु सेना के अंतर्गत आता है और अंतरिम नागरिक उड्डयन कार्यों के निर्माण के लिए जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है।
- पिछले साल ही उड़ान स्कीम-4 के तहत दिल्ली-बरेली रूट के लिए अलायन्स एयर को ठेका मंजूरी दी थी

संबंधित आलेख:

- कालबुर्गी से तिरुपति के बीच सीधी उड़ान
- उद्देश्य मूल्यांकन और योजना की पारदर्शिता के लिए उड़ान कॉल

सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) स्कीम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - ऊर्जा संसाधन

सुर्खिओ में क्यों-

- लोक सभा को 'सतत' योजना के बारे में बताया गया।

- **मंत्रालय:** पेट्रोलियम मंत्रालय

अन्य संबंधित तथ्य

- 'सतत' योजना 01 अक्टूबर, 2018 को शुरू की गई थी
- ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां (OGMC) कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) की खरीद के लिए संभावित उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित कर रही हैं।
- योजना के तहत प्रावधान: (1) OGMCs द्वारा लंबी अवधि के समझौतों के साथ सीबीजी को बंद करने का सुनिश्चित मूल्य; (2) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत किण्वित कार्बनिक खाद (FOM) के रूप में CBG पौधों से उत्पादित जैव खादों का समावेश; (3) RBI द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत CBG परियोजनाओं का समावेश
- 9 सीबीजी संयंत्रों को चालू करके आपूर्ति शुरू कर दी।
- ये संयंत्र आंध्र प्रदेश (1), गुजरात (3), हरियाणा (1), महाराष्ट्र (3) और तमिलनाडु (1) में स्थित हैं।
- ये संयंत्र उद्यमियों और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं जिन्होंने इन संयंत्रों को विकसित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए।

दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर; दूरसंचार

सुर्खिओ में क्यों-

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया।
- अब, इनमें 'विश्वसनीय टेलीकॉम उत्पाद' खरीदने और 'विश्वसनीय टेलीकॉम उपकरण स्रोतों से सोर्सिंग उपकरण' के रूप में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसका मतलब यह है कि नामित प्राधिकरण इन दो पहलुओं (रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा) को निर्दिष्ट कर सकता है और दूरसंचार कंपनियों से उन उत्पादों का उपयोग नहीं करने के लिए कहेगा, जिन्हें किसी भी समय असुरक्षित माना गया।
- नए मानदंड 15 जून, 2021 से लागू होंगे।
- प्रवर्तन के बाद, दूरसंचार कंपनियां किसी भी उत्पाद का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगी जो कि विश्वसनीय दूरसंचार उपकरण स्रोत-सूची या विश्वसनीय दूरसंचार उत्पाद सूची में दिखाई नहीं देती हैं।
- यदि कोई टेलीकॉम कंपनी किसी ऐसे उपकरण का उपयोग करके अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है जो किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं है, तो उसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

क्या आप जानते हैं?

- दिसंबर 2020 में, भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दूरसंचार क्षेत्र पर "राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश" की स्थापना को मंजूरी दी।
- **उद्देश्य:** दूरसंचार उत्पादों और उनके स्रोतों को 'विश्वसनीय' और 'गैर-विश्वसनीय' श्रेणियों के द्वारा वर्गीकृत करना।
- उत्पादों की सूची दूरसंचार कंपनियों को अपने नेटवर्क में उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- NCSC उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी के आधार पर अपना निर्णय करेगा।

अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021 जारी किए गए।
- इसके द्वारा, कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से "अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण / परमिट" के लिए आवेदन कर सकता है।
- **मंत्रालय:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने और जमा करने के 30 दिनों के भीतर शुल्क जमा करने के बाद इसे जारी किया जाएगा।
- यह 01 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
- नए नियम राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे और उनका राजस्व बढ़ाएंगे।

रामागुंडम में 100 मेगावाट का तैरता हुआ सौर ऊर्जा सयंत्र

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर; पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा

सुर्खिओ में क्यों-

- एनटीपीसी रामागुंडम (तेलंगाना में) में अपने थर्मल प्लांट के जलाशय में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट (उत्पादन क्षमता द्वारा) विकसित कर रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत 2022 तक अपने नवीकरणीय क्षमता के 175 GW के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से ही ट्रैक पर है। भारत ने 2030 तक 450 GW को भी लक्षित किया है।

वन नेशन, वन गैस ग्रिड

संदर्भ: जनवरी 2021 में, प्रधान मंत्री ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक में मंगलुरु तक 450 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह आयोजन 'वन नेशन, वन गैस ग्रिड ' के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पाइपलाइन की मुख्य विशेषताएं

- **द्वारा निर्मित:** 450 किलोमीटर की पाइपलाइन गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बनाई गई है
- **परिवहन क्षमता:** प्रति दिन 12 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर
- **गंतव्य:** यह कोच्चि से मंगलुरु तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) रेगीजेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस ले जाएगा
- **भौगोलिक चुनौतियां:** पाइप लाइन बिछाना एक इंजीनियरिंग चुनौती थी क्योंकि पाइपलाइन के मार्ग में इसे 100 से अधिक जलीय स्थानों को पार करना आवश्यक था। यह एक विशेष तकनीक के माध्यम से किया गया जिसे क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि कहा जाता है

- **अंतिम उपयोगकर्ता:** पाइपलाइन घरों, परिवहन क्षेत्र और पाइपलाइन के साथ जिलों में वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती ईंधन की आपूर्ति करेगी।
- **रोजगार:** इस पाइपलाइन के निर्माण से 1.2 मिलियन मानव दिवस रोजगार उत्पन्न हुए हैं

वन नेशन, वन गैस ग्रिड

- योजना और परिचालन उद्देश्यों के लिए भारतीय विद्युत प्रणाली को पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है।
- वन नेशन, वन गैस ग्रिड इन क्षेत्रीय ग्रिडों के एकीकरण को संदर्भित करता है, इस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों जैसे विभिन्न हितधारकों को प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करता है।

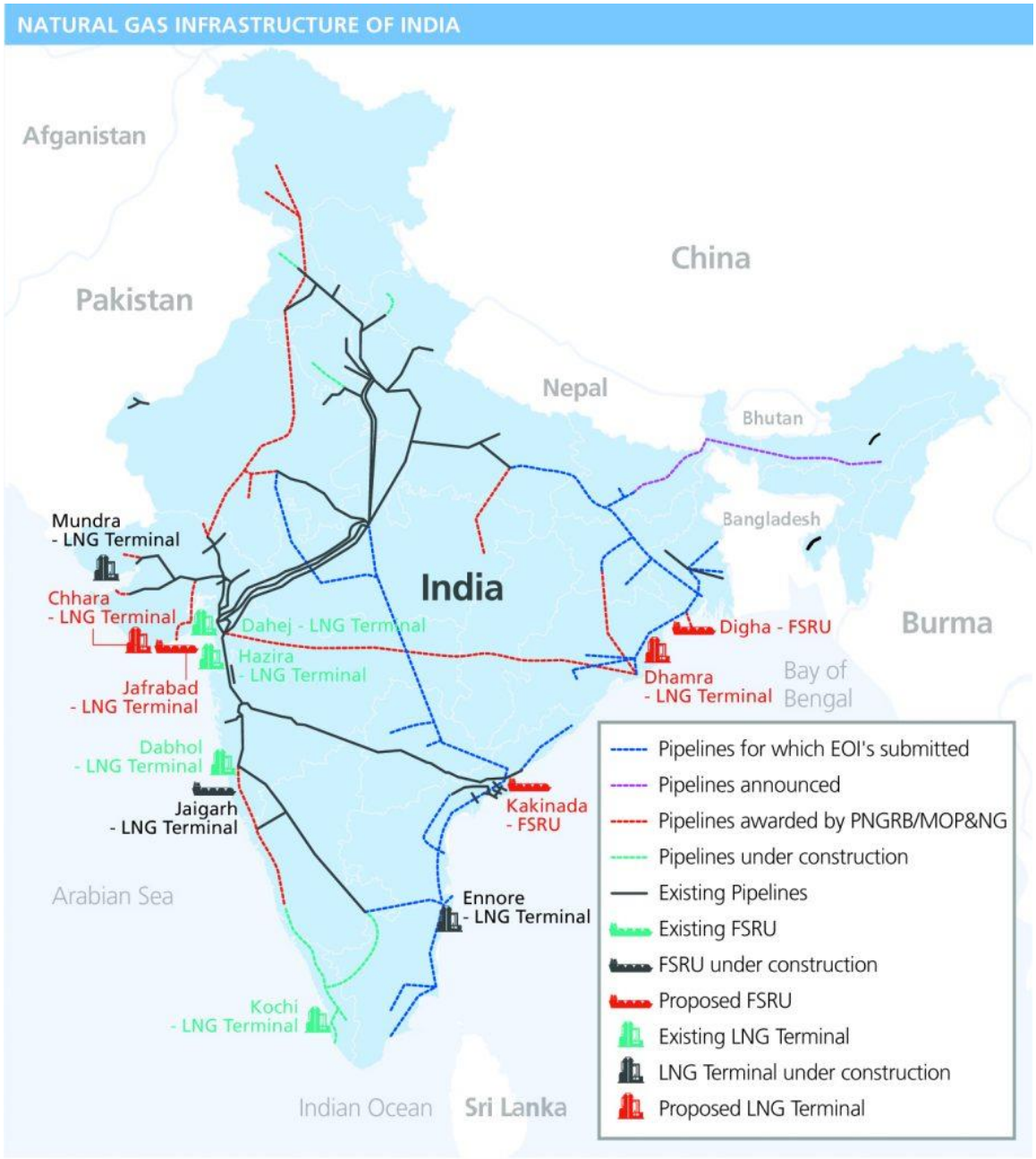

चित्र स्रोत: ICIS

वन नेशन वन ग्रिड के फायदे

- **राष्ट्र को जोड़ना:** एक राष्ट्र और एक गैस ग्रिड के साथ, प्राकृतिक गैस से उत्पादित ऊर्जा पूरे देश में एकल स्रोत के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।
- **तेजी से विस्तार में मदद करता है:** 2014 से पहले 27 वर्षों में, केवल 15,000 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान में देश भर में 16,000 किमी से अधिक गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है जो अगले 5-6 वर्षों में पूरा हो जाएगा
- **क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करता है:** यह गैस उपलब्धता के क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने में मदद करेगा क्योंकि वर्तमान में प्राकृतिक गैस केवल देश के पास सीमित है।
- **गैस आधारित अर्थव्यवस्था:** भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने से ग्रिड गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएगा।
- **स्वच्छ पर्यावरण:** ऐसे समय में जब पारंपरिक स्रोत कम हो रहे हैं खनन को अधिक गहराई और क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है, प्राकृतिक गैस वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण को रोककर यह एक वरदान साबित हो सकता है।
- पेरिस जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है: भारत ने दिसंबर 2015 में COP21 पेरिस समझौते में प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि 2030 तक, यह 2005 के 33% कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। घरेलू गैस ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस, परिवहन क्षेत्र के साथ-साथ उद्योगों और वाणिज्यिक इकाइयों के लिए ईंधन के रूप में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आगे की राह

- छोटे फर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्राकृतिक गैस में निवेश को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
- सरकार को प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था और इसके लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।
- गैस के अधिक उत्पादन के लिए अधिक एलएनजी टर्मिनलों की आवश्यकता है
- इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न खिलाड़ियों जैसे केंद्र सरकार, निजी खिलाड़ियों, राज्य सरकारों, आर एंड डी संगठनों (पूर्व: सीएसआईआर) और विदेशी खिलाड़ियों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्राकृतिक गैस विपणन सुधार

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की 'टिकाऊ' दृष्टि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर; वातावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- 150 वर्ग किमी से अधिक नीति आयोग- प्रायोगिक समग्र के चरण I और ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए टिकाऊ दृष्टि के लिए भूमि का (18%) उपलब्ध कराया जा रहा है।
- यह द्वीप अंडमान और निकोबार समूह में सबसे दक्षिणी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह अपनी तटरेखा के लगभग एक चौथाई हिस्से को कवर करेगा।
- समग्र योजना में एक प्रमुख भाग के उपयोग की परिकल्पना की गई है जो कि वन और तटीय प्रणाली है।
- निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं में दक्षिण-खाड़ी में एक हवाई अड्डा परिसर, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (टीएसपी), एक समानांतर-टू-द-कोस्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तट पर एक भंडारण परिसर शामिल है।
- **नोडल एजेंसी:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)
- जनवरी 2021 में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़ (NBWL) की स्थायी समिति ने पूरे गैलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य को बंदरगाह के लिए अनुमति देने के लिए चयनित किया।

क्या आप जानते हैं?

- निकोबार मेगापोड विश्व स्तर पर लुप्तप्राय पक्षी है जो निकोबार के लिए अद्वितीय है।
- प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र शोमेन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान हैं।

ई-टेंड्रिंग पोर्टल 'प्रणीत'

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खिओ में क्यों-

- पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID), केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने एक ई-टेंडरिंग पोर्टल-PRITIT की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह कम कागजी कार्रवाई और संचालन में आसानी से बढ़ावा देगा, जिससे निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाएगी।
- **द्वारा प्रमाणित:** मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (STQC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- पावर ग्रिड अब भारत में एकमात्र संगठन है, जिसके पास SAP आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (SRM) पर एक eProcurement समाधान है, जो STQC द्वारा निर्धारित सुरक्षा और पारदर्शिता से संबंधित सभी लागू आवश्यकताओं के अनुरूप है।

दीघा और कंकड़बाग सीवरेज परियोजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्रों के लिए एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क के विकास के लिए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

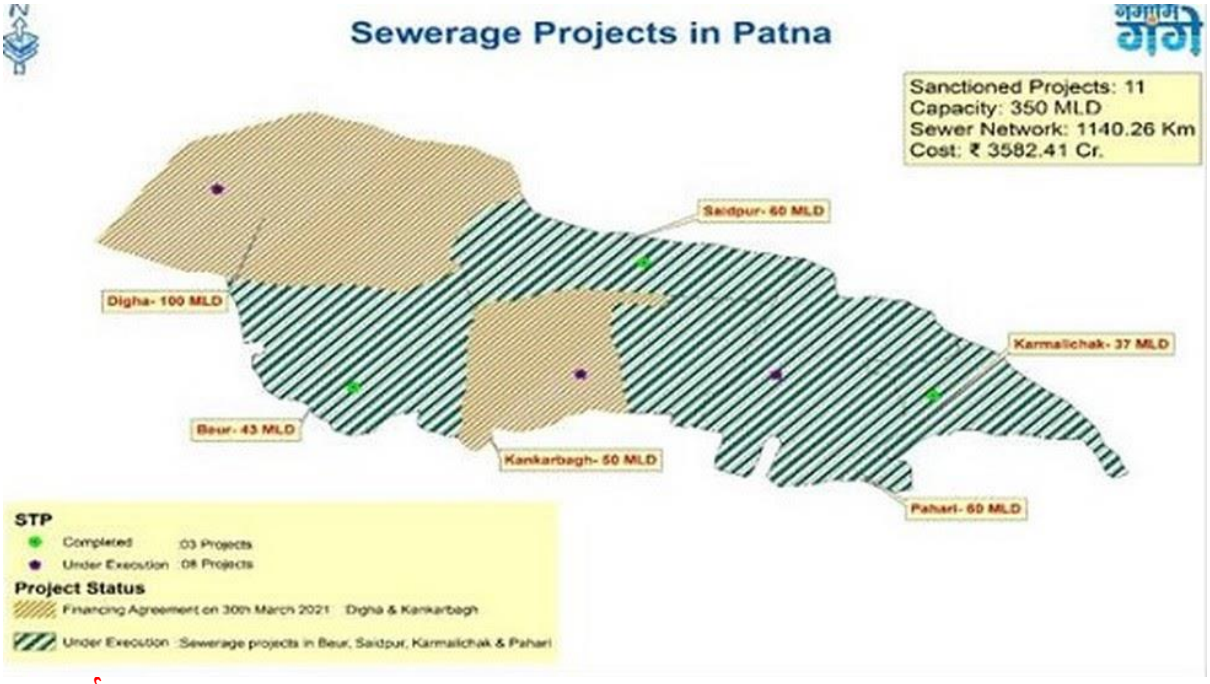

महत्वपूर्ण तथ्य

- परियोजना के दायरे में पटना के दीघा और कंकरबाग क्षेत्रों में 453 किमी से अधिक के सीवरेज नेटवर्क के साथ 150 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास शामिल है, जो गंगा नदी के किनारे सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है।
- यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट , ट्रांसफर ('DBOT') क्षेत्र और हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) क्षेत्र का मिश्रण शामिल है।
- इसके कार्यान्वयन के साथ, पटना शहर के सभी सीवेज जोन को सीवरेज नेटवर्क और सीवेज उपचार क्षमता के साथ कवर किया जाएगा।
- गंगा नदी में किसी भी अनुपयोगी अपशिष्ट को रोकने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य को हासिल होने में मदद मिलेगी।

संबंधित आलेख:

- नमामि गंगे मिशन के तहत मेगा विकास परियोजनाएं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

अमोनिया -1 उपग्रह का प्रक्षेपण

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; अंतरिक्ष

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया -1 उपग्रह और 18 सह-यात्री उपग्रहों को PSLV-C51 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- PSLV-C51, PSLV का 53 वां मिशन है।
- अमेजोनिया-1 प्रक्षेपण का पहला उपग्रह है।
- PSLV-C51/Amazonia-1 न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है।
- NSIL अंतरिक्ष विभाग के द्वारा एक भारत सरकार की कंपनी है।
- अमेजोनिया-1 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (INPE) का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- यह उपग्रह उपयोगकर्ताओं को अमेज़ॅन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील के क्षेत्र में विविध कृषि के विश्लेषण के लिए रिमोट सेंसिंग जानकारी प्रदान करेगा।

संबंधित आलेख:

- CMS-01 सफलतापूर्वक PSLV-C50 द्वारा लॉन्च किया गया
- इसरो की सफलताएँ

टीएलआर 7/8: इंडियन लैब द्वारा विकसित कोवाक्सिन का प्रमुख अणु

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक; भारतीयों की उपलब्धियां

सुर्खिओ में क्यों-

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (IICT), काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) लैब ने COVAXIN के लिए महत्वपूर्ण अणु के विकास में मदद की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कोवाक्सिन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी वैक्सीन है।
- यह एक अत्यधिक शुद्ध, संपूर्ण विषाणु, निष्क्रिय SARS-Cov-2 है।
- इसे Algel-IMDG के साथ तैयार किया गया है, जो शरीर को नुकसान पहुँचाए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के अपेक्षित प्रकार को उत्पन्न करने के लिए एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड gel पर सहायक के रूप में TLR 7/8 को रासायनिक रूप से अवशोषित किया जाता है।

संबंधित आलेख:

- एक प्रभावी टीकाकरण वितरण नीति की ओर

मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (MTRC)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- मुंबई में वेस्टर्न रेलवे ट्रेनों में मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन (MTRC) सिस्टम शुरू किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली एक प्रभावी और तकनीकी रूप से विकसित संचार प्रणाली है।
- यह प्रभावी दुर्घटनाओं के माध्यम से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और देरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- MTRC हवाई जहाजों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ARC) के समान कार्य करता है।
- यह ट्रेन और नियंत्रण कक्ष के बीच संचार की निगरानी को पता तथा सहायता करेगा।
- यह पहली बार है कि MTRC को भारतीय रेलवे में साधिकार किया गया है।
- चर्चगेट और विरार के बीच चलने वाली 100 में से 90 रेक में नई प्रणाली पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण को जुटाना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - प्रौद्योगिकी; वातावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में एक नई रिपोर्ट मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया जारी की गई।
- **द्वारा जारी:** NITI Aayog और Rocky Mountain Institute (RMI) भारत

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए भारत के संक्रमण में वित्त की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- इसने यह भी विश्लेषण किया है कि अगले दशक में संक्रमण ईवीएस में 266 बिलियन अमरीकी डॉलर के पूंजी निवेश, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और बैटरी की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में उपभोक्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उच्च ब्याज दर, बीमा दर और कम ऋण-से-मूल्य अनुपात।
- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए 10 समाधानों की पहचान की गई है।
- वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, एनबीएफसी तथा उद्योग और सरकार समाधानों को अपनाने में सक्षम होंगे।

संबंधित आलेख:

- बिजली के वाहन
- ऑटो उद्योग पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव

हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण; विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग को वैज्ञानिकों द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), पणजी, गोवा से लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- जहाज पर एक दल सिंधु साधना (Sindhu Sadhana) नामक पोत के माध्यम से इस अनुसंधान परियोजना पर हिंद महासागर में 10,000 समुद्री मील की यात्रा करके समुद्र के आंतरिक भाग की कार्यपद्धति को जान जा सके।
- यह भारत में अपनी तरह का पहला अनुसंधान प्रोजेक्ट है।
- **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन, पोषक तत्त्वों में कमी और बढ़ते प्रदूषण के लिये जैव रसायन तथा महासागर की प्रतिक्रिया को समझना।
- **अवधि:** 3 वर्ष

मार्टियन 'ब्लूबेरी' पृथ्वी पर एक समानांतर मिलना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अंतरिक्ष; विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में हुए एक शोध पत्र के अनुसार, मार्टियन ब्लूबेरी पृथ्वी पर एक समानांतर है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2004 में, नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर 'ऑपर्च्युनिटी' ने ग्रह पर कई छोटे-छोटे गोले पाए, जिन्हें अनौपचारिक रूप से मार्टियन ब्लूबेरी नाम दिया गया।
- अवसर के स्पेक्ट्रोमीटर ने नोट किया कि वे हेमटाइट्स नामक लोहे के ऑक्साइड यौगिक से बने थे।
- हेमाटाइट्स की उपस्थिति से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था।
- हेमेटाइट को ऑक्सीकरण वातावरण में बनाने के लिए जाना जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- हेमटेट सम्मेलनों के गुजरात में झुरान गठन (जो 145 और 201 मिलियन वर्ष पुराना है) के अध्ययन से पता चला है कि वे मंगल ग्रह पर मिलते जुलते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, 2019

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - शिक्षा और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- राज्यसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2019 पारित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया है।
- ये संस्थान हैं: (1) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान और प्रबंधन कुंडली, हरियाणा में; (2) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तमिलनाडु का तंजावुर में;
- विधेयक इन संस्थानों को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन के रूप में घोषित करता है।

RE-HAB परियोजना का पुन: शुरूआत

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता; वातावरण

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में प्रोजेक्ट आरई-एचएबी (हाथी-मानव संघर्ष कम करने हेतु मधुमक्खियों का उपयोग) कर्नाटक के कोडागु में शुरू किया गया।
- **द्वारा शुरू किया गया:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)
- **उद्देश्य:** मानव बस्तियों में हाथी के हमलों को विफल करने हेतु मधुमक्खियों का उपयोग करके "मधुमक्खी बाड़" का निर्माण करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ऐसा माना जाता है, कि हाथी कहीं भी मधुमक्खियों के करीब नहीं जाएंगे, इसलिए जंगल और गाँवों की सीमा पर मधुमक्खी के बक्से लगाए जाएंगे
- ये स्पॉट नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व के क्षेत्र में स्थित हैं, जिन्हें संघर्ष क्षेत्र कहा जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि हाथियों के डर से मधुमक्खियों को मानव परिदृश्य में स्थानांतरित होने से रोका जाएगा।
- यह KVIC के 'राष्ट्रीय शहद मिशन' के अंतर्गत एक उप-मिशन है।

उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता

संदर्भ: एआई हमें भूख, गरीबी और बीमारी के उन्मूलन की दिशा में छलांग लगाती है तथा जलवायु परिवर्तन के शमन, शिक्षा और वैज्ञानिक खोज के लिए नए और अकल्पनीय रास्ता दिखाती है।

लाभ और संभावित

- **बहु-क्षेत्रीय अनुप्रयोग:** पहले से ही एआई ने फसल की पैदावार, व्यापार उत्पादकता बढ़ाने, ऋण में सुधार और कैंसर का पता लगाने में तेजी से अधिक मदद किया।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है:** यह 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में 15 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देकर वैश्विक जीडीपी में 14% जोड़ सकता है। गूगल ने विश्व भर में "एआई फॉर गुड" 2,600 से अधिक उपयोग मामलों की पहचान की है।
- **इंस्बेलर्स फॉर SGDs:** नेचर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के प्रभाव की समीक्षा करते हुए उसके स्वभाव रूप में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि एआई सभी एसडीजी लक्ष्यों के 134 या 79% पर एक संबल के रूप में कार्य कर सकता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **बिग कार्बन फुटप्रिंट:** एआई को बड़े पैमाने पर कम्प्यूटेशनल क्षमता की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है अधिक पॉवर हंगरी डेटा केंद्र और एक बड़ा कार्बन पदचिह्न।
- **कम आय वाली नौकरियों का नुकसान:** रोबोटिक्स और एआई कंपनियां उन बुद्धिमान मशीनों का निर्माण कर रही हैं जो आम तौर पर निम्न-आय वाले श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करती हैं जैसे कैशियर को बदलने के लिए स्वयं-सेवा कियोस्क, फील्ड वर्कर्स को बदलने के लिए फल-पिकिंग रोबोट आदि। एआई द्वारा कई डेस्क जॉब्स को भी संपादित किया जाएगा। जैसे कि एकाउंटेंट, वित्तीय व्यापारी और मध्यस्थिति प्रबंधक।
- **विधियाँ असमानताएँ:** एआई डिजिटल बहिष्करण को संयोजित करना, श्रमिकों को बचाने के लिए स्पष्ट नीतियों के बिना नए अवसरों का वादा करना तथा वास्तव में गंभीर नई असमानताएं पैदा करना आदि।
- **उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन को मजबूत करें:** निवेश उन देशों में स्थानांतरित होने की संभावना है जहां एआई-संबंधित कार्य पहले से ही स्थापित हैं, देशों के बीच और भीतर अंतराल को चौड़ा करना।

- **मौजूदा पूर्वाग्रहों पर रोक लगाना:** मौजूदा वर्कफोर्स प्रोफाइल के आधार पर AI-एन्हांस्ड रिक्रूटमेंट इंजन, ने खुद को सिखाया कि पुरुष उम्मीदवार महिला के लिए बेहतर थे। AI चेहरे की पहचान और निगरानी तकनीक रंग और अल्पसंख्यकों के लोगों के खिलाफ भेदभाव।
- **गोपनीयता की चिंता:** एआई महत्वपूर्ण गोपनीय डेटा को प्रदर्शित करता है। वोटिंग निर्णयों को बदलने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका-एल्गोरिदम और अधिक डेटा का उपयोग किया गया।

आगे की राह

- एआई गवर्नेंस के लिए केवल "पूरे समाज" का दृष्टिकोण हमें व्यापक-आधारित नैतिक सिद्धांतों, संस्कृतियों और आचार संहिता को विकसित करने में सक्षम करता है।
- एआई की वैश्विक पहुंच को देखते हुए, इस तरह के दृष्टिकोण पर "पूरे समाज" तथा "पूरे विश्व" को आराम करना चाहिए।
- वैश्विक सहयोग पर बहु-हितधारक प्रयासों की आवश्यकता है, इसलिए एआई का उपयोग "भरोसेमंद, मानवाधिकार-आधारित, सुरक्षित और टिकाऊ, शांति को बढ़ावा देने" के लिए किया जाता है।
- डिजिटल भविष्य को बहु-हितधारक शासन संरचनाओं के बिना सही के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभांश निष्पक्ष, समावेशी और न्यायपूर्ण हों।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वोटिंग

CALM2 म्यूटेशन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; जैव प्रौद्योगिकी

सुर्खिओ में क्यों-

- ऑस्ट्रेलिया में, अग्रणी वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ हाल ही में एक अध्ययन के बाद पता चला है कि दोषी बाल हत्यारे कैथलीन फोल्बिग की क्षमा के लिए कह रहे हैं कि उसके पीड़ितों (अपने बच्चों) की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- चिकित्सा विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि एक दुर्लभ आनुवंशिक दोष के कारण उसके बच्चों की मृत्यु हो गई।
- उन्हें अपनी माँ से एक आनुवंशिक परिवर्तन विरासत में मिला, जिसे CALM2 कहा जाता है।
- CALM-2 उत्परिवर्तन हृदय की गिरफ्तारी के कारण अचानक मृत्यु का कारण बनता है।
- कैलमोडुलिन-2 एक प्रोटीन है जो मनुष्यों में CALM2 जीन द्वारा एन्कोडेड है।
- CALM2 में उत्परिवर्तन हृदय से संबंधित हैं।

इसरो की अंतरिक्ष संपत्ति संचालित करने के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस- III - अंतरिक्ष; विज्ञान और तकनीक

सुर्खिओ में क्यों-

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इसरो की पूंजी गहन अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का स्वामित्व और संचालन करेगा।
- नासा और इसरो NISAR नामक उपग्रह विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं।
- यह एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे आकार के क्षेत्रों में 0.4 इंच के रूप में पृथ्वी की सतह के आंदोलनों का पता लगाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए दो नए संचार उपग्रहों का स्वामित्व लेने के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ चर्चा के अग्रिम चरण में है।
- इन उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर निजी कंपनियों को डीटीएच और ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ पट्टे पर दिए जाएंगे।
- NISAR का नाम NASA-ISRO-SAR के लिए छोटा है।
- एसएआर ने सिंथेटिक एपर्चर रडार को संदर्भित किया है जो नासा पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग करेगा।
- इसके अलावा, SAR उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों के उत्पादन के लिए एक तकनीक को संदर्भित करता है।
- सटीकता के कारण, रडार बादलों और अंधेरे में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात डेटा एकत्र कर सकता है।
- नासा उपग्रह के लिए एक रडार, विज्ञान डेटा, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम के लिए एक उच्च दर संचार उपतंत्र प्रदान करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSE) है।
- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की एक वाणिज्यिक शाखा और विज्ञान विभाग की सहायक कंपनी है।
- **स्थापित:** 2019
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** अंतरिक्ष विभाग (DoS) और कंपनी अधिनियम 2013।
- **उद्देश्य:** भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना।
- **मुख्यालय:** बेंगलुरु।

संबंधित आलेख:

- CMS-01 सफलतापूर्वक PSLV-C50 द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसरो की सफलताएँ

लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक : लिडार (LIDAR)

लिडार एक 'सुदूर सम्वेदी तकनीक' है, जिसमें पल्स लेज़र के रूप में प्रकाश का उपयोग करके विमान में सुसज्जित लेज़र उपकरणों के माध्यम से किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है।

- लिडार एक स्पंदित लेजर का उपयोग पृथ्वी की सतह से एक वस्तु की चर दूरी की गणना करने के लिए करता है।
- लिडार एक साधारण सिद्धांत का पालन करता है - पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लेजर प्रकाश डालना और लिडार स्रोत पर वापस आने में लगे समय की गणना करना। जिस गति से प्रकाश जाता है (लगभग 186,000 मील प्रति सेकंड), यह देखते हुए कि लिडार के माध्यम से सटीक दूरी को मापने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज प्रतीत होती है।
- ये हल्की पल्स - एयरबोर्न सिस्टम द्वारा एकत्र की गई जानकारी के साथ पृथ्वी की सतह और लक्ष्य वस्तु के बारे में सटीक 3D जानकारी उत्पन्न करती हैं।
- एक लिडार उपकरण के तीन प्राथमिक घटक हैं - स्कैनर, लेजर और जीपीएस रिसीवर। डेटा संग्रह और विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य तत्व फोटोडेटेक्टर और प्रकाशिकी हैं।
- **दो प्रकार:** डेटा एकत्र करने के लिए एक हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर स्थापित एयरबोर्न लिडार और सटीक डेटा बिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी की सतह पर वाहनों या तिपाई पर स्थापित स्थलीय लिडार सिस्टम।

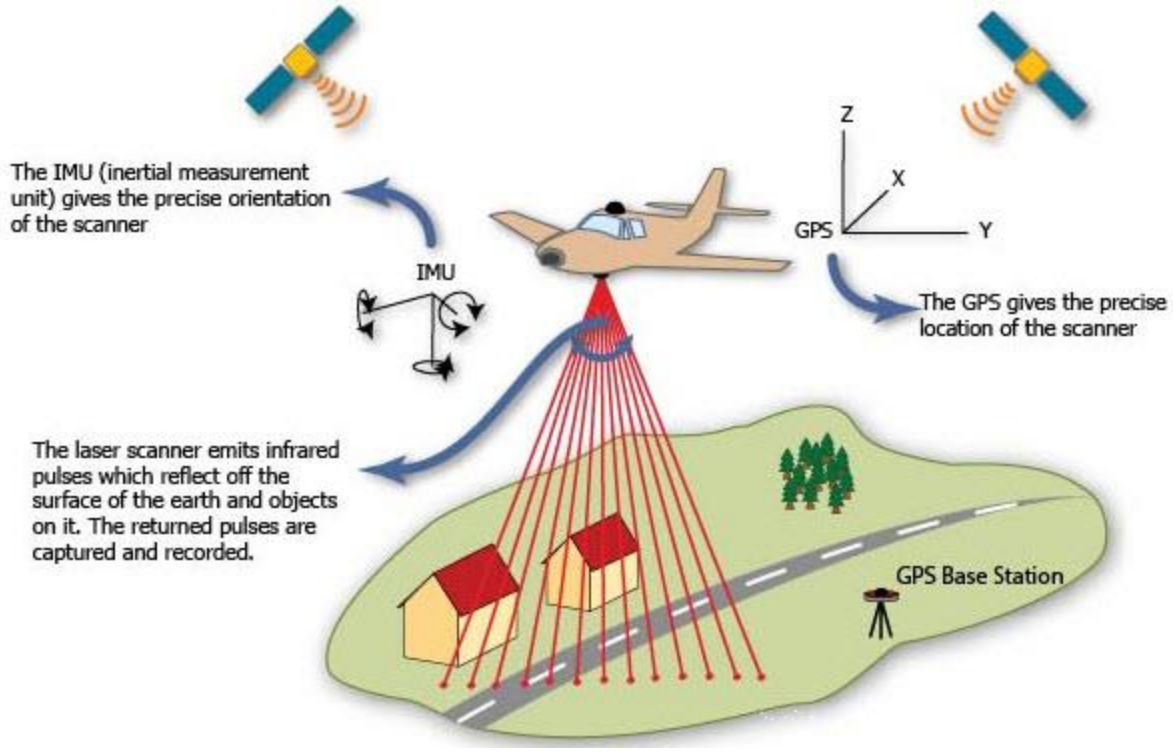

लिडार के अनुप्रयोग

- **समुद्र विज्ञान:** लिडार प्रौद्योगिकी का उपयोग भूमि को मापना , सीफ्लोर और रिवरबेड ऊँचाई को मापना तथा समुद्र की सतह में फाइटोप्लांकटन प्रतिदीप्ति और बायोमास की गणना के लिए किया जाता है जो बहुत चुनौतीपूर्ण है।
- **डिजिटल एलिवेशन या टेरेन मॉडल:** सड़कों, बड़े भवनों और पुलों के निर्माण के दौरान इलाके की ऊँचाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। LiDAR तकनीक में x, y और z निर्देशांक हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नयन के 3 डी प्रतिनिधित्व का उत्पादन करने के लिए अविश्वसनीय रूप से आसान बनाता है कि संबंधित पक्ष अधिक आसानी से आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
- **कृषि:** कृषि क्षेत्र में LiDAR प्रौद्योगिकी के विशिष्ट अनुप्रयोगों में उपज दरों, फसल स्काउटिंग और बीज फैलाव का विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, यह अभियान योजना के लिए भी उपयोग किया जाता है, वन चंदवा के तहत मानचित्रण, और बहुत कुछ।
- **सुरक्षा:** LiDAR का उपयोग सैन्य द्वारा राष्ट्रीय सीमाओं के पास विभिन्न सुरक्षा अभियानों को करने के लिए किया जाता है।
- **बचाव मिशन:** जब अधिकारी समुद्री दुर्घटना के मामले में या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए समुद्र की सतह की सही गहराई जानना चाहते हैं, तो वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए LiDAR तकनीक का उपयोग करते हैं

LiDAR के उपयोग के लाभ

- **डेटा को जल्दी और उच्च सटीकता के साथ एकत्र किया जा सकता है:** LiDAR एक हवाई संवेदी तकनीक है जो डेटा संग्रह को तेज़ बनाता है और स्थितिगत लाभ के परिणामस्वरूप अत्यधिक सटीकता के साथ आता है।
- **सरफेस डेटा का नमूना घनत्व अधिक होता है:** LiDAR डेटा संग्रहण के अन्य तरीकों जैसे कि फोटोग्राममिति की तुलना में बहुत अधिक सतह घनत्व देता है। यह कुछ प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए परिणामों में सुधार करता है जैसे कि बाढ़ का मैदान।

- **घने जंगल में ऊंचाई डेटा एकत्र करने में सक्षम:** LiDAR तकनीक घनी आबादी वाले जंगल से उच्च मर्मज्ञ क्षमताओं के लिए ऊंचाई डेटा एकत्र करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह घने जंगलों वाले क्षेत्रों को भी मैप कर सकता है।
- **दिन और रात का उपयोग किया जा सकता है:** LiDAR तकनीक का उपयोग दिन और रात में सक्रिय रोशनी सेंसर के लिए किया जा सकता है। यह अंधेरे और प्रकाश जैसी हल्की विविधताओं से प्रभावित नहीं है। इससे इसकी कार्यक्षमता में सुधार होता है।
- **यह चरम मौसम से प्रभावित नहीं होता है:** LiDAR तकनीक चरम मौसम की स्थिति जैसे कि अत्यधिक धूप और अन्य मौसम परिदृश्यों से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब है कि डेटा को अभी भी इन शर्तों के तहत एकत्र किया जा सकता है और विश्लेषण के लिए भेजा जा सकता है।
- कोई ज्यामिति विकृतियाँ नहीं है
- इसे अन्य डेटा स्रोतों के साथ एकीकृत किया जा सकता है
- इसकी न्यूनतम मानवीय निर्भरता है
- भूतल डेटा में एक उच्च नमूना घनत्व है
- दुर्गम और सुविधा रहित क्षेत्रों को मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है

LiDAR के नुकसान

- कुछ अनुप्रयोगों में उच्च परिचालन लागत
- अपवर्तन के प्रभाव के कारण भारी बारिश या कम लटके बादलों के दौरान अप्रभावी। हालांकि, एकत्र किए गए डेटा का उपयोग अभी भी विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।
- उच्च सूर्य कोणों और प्रतिबिंबों पर क्रमबद्ध
- अशांत टूटने वाली तरंगों के लिए अविश्वसनीय है क्योंकि यह दालों के प्रतिबिंब को प्रभावित करेगा
- कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं
- बहुत बड़े डेटा सेट जिनकी व्याख्या करना मुश्किल है।
- लेजर बीम उन मामलों में मानव आंख को प्रभावित कर सकते हैं जहां बीम शक्तिशाली है
- कुशल डेटा विश्लेषण तकनीकों की आवश्यकता है
- 500-2000 मीटर के बीच कम परिचालन ऊंचाई

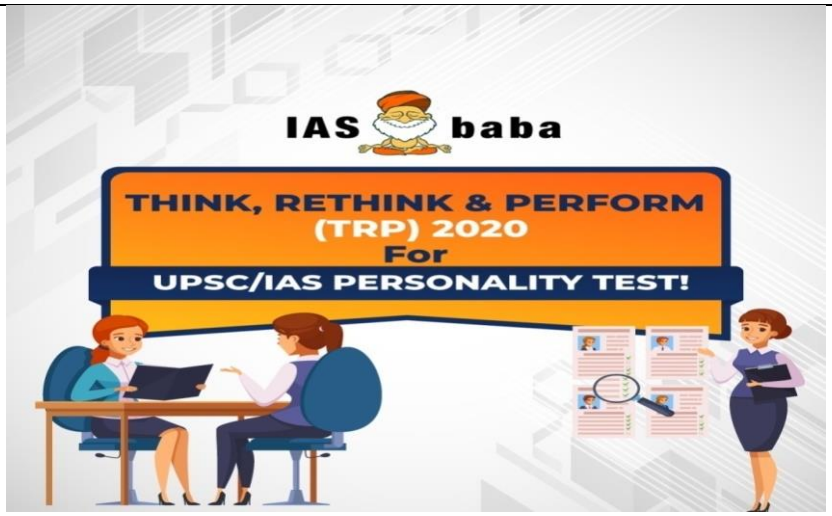

आपदा प्रबंधन

सिमलीपाल वन की आग

संदर्भ: सिमलीपाल वन आरक्षित क्षेत्र अक्सर शुष्क मौसम जंगल की आग का कारण बनता है। फरवरी 2021 में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में शुरू हुई आग लगभग एक सप्ताह तक भड़की थी, जिसे अंत में काबू कर लिया गया।

सिमलीपाल रिजर्व के बारे में

- **स्थान:** सिमलीपल का नाम 'सिमुल' (Simul- सिल्क कॉटन) के पेड़ से लिया गया है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है।
- **संरक्षण:** यह एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। इसके अलावा, सिमिलिपाल और आस-पास के क्षेत्र, जिसमें 5,569 वर्ग किमी शामिल हैं तथा भारत सरकार द्वारा 22 जून 1994 को एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जो पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है
- **जैव विविधता में समृद्ध:** सिमिलिपल ऑर्किड की 94, पौधों की लगभग 3,000, उभयचरों की 12, सरीसृपों की 29, पक्षियों की 264 और स्तनधारियों की 42 प्रजातियों का निवास है। इनमें साल वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है।
- **मानव बस्तियाँ:** रिजर्व के संक्रमण क्षेत्र में 1,200 गाँव हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 4.5 लाख है। तथा आदिवासियों की आबादी लगभग 73 प्रतिशत है।

सिमलीपाल वन कितना अग्नि प्रवण है?

- आम तौर पर ग्रीष्मकाल की शुरुआत और शरद ऋतु के अंत में, वन क्षेत्र जंगल की आग की चपेट में रहता है।
- यह एक बार-बार वार्षिक घटना है, लेकिन वर्षा की अवधि कम होने के कारण आग नियंत्रण में रहती हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में क्रमशः 10.8 और 21 मिमी की बारिश होती है।
- यह अवधि वन क्षेत्रों में पर्णपाती जंगलों के बहने के साथ मेल खाती है। गिरी हुई पत्तियाँ आग पकड़ने के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं और पूरे वन क्षेत्र में इन जंगल की आग को फैलने की सुविधा प्रदान करती है

जंगल की आग का कारण

- **प्राकृतिक कारण** जैसे प्रकाश व्यवस्था या बढ़ते हुए तापमान भी कभी-कभी इन आग का कारण बनते हैं। सूखे पत्तों और पेड़ों की छाल के साथ, यहां तक कि एक चिंगारी से भीषण आग लग सकती है।
- **अवैध शिकार:** अधिकांश आग को मानव निर्मित उत्पादों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शिकार करने तथा शिकारियों ने जंगली जानवरों को हटाने के लिए जंगल के एक छोटे से हिस्से को आग लगा देते है जिससे ऐसी आग लग जाती है।
- **महुआ के फूलों का संग्रह:** महुआ के फूलों के संग्रह के लिए जमीन पर सूखे पत्तों को साफ करने के लिए ग्रामीणों द्वारा जंगल के इलाकों में आग लगाई जाती है। इन फूलों का उपयोग एक पेय तैयार करने के लिए किया जाता है जो प्रकृति में नशा के रूप उपयोग किया जाता है।
- **पारंपरिक प्रथाएँ:** ग्रामीणों का यह भी मानना है कि दोबारा पेड़ लगाने पर खारे पेड़ों के जलने से बेहतर विकास होगा।
- **जलवायु परिवर्तन:** इस वर्ष, मानव निर्मित उत्पादों के साथ, गर्मी की शुरुआत में अधिक गर्मी होने से स्थिति को और खराब कर देती है।

इन जंगल की आग को कैसे नियंत्रित और रोका जाता है?

इस तरह की आग को आमतौर पर प्राकृतिक बारिश द्वारा नियंत्रण में लाया जाता है। आग को रोकने के कुछ तरीकों में शामिल हैं

- आग लगने का पूर्वानुमान दिन

- **अग्नि रेखाएं बनाना:** वन की अग्नि रेखाएं जो स्ट्रिप्स वनस्पतियों से दूर रखी जाती हैं, जंगल को आग से फैलने से रोकने के लिए डिब्बों को तोड़ने में मदद करती हैं।
- सूखे बायोमास के समाशोधन स्थल
- शिकारियों पर नकेल
- आग की घटनाओं को कम करने के लिए समुदाय के सदस्यों सहित

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ऑस्ट्रेलिया वाइल्डफायर
- अमेज़ॅन वर्षावन आग

एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - आपदा प्रबंधन

सुर्खिओ में क्यों-

- चालक के बगल तथा एक वाहन की अगली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी की गई है।
- **मंत्रालय:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- 1 अप्रैल, 2021 (नए मॉडल) और 31 अगस्त, 2021 (मौजूदा मॉडल) के बाद निर्मित वाहनों को एयरबैग के साथ लगाया जाएगा।
- यह सेफ्टी फीचर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के सुझावों पर आधारित है।
- यह एम -1 श्रेणी के सभी मौजूदा मॉडलों के लिए अनिवार्य है – यात्री, मोटर वाहन जिनमें चालक के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

एयरबैग्स

- टकराव के दौरान एक एयरबैग यात्री और कार के डैशबोर्ड के बीच एक सुरक्षात्मक गद्दे जैसा पॉप अप होता है।
- मध्यम से गंभीर दुर्घटनाओं में, वाहन के कठिन संरचनाओं में संपर्क करने से किसी व्यक्ति के सिर और छाती को रोकने के लिए फ्रंट एयरबैग को फुलाया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दुनिया के सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों का 10% हिस्सा होता है।
- ऑटोमोबाइल में कुछ अन्य सुरक्षा विशेषताएं हैं:

1. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
2. स्पीड अलर्ट सिस्टम
3. रिवर्स पार्किंग सेंसर
4. ड्राइवर और यात्री सीट बेल्ट अनुस्मारक
5. केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

चीन की साइबर आंख और भारत

संदर्भ: हाल ही में, एक साइबर खुफिया फर्म का दावा है कि चीनी सरकार से जुड़े हैकिंग समूह ने भारत के कोविद -19 टीकाकरण कार्यक्रम के वर्तमान में उपयोग होने वाले दो टीकों के निर्माताओं को लक्षित किया है।

स्टोन पांडा और टीके

- 'स्टोन पांडा' नाम से प्रचलित चीन के एक हैकर समूह द्वारा 'भारत बायोटेक' और 'सीरम इंस्टीट्यूट' की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कई सुभेद्यताएँ खोजी गई थीं।
- इन कंपनियों ने कोवाक्सिन और कोविशिल्ड को विकसित किया है, जिनका उपयोग वर्तमान में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोविद -19 टीके के परीक्षण की प्रक्रिया में हैं जो दुनिया भर में मूल्य मिल सकता हैं।
- **साइबर हमलों में वृद्धि:** कोविद -19 वैक्सीन के विकास में शामिल कुछ भारतीय कंपनियों ने बताया कि उन्होंने पिछले छह महीनों में चीन और रूस जैसे देशों से विदेशी संस्थाओं द्वारा साइबर हमले के प्रयासों में लगभग सौ गुना वृद्धि देखी है।

संभावित कारण:

- जून 2020 में एक प्रमुख कारक दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष है।
- ये प्रयास एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं - भविष्य में आगे के संचालन के लिए आधार का परीक्षण करने और रखने के लिए।
- उनका उपयोग डायवर्सनरी टैक्टिक के रूप में भी किया जा सकता है।
- जब वैक्सीन कंपनियों को लक्षित किया जाता है, तो इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का हो सकता है। एसआईआई और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम के खिलाफ स्टोन पांडा के हमले के पीछे का कारण कंपनियों की बौद्धिक संपदा को निकालना और "भारतीय दवा कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ" हासिल करना था।

विभिन्न निगरानी और हैकिंग के प्रयासों और उनके निहितार्थों पर एक नज़र:

- सितंबर 2020 में डिजिटल फुटप्रिंट की निगरानी: पिछले साल भारत और चीन संबंधों के बीच में खटास के साथ, चीनी सरकार से जुड़ी कंपनी के हजारों भारतीय नागरिकों के डिजिटल फुटप्रिंट पर नजर रखने के प्रयास सितंबर महीने में सबूत सामने आए।
- रेड इको और शैडोपैड: पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैलवेयर का खतरा: नवंबर में, सरकार को अपने पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में एक मैलवेयर के खतरे से अवगत कराया गया था -जो पिछले महीने एक चीनी राज्य समर्थित फर्म से जुड़ा था।

निहितार्थ

- **"सूचना पुस्तकालय" का रखरखाव:** सितंबर 2020 के दौरान निगरानी रखने वालों में न केवल प्रभावशाली राजनीतिक और औद्योगिक आंकड़े शामिल थे, बल्कि प्रमुख पदों, न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों, पत्रकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, धार्मिक हस्तियों, कार्यकर्ताओं आदि में नौकरशाह शामिल थे।
- **डेटाबेस टैक्टिकल पैंतरेबाज़ी के लिए उत्तरदायी है:** इस तरह के डेटा का संग्रह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह लगभग सभी डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। हालाँकि, साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों की राय है कि एकत्र की गई जानकारी सामरिक पैंतरेबाज़ी के लिए निगरानी एक साथ रखी जा सकती है या उनके संस्थानों के तहत व्यक्तियों को लक्षित कर सकती है।
- **पावर ग्रिड की स्थिरता और अखंडता पर हमला:** रेड इको की पावर शैडोपैड मैलवेयर के माध्यम से पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (POSOCO) के देश के लोड डिस्पैच केंद्र को लक्षित करने का प्रयास, देश के पावर ग्रिड के सुचारू संचालन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

चुनौतियां

- भारत ने स्वेच्छा से इन प्रयासों के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यह अन्य कंपनियों को छोड़ सकता है और सरकारी निकाय इस तरह के हमलों के प्रति अपनी भेद्यता के बारे में अंधेरे में हो सकते हैं।
- सरकार के आदेश की श्रृंखला पर बहुत कम स्पष्टता है जहां साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, क्योंकि विभिन्न एजेंसियां इस मुद्दे से निपटती हैं। इससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इस तरह के साइबर खतरों की स्थिति में सभी किससे संपर्क करें।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वैक्सीन राष्ट्रवाद

मैरीटाइम इंडिया समिट 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने 'मैरीटाइम इंडिया समिट 2021' का उद्घाटन किया।

शिखर सम्मेलन के मुख्य अंश

- मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 सरकार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 870 मिलियन टन (2014) से बढ़कर 1550 मिलियन टन हो गई है।
- कांडला में वाधवन, पारादीप और दीनदयाल पोर्ट को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के साथ मेगा पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों का परिचालन करना है।
- भारत में विशाल समुद्र तट पर 189 प्रकाश स्तंभ हैं।
- इसने 78 प्रकाश स्तंभों से जुड़े भूमि में पर्यटन को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया है।
- कोच्चि, मुंबई, गुजरात और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों और शहरों में शहरी जल परिवहन प्रणालियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय शिपयार्ड के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दी गई है।
- पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने $ 400 बिलियन की निवेश योग्य परियोजनाओं की सूची बनाई है जिसमें 31 बिलियन डॉलर की निवेश क्षमता है।
- **सागर-मंथन:** मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर शुरू किया गया है।
- यह समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव क्षमताओं, सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक सूचना प्रणाली है।
- सरकार पूरे देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर सौर और पवन-आधारित बिजली प्रणाली स्थापित करने की योजना में है।
- इसका लक्ष्य भारतीय बंदरगाहों पर तीन चरणों में 2030 तक कुल ऊर्जा का 60% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है।

नेगेव लाइट मशीन गन्स (LMGs)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- भारतीय सेना इज़राइल से पहली बार नई लाइट मशीन गन्स (LMG) को शामिल किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अनुबंधित नेगेव 7.62X51 मिमी LMG एक लड़ाकू आधिकारिक हथियार है।
- वर्तमान में यह दुनिया भर के कई देशों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- यह LMG एक सैनिक की घातकता और रेंज को बहुत बढ़ा देगा।

ईंधन सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम DRDO द्वारा विकसित किया गया।
- यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस प्रणाली को DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (NMRL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- AIP में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की घातकता पर बल गुणक प्रभाव होता है।
- एआईपी तकनीक समंदर के अंदर पनडुब्बियों को ज्यादा देर तक रहने में मदद करता है।
- AIP में अन्य तकनीकों की तुलना में प्रदर्शन में भी योग्यता है।
- NMRL का AIP अद्वितीय है क्योंकि हाइड्रोजन जहाज पर उत्पन्न होता है।

UAPA अधिनियम के तहत गिरफ्तारी में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - तृतीय - आतंकवाद

सुर्खिओ में क्यों-

- गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, 2019 में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां [रोकथाम] अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या में वर्ष 2015 की तुलना में 72% की वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2019 में, उत्तर प्रदेश (498), मणिपुर (386), तमिलनाडु (308), जे एंड के (227) और झारखंड (202) में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुईं।
- 2016-2019 के बीच यूएपीए के द्वारा दर्ज किए गए मामलों में से केवल 2.2% अदालत द्वारा सजा में ख़त्म हुए।
- यूएपीए के द्वारा मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की जाती है।
- यूएपीए के द्वारा जमानत मिलना दुर्लभ है और जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने में 180 दिन तक का समय लगता है।

पार्श्व निगरानी: साइबर अपराध वालंटियर्स कार्यक्रम

संदर्भ:

- गृह मंत्रालय (एमएचए) के द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने राष्ट्र की सेवा करने और देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान हेतु नागरिकों को एक ही मंच पर लाने के लिये साइबर अपराध वालंटियर्स कार्यक्रम की परिकल्पना की है।

- अवैध/गैर-कानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और उसे हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुविधा हेतु साइबर अपराध वालंटियर्स के रूप में पंजीकृत होने के लिये अच्छे नागरिकों का स्वागत किया जाता है।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य नोडल अधिकारी कार्यक्रम के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में वालंटियर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी रखते हैं।

पार्श्व निगरानी

- निगरानी का यह रूप, जो नागरिकों को एक दूसरे को "निगरानी" करने में सक्षम बनाता है, जिसे पार्श्व निगरानी कहा जाता है
- जबकि किसी भी प्रकार की निगरानी सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति के बीच शक्ति का असंतुलन निगरानी में दिखाती है और पार्श्व निगरानी विशेष रूप से यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति का असंतुलन अब मौजूद नहीं है

उत्पन्न चिंताएँ:

- **लेटरल सर्विलांस का कारण:** जहां कहीं भी राज्य यह पहचानता है कि यह "हर जगह नहीं हो सकता", यह इस तंत्र को तैनात करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह संगठित और राज्य प्रायोजित होता है
- **हर्ट्स गोपनीयता:** समुदाय के निर्माण और पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने जैसे भावनात्मक उद्देश्यों के लिए पार्श्व निगरानी का उपयोग किया जाता है जहां भावनात्मक और सामाजिक कारक एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रकार ये ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां समुदाय की बेहतर के लिए गोपनीयता को कम किया जा सकता है।
- **सामाजिक भेदभाव:** निगरानी तकनीकें न केवल सामाजिक नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में बल्कि सामाजिक बहिष्कार के लिए भी एक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार पार्श्व निगरानी उन लोगों के बीच भेदभाव करना आसान बनाती है जो बहुमत के सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हैं
- **निराश्रितों की संस्कृति:** राज्य द्वारा प्रायोजित पार्श्व निगरानी हानिकारक है क्योंकि यह 'घृणा', 'भय' और 'शत्रु के खिलाफ निरंतर संदेह' की संस्कृति पैदा करता है। यह संस्कृति लोगों पर उनकी अपनी सुरक्षा के लिए नजर रखने के लिए रखती है और इससे समाज में अपराध की आशंका बढ़ जाती है।
- **सोसाइटी में विडन फॉल्टलाइन:** इस तरह के कथित खतरों में हमारे समाज में असहिष्णुता, पूर्वाग्रह, ज़ेनोफोबिया और जातिवाद को बढ़ाने की प्रवृत्ति है, जबकि निजता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है, परिणामस्वरूप मुक्त भाषण और व्यवहार की अभिव्यक्ति

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नए आईटी नियम

मिलान-2T

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खिओ में क्यों-

- रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग (MoD) ने भारतीय सेना को MILAN-2T एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGMs) की आपूर्ति के लिए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (DPSU) भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मिलान -2 T, 1,850 मीटर की रेंज के साथ एक टेंडम वारहेड एटीजीएम है, जिसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से फ्रांस की एक रक्षा फर्म से मिले लाइसेंस के तहत विकसित किया जा रहा है।
- इन मिसाइलों को जमीन से और वाहन-आधारित लांचर से भी दागा जा सकता है।

- इन्हें आक्रामक और रक्षात्मक कार्यों दोनों के लिए एंटी-टैंक रोल में भी तैनात किया जा सकता है।
- इन मिसाइलों का इंडक्शन सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को और बढ़ाएगा जो तीन साल में पूरी होगी।
- यह रक्षा क्षेत्र में आत्मानिभर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कदम है।

विविध

समाचार	विवरण में
1. **पूर्णागिरि मंदिर**	• हाल ही में पूर्णागिरि मंदिर खबरों में था। • हाल ही में टनकपुर (उत्तराखंड) -दिल्ली जंक्शन स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया था। • पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित किया गया। • उत्तराखंड में नवरात्रि पर अन्नपूर्णा के मंदिर क्षेत्र में पूर्णागिरि मेले का आयोजन करता है। • यह मंदिर उत्तराखंड के चंपावत में काली नदी के दाहिने किनारे पर टनकपुर से 20Km की दूरी पर स्थित है। • पूर्णागिरि देवी मंदिर 108 सिद्ध पीठों में से एक है।
2. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	• राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। • यह 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। • इस दिन, भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की , जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। • इस दिन का उद्देश्य मानव जीवन में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश जानना है। • **थीम:** फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन: इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क '।
3. सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम (SKAT)	• सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम (SKAT) श्रीलंका की वायु सेना (SLAF) की 70 वीं वर्षगांठ समारोह के भाग के रूप में 3 से 5 मार्च तक कोलंबो में गॉल फेस पर एक एयरशो में प्रदर्शन करेगी। • 1996 में किरण एमके -2 विमान के साथ टीम का गठन किया गया। • 2015 में हॉक विकसित जेट प्रशिक्षकों के साथ SKAT टीम को फिर से पुनर्जीवित किया गया। • SKAT टीम, जिसे 52 स्क्वाड्रन या द शार्क के रूप में भी जाना जाता है जो यह बीदर में स्थित है
4. सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च	• सदियों पुराना सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च केरल के चेप्पड में स्थित है • अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की मान्यता के साथ राष्ट्रीय महत्व का एक

	केंद्र-संरक्षित स्मारक बनने के लिए तैयार किया गया • यह चर्च केरल में सबसे दुर्लभ में से एक है। • इसमें वेदी की दीवारों पर दुर्लभ और सुंदर भित्ति चित्रों के साथ पारंपरिक केरल चर्च वास्तुशिल्प पैटर्न है। • इन चित्रों में फ़ारसी और केरल भित्ति कला शैली निहित हैं
5. व्यायाम डेजर्ट फ्लैग VI	• भारतीय वायु सेना पहली बार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भाग ले रही है • इसमें यूएई, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायु सेनाएं शामिल हैं। • यह एक वार्षिक बहु-राष्ट्रीय बड़ा शक्ति रोजगार युद्ध अभ्यास है। • द्वारा मेजबानी: संयुक्त अरब अमीरात वायु सेना • भारतीय वायुसेना छह Su-30 MKI, दो C-17 और एक IL-78 टैंकर विमानों के साथ भाग ले रही है। • **उद्देश्य:** एक नियंत्रित वातावरण में सिम्युलेटेड वायु से निपटने के कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देते समय प्रतिभागी बलों को परिचालन जोखिम प्रदान करना।
6. आईएनएस करंज	• इंडियन नेवी की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन आईएनएस करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में प्रमाणित किया गया है। • स्कॉर्पीन पनडुब्बियां विश्व की सबसे विकसित पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक हैं। • अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक घातक और गुप्तचर, ये पनडुब्बियां समुद्री सतह के ऊपर या नीचे किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए शक्तिशाली हथियारों और सेंसर से सुसज्जित हैं।
7. डस्टलिक	• भारत - उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास "DUSTLIK II" विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया, रानीखेत (उत्तराखंड) में शुरू हुआ। • संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पर्वतीय / ग्रामीण / शहरी परिदृश्यों में आतंकवादियों के संचालन के क्षेत्र में दोनों टुकड़ियाँ अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगी • यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है
8. बारलाचा	• बारा-ला ला को बर-लचा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। • यह ज़ांस्कर क्षेत्र में एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। • यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। • यह लेह-मनाली राजमार्ग के साथ स्थित है। • यह दर्रा भगा नदी और युनाम नदी के बीच जल-विभाजन के रूप में भी कार्य करता है। • भगा नदी, चिनाब नदी की एक सहायक नदी है जो सूर्या ताल झील से निकलती है
9. स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव	• भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया • समिति को आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जाता है।

	• 75 वर्ष के जश्न के लिए 5 स्तंभ तय किए गए। • **5 स्तंभ:** स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्य और 75 पर संकल्प। • राष्ट्रीय समिति के सदस्य: राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्य मंत्री, राजनीतिक नेता, वैज्ञानिक, अधिकारी, मीडिया व्यक्तित्व, आध्यात्मिक नेता और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल है
10. गांधी शांति पुरस्कार	• वर्ष 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। • **2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार:** (दिवंगत) महामहिम सुल्तान कबूस बिन ओमान के अल सईद को मिला • 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान • गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। • यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए अनावृत है। • गांधी शांति पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है, और इसमें दो पदेन सदस्य होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। • पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए , एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला / हथकरघा वस्तु दिए जाते है
11. इंडो-कोरियन फ्रेंडशिप पार्क	• भारत के पहले इंडो-कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र कोरिया और भारत ने दिल्ली कैंटोनमेंट में हुआ। • यह दिल्ली छावनी में है। • यह पार्क मजबूत भारत-दक्षिण कोरिया के मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। • यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कोरियाई युद्ध 1950-53 में भाग लेने वाले 21 देशों के हिस्से के रूप में भारत के योगदान का एक स्मारक भी है। • पार्क के स्तंभों में से एक में नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के कोरिया का वर्णन "द लैंप ऑफ़ द ईस्ट" है, जो 1929 में कोरियाई दैनिक "डोंग-ए-विल्बो" में प्रकाशित हुआ था।
12. वज्र प्रहार 2021	• हाल ही में इंडो-यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 का 11 वां संस्करण बकलोह, HP में आयोजित किया गया। • यह संयुक्त अभ्यास, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। • **उद्देश्य:** संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना इसके अतिरिक्त विशेष बलों के बीच अंतर को बेहतर बनाना

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मॉडल प्रश्न: (उत्तर अंत में दिए गए हैं)

Q.1 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए मनाया जाता है?

a) शून्य की खोज
b) रमन प्रभाव
c) पाइथोगोरस प्रमेय
d) भारत में थोरियम का भंडार

Q.2 GAVI वैक्सीन गठबंधन निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक कार्यक्रम है?

a) भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका
b) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस
c) यूके और यूएसए
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.3 हाल ही में अमेजोनिया -1 पीएसएलवी-सी 51 रॉकेट के माध्यम से शुभारंभ किया गया उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का है?

a) चीन b) जापान
c) यूएई d) ब्राजील

Q.4 FATF की स्थापना निम्नलिखित में से किससे पकड़ने के लिए की गई थी?

a) मनी लॉन्ड्रिंग
b) आतंक वित्तपोषण
c) विदेशी प्रजातियों का अवैध व्यापार
d) दोनों (a) और (b)

Q.5 बॉन्ड यील्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ब्याज दरों में गिरावट से बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है।
2. बढ़ती ब्याज दरों से बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, और बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6 विकास नीति समिति निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक संस्था है?

a) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
b) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
c) विश्व स्वास्थ्य संगठन
d) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

Q.7 Aos निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है?

a) नागालैंड b) मणिपुर
c) मिजोरम d) मेघालय

Q.8 मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (MTRC) प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह व्यवस्था करने वाला मुंबई पहला राज्य बन गया है।
2. यह प्रभावी दुर्घटनाओं के माध्यम से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और देरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9 सुगम्य भारत ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?

a) विद्युत मंत्रालय
b) पर्यावरण मंत्रालय
c) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
d) अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

Q.10 बीएस-VI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. BS-VI ग्रेड ईंधन में 10 पीपीएम सल्फर है।
2. BS VI डीजल कारों में पार्टिकुलेट मैटर को 80% तक नीचे ला सकता है।

3. BS-VI के तले सभी वाहनों के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD) अनिवार्य है।

उपरोक्त में से कौन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3 ही
d) 1, 2 और 3

Q.11 हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ER & D) नीति शुरू की गई थी:

a) गुजरात b) महाराष्ट्र
c) कर्नाटक d) तेलंगाना

Q.12 प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है?

a) पर्यावरण मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) विद्युत मंत्रालय
d) पर्यटन मंत्रालय

Q.13 प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है?

a) पहचान किए गए ग्रामीण स्कूलों का एकीकृत विकास
b) पहचान किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का एकीकृत विकास
c) पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास
d) चिन्हित रेलवे स्टेशनों का एकीकृत विकास

Q.14 हाल ही में नाग नदी चर्चा में थी। यह निम्न में से किसके माध्यम से बहती है?

a) नागपुर b) नागालैंड
c) उत्तराखंड d) अहमदाबाद

Q.15 विश्व सीमा संगठन (WCO) का मुख्यालय कहां है?

a) ब्रुसेल्स b) एम्स्टर्डम
c) न्यूयॉर्क d) नई दिल्ली

Q.16 हिमालयन सीरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका IUCN स्टेटस लगभग संकट में है
2. यह CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/ या सही है?

a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 बागवानी निम्नलिखित में से किसकी खेती से संबंधित है?

a) मधुमक्खियों
b) रेशम के कीड़े
c) केवल फूलों और सजावटी पौधों
d) फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधे

Q.18 "ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स -2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

a) पर्यावरण मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
d) एमईएमएस मंत्रालय

Q.19 निम्नलिखित में से कौन सा / से आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

1. आयुर्वेद
2. योग और प्राकृतिक चिकित्सा
3. यूनानी
4. सिद्ध
5. होमियोपैथी
6. एलोपैथी

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 2, 3, 4 और 5
b) केवल 2, 3, 5 और 6
c) केवल 1, 2, 3, 4 और 5
d) केवल 1, 2 और 3

Q.20 निम्न में से कौन नॉर्डिक क्षेत्र में नहीं आता है?

a) डेनमार्क b) नॉर्वे
c) स्वीडनd) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.21 भारत के पहले ट्रांसजेंडर समुदाय डेस्क का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था?

a) मध्य प्रदेश
b) तेलंगाना
c) महाराष्ट्र
d) गुजरात

Q.22 एग्रोफोरेस्ट्री (एसएमएएफ) योजना पर उप-मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह योजना राष्ट्रीय कृषि नीति 2014 की सिफारिश का एक हिस्सा है।
2. भारत ऐसी व्यापक नीति रखने वाला पहला देश है

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह एक स्वायत्त निकाय है।
2. यह कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.24 निम्नलिखित सुरक्षा सुविधाओं पर विचार करें:

1. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
2. स्पीड अलर्ट सिस्टम
3. रिवर्स पार्किंग सेंसर
4. केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

ये निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं?

a) विमान b) सीप्लेन
c) ऑटोमोबाइल्स d) जहाजों

Q.25 हाल ही में सिंगोरगढ़ किला सुर्खियों में था। यह स्थित है?

a) राजस्थान b) गुजरात
c) उत्तर प्रदेश d) मध्य प्रदेश

Q.26 सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनूठी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?

a) इसके शहर क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित थे
b) इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे
c) इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था
d) इनमें से कोई नहीं

Q.27 उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?

a) समय पर उड़ानों को चलाने के लिए।
b) भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए
c) आम आदमी के लिए उड़ानें सस्ती करना
d) उड़ान यात्रियों को स्वच्छ और सस्ता भोजन प्रदान करना।

Q.28 SATAT योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

a) एमएसएमई मंत्रालय
b) पेट्रोलियम मंत्रालय
c) वस्त्र मंत्रालय
d) शिक्षा मंत्रालय

Q.29 हाल ही में देवारा काडु समाचारों में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?

a) पवित्र सरोवर b) पवित्र नदी
c) पवित्र जनजाति d) पवित्र विवाह

Q.30 इंदिरा साहनी का फैसला निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?

a) मौलिक अधिकार
b) संविधान की मूल संरचना
c) आपातकालीन प्रावधान
d) नौकरियों और शिक्षा में 50% आरक्षण

Q.31 इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करें:

1. उच्च ब्याज दर
2. उच्च बीमा दर
3. कम ऋण-से-मूल्य अनुपात

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.32 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है।
2. जहाज पर उत्पन्न हाइड्रोजन AIP को विशिष्ट बनाता है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.33 कुसुम योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
a) पर्यावरण मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) कृषि मंत्रालय
d) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

Q.34 मैत्री सेतु पुल निम्नलिखित में से किस देश के बीच बनाया गया है?
a) भारत और नेपाल
b) भारत और म्यांमार
c) भूटान और नेपाल
d) भारत और बांग्लादेश

Q.35 फेनी नदी निम्नलिखित में से किसके बीच बहती है?
a) त्रिपुरा और मिजोरम
b) त्रिपुरा और बांग्लादेश
c) त्रिपुरा और नागालैंड
d) त्रिपुरा और मेघालय

Q.36 हाल ही में दूरसंचार कंपनियों के लिए संशोधित लाइसेंस शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विश्वसनीय दूरसंचार उत्पादों की खरीद के लिए रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा नए मापदंड हैं
2. राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समन्वयक (NCSC) द्वारा जिन दूरसंचार कंपनियों के उत्पादों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, उनकी सूची को मंजूरी दे दी गई है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37 निम्नलिखित में से कौन QUAD का सदस्य नहीं है
a) जापान
b) यूएसए
c) भारत 1 और 2 दोनों
d) चीन

Q.38 बामियान घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?
a) भारत
b) अफगानिस्तान
c) कनाडा
d) ब्राजील

Q.39 बामियान बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे गुप्त, ससानियन और हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम के महान उदाहरण हैं।
2. यूनेस्को ने 2003 में विश्व विरासत स्थलों की अपनी सूची में उनके अवशेषों को शामिल किया
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.40 निम्नलिखित में से कौन-सा लेख राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है?
a) अनुच्छेद 243 कb) अनुच्छेद 240 क
c) अनुच्छेद 244 कd) अनुच्छेद 217

Q.41 झुरान का गठन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है?
a) ओडिशा b) तमिलनाडु

c) असम d) गुजरात

Q.42 वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है:

a) केरल
b) तमिलनाडु
c) आंध्र प्रदेश
d) मेघालय

Q.43 निम्न में से किसके द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण ढाँचे के हिस्से के रूप में नागरिकों को अब उचित दरों पर परीक्षण किए गए अपने नलों में पानी की गुणवत्ता मिल सकती है?

a) स्वच्छ भारत अभियान
b) जल जीवन मिशन
c) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
d) आत्मानिर्भर भारत

Q.44 भोना धार्मिक संदेश के साथ मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है?

a) ओडिशा b) तमिलनाडु
c) असम d) गुजरात

Q.45 प्रोजेक्ट Re-HAB निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है?

a) पर्यावरण मंत्रालय
b) एनआईटीआईयोग
c) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)
d) इसरो

Q.46 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी आबादी ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित है।
2. यह IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 डिजीलॉकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
2. डिजीलॉकर सिस्टम में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.48 कोमोरोस द्वीपसमूह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है?

a) हिंद महासागर
b) अटलांटिक महासागर
c) प्रशांत महासागर
d) आर्कटिक महासागर

Q.49 IQ Air की वैश्विक वायु प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार, निम्न में से किस देश में शीर्ष 15 में सबसे प्रदूषित शहर हैं?

a) चीन b) भारत
c) बांग्लादेश d) पाकिस्तान

Q.50 हाल ही में दिए गए बीमा संशोधन विधेयक 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक बीमा कंपनी में अनुमत अधिकतम विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 100% कर देता है।
2. अधिनियम निवेशकों को एक बीमा कंपनी में पूंजी का 49% तक रखने की अनुमति देता है, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक भारतीय इकाई के पास होना चाहिए

उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.51 वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 20 साल पूरे होने के बाद और निजी वाहनों के मामले में 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट प्रदान करता है
2. कोई भी वाहन जो फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है, उसे जीवन वाहन के अंत के रूप में घोषित किया जा सकता है
उपरोक्त में से कौन सा सही है/ या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.52 न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
2. यह इसरो के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निम्नलिखित में से कौन से हैं?
1. महान अंडमानी
2. ओनगे
3. जारवा
4. धूमधाम
5. प्रहरी
सही कोड का चयन करें:
a) केवल 1, 2, 3
b) केवल 2 और 4
c) केवल 1, 2, 3 और 4
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.54 हीलियम गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक अक्रिय गैस है।
2. राजस्थान में भारत का राजमहल ज्वालामुखी बेसिन अरबों वर्षों से फंसे हीलियम का भंडार है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.55 ग्राम उजाला कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रत्येक घर में 10 एलईडी तक लगेंगी।
2. पहले चरण में, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य वायरस क्या है?
a) सार्स और एचआईवी
b) मर्स और इन्फ्लूएंजा
c) सार्स और मर्स
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.57 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्र द्वारा संचालित अधिकांश निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों के साथ विदेशी व्यापार भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 45% है।
2. प्रत्येक जिले से निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियाँ (SEPC) बनाई जा रही हैं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.58 संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवा (UNOPS) ने भारत के प्रमुख कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में

जल जीवन मिशन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है?

a) यूएसए b) इज़राइल

c) फ्रांस d) डेनमार्क

Q.59 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Xorai एक शंक्वाकार टोपी है जो बांस से बनी और सूखे टोको से ढकी होती है

2. जैपी बेल-धातु से बना तथा प्रमुख रूप से तल पर एक स्टैंड के साथ बिना कवर के एक ट्रे है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.60 उड़गर, अक्सर समाचारों में देखा जाता है, निम्न में से किस देश से संबंधित हैं?

a) हांगकांग

b) जापान

c) तुर्की

d) चीन

Q.61 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. निमोनिया को बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यकलापों को बचपन में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था।

2. सुरक्षा, सेवा, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षीत मातृसदन अश्वसन (SUMAN) और सेवाओं को अस्वीकार करने के लिए शून्य सहिष्णुता शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 तपेदिक का प्रेरक एजेंट है:

a) एक विषाणु

b) जीवाणु

c) कुपोषण

d) प्रोटोजोअन

Q.63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि (IWT) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2. विश्व बैंक किसी भी विवाद समाधान के लिए स्थायी गारंटी था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/ या सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.64 भारतीय सहसंयोजन की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किसके साथ है?

a) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

b) भारत के भागों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

c) भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद

d) दलबदल विरोधी कानून

Q.65 इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल (IMC) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था?

a) पर्यावरण मंत्रालय

b) वित्त मंत्रालय

c) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

d) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

Q.66 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें:

1. कानून मंत्री को नए CJI की नियुक्ति के लिए निवर्तमान CJI की सिफारिश लेनी होगी

2. भारतीय संविधान सीजेआई की नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.67 अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर निम्नलिखित में से कौन सा है?
a) केप ऑफ गुड होप
b) केप अगुलहास
c) केप हैंगकलिप
d) केप पॉइंट

Q.68 टाइग्रे क्षेत्र, जो अधिकतर समाचारों में देखा जाता है, निम्न में से किस देश का है?
a) इरिट्रिया
b) इथियोपिया
c) सूडान
d) लीबिया

Q.69 हाल ही में ट्राइबल टीबी पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी?
a) स्वास्थ्य मंत्रालय
b) जनजातीय मामलों का मंत्रालय
c) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
d) अर्थव्यवस्था मंत्रालय

Q.70 NISAR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो हाल ही में खबरों में था:
1. इसे इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी, JAXA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा
2. यह एक टेनिस कोर्ट के आधे आकार के क्षेत्रों में 0.4 इंच के रूप में पृथ्वी की सतह के घूमने की प्रक्रिया का पता लगाएगा।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/ या सही है?
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.71 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नई खोज की जाने वाली Hypnea Indica और Hypnea Bullata तट के अंतर्दलीय क्षेत्रों में विकसित होती हैं।
2. जीनस Hypnea में कैल्केरियास, इरेक्ट, ब्रांकेड लाल समुद्री शैवाल होते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.72 हार्ट ऑफ एशिया - इस्तांबुल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश की एक पहल है?
a) अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान
b) अफगानिस्तान और भारत
c) तुर्की और भारत
d) अफगानिस्तान और तुर्की

Q.73 हाल ही में संकल्प 46 / L1, समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?
a) श्रीलंका में मानव अधिकारों का दुरुपयोग
b) म्यांमार तख्तापलट
c) हौथिस के खिलाफ सऊदी अरब का संकल्प
d) कोविद -19 से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र का संकल्प

Q.74 हाल ही में छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया?
a) मध्य प्रदेश b) उत्तर प्रदेश
c) राजस्थान d) छत्तीसगढ़

Q.75 नमामि गंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य गंगा के तटों पर बसे शहरों और गांवों के साथ-साथ एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक और स्थायी समाधान प्रदान करना है।
2. इसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.76 हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल पीपीपी मॉडल में से किसका मिश्रण है:
1. ईपीसी – इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
2. बीओटी - बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर
3. डीबीएफओ - डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट
4. BOO - बिल्ड ओन ऑपरेट

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 1, 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) केवल 1 और 4

Q.77 हाल ही में एक नई तितली प्रजाति नेकदुबा सिंहला रामास्वामी सदाशिवन, भारत के किस क्षेत्र में पाई गई?

a) पूर्वी घाट

b) पश्चिमी घाट

c) हिमालय

d) नॉर्थ ईस्ट

मार्च 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1	B	23	D	45	A	67	B
2	D	24	C	46	B	68	B
3	D	25	D	47	D	69	A
4	B	26	C	48	B	70	B
5	C	27	C	49	B	71	C
6	B	28	B	50	B	72	D
7	A	29	A	51	B	73	A
8	C	30	D	52	A	74	A
9	C	31	D	53	D	75	A
10	D	32	C	54	A	76	A
11	C	33	D	55	B	77	B
12	D	34	D	56	C		
13	C	35	B	57	C		
14	A	36	C	58	D		
15	A	37	D	59	D		
16	B	38	B	60	D		
17	D	39	C	61	C		
18	C	40	A	62	B		
19	C	41	D	63	C		
20	D	42	A	64	A		
21	B	43	B	65	D		
22	C	44	D	66	A		

IASbaba
One Stop Destination for UPSC Preparation

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (AIPTS+) – 2021

BOTH in ENGLISH and Hindi (हिन्दी)

- TOTAL NO. OF TESTS = 62 TESTS
  - 52 General Studies (Paper 1) Tests
  - 10 CSAT (Paper 2) Tests.
- ONLINE All India Prelims Test Series (AIPTS) - 2021 is available BOTH in ENGLISH and HINDI
- DETAILED SOLUTION & TECHNIQUES to Decipher the Correct Answer (Elimination Technique)
- With increasing IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS (CA) in the exam, we have Current Affairs Test held every 15 days.
- All the Tests are FLEXIBLE and will be Valid till next Prelims Exam (2021)
- ALL INDIA RANKING - the scores and ranks will be displayed after every test.
- DOUBTS RESOLUTION PAGE- We have a comment section for every question in a Test.
- DETAILED ASSESSMENT OF YOUR PERFORMANCE- For you to analyse your performance we provide 2 tools Time Analytics and Subject-wise Analytics.

NEW !

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES+ (AIPTS+): ALL THE FEATURES OF AIPTS with Video Discussions of BOTH GS & CSAT TESTS

Register Now